चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

www.chauthiduniya.com

समय के साथ बदलते मुस्लिम चेहरे

पेज-3

शिष्टाचार भूलते कांग्रेसी

पेज-4

राजस्थानी संस्कृति को संजोने का प्रयास

पेज-5

ईरान के ख़िलाफ़ साजिश!

पेज-11

1986 से प्रकाशित | दिल्ली, 27 फरवरी-04 मार्च 2012 | मूल्य 5 रुपये

रायबरेली-अमेठी-सुल्तानपुर में

कांग्रेस जीतेगी या हारेगी

राजनीति में ऐसे नेताओं की भी कमी नहीं है, जो यह मानकर चलते हैं कि किसी विशेष इलाक़े से चुनाव लड़कर वे उस क्षेत्र की जनता पर एहसान करते हैं, क्योंकि किसी लोकप्रिय नेता के चुनाव लड़ने से पिछड़ा इलाक़ा भी सुर्ख़ियों में आ जाता है, लेकिन सुर्ख़ियों में आने भर से क्या होता है? ऐसी ही कहानी अमेठी, रायबरेली एवं सुल्तानपुर की भी है. गांधी परिवार के इन संसदीय क्षेत्रों की हालत भी चिराग़ तले अंधेरा जैसी है. राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में घूम-घूमकर यह प्रचार कर रहे हैं कि राज्य के विकास के लिए केंद्र से जो पैसा भेजा जाता है, उसे बसपा का जादुई हाथी खा जाता है, लेकिन ख़ुद अमेठी, जहां से राहुल गांधी चुनकर आते हैं या फिर रायबरेली, जहां से उनकी मां एवं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सांसद हैं, वहां की हालत क्या है? अमेठी से सटे सुल्तानपुर की हालत क्या है? पेश है इन तीनों संसदीय क्षेत्रों की बदहाली को बयां करती चौथी दुनिया की यह ख़ास रिपोर्ट :-

अजय कुमार

आज़ादी से पहले तक जिस उत्तर प्रदेश को हिंदुस्तान का ताज होने का गौरव प्राप्त था, वही आज देश का सबसे पिछड़ा राज्य बन गया है. देश को कई प्रधानमंत्री और क़द्दावर हस्तियां देने वाले उत्तर प्रदेश की दुर्दशा देखकर यह सोचना भी कठिन हो जाता है कि यह राज्य अपनी इस हालत से कैसे छुटकारा पाएगा. इसके लिए जनता को कमर कसनी होगी या फिर रॉबिन हुड जैसा कोई नेता आकर इसकी तक़दीर और तस्वीर बदलेगा. विकास के मामले में वैसे तो पूरा प्रदेश ही पिछड़ा हुआ है, लेकिन अफ़सोस तब और बढ़ जाता है, जब इसके सबसे महत्वपूर्ण संसदीय क्षेत्रों अमेठी और रायबरेली की ओर नज़र जाती है. विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि ये वही क्षेत्र हैं, जहां से इस देश को प्रधानमंत्री मिला. जो देश के सबसे ताक़तवर राजनीतिक परिवार के चुनाव क्षेत्र हैं. फ़िरोज़ गांधी से लेकर इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अब शायद प्रियंका और उनके पति रॉबर्ट वडेरा भी. ये चंद नाम हैं, जो भारतीय राजनीति के सबसे मज़बूत परिवार के हैं. कांग्रेस 50 वर्षों तक सत्ता में रही. ज़ाहिर है, जिन संसदीय क्षेत्रों से ऐसे लोग चुनाव लड़ते और जीतते रहे हों, उन क्षेत्रों का मुस्तक़बिल तो आसमान की बुलंदियों पर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. क्या गांधी ख़ानदान की नई पीढ़ी अपनी राजनीतिक विरासत को संभाल पाने में असफल साबित हुई?

बदहाल विरासत

रायबरेली, अमेठी एवं सुल्तानपुर, ये तीनों संसदीय क्षेत्र गांधी परिवार की राजनीतिक विरासत माने जाते हैं. यहीं से 2009 के लोकसभा चुनाव में फ़तेह हासिल करने वाले राहुल एवं सोनिया आज कांग्रेस और सत्ता की धुरी बने हुए हैं, लेकिन कभी भी गांधी परिवार ने अमेठी-रायबरेली के विकास की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया. बात रायबरेली की करें तो यहां उद्योग के नाम पर 1972 में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री और 1992 में फ़िरोज़ गांधी थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट ही लग पाया. इसके बाद मानो यहां सूखा पड़ गया. इस दौरान कुछ उद्योगपतियों ने ज़रूर अपने प्लांट लगाए, जिनमें बिरला सीमेंट फैक्ट्री, भवानी पेपर मिल, इंडो-गल्फ फर्टिलाइजर एवं रायबरेली टेक्सटाइल मिल के अलावा इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट को गिनाया जा सकता है, लेकिन यह ऊंट के मुंह में ज़ीरा जैसा रहा. इससे न तो युवाओं को कोई ख़ास रोज़गार के अवसर मिले और न रायबरेली को कोई फ़ायदा मिला. युवाओं को उच्च शिक्षा और नौकरी के लिए अन्य राज्यों के शहरों की तरफ़ न चाहते हुए भी पलायन करना पड़ता है. रायबरेली में आज भी कोई ऐसी संस्था नहीं है, जहां से यहां के युवक तकनीकी शिक्षा हासिल कर सकें. युवा पीढ़ी शिक्षा के सीमित साधनों और बेरोज़गारी से जूझ रही है तो किसान बिजली और सिंचाई के पर्याप्त साधन न होने के कारण परेशान हैं. कहने को यहां थर्मल पॉवर प्लांट लगा है, लेकिन इसकी बिजली रायबरेली वालों को नहीं मिलती. सोनिया गांधी ने यहां रेल कोच फैक्ट्री लगाने की बात कही थी, लेकिन इस काम में भी काफ़ी देरी हुई. साथ ही फैक्ट्री के लिए अधिग्रहीत की गई ज़मीन का न तो मुआवज़ा मिला और न किसी को नौकरी मिली. मुंशीगंज चीनी मिल अभी भी बंद पड़ी है. आईटीआई की ख़स्ता हालत से बेरोज़गारी बढ़ी, सो अलग. यहां की सड़कों और चौराहों को देखकर ऐसा लगता है, जैसे हम आदिम युग में पहुंच गए हों. लोग तो अब यहां तक कहने लगे हैं कि जब जगह-जगह गड्ढे और सड़क पर उड़ती धूल दिखाई पड़ने लगे तो समझ लें कि आप देश की सबसे ताक़तवर राजनीतिक महिला सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र में आ गए हैं. यही हाल राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी का है, जिसका नया नाम छत्रपति शाहू जी महाराज नगर है. राहुल भले ही चुनावी समर में प्रदेश की जनता को विकास के सपने दिखा रहे हों, लेकिन अपने संसदीय क्षेत्र में उन्होंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया है, जिससे उनकी बातों पर विश्वास किया जा सके. राहुल अमेठी आते ज़रूर हैं, लेकिन दलितों के घर खाना खाकर और गांवों में चौपाल लगाकर पिकनिक मनाने के लिए. यहां तक कि उनके पास सांसद निधि की पूरी रक़म ख़र्च करने का भी समय नहीं रहता. 2009-10 के आंकड़ों के मुताबिक़, अमेठी में राहुल गांधी की सांसद निधि की महज़ 35 फ़ीसदी रक़म ख़र्च हो पाई, वहीं रायबरेली में सोनिया गांधी की सांसद निधि की महज़ 58 फ़ीसदी रक़म ख़र्च हो सकी. अगर राहुल और सोनिया अपनी सांसद निधि को ही सलीक़े से ख़र्च कर देते तो अमेठी और रायबरेली की क़िस्मत संवर जाती. वहीं सुल्तानपुर, जिसमें अमेठी के 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और जहां के सांसद भी कांग्रेस के हैं, वहां की हालत भी कम ख़राब नहीं है. गांधी परिवार के इन संसदीय क्षेत्रों की हालत भी चिराग़ तले अंधेरा जैसी है. राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में घूम-घूमकर यह प्रचार कर रहे हैं कि राज्य के विकास के लिए केंद्र से जो पैसा भेजा जाता है, उसे बसपा का जादुई हाथी खा जाता है, लेकिन ख़ुद अमेठी, जहां से राहुल गांधी चुनकर आते हैं या फिर रायबरेली, जहां से उनकी मां एवं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सांसद हैं, वहां की हालत क्या है? अमेठी से सटे सुल्तानपुर की हालत क्या है? पेश है इन तीनों संसदीय क्षेत्रों की बदहाली को बयां करती चौथी दुनिया की यह ख़ास रिपोर्ट :-

2009-10 के आंकड़ों के मुताबिक़, अमेठी में राहुल गांधी की सांसद निधि की महज़ 35 फ़ीसदी रक़म ख़र्च हो पाई, वहीं रायबरेली में सोनिया गांधी की सांसद निधि की महज़ 58 फ़ीसदी रक़म ख़र्च हो सकी. अगर राहुल और सोनिया अपनी सांसद निधि को ही सलीक़े से ख़र्च कर देते तो अमेठी और रायबरेली की क़िस्मत संवर जाती. वहीं सुल्तानपुर, जिसमें अमेठी के 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और जहां के सांसद भी कांग्रेस के हैं, वहां की हालत भी कम ख़राब नहीं है.

ग़लती किसकी

आख़िर कांग्रेस के प्रथम परिवार के क्षेत्रों की यह हालत क्यों है, सोनिया और राहुल गांधी के सिपहसालार कौन हैं और किनकी वजह से गांधी ख़ानदान के पारंपरिक संसदीय क्षेत्र अमेठी, रायबरेली और सुल्तानपुर अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहे हैं? इस सवाल का जवाब जानना भी ज़रूरी है. एक ज़माना था, जबकि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी अपने क्षेत्र के लिए कम से कम

(शेष पृष्ठ 2 पर)

अब यह बात मुख्यमंत्री एन किरण कुमार रेड्डी तक पहुंच गई है. उम्मीद है कि वह इस पर गंभीरता से विचार करेंगे.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

भ्रष्टाचार, बाबू और राजनेता

हाल में आंध्र प्रदेश के दो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी बी पी आचार्य एवं वाई श्रीलक्ष्मी को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया. इस वजह से आंध्र प्रदेश के बाबुओं और नेताओं के बीच विवाद पैदा होता दिख रहा है. बाबुओं का कहना है कि सीबीआई उन्हें परेशान कर रही है, जबकि जिन नेताओं को निर्णय लेने का अधिकार है, उनके ख़िलाफ़ सीबीआई कुछ नहीं कर रही है. दो अन्य अधिकारियों, एल वी सुब्रह्मण्यम और विश्वेश्वर राव का भी नाम घोटाले में आ रहा है. सूत्रों का कहना है कि आंध्र प्रदेश आईएएस संगठन ने हाल में इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बैठक की है, लेकिन नेता भी शांति से नहीं बैठे हैं. उनका कहना है कि बाबू लोग अपना बचाव करने के लिए ऐसा कह रहे हैं. अब यह बात मुख्यमंत्री एन किरण कुमार रेड्डी तक पहुंच गई है. उम्मीद है कि वह इस पर गंभीरता से विचार करेंगे. देखना यह है कि आंध्र प्रदेश के बाबुओं और राजनेताओं के बीच आरोप–प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है, वह कब ख़त्म होता है.

एनईसी की परेशानी

क्या किसी सरकारी परिषद की पूर्णकालिक सदस्यता का मतलब जीवनपर्यंत सदस्यता से है. उत्तर–पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय आजकल कुछ ऐसी ही समस्या का सामना कर रहा है. दो पूर्व अधिकारी 1990 की शुरुआत में ही सेवानिवृत्त हो गए थे, लेकिन उन्हें लगभग आठ साल पहले उत्तर पूर्व परिषद का पूर्णकालिक सदस्य बना दिया गया था. उस समय से दोनों बाबू राज्यमंत्री को मिलने वाली सुविधाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं. ऐसा इसलिए हो रहा है, क्योंकि एनईसी एक्ट–1971 में सेवानिवृत्ति संबंधी प्रावधानों को शामिल ही नहीं किया गया है. सूत्रों के अनुसार, इंद्रजीत कौर बोर्थाकुर और पी पी श्रीवास्तव इतने उम्रदराज़ हो गए हैं कि अब उनसे काम नहीं होता है. उनका अधिकांश समय शिलांग के एनईसी सचिवालय की जगह दिल्ली में व्यतीत होता है. अब इससे मंत्रालय की परेशानी बढ़ गई है. उत्तर–पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय ने क़ानून मंत्रालय को लिखा है कि काउंसिल की पूर्णकालिक सदस्यता की अवधि तीन साल की जाए, ताकि काम में तेज़ी आ सके. देखना यह है कि क़ानून मंत्रालय कितने दिन में इस समस्या का समाधान कर पाता है.

पेट्रोलियम मंत्रालय के बाबू

पेट्रोलियम मंत्रालय में अधिकारी स्तर पर कुछ फेरबदल हो रहा है. लगता है, पेट्रोलियम मंत्री जयपाल रेड्डी वर्तमान में काम कर रहे बाबुओं से ख़ुश नहीं हैं या फिर किसी और वजह से वह यहां नए बाबुओं को लाना चाहते हैं. सूत्रों का कहना है कि मंत्रालय के उत्खनन डिवीजन के उच्च अधिकारियों को बदला गया है. के जी बेसिन और लाखों डॉलरों की डील को लेकर यह डिवीजन विवादों में रहा था. आंध्र प्रदेश कैडर के अधिकारी गिरिधर अरमाने को उत्खनन डिवीजन का संयुक्त सचिव बनाया गया है. यही नहीं, गिरिधर ने भी इस डिवीजन में दो नए निदेशकों की नियुक्ति की है. महाराष्ट्र कैडर के आईएएस अधिकारी अतुल एन पाटने को पी एस दास की जगह उत्खनन डिवीजन का नया निदेशक बनाया गया है. सूत्रों का कहना है कि विभाग में हो रहे फेरबदल पर मिश्रित प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. पी एस दास, जिन्हें इस डिवीजन से बाहर कर दिया गया है, ख़ासे नाराज़ हैं. आगे क्या होता है, यह तो समय बताएगा. क्या इस फेरबदल से विभाग के कामकाज में तेज़ी आएगी या फिर नए लोग भी उसी पुराने रास्ते पर चलते नज़र आएंगे, जैसा पहले से होता रहा है. हमारे पास इंतज़ार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है. उम्मीद तो यही करनी चाहिए कि रेड्डी के इस निर्णय से मंत्रालय का कुछ भला हो जाए.

dilipcherian@gmail.com

साउथ ब्लॉक

एस नरसिंह राव सीआईएल के चेयरमैन बनेंगे

1986 बैच के आईएएस अधिकारी एस नरसिंह राव को कोल इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन एवं एमडी बनाया जा सकता है. राव अभी हैदराबाद के सींगरेनी कोलियरी कंपनी लिमिटेड के चेयरमैन एवं एमडी हैं. वह जोहरा चटर्जी की जगह लेंगे, जिनके पास इस विभाग का अस्थायी दायित्व है.

टी श्रीनिधि मुख्य आयुक्त बने

1979 बैच के सीएसएस कैडर के अधिकारी टी श्रीनिधि शहरी विकास मंत्रालय में मुख्य आयुक्त बनाए जाएंगे. वह वी के साधु की जगह लेंगे.

उत्पल कृषि एवं सहकारिता विभाग में

1986 बैच के आईएएस अधिकारी उत्पल कुमार सिंह को भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग में संयुक्त सचिव बनाया जाएगा. वह पंकज कुमार की जगह लेंगे, जिन्हें दूरसंचार विभाग में सीवीओ बनाया गया है.

महेश संयुक्त विकास आयुक्त बने

1988 बैच के आईओएफएस अधिकारी महेश चंद गुप्ता को कपड़ा मंत्रालय में संयुक्त विकास आयुक्त बनाया जाएगा. वह एस के झा की जगह लेंगे.

जगदीश और कौरा संयुक्त सचिव

1983 बैच के आईएएस अधिकारी जगदीश प्रसाद मीणा को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में संयुक्त सचिव बनाया गया है. वह अमृत लाल मीणा की जगह लेंगे. इससे पहले वह गृह मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में संयुक्त सचिव थे. इसी तरह बी बी कौरा को दूरसंचार विभाग में संयुक्त सचिव बनाया गया है.

कांग्रेस जीतेगी या हारेगी

पृष्ठ एक का शेष

सोचते तो थे. उन्होंने कुछ काम भी किया. इंदिरा गांधी एवं राजीव गांधी के समय में रायबरेली और अमेठी वालों के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर प्रधानमंत्री निवास तक के दरवाज़े खुले रहते थे. यहां के निवासी बिना झिझक दिल्ली पहुंच कर अपने नेताओं से मिल लेते थे. इंदिरा गांधी ने रायबरेली की देखभाल के लिए सांसद प्रतिनिधि के रूप में यशपाल कपूर और माखन लाल फोतेदार जैसे बड़े नेताओं को लगा रखा था. वे लगातार रायबरेली की जनता के संपर्क में रहते थे. उनकी ज़िम्मेदारी अपनी नेता इंदिरा गांधी को ख़ुश करने से अधिक रायबरेली की जनता के प्रति थी. वे जनता के गुस्से और ख़ुशी दोनों से अपनी नेता को अवगत कराते थे. अमेठी से सांसद रहे और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाले राजीव गांधी भी अपनी मां इंदिरा गांधी के पदचिन्हों पर चले. उन्होंने अमेठी की जनता के लिए अपने कार्यालय और घर के दरवाज़े कभी बंद नहीं होने दिए, लेकिन वह ज़माना अब लद चुका है. सोनिया और राहुल के आने के बाद इन दोनों का अपने क्षेत्र की जनता से सीधा संवाद कभी नहीं रहा. सोनिया के सांसद प्रतिनिधि किशोरी लाल हों या फिर राहुल गांधी के सांसद प्रतिनिधि कनिष्क सिंह, दोनों को ही रायबरेली–अमेठी की जनता नहीं जानती है. ये दोनों सांसद प्रतिनिधि भी जनता की बजाय अपने नेता को ख़ुश करने में ज़्यादा लगे रहते हैं. इनका अधिकांश समय दिल्ली में गुज़रता है, जिसकी वजह से जनता की नाराज़गी अपने नेताओं के प्रति बढ़ती जा रही है. सांसद निधि का पैसा भी बड़े–बड़े स्कूल चलाने वालों को दे दिया जाता है. असल मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जाता है. यही वजह है कि विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार पर आए राहुल और सोनिया की सभाओं में पहले जैसी भीड़ नहीं जुट पा रही थी. इस बात का आभास होते ही गांधी परिवार अपनी बेटी प्रियंका को मैदान में ले आया, ताकि जनता और नेताओं के बीच की संवादहीनता की खाई को पाटा जा सके, लेकिन उसका यह क़दम भी कारगर नहीं रहा.

जनता ग़ुस्से में है

जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व फ़िरोज़ गांधी, इंदिरा गांधी, संजय गांधी एवं राजीव गांधी कर चुके हों, वहां के लोगों को बिजली, सड़क और पीने के लिए साफ़ पानी न मिले, रोज़गार के लिए लोगों को पलायन करना पड़े, तो ज़ाहिर है कि उसका ख़ामियाज़ा भी गांधी परिवार और कांग्रेस को ही भुगतना पड़ेगा. इस विधानसभा चुनाव में राहुल और प्रियंका जहां भी जा रहे हैं, उनसे जनता सवाल पूछ रही है, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं होता. प्रियंका तीन साल बाद पहुंचीं तो सिवाय इसके कि मेरे भाई को जिताओ, उनके पास कहने को कुछ नहीं था. उनके रोड शो में लोग नहीं पहुंचे. नतीजतन, कई सभाएं रद्द करनी पड़ीं. गांधी परिवार की कर्मस्थली में कांग्रेस विधायकों की निष्क्रियता से उपजा रोष प्रियंका, राहुल और सोनिया के करिश्मे पर भी भारी दिख रहा है. दरअसल, आम आदमी की छोटी–छोटी ज़रूरतें प्रियंका, सोनिया या फिर राहुल गांधी की बड़ी–बड़ी बातों और योजनाओं से कहीं ज़्यादा बड़ी हो गई हैं, लेकिन शायद इसका एहसास उन्हें नहीं है. जनता को शिकायत है कि कांग्रेस विधायकों ने उसका कोई काम नहीं किया. राशनकार्ड और विकलांगता प्रमाणपत्र बनवाने जैसे छोटे–छोटे कामों के लिए भी विधायकों से जनता को समय नहीं मिल पाता. रायबरेली और अमेठी के 10 में से सात विधायकों से जनता कुछ ज़्यादा ही नाराज़ है. जिन प्रतिनिधियों को उसे वोट देना है, उन्हें वह सबक़ ज़रूर सिखाना चाहती है. चौथी दुनिया को मिली जानकारी के मुताबिक, प्रियंका गांधी सुल्तानपुर में थीं. रास्ते में उनके ही एक प्रत्याशी मुईद अहमद की सभा थी. मुईद अहमद ने प्रियंका से मंच पर आकर अपने पक्ष में कुछ बोलने की गुज़ारिश की, लेकिन प्रियंका ने उनकी नहीं सुनी और आगे बढ़ गईं. बेचारे मुईद अहमद क़रीब 20 मीटर तक पीछे भागते रहे, लेकिन प्रियंका आख़िरकार नहीं आईं. अब सवाल यह उठता है कि वहां उपस्थित जनता भला क्यों मुईद साहब को वोट देगी, जबकि वह देख रही है कि उनके नेता ही उन्हें भाव नहीं दे रहे हैं. गांधी परिवार को शायद इसका अंदाज़ा नहीं है कि रायबरेली और अमेठी की जनता उसे सिर–आंखों पर बैठाती है, लेकिन जब नाराज़ होती है तो इंदिरा गांधी जैसी नेता को भी धूल चटा देती है. 1977 में अमेठी से संजय गांधी की जगह जनता पार्टी के रवींद्र प्रताप सिंह को और रायबरेली से इंदिरा गांधी की जगह राज नारायण को जिताकर जनता अपना गुस्सा ज़ाहिर कर चुकी है. इस बार भी जनता में गुस्सा है और वह ज़ाहिर भी हो रहा है. अब उसे राहुल, सोनिया और प्रियंका न देखना चाहें तो भले न देखें.

बचेगा प्रियंका का जादू?

प्रियंका और उनके पति रॉबर्ट वडेरा के भी राजनीति में आने की संभावना बनती दिख रही है, लेकिन हालिया दौरे के दौरान प्रियंका गांधी को जनता की मनोदशा समझ में आ गई. विधायकों के ख़िलाफ़ जनता के गुस्से का रुख़ वह अपनी तरफ़ मोड़कर चुनावी नुक़सान की भरपाई करना चाह रही हैं. सोची–समझी रणनीति के तहत ही प्रचार के दौरान वह जनता की डांट तक सुन रही हैं और माफ़ी भी मांग रही हैं. वह करें भी तो क्या? लेकिन जानकारी के मुताबिक़, प्रियंका के रोड शो में भी महिलाओं को बुलाने के लिए रुपये बांटे जा रहे हैं, फिर भी महिलाएं उन्हें सुनने नहीं आ रही हैं. प्रियंका रोड शो और नुक्कड़ सभाएं कर रही हैं, लेकिन उसका असर नहीं हो रहा है. एक चर्चा तो यह भी है कि अगर कांग्रेस प्रियंका गांधी को बतौर सीएम प्रोजेक्ट करती तो उसे उसका फ़ायदा मिलता, लेकिन यह उतना आसान भी नहीं है. राजनीतिक विरासत की लड़ाई भी अजीब होती है. पिछले दिनों जब रॉबर्ट वडेरा ने ख़ुद और प्रियंका के राजनीति में आने के संकेत भर दिए तो घमासान मच गया था. ख़ुद कांग्रेस के भीतर भी सुगबुगाहट शुरू हो गई थी. आनन–फ़ानन में प्रियंका को बयान देकर मामले को शांत करना पड़ा था. एक सवाल और भी है, वह यह कि गांधी परिवार के पास तीन ही पुश्तैनी सीट हैं. एक सोनिया के लिए, एक राहुल के लिए और ज़रूरत पड़ी तो एक प्रियंका के लिए. अगर कल को रॉबर्ट वडेरा संसद सदस्य बनने की इच्छा ज़ाहिर करते हैं, तब कौन उनके लिए सीट ख़ाली करेगा और वह कौन सी सीट होगी. बहरहाल, इस चुनाव में देखना यह है कि प्रियंका का जादू चलता है या नहीं.

गांधी ख़ानदान की विरासत

रायबरेली, अमेठी और सुल्तानपुर, ये संसदीय क्षेत्र गांधी परिवार से पहचाने जाते हैं. यहां से गांधी परिवार या उसके क़रीबी ही जीतते हैं. यहीं से जीतकर इंदिरा और राजीव गांधी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे, वहीं फ़िरोज़ गांधी, अरुण नेहरू, संजय गांधी, सतीश शर्मा एवं शीला कौल जैसे नेताओं ने भी राजनीति के क्षेत्र में काफ़ी नाम कमाया. अब राहुल और सोनिया गांधी यहां की कमान संभाल रहे हैं. आज़ादी के बाद से यहां से गांधी परिवार लगातार चुनाव लड़ता आया और जब वह नहीं लड़ा तो उसने जिसके सिर पर हाथ रख दिया, क्षेत्र की जनता ने उसे जीत की माला पहना दी. इन क्षेत्रों में अपवाद को छोड़कर गांधी परिवार या उसके द्वारा तय प्रत्याशी को कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ा. इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ती रहीं, जीतती भी रहीं. हालांकि एक बार वह हारीं भी, इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव में. इसके बाद कुछ समय के लिए संजय गांधी भी राजनीति में दिखे. संजय इमरजेंसी के बाद चुनाव मैदान में आए. 1977 में हारे तो 1980 में अमेठी से चुनाव लड़े और जीते. 1980 में संजय गांधी और 1984 में इंदिरा गांधी की असामयिक मौत के बाद राजीव गांधी राजनीति में आए. राजीव गांधी ने अमेठी से चुनाव लड़ा और जीते भी. इसके कुछ सालों के बाद सोनिया गांधी ने अमेठी से अपनी संसदीय राजनीति की शुरुआत की. बाद में बेटे राहुल गांधी के लिए अमेठी छोड़कर उन्होंने रायबरेली को चुना.

अगर विधानसभा चुनाव में रायबरेली, अमेठी और सुल्तानपुर में कांग्रेस के प्रत्याशी बहुमत से न जीतकर बहुमत से हार जाते हैं तो इसका बड़ा प्रभाव कांग्रेस की केंद्रीय राजनीति पर पड़ेगा. राजनीतिक रूप से यह साबित हो जाएगा कि सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका अब वोट दिलाने वाले व्यक्तित्व नहीं रहे. जो जीतेंगे, वे अपने काम और अपनी मेहनत से जीतेंगे. अगर इन तीनों चुनाव क्षेत्रों में कांग्रेस बहुमत की सीट जीत जाती है तो देश में हारती और निराशा में घिरी कांग्रेस को नई ज़िंदगी मिल जाएगी.

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 3 अंक 51
दिल्ली, 27 फरवरी–04 मार्च 2012
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार–झारखंड)
प्रथम तल, विराट कॉम्प्लेक्स के पीछे, सरदार पटेल पथ, कृष्णा अपार्टमेंट के नज़दीक, बोरिंग रोड, पटना–800013
फोन : 0612 2570092, 9431421901

ब्यूरो चीफ (लखनऊ)
अजय कुमार
जे–3/2 डालीबाग कॉलोनी, हजरतगंज, लखनऊ–226001
फोन : 0522–2204678, 9415005111

प्रबंध संपादक
श्रीनिवास गुप्ता (ठाकुर) (उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड)
सी–20, ट्रांस यमुना, एनएच–2, आगरा
फोन : 0526–4064901, 9837082462

प्रबंध संपादक (महाराष्ट्र)
प्रवीण महाजन
मुरलीधर कॉम्प्लेक्स, बुटीवाडा के सामने होटल गणराज के बाजू में टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर–440012
फोन नं : 0712–2544988, 2549846

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के– 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के–2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.
संपादकीय 0120–4783999/011–23418962
0120–6450888, 0120–6452888
0120–6451999
विज्ञापन व प्रसार +91 120–4783999
+91 9266627366
फैक्स न. 0120–2544378

पृष्ठ–16+4 (बिहार–झारखंड, उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड एवं महाराष्ट्र)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

जिस क़ानून मंत्री पर देश के संविधान की रक्षा की ज़िम्मेदारी है, वही वोटों के लालच में कह देता है कि अदालत से भी कभी-कभी फ़ैसला हक़ में नहीं मिलता, मगर हमें सब्र रखना होगा.

समय के साथ बदलते मुस्लिम चेहरे

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

उत्तर प्रदेश की राजनीति में तमाम मुस्लिम चेहरे मोर्चा संभाले हुए हैं. ये चेहरे सभी दलों में मौजूद हैं. कहीं ये शो पीस की तरह हैं तो कई जगह इनके कंधों पर वोट बैंक की ज़िम्मेदारी है. कोई भी दल ऐसा नहीं है, जो मुस्लिम चेहरों को आगे करके अल्पसंख्यकों को लुभाने के लिए दाना न डाल रहा हो. यह और बात है कि जितने सयाने राजनीतिक दल हो गए हैं, उससे कम चालाक मुस्लिम मतदाता भी नहीं हैं. इसीलिए वे सुन तो सबकी रहे हैं, लेकिन किसी को आश्वासन नहीं दे रहे हैं. वे जानते हैं कि उन्हें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करके नेताओं ने दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया है. नेताओं की मौकापरस्त राजनीति के कारण ही मुस्लिम समुदाय आज भी समाज के साथ घुल–मिल नहीं पाया है. सरकारों की ग़लत नीतियों के कारण देश एवं प्रदेश में आतंकवाद बढ़ रहा है. अधिकांश मामलों में देखा यही जाता है कि आतंकवादी बाहर से आते हैं और देश के सीधे–सादे युवकों को बहला–फुसला और गुमराह कर उन्हें अपने साथ जोड़ लेते हैं. राजनीतिक दल इन बातों की अनदेखी करके झूठी सहानुभूति दिखाते हैं, जैसा कि आरक्षण के नाम पर बरगला कर किया जा रहा है. अब बात विभिन्न राजनीतिक दलों में मुस्लिम नेताओं या चेहरों की. क़रीब दो दर्जन ऐसे नाम उभर कर सामने आते हैं, जो अपनी कौम को किसी विशेष दल के पक्ष में लुभाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनमें सलमान खुर्शीद, आजम खां, रशीद मसूद, डॉ. अयूब, शफीकुर्रहमान बर्क, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, क्रिकेटर से नेता बने अजहरुद्दीन, राशिद अल्वी, अहमद हसन, अम्मार रिजवी, जफर अली नकवी, हाजी याकूब कुरैशी, मुख्तार अब्बास नकवी, सलीम शेरवानी एवं अमीर रश्दी (उलेमा काउंसिल) आदि प्रमुख रूप से शामिल हैं. ये वे नाम हैं, जो खुलकर किसी एक दल विशेष के पक्ष में हवा बनाने का काम कर रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ़ इमाम बुखारी जैसे धर्मगुरुओं और जफरयाब जिलानी जैसे बुद्धिजीवियों की भी कमी नहीं है, जो पर्दे के पीछे से किसी न किसी दल का समर्थन कर रहे हैं.

इन तमाम मुस्लिम चेहरों के बीच कई नाम ऐसे भी हैं, जिनका कभी राजनीति में सिक्का चलता था, लेकिन इस चुनाव में वे कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं. इनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं तेजतर्रार नेता आरिफ मोहम्मद खान, कभी संजय गांधी के क़रीबी रहे अकबर अहमद डंपी, उमराव जान जैसी फिल्म का निर्माण करके सुर्खियों में आने वाले मुजफ्फर अली (जो लखनऊ से न केवल लोकसभा का चुनाव लड़े, बल्कि कई बार चुनाव प्रचार अभियान में भी दिखे), फिल्म अभिनेत्री शबाना आज़मी, राजा महमूदाबाद मोहम्मद आमिर मोहम्मद खां, बस्ती के मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ और मोहसिना किदवई जैसे नाम शामिल हैं. उक्त सभी नेता भले ही आज की मौकापरस्त राजनीति में अपने आपको फिट न समझ रहे हों, लेकिन उनके मन का गुबार ठंडा नहीं दिखता. ऐसा ही कुछ पिछले दिनों आरिफ की बातों में देखने को मिला. आरिफ वैसे तो कई वर्षों से भाजपा में हैं, लेकिन वह पार्टी के लिए वोट मांगने कहीं नहीं जाते. इसका कारण भी वह कोई खास नहीं बताते. अपनी स्टाइल से राजनीति करने वाले आरिफ साहब का कभी सिक्का चलता था. वह सच्चे अर्थों में धर्मनिरपेक्ष थे तो पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसे नेताओं के क़रीबी. अटल जी से प्रभावित आरिफ मोहम्मद खां ने कभी दलगत राजनीति नहीं की. यही वजह थी कि उन्हें राजनीति और मुस्लिम समाज में वह स्थान नहीं मिला, जिसके वह हकदार थे. आरिफ के बारे में एक घटना काफी चर्चा में रही थी. बात उस समय की है, जब प्रदेश में आपातकाल के बाद राम नरेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनी थी और आरिफ मोहम्मद खां एवं मुख्तार अनीस उपमंत्री के रूप में उसमें शामिल थे. उस समय लखनऊ में शिया–सुन्नी दंगे से माहौल बिगड़ गया. उपमंत्री की हैसियत से आरिफ एवं मुख्तार अनीस को दंगा प्रभावित क्षेत्रों में भेजा गया. वहां दोनों में झगड़े जैसे हालात पैदा हो गए. आरिफ को लगता था कि सुन्नियों पर अत्याचार हुआ है, जबकि मुख्तार अनीस शियाओं पर अत्याचार की बात कह रहे थे. आरिफ सुन्नी बिरादरी से ताल्लुक रखते थे, उन्हें लगा कि सुन्नियों पर अत्याचार हुआ है, लेकिन वह अपना पक्ष मज़बूती से नहीं रख पा रहे हैं. इसके लिए स्वयं को ज़िम्मेदार मानते हुए उन्होंने विधानसभा में ही अपना इस्तीफ़ा दे दिया.

अगर बात उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई मुस्लिम राजनीतिक परिवारों के रसातल में जाने की करें तो इसकी प्रमुख वजह मुस्लिम नेताओं द्वारा परिवारवाद को बढ़ावा न देना है. हिंदू नेताओं के ठीक विपरीत मुस्लिम नेता अपने बच्चों को राजनीति में लाने की बजाय अन्य क्षेत्रों में भेजने को ज़्यादा तरजीह देते हैं. इसीलिए मुस्लिम राजनीतिक घराने समय के साथ हाशिए पर चले जाते हैं और उनकी जगह नए चेहरे और नए घराने ले लेते हैं.

लंबे समय तक राजनीति में रहने के बाद भी वह वहां कभी सहज नहीं दिखे. उन्होंने राजनीति में अपने आपको अनफिट देखकर सारा ध्यान लेखन में लगाना शुरू कर दिया. उनके लेख विभिन्न समाचारपत्रों–पत्रिकाओं में अक्सर दिखाई देते हैं, वही उनकी पहली किताब टेक्स्ट इन कांटेक्स्ट 2001 में बेस्ट सेलर रही. आरिफ मोहम्मद खां पिछले दिनों अलीगढ़ में दिखाई दिए. वह एक पारिवारिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए थे. भले ही वह आजकल राजनीति से दूर हों, लेकिन उनके चेहरे पर मुसलमानों के नाम पर हो रही वोट बैंक की राजनीति का मलाल साफ दिखा. पिछड़े मुस्लिमों को आरक्षण के मामले पर केंद्रीय क़ानून मंत्री सलमान खुर्शीद के बयान से नाराज़ आरिफ ने दो टूक कहा कि उनका बयान बेतुका और मुसलमानों को भरमाने वाला है. 70 प्रतिशत पिछड़े मुसलमानों को पहले से ही आरक्षण का फ़ायदा मिल रहा है. उन्होंने कहा कि पसमांदा मुसलमानों को अगर आरक्षण मिला है तो मंडल आयोग की वजह से. काका कालेलकर या मंडल आयोग के आगे कोई मुस्लिम नेता अपनी कौम के लिए आरक्षण मांगने नहीं गया था. उन्होंने खुर्शीद से सवाल किया कि जब 27 फ़ीसदी में मुसलमानों को आरक्षण मिल रहा है तो फिर अब वह किसे आरक्षण देने की बात कर रहे हैं.

अगर बात उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई मुस्लिम राजनीतिक परिवारों के रसातल में जाने की करें तो इसकी प्रमुख वजह मुस्लिम नेताओं द्वारा परिवारवाद को बढ़ावा न देना है. हिंदू नेताओं के ठीक विपरीत मुस्लिम नेता अपने बच्चों को राजनीति में लाने की बजाय अन्य क्षेत्रों में भेजने को ज़्यादा तरजीह देते हैं. इसीलिए मुस्लिम राजनीतिक घराने समय के साथ हाशिए पर चले जाते हैं और उनकी जगह नए चेहरे और नए घराने ले लेते हैं.

सियासत में रियासत

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार एक दर्जन से ज़्यादा राजघरानों के सदस्य अपना भाग्य आजमा रहे हैं. हाल में कांग्रेस से अलग हुए राजा बुंदेला अपनी पार्टी बुंदेलखंड विकास कांग्रेस के टिकट पर झांसी से चुनाव मैदान में हैं. उन्होंने बुंदेलखंड को पृथक राज्य बनाए जाने की मांग को लेकर बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया. रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया पांचवी बार प्रतापगढ़ के कुंडा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं. इससे पहले वह 1993, 1996, 2002 एवं 2007 में निर्वाचित हुए. उन्हें कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह, राम प्रकाश गुप्ता एवं मुलायम सिंह यादव जैसे मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने का मौक़ा मिला. इसी तरह भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे आगरा के भदावर राजघराने के महेंद्र अरिदमन सिंह तीन बार जनता दल और दो बार भाजपा के टिकट पर चुनाव जीते. इस बार वह सपा के उम्मीदवार हैं. इससे पूर्व वह 1989, 1991, 1993, 1996 एवं 2002 में चुनाव जीत चुके हैं. गोंडा जिले की मनकापुर रियासत के राजा आनंद सिंह नवसृजित गौरा सीट से चुनाव मैदान में हैं, जबकि महराजगंज की सिसवां सीट से, जहां मतदान हो चुका है, सिसवां के कुंवर शिवेंद्र प्रताप सिंह सपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में हैं. शिवेंद्र सिंह के पिता यादवेंद्र सिंह उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं. शिवेंद्र सिंह पिछले कई चुनावों में जीत दर्ज करा चुके हैं. वह भाजपा सरकार में राज्यमंत्री रहे. रायबरेली के तिलोई विधानसभा क्षेत्र से मयंकेश्वर शरण सिंह लगातार चौथी बार चुनाव मैदान में हैं. वह पिछला चुनाव सपा से जीते थे, लेकिन उससे पहले के दोनों चुनाव वह भाजपा के टिकट पर जीते थे. इसी ज़िले की अरखा रियासत के कुंवर अजय पाल सिंह कांग्रेस से दूसरी बार चुनाव मैदान में हैं. पिछले चुनाव में उन्होंने डलमऊ से बसपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य को पराजित किया था. वहां की रानियां भी चुनाव मैदान में हैं.

गोंडा के परसपुर स्टेट राजघराने के दो लोग एक–दूसरे के ख़िलाफ़ चुनाव मैदान में ताल ठोंक रहे हैं. कर्नेलगंज सीट से सपा उम्मीदवार के रूप में योगेश प्रताप सिंह और बसपा उम्मीदवार के रूप में अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला चुनाव मैदान में हैं. दोनों ही पहले इसी क्षेत्र से विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं. योगेश सपा सरकार में राज्यमंत्री रहे हैं. पिछले चुनाव में इस सीट से अजय प्रताप सिंह कांग्रेस के टिकट पर निर्वाचित हुए थे, लेकिन बाद में उन्होंने विधायकी एवं कांग्रेस दोनों छोड़ दी और उपचुनाव में उनकी बहन बृज कुंवरि बसपा उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित हुईं. सुल्तानपुर के सांसद डॉ. संजय सिंह की पत्नी अमिता सिंह एक बार फिर अमेठी विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में हैं. वह 2002 में सामान्य, फिर 2004 में उपचुनाव जीतीं और 2007 में पुन: विधानसभा चुनाव जीत गईं. विधानसभा में सपा की सदस्य रहीं उर्मिला यादव इस बार कांग्रेस से चुनाव लड़ रही हैं. वह मैनपुरी के भारसौल राजघराने की सदस्य हैं. वह 1993 में मैनपुरी की घिरौर सीट से सपा उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित हुई थीं.

गोंडा के परसपुर स्टेट राजघराने के दो लोग एक–दूसरे के ख़िलाफ़ चुनाव मैदान में ताल ठोंक रहे हैं. कर्नेलगंज सीट से सपा उम्मीदवार के रूप में योगेश प्रताप सिंह और बसपा उम्मीदवार के रूप में अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला चुनाव मैदान में हैं.

वोट पाने के लिए हर हथकंडा

दिल्ली में राहुल की ताजपोशी का लक्ष्य पूरा करने के लिए कांग्रेस हर वह हथकंडा अपना रही है, जिससे मुस्लिमों के वोट फिर से उसकी झोली में आ जाएं. ऐसा करते समय उसे न तो इस बात की चिंता रही कि वह संविधान से खिलवाड़ कर रही है और न इस बात की कि उसके नेताओं के आचरण से चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था को ठेस पहुंच रही है. इसे कांग्रेस की क़िस्मत कहिए या बदक़िस्मती कि उसे मुसलमानों को रिझाने के लिए उन सलमान खुर्शीद का सहारा लेना पड़ रहा है, जिन्हें मुस्लिम समाज मुसलमान कम अंग्रेज ज़्यादा समझता है. मुसलमानों को रिझाने के प्रयासों के दौरान संविधान और संवैधानिक संस्थानों पर जो हमले किए जा रहे हैं, उसकी चिंता न कांग्रेस को है और न सलमान खुर्शीद को. जिस क़ानून मंत्री पर देश के संविधान की रक्षा की ज़िम्मेदारी है, वही वोटों के लालच में कह देता है कि अदालत से भी कभी-कभी फ़ैसला हक़ में नहीं मिलता, मगर हमें सब्र रखना होगा. यह बयान बाटला मुठभेड़ कांड के संबंध में दिया गया था. आचार संहिता लागू होने के बावजूद सलमान खुर्शीद अल्पसंख्यकों के लिए 9 फ़ीसदी कोटा बढ़ाने की बात करते हैं. जब पानी सिर से ऊपर हो गया तो वह चुनाव आयोग से माफी मांगकर पल्ला झाड़ने की कोशिश करने लगे. होना तो यह चाहिए था कि अगर वह सही थे तो माफी मांगने की बजाय मंत्री पद छोड़ देते और इस लड़ाई को आगे जारी रखते, लेकिन शायद उनके पास दो रास्ते हैं. एक रास्ते पर चलकर वह मुसलमानों को बरगलाते हैं तो दूसरी तरफ़ सत्ता का सुख हासिल करते हैं.

इस प्रकरण पर कांग्रेस आलाकमान की प्रतिक्रिया ज़्यादा अच्छी नहीं रही, ख़ासकर राहुल गांधी की, जो उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार की बागडोर संभाले हुए हैं. वह क्यों इस मसले पर ख़ामोश रहे? कांग्रेस के पीएम इन वेटिंग राहुल गांधी कुछ समय पहले तक लोकपाल को संवैधानिक दर्जा दिलाकर उसे मज़बूत बनाने की बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने यह नहीं देखा कि उनकी ही पार्टी के नेता और मंत्री चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्थानों का मखौल उड़ा रहे हैं. सलमान खुर्शीद पहले ऐसे नहीं थे. वह विवादों से दूर रहते थे. हो सकता है, उन्होंने इस तरह का बयान अपनी पार्टी के नेता एवं राहुल गांधी के क़रीबी दिग्विजय सिंह से प्रभावित होकर अपने आपको राहुल की गुडलिस्ट में शामिल कराने के लिए दिया हो. सलमान ख़ुर्शीद के बदले रूप को देखकर लोग यह कहने लगे हैं कि वह अपनी छवि चमका कर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल होना चाहते हैं. ज़ाहिर है, मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने के लिए बसपा, सपा एवं कांग्रेस के बीच होड़ मची है. कांग्रेस ने तो सारी हदें पार कर दी हैं. कभी मुस्लिम मतों के सहारे उत्तर प्रदेश में बरसों तक राज करने वाली कांग्रेस बीते 22 सालों से हाशिए पर है तो निश्चित रूप से इसकी वजह मुसलमानों का उससे रूठ जाना रहा है.

अजय कुमार
feedback@chauthiduniya.com

मौलाना कल्वे जव्वाद इमामबाड़ा नाज़िम साहब में मौजूद लोगों की भीड़ को यह बताने के लिए निकल पड़े कि कांग्रेस ने उनकी बातें मान ली हैं. अब हम राहुल के रोड शो में कोई रोड़ेबाजी नहीं करेंगे.

शिष्टाचार भूलते कांग्रेसी

संजय सक्सेना

उत्तर प्रदेश में अपनी दाल न गलती देख कांग्रेस ने राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए चुनाव आयोग को ठेंगा दिखाने और विपक्ष का अपमान करने की नई मुहिम छेड़ दी है. कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी सहित कोई न कोई नेता नित्य-प्रतिदिन चुनाव आयोग, विपक्षी नेताओं और उनकी पार्टियों के बारे में नुक्ताचीनी और अमर्यादित टिप्पणी करते रहते हैं. राहुल गांधी ने लखनऊ में एक जनसभा के दौरान प्रतीकात्मक रूप से समाजवादी पार्टी का घोषणापत्र फाड़कर अशिष्टता की सभी हदें पार कर दीं, वहीं पिछले दिनों मुस्लिम आरक्षण को लेकर टिप्पणी करने पर केंद्रीय क़ानून मंत्री सलमान ख़ुर्शीद द्वारा चुनाव आयोग से माफ़ी मांगे जाने के बाद इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा मुसलमानों का कोटा बढ़ाने का विवादास्पद बयान देकर आग में घी डालने का काम करते दिखे. उन्होंने चुनाव आयोग को नोटिस भेजने की धमकी भी दी. सलमान ख़ुर्शीद भी आयोग की फटकार और अपने द्वारा माफ़ी मांगने के बावजूद मुसलमानों को आरक्षण देने का मसला उठाने का कोई मौक़ा नहीं छोड़ रहे हैं.

फोटो- *प्रभात पाण्डेय*

पिछले दिनों मुस्लिम आरक्षण को लेकर टिप्पणी करने पर केंद्रीय क़ानून मंत्री सलमान ख़ुर्शीद द्वारा चुनाव आयोग से माफ़ी मांगे जाने के बाद इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा मुसलमानों का कोटा बढ़ाने का विवादास्पद बयान देकर आग में घी डालने का काम करते दिखे. उन्होंने चुनाव आयोग को नोटिस भेजने की धमकी भी दी. सलमान ख़ुर्शीद भी आयोग की फटकार और अपने द्वारा माफ़ी मांगने के बावजूद मुसलमानों को आरक्षण देने का मसला उठाने का कोई मौक़ा नहीं छोड़ रहे हैं.

कांग्रेस के युवराज एवं सांसद राहुल गांधी का असंसदीय रूप लखनऊ के डीएवी कॉलेज में आयोजित जनसभा के दौरान दिखा. अपनी बात जनता के दिलो-दिमाग़ में भरने के लिए उतावले राहुल ने भाजपा, बसपा और समाजवादी पार्टी सभी पर जमकर हल्ला बोला. उन्होंने कहा कि पिछले 22 सालों से उत्तर प्रदेश में सरकारें कोरे वादों पर चल रही हैं. यह कहते हुए उन्होंने एक काग़ज़ जनता की तरफ़ लहराया और उसके बाद वह उसे सपा के वादों की लिस्ट बताकर पढ़ने का नाटक करने लगे. फिर आक्रोश जताते हुए उसे फाड़ भी दिया और बोले, अब खोखले वादे नहीं, काम चाहिए. यह बात समाजवादी पार्टी तक पहुंची तो मुलायम सिंह ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि अभी वह युवा हैं और उन्हें शिष्टाचार सीखना होगा. जब चौथी दुनिया ने कांग्रेसी नेताओं से इस संबंध में बात की तो वे नाम गुप्त रखने की शर्त पर बोले कि राहुल ने किसी पार्टी की कोई लिस्ट फाड़ी थी. खोज-ख़बर की गई तो उनकी बात में दम निकला यानी कांग्रेसी सही कह रहे थे. राहुल ने सपा के वादों की लिस्ट नहीं, वह पन्ना फाड़ा था, जिसमें लखनऊ विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों और मंच पर मौजूद नेताओं के नाम लिखे थे. बाद में इन फटे पन्नों को कांग्रेस के एक दिग्गज नेता ने उठा लिया.

राहुल की तरह ही बड़बोले बेनी प्रसाद वर्मा आचार संहिता तोड़ने में पीछे नहीं हैं. राहुल ने लखनऊ में, तो उसी दिन बेनी बाबू ने कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह और केंद्रीय क़ानून मंत्री सलमान ख़ुर्शीद की मौजूदगी में कायमगंज में आयोजित चुनावी रैली में घोषणा करते हुए कहा, चुनाव आयोग चाहे तो मुझे नोटिस दे दे, लेकिन मुसलमानों का आरक्षण बढ़ाया जाएगा. उन्होंने कहा कि ख़ुर्शीद मुसलमानों के हक़ की लड़ाई बहुत ईमानदारी से लड़ रहे हैं. जबकि ख़ुर्शीद ने फ़र्रुख़ाबाद सदर से कांग्रेस प्रत्याशी एवं अपनी पत्नी लुईस ख़ुर्शीद के समर्थन में आयोजित चुनावी सभा में अपनी बात अलग अंदाज़ में रखते हुए कहा कि जब उन्होंने मुसलमानों का आरक्षण बढ़ाने संबंधी बात संसद में कही थी तो कोई विवाद नहीं हुआ, लेकिन जब उसे फ़र्रुख़ाबाद में दोहराया तो हंगामा खड़ा हो गया. उन्होंने भाजपा नेता अरुण जेटली की तरफ़ इशारा करते हुए कहा, जब मैं मुसलमानों की बात करता हूं तो वह कहते हैं कि मैं एक ही क़ौम की बात करता हूं. मैं पूछता हूं कि वह एक ही समुदाय का विरोध क्यों करते हैं. कांग्रेस के नेता हवा का रुख़ अपनी तरफ़ करने के लिए जो हथकंडे अपना रहे हैं, उसमें वे कितने सफल होंगे, यह आगामी छह मार्च को वोटिंग मशीन खुलने के बाद साफ़ हो जाएगा.

feedback@chauthiduniya.com

हेलीकॉप्टर से प्रचार और पांच सितारा में विश्राम

उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने 40, भारतीय जनता पार्टी ने 35, समाजवादी पार्टी ने 5, बसपा ने 3, जदयू ने 5 और अमर सिंह की राष्ट्रीय लोकमंच पार्टी ने अपने दो स्टार प्रचारकों की सूची निर्वाचन आयोग को दे रखी है. ये स्टार प्रचारक जिन क्षेत्रों में अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के प्रचार के लिए जाते हैं तो उस पर आया ख़र्च पार्टी के चुनाव व्यय में जुड़ रहा है. यदि स्टार प्रचारक हेलीकॉप्टर का प्रयोग प्रचार के लिए करते हैं तो उसका व्यय संबंधित प्रत्याशी के चुनाव ख़र्च में जोड़ा जा रहा है. विधानसभा चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी को 16 लाख रुपये तक ख़र्च करने की अनुमति है. स्टार प्रचारकों को पार्टी प्रत्याशी के क्षेत्र में पहुंचाने के लिए कांग्रेस ने 3 चॉर्टर प्लेन और 8 हेलीकॉप्टर किराये पर लिए हैं. भाजपा ने 3 चॉर्टर प्लेन और 7 हेलीकॉप्टरों का प्रबंध किया है. सपा ने भी एक निजी कंपनी के 3 हेलीकॉप्टर और एक चॉर्टर प्लेन ले रखे हैं. बसपा ने दो चॉर्टर प्लेन और 4 हेलीकॉप्टर दो निजी कंपनियों से लिए हैं. जदयू ने 2 हेलीकॉप्टर पार्टी अध्यक्ष शरद यादव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए ले रखे हैं.

रालोद अध्यक्ष अजीत सिंह और उनके पुत्र जयंत चौधरी ने एक हेलीकॉप्टर चुनाव प्रचार के लिए ले रखा है. निजी क्षेत्र की कंपनियों ने 80 से 95 हज़ार रुपये प्रति घंटे के किराए पर हेलीकॉप्टर और 2 लाख रुपये प्रति घंटे की दर से चॉर्टर प्लेन उपलब्ध कराए. दिल्ली की एक निजी कंपनी सुमित हेलीकॉप्टर ने 2 हेलीकॉप्टर और एक चॉर्टर प्लेन एक माह के लिए कांग्रेस पार्टी को उपलब्ध कराया है. बसपा द्वारा लिए गए चॉर्टर प्लेन एवं हेलीकॉप्टर का उपयोग पार्टी प्रमुख मायावती के अलावा सतीश चंद्र मिश्र, नसीमुद्दीन सिद्दीक़ी, स्वामी प्रसाद मौर्य और राम अचल राजभर कर रहे हैं. समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव, अखिलेश सिंह, शिवपाल सिंह यादव, आज़म ख़ां एवं अबू आशिम आज़मी (महाराष्ट्र) हेलीकॉप्टर और चॉर्टर प्लेन से चुनाव प्रचार करने गांव-गांव जा रहे हैं. भाजपा के नितिन गडकरी, मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, विनय कटियार, मुख्तार अब्बास नक़वी, हेमामालिनी एवं शत्रुघ्न सिन्हा जैसे स्टार प्रचारक हेलीकॉप्टर लेकर गांव-गांव घूम रहे हैं. सुमित हेलीकॉप्टर के अलावा एरोटेक एविएशन, एयर चॉर्टर सर्विस, डेकेन एविएशन जैसी एक दर्जन निजी कंपनियों ने अपने चॉर्टर विमान और हेलीकॉप्टर प्रदेश के राजनीतिक दलों को उपलब्ध करा रखे हैं. इनमें वीटी-एसी-बी-350,वीटी-वीएनजे-डीके-17, वीटी एजेडवाई- ईसी-145, वीटी-एसीएच-पीसी-12, वीटी-वीएलएन-एफ-2000 और वीटी-आरएएम-सी-90 जैसे हेलीकॉप्टर प्रमुख हैं. माना जा रहा है कि इन निजी कंपनियों से राजनीतिक पार्टियां कम राशि का बिल (निर्धारित मानक किराये से कम) ले रही हैं, ताकि हेलीकॉप्टरों और चॉर्टर विमानों पर हुई व्यय राशि कम करके दिखाई जा सके. इसके विपरीत सरकारी क्षेत्र की पवन हंस कंपनी, जिसके ज़्यादातर हेलीकॉप्टर और चॉर्टर प्लेन कांग्रेस पार्टी ने ले रखे हैं, का किराया सवा लाख रुपये प्रति घंटा निर्धारित है. पवन हंस सरकारी क्षेत्र की कंपनी होने के कारण कम राशि का बिल नहीं दे रही है.

मौलानाओं को मनाने की कोशिश

बीती 16 फरवरी, दृश्य नंबर एक. दोपहर दो से तीन बजे का समय. कांग्रेस कार्यकर्ता लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट के बाहर राहुल का इस्तक़बाल करने के लिए पूरे लाव-लश्कर के साथ मौजूद थे. राहुल का रथ इंतज़ार कर रहा था. सड़क पर जगह-जगह थोड़ी-बहुत भीड़ थी. दृश्य नंबर दो. पुराने लखनऊ के जौहरी मोहल्ले में दोपहर क़रीब डेढ़ बजे से चार बजे तक मौलाना कल्वे जव्वाद के घर पर कांग्रेस नेता जगदंबिका पाल मौलाना को मनाने में व्यस्त थे. एक तरफ़ वह मोबाइल पर राहुल की लैंडिंग की जानकारी ले रहे थे तो दूसरी ओर मौलाना को उनकी मांगें पूरी होने का भरोसा दिला रहे थे. इधर राहुल अमौसी एयरपोर्ट से भीड़ के साथ शहर में रोड शो के लिए निकले, उधर मौलाना कल्वे जव्वाद इमामबाड़ा नाज़िम साहब में मौजूद लोगों की भीड़ को यह बताने के लिए निकल पड़े कि कांग्रेस ने उनकी बातें मान ली हैं. अब हम राहुल के रोड शो में कोई रोड़ेबाजी नहीं करेंगे.

दरअसल, 16 फरवरी को दोपहर एक बजे से चार बजे तक शहर की ये दो तस्वीरें थीं, मक़सद एक ही था. चेहल्लुम पर दिल्ली के शाहेमर्दा कर्बला में मातमदारों के साथ हुई ज़्यादती के बाद मौलानाओं के विरुद्ध एफआईआर दर्ज होने के विरोध में शिया तबक़े के लोगों ने राहुल गांधी के रोड शो का विरोध करने और उन्हें काले झंडे दिखाने का ऐलान कर रखा था. रोड शो का विरोध न हो, इसीलिए शिया धर्मगुरु मौलाना कल्वे जव्वाद को मनाने कांग्रेसी सांसद जगदंबिका पाल उनके घर पहुंचे थे. पाल ने मौलाना की राहुल से बात कराई. इसके तक़रीबन आधा घंटे बाद ही दिल्ली में उन लोगों के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज हो गई, जिन पर चेहल्लुम के दिन फ़साद करने का आरोप था. एफआईआर दर्ज होने की मुकम्मल जानकारी दिल्ली के लोगों ने मौलाना को दी तो राहुल के रोड शो का विरोध करने का इरादा बदल दिया गया. इसके कोई एक घंटे बाद ही सपा नेता शिवपाल सिंह यादव भी मौलाना के यहां पहुंच गए. शिवपाल ने मौलाना को इस बात के लिए मनाने की पूरी कोशिश की कि उनके समुदाय के लोग समाजवादी पार्टी का ही समर्थन करेंगे. मौलाना ने समर्थन को लेकर सीधे तौर पर कोई आश्वासन तो नहीं दिया, लेकिन यह बात ज़रूर कही कि अखिलेश यादव एक नेक और शरीफ़ इंसान हैं. अल्लाह तअला उन्हें कामयाबी देगा.

चेहल्लुम पर दिल्ली के शाहेमर्दा कर्बला में मातमदारों के साथ हुई ज़्यादती के बाद मौलानाओं के विरुद्ध एफआईआर दर्ज होने के विरोध में शिया तबक़े के लोगों ने राहुल गांधी के रोड शो का विरोध करने और उन्हें काले झंडे दिखाने का ऐलान कर रखा था.

अजय कुमार
feedback@chauthiduniya.com

प्रपत्र-4
(नियम 8 देखिए)
चौथी दुनिया

1.प्रकाशन का स्थान	नई दिल्ली
2.प्रकाशन अवधि	साप्ताहिक, प्रति रविवार
3. मुद्रक का नाम	रामपाल सिंह भदौरिया
राष्ट्रीयता	
(क) क्या भारत का नागरिक है	हां
(ख) यदि विदेशी है तो मूल देश का नाम व पता	XXX
पता	29, डीडीए फ्लैट, चित्रा विहार, विकास मार्ग, दिल्ली-110092
4.प्रकाशक का नाम	रामपाल सिंह भदौरिया
(क) क्या भारत का नागरिक है	हां
(ख) यदि विदेशी है तो मूल देश का नाम व पता	XXX
पता	29, डीडीए फ्लैट, चित्रा विहार, विकास मार्ग, दिल्ली-110092
5.संपादक का नाम	संतोष भारतीय
राष्ट्रीयता	
(क) क्या भारत का नागरिक है	हां
(ख) यदि विदेशी है तो मूल देश का नाम व पता	XXX
पता	अंकुश पब्लिकेशंस प्रा.लि. के-2, गेनन, दूसरी मंजिल, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001
6. उन व्यक्तियों के नाम व पते, जो समाचार पत्र के स्वामी हैं एवं कुल पूंजी के एक प्रतिशत से ज़्यादा के साझेदार या शेयरधारक हैं.	अंकुश पब्लिकेशंस प्रा.लि. 98, मित्तल चैम्बर्स, नरीमन प्वाइंट, मुंबई-400021 1. शाकंभरी ट्रैडर्स लिमिटेड, 98, मित्तल चैम्बर्स, नरीमन प्वाइंट, मुंबई-400021 2. गेनन डकरली फाइनेंस लिमिटेड, न्यू एक्सेलर बिल्डिंग, तीसरी मंजिल, ए. के. नायक मार्ग, फोर्ट, मुंबई-400001 3. एम आर होल्डिंग लिमिटेड, न्यू एक्सेलर बिल्डिंग, तीसरी मंजिल, ए. के. नायक मार्ग, फोर्ट, मुंबई-400001

मैं रामपाल सिंह भदौरिया एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सत्य हैं.

हस्ताक्षर
रामपाल सिंह भदौरिया
प्रकाशक

दिनांक: 29 फरवरी, 2012

समय के साथ-साथ इन हवेलियों की फीकी पड़ती चमक ने कमल मोरारका को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि कैसे अपनी पुरानी विरासत को ज़िंदा रखा जाए.

शेखावाटी उत्सव-2012

राजस्थानी संस्कृति को संजोने का प्रयास

सभी फोटो-*प्रभात पाण्डेय*

हर वर्ष की तरह इस बार भी शेखावाटी के नवलगढ़ में आयोजित वार्षिक उत्सव में राजस्थान की विभिन्न संस्कृतियों की झलक प्रस्तुत की गई, जिसमें जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े लोगों ने भाग लिया, विशेषकर आसपास के स्कूल-कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों ने खेलकूद, नृत्य, संगीत और इस तरह की अन्य कलाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया. इसके लिए उन्हें मोरारका फाउंडेशन की ओर से पुरस्कार भी दिए गए, ताकि वे अपनी प्रतिभा को और निखार सकें. उप राष्ट्रपति हामिद अंसारी की पत्नी सलमा अंसारी के हाथों पुरस्कार पाकर बच्चे काफ़ी ख़ुश दिखाई दिए. सलमा अंसारी का नवलगढ़ का यह पहला दौरा था.

डॉ. क़मर तबरेज़

भारत विभिन्न संस्कृतियों एवं परंपराओं का देश है. यही विशेषता इसे दुनिया के अन्य देशों से अलग पहचान दिलाती है, लेकिन इस समय दुनिया में जितनी तेज़ी से परिवर्तन देखने को मिल रहा है, उसमें प्राचीन संस्कृतियों को बरक़रार रख पाना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है. हालांकि ऐसा नहीं है कि हमने नई चीज़ों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है. देश के विभिन्न क्षेत्रों में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं, जो अपने गौरवशाली अतीत एवं प्राचीन सभ्यता को दोबारा ज़िंदा करने के लिए प्रयासरत हैं. उन्हीं में से एक राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र के नवलगढ़ क़स्बे से संबंध रखने वाले प्रसिद्ध उद्योगपति एवं समाजसेवी कमल मोरारका हैं, जो पिछले 16 वर्षों से शेखावाटी की गौरवशाली विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए पूरे प्रयास कर रहे हैं. इसका नज़ारा हमें हर वर्ष शेखावाटी उत्सव के रूप में देखने को मिलता है.

हर साल की तरह इस बार भी बीती 9 से 12 फरवरी तक राजस्थान के नवलगढ़ क़स्बे में शेखावाटी उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया. इस 17वें शेखावाटी उत्सव की अहमियत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस बार आयोजित होने वाले रंगारंग कार्यक्रमों की शुरुआत जम्मू-कश्मीर के कृषि मंत्री गुलाम हसन मीर द्वारा की गई. इसके अलावा उप राष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी की पत्नी सलमा अंसारी ने अपनी दोनों बेटियों के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया. उल्लेखनीय है कि राजस्थान के तीन ज़िलों झुंझुनू, सीकर और चुरू को मिलाकर बना शेखावाटी क्षेत्र अपनी नक़्क़ाशीदार पुरानी हवेलियों, अपने किसानों एवं जांबाज़ सैनिकों के कारण देश-विदेश में प्रसिद्ध है. यहां की शानदार हवेलियां और लोक संस्कृति देश-विदेश के पर्यटकों को यहां का दौरा करने पर मजबूर करती हैं, जो राज्य की आय का एक बड़ा साधन है. समय के साथ-साथ इन हवेलियों की फीकी पड़ती चमक ने कमल मोरारका को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि कैसे अपनी पुरानी विरासत को ज़िंदा रखा जाए. इसके लिए उन्होंने 1996 से प्रतिवर्ष शेखावाटी उत्सव आयोजित कर यहां की ख़स्ताहाल होती हवेलियों को संरक्षित करने के लिए लोगों को जागरूक करने का सिलसिला शुरू किया, जिसने उन्हीं जैसे हवेलियों के अन्य मालिकों को भी अपनी पारिवारिक धरोहर संरक्षित करने के लिए मजबूर किया. कमल मोरारका के इसी प्रयास का परिणाम है कि आज नवलगढ़ की अधिकतर हवेलियां अपनी पुरानी शान को दोबारा हासिल करने में कामयाब हो रही हैं और दिनोंदिन पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है. ज़ाहिर है, जहां पर पर्यटक ज़्यादा संख्या में आएंगे, वहां पर मूलभूत सुविधाओं की भी उचित व्यवस्था करनी होगी. मसलन उनके ठहरने के लिए अच्छे होटल, अच्छी सड़कें, बिजली-पानी की आपूर्ति की उचित व्यवस्था और साथ ही विदेशी मेहमानों के मार्गदर्शन के लिए शिक्षित गाइड्स की उपलब्धता आदि. मोरारका फाउंडेशन की नज़र इन सभी चीज़ों पर है और वह ये सारी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए कमर कसे हुए है.

हर वर्ष की तरह इस बार भी शेखावाटी के नवलगढ़ में आयोजित वार्षिक उत्सव में राजस्थान की विभिन्न संस्कृतियों की झलक प्रस्तुत की गई, जिसमें जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े लोगों ने भाग लिया, विशेषकर आसपास के स्कूल-कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों ने खेलकूद, नृत्य, संगीत और इस तरह की अन्य कलाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया. इसके लिए उन्हें मोरारका फाउंडेशन की ओर से पुरस्कार भी दिए गए, ताकि वे अपनी प्रतिभा को और निखार सकें. उप राष्ट्रपति हामिद अंसारी की पत्नी सलमा अंसारी के हाथों पुरस्कार पाकर बच्चे काफ़ी ख़ुश दिखाई दिए. सलमा अंसारी का नवलगढ़ का यह पहला दौरा था. यहां आकर उनके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा, जब उन्होंने मोरारका रिसर्च फाउंडेशन के ज़रिये यहां के स्थानीय काश्तकारों के लिए चलाई जा रही ऑर्गेनिक खेती की विभिन्न परियोजनाओं को देखा. उन्होंने यहां के खेतों पर जाकर वहां उगाई जाने वाली फ़सलों का जायज़ा लिया. उन्होंने कहा कि मोरारका फाउंडेशन द्वारा जन कल्याण एवं उत्थान करने से इतनी बड़ी क्रांति आई है और शेष भारत के लोगों को इसका पता ही नहीं. स्कूली बच्चे-बच्चियों और महिला किसानों को पुरस्कार देते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान के लोग अपने जीवन में इतनी मेहनत करते हैं, कई समस्याओं का सामना करते हैं, लेकिन उनके चेहरों पर हर वक़्त मुस्कान छाई रहती है. उन्होंने कहा कि वह यह मुस्कान अपने साथ लेकर जाना चाहती हैं. उन्होंने नवलगढ़ के जांबाज़ सैनिकों की क़ुर्बानियों को भी याद किया, जिन्होंने पाकिस्तान के साथ होने वाले कारगिल युद्ध में आगे बढ़कर मोर्चा लिया.

जम्मू-कश्मीर के कृषि मंत्री गुलाम हसन मीर ने शेखावाटी उत्सव का विधिवत उद्घाटन किया. उन्होंने मोरारका फाउंडेशन द्वारा ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कमल मोरारका का आभार व्यक्त करते हुए कहा, आपने रेगिस्तान को गुलिस्तां में बदल दिया है. इसलिए मैं यहां बहुत कुछ सीखने के लिए आया हूं, ताकि जब मैं अपने राज्य जम्मू-कश्मीर वापस जाऊं तो वहां के किसानों को भी कुछ उपहार दे सकूं. गुलाम हसन मीर के साथ जम्मू-कश्मीर के कृषि विभाग का एक शिष्टमंडल भी नवलगढ़ आया था, जिसने खेतों में जाकर ऑर्गेनिक खेती का जायज़ा लिया. मोरारका ऑर्गेनिक खेती के विशेषज्ञ डॉ. मुकेश गुप्ता ने इस शिष्टमंडल को ऑर्गेनिक खेती की विस्तृत जानकारी दी. गुलाम हसन मीर ने मोरारका फाउंडेशन से जुड़े वैज्ञानिकों को जम्मू-कश्मीर आने का निमंत्रण दिया है, ताकि वे राज्य में ज़ाफ़रान की तेज़ी से घटती पैदावार के कारण खोज कर ज़ाफ़रान की पैदावार में बढ़ोत्तरी करने के तरीक़े बताएं. मोरारका फाउंडेशन द्वारा जम्मू-कश्मीर सरकार को विश्वास दिलाया गया कि राज्य में अगली फ़सल मोरारका रिसर्च फाउंडेशन के इन्हीं वैज्ञानिकों की देखरेख में तैयार होगी. लिहाज़ा जम्मू-कश्मीर के किसानों को अपनी फ़सल से संबंधित अधिकतर शिकायतें दूर होने की उम्मीद पैदा हो गई है. शेखावाटी के इस उत्सव में विभिन्न प्रकार के रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिनमें स्थानीय खेल, मटका दौड़, रस्साकशी, मेहंदी, रंगोली, पोस्टर व पेंटिंग, घोड़े एवं ऊंट का नाच एवं नृत्य-संगीत आदि प्रतियोगिताएं प्रमुख थीं. नवलगढ़ के ऐतिहासिक सूर्य मंडल स्टेडियम में यह चार दिवसीय उत्सव धूमधाम से मनाया गया, जिसमें दूरदराज़ के क्षेत्रों के हर उम्र के पुरुषों एवं महिलाओं ने भाग लिया. स्टेडियम में डाउन टू अर्थ द्वारा लगाई गई विभिन्न दुकानों पर लोग ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थों का स्वाद चख रहे थे. देश भर से आए मेहमानों ने यहां की गई बेहतरीन व्यवस्था के लिए मोरारका फाउंडेशन का आभार व्यक्त किया.

tabrez@chauthiduniya.com

बिहार में तक़रीबन साढ़े पांच हज़ार सरकारी नलकूप (स्टेट बोरिंग) हैं, जिनमें अधिकतर ख़राब हो चुके हैं. इसे राज्य का दुर्भाग्य ही कहेंगे कि पिछले कई दशकों से कोई सिंचाई परियोजना नहीं बनी है.

स्टेट बोरिंग के बग़ैर किसानी कैसे होगी

पंजाब एवं हरियाणा जैसे कृषि प्रधान राज्यों में जब भी चुनाव होते हैं, खेती और किसानों से जुड़े मुद्दे हावी रहते हैं. चाहे किसानों के लिए रियायती दर पर क़र्ज़ का सवाल हो या सिंचाई के लिए नियमित रूप से बिजली की आपूर्ति. इन राज्यों में शासन चाहे जिसका रहे, कोई किसानों को नाराज़ नहीं करना चाहता. यहां के चुनावी इतिहास पर नज़र डालें तो किसानों की नाराज़गी के चलते कई पार्टियों को भारी क़ीमत चुकानी पड़ी. वहीं बिहार में समाजवादी कहलाने वाले लालू प्रसाद यादव के पंद्रह वर्षों के शासन और मौजूदा समाजवादी चेहरे एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दूसरी पारी में भी कोई सिंचाई परियोजना धरातल पर नहीं उतर पाई है.

अभिषेक रंजन सिंह

सत्तर के दशक में जब तत्कालीन बिहार सरकार ने प्रदेश के हर ज़िले में लाखों रुपये ख़र्च कर सरकारी नलकूप (स्टेट बोरिंग) लगाना शुरू किया था, तो किसानों को लगा कि अब खेती की लागत कम होगी और उनका राज्य भी कृषि के मामले में पंजाब-हरियाणा की बराबरी कर सकेगा. शुरुआती कुछ वर्षों तक स्टेट बोरिंग ने ठीक तरह से काम किया, लेकिन उसके बाद के वर्षों में ज़्यादातर नलकूप सरकारी लापरवाही के चलते ठप हो गए. हर ज़िले में स्टेट बोरिंग के लिए बाक़ायदा एक भवन, ऑपरेटर के रहने के लिए एक कमरा और हर खेत में पक्का नाला बनवाया गया था. हालांकि अब इन सबका वजूद ख़त्म हो गया है. बिजली के अभाव के कारण अधिकांश सरकारी नलकूप बंद हो चुके हैं. कई जगहों पर मोटरें जल चुकी हैं. जो थोड़ी-बहुत बची हैं, उन पर चोरों की नज़र लगी हुई है. कभी खेतों में अपनी घरघराहट के साथ प्रचुर मात्रा में पानी देने वाले सरकारी नलकूपों के भवन जर्जर हो चुके हैं तो कुछ ज़मींदोज़ भी हो गए. अब वहां सिवाय वीरानी के कुछ भी नहीं बचा है. किसान बच्चा बाबू कहते हैं, जब गांवों में सरकारी नलकूप लगाए गए तो इनसे किसानों को काफी फ़ायदा होता था. पूरे रबी सीजन में महज़ तीन सौ रुपये में एक एकड़ खड़ी फ़सल की सिंचाई हो जाती थी. वहीं अब निजी पंपसेट से 100 या 110 रुपये प्रति घंटा की दर से सिंचाई होती है. अमूमन गेहूं की फ़सल में कम से कम तीन बार सिंचाई करनी पड़ती है, जिसमें 18 से 20 घंटे लगते हैं. इसी तरह मक्के की फ़सल में कम से कम पांच बार सिंचाई करने की आवश्यकता होती है, जिसमें कुल 36 से 40 घंटे लगते हैं. इस लिहाज़ से देखें तो गेहूं और मक्के की फ़सल तैयार करने में किसानों को सिर्फ़ सिंचाई में ही तीन से चार हज़ार रुपये ख़र्च करने पड़ते हैं. खाद और कीटनाशक का ख़र्च अलग से. ऐसे में आम किसान कैसे खेती कर सकता है, यह बहुत बड़ा सवाल है. बिहार के छोटे किसानों को किराए के पंपसेट से सिंचाई करनी पड़ती है. ऐसे में डीजल की बेतहाशा बढ़ रही क़ीमतों से किसानों के चेहरे मुरझा गए हैं.

पंजाब, हरियाणा एवं अन्य कृषि प्रधान राज्यों में डीजल से चलने वाले पंपसेटों का सिंचाई के लिए इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि वहां की सरकारों ने हर खेत में बिजली पहुंचाई है. रबी और ख़रीफ़ के सीजन में किसान बिजली से चलने वाली मोटरों से अपनी फ़सलों की सिंचाई करते हैं, इससे उनकी कृषि लागत कम पड़ती है. वहीं इसके विपरीत बिहार में खेती-किसानी करना घाटे का सौदा हो गया है. ख़ुद को लोक नायक जयप्रकाश नारायण का शिष्य एवं समाजवादी मानने वाले पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने अपने डेढ़ दशकों के शासन में किसानों से मज़ाक के अलावा कुछ नहीं किया. अगर लालू प्रसाद सरकारी नलकूप (स्टेट बोरिंग) की हालत दुरुस्त कर देते तो यह राज्य के लाखों किसानों के लिए बड़ी बात होती. अब बात करते हैं बिहार के दूसरे समाजवादी नेता एवं मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की. वह बिहार में अपनी दूसरी पारी खेल रहे हैं. किसानों के लिए उन्होंने कई योजनाएं चलाई हैं, जिनका लाभ भी लोगों को मिल रहा है, लेकिन हर खेतों में बिजली पहुंचाने की उनकी घोषणा अभी तक पूरी नहीं हो सकी है. बिहार में तक़रीबन साढ़े पांच हज़ार सरकारी नलकूप (स्टेट बोरिंग) हैं, जिनमें अधिकतर ख़राब हो चुके हैं. इसे राज्य का दुर्भाग्य ही कहेंगे कि पिछले कई दशकों से कोई सिंचाई परियोजना नहीं बनी है. अगर बनी भी तो उसकी हालत कैमूर-रोहतास स्थित दुर्गावती जलाशय जैसी हो गई. उल्लेखनीय है कि दुर्गावती जलाशय परियोजना 37 साल बीत जाने के बाद भी पूरी नहीं हो सकी है. भभुआ (कैमूर), रोहतास, बक्सर और भोजपुर ज़िलों की पहचान धान के कटोरे के रूप में होती है. यहां बेहतरीन किस्म के धान की पैदावार होती है, लेकिन पानी की कमी के चलते पूरे शाहाबाद इलाक़े की गौरवमयी पहचान ख़त्म हो रही है. पुरानी नहरों में पानी नहीं है, नई नहरें बनाई नहीं जा रही हैं. कोसी परियोजना का उदाहरण लोगों के सामने है. बिहार का शोक कहलाने वाली इस नदी पर बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई के लिए करोड़ों रुपये ख़र्च किए गए, लेकिन जिस मक़सद से यह परियोजना बनी, वह आज तक पूरा नहीं हो सका. कोसी परियोजना में किस कदर लूट मची, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उस समय जो इंजीनियर या बाबू इसमें कार्यरत थे, उनकी पांचों उंगलियां घी में डूबी रहती थीं. कहने का मतलब यह है कि कोसी परियोजना में कार्यरत बड़े से लेकर छोटे कर्मचारियों ने ख़ूब धन कमाया.

ग़ौरतलब है कि बिहार के बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, मधेपुरा, भागलपुर एवं सहरसा में मक्के का रिकॉर्ड उत्पादन होता है, लेकिन यहां के किसान सिंचाई के लिए पूरी तरह डीजल के पंपसेटों पर निर्भर हैं, जिससे उन्हें कृषि का उचित लाभ नहीं मिल पाता है. यहां के किसानों की एक और बड़ी समस्या है मक्का आधारित उद्योगों का न होना. कोसी-फरकिया इलाक़े में किसान स्थानाभाव के चलते मक्के को सड़क पर सुखाते हैं. इस वजह से उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है. ऐसे में बाज़ार में उसे उचित भाव नहीं मिलता. आंध्र प्रदेश में भी मक्के की खेती की जाती है, उत्पादन के लिहाज़ से बिहार उससे आगे है, लेकिन गुणवत्ता में पीछे. दरअसल आंध्र प्रदेश की सरकार ने हर ज़िले और तहसील में मक्का प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किए हैं. इससे वहां के किसानों को बाज़ार से उचित भाव मिलता है. अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोक लुभावन वादे छोड़कर इन इलाक़ों में मक्का आधारित उद्योग स्थापित कर दें तो यहां के किसानों की आर्थिक हालत बेहतर हो सकती है. जब देश गुलाम था, उस समय अंग्रेज चंपारण, भोजपुर एवं शाहाबाद इलाक़े से लोगों को गिरमिटिया मज़दूर बनाकर मॉरीशस, फिजी और सूरीनाम में गन्ने की खेती कराने के लिए ले जाते थे. बिहार से गए इन मज़दूरों ने अपनी मेहनत से दुर्गम समझे जाने वाले इन देशों की तस्वीर बदल दी. वक़्त बदल गया, अंग्रेज भी चले गए, लेकिन वहां गए हज़ारों बिहारी मज़दूर वहीं रह गए. कई पीढ़ियां गुजर गईं. कुछ लोगों ने तो वहां की राजनीति में अच्छा मुक़ाम भी बना लिया है. मॉरीशस इसका सबसे बेहतर उदाहरण है, जहां बिहार मूल के कई लोग राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बने. आज़ादी के बाद भी बिहार के मज़दूरों एवं किसानों की हालत नहीं बदली. हालांकि अब बिहार के भूमिहीन किसान एवं मज़दूर मॉरीशस या फिजी नहीं जाते, लेकिन पंजाब और हरियाणा के खेतों में दो जून की रोटी के लिए कड़ी मेहनत करने को विवश हैं.

arsingh@chauthiduniya.com

बहुत याद आते हैं दूबे जी

दूबे जी कोई बड़ा नाम नहीं हैं, उनका पूरा नाम भी बहुत कम लोगों को पता होगा. दूबे जी किस हाल में हैं, इसकी जानकारी भी नहीं है. दूबे जी बिहार राजकीय सरकारी नलकूप विभाग में एक मामूली ऑपरेटर थे. गांव में बिजली आई कि नहीं, इसका पता लोगों को उनकी पुरानी साइकिल के घुसते ही पता लग जाता था. दूबे जी के आते ही किसान अपने खेतों की तरफ़ और बच्चे तौलिया-गमछा लेकर नहाने के लिए दौड़ पड़ते थे. दूबे जी किस ज़िले के, किस गांव के थे, इससे लोगों को कोई मतलब नहीं था. दूबे जी एक मामूली सरकारी मुलाजिम थे, लेकिन किसानों की नज़र में वह काफी बड़ी शख्सियत थे. यही वजह थी कि सभी लोग उनका बेहद सम्मान करते थे. उन दिनों जब स्टेट बोरिंग चालू हालत में थी, तब दूबे जी अपनी ड्यूटी को लेकर काफी ईमानदार थे, लेकिन अब दूबे जी नज़र नहीं आते. काफी वर्षों से उनकी कोई ख़बर नहीं है. संभवत: वह रिटायर भी हो चुके होंगे. दूबे जी को देखे 25 साल बीत गए, लेकिन उनकी यादें आज भी ताज़ा हो जाती हैं, जब मैं सड़क के किनारे स्टेट बोरिंग के ज़र्जर हो चुके भवन को देखता हूं. दूबे जी खगड़िया ज़िला अंतर्गत गोगरी तहसील में बतौर ऑपरेटर काम करते थे. ऐसे न जाने कितने दूबे जी बिहार में और होंगे, जिन्होंने अपने प्रयासों से किसानों के दिलों में अपने लिए जगह बनाई है.

मेरी दुनिया.... ख़बरदार आतंकवाद !

भारत और दक्षिण एशिया

संतुलन से लेकर आपसी सहयोग तक

क्या अतीत की पिछली घटनाओं और उनके तर्क से यह संकेत नहीं मिलता कि अपने पड़ोसियों को लेकर हमारी नीति में परिवर्तन की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें भारत को संतुलित करने के प्रयास से लेकर लंबे समय तक इसके साथ आपसी सहयोग भी शामिल है? क्या कारण है कि हमारे पड़ोसी देश, ख़ास तौर पर पाकिस्तान और किसी हद तक बांग्लादेश, श्रीलंका एवं नेपाल अपने ही हित में क्षेत्र की सबसे बड़ी और सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ मिलकर सहयोग नहीं करते? उनका व्यवहार द्विपक्षीय क्यों रहा है और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क) में भारत को संतुलित करने के विविध उपायों में एक रहा है. पाकिस्तान सैन्य रूप में भारत से बराबरी करने की कोशिश में जुटा है या फिर अन्य देश ग़ैर सैन्य रूप में कूटनीतिक चालबाज़ी या असहयोग या भारत के अंदर बग़ावत को हवा देने या फिर क्षेत्र से अतिरिक्त मामलों को, विशेषकर चीनी सहयोग से उठाने के लिए प्रयत्नशील हैं?

जब शक्ति के नए ध्रुवों का उदय होता है तो संतुलन बनाम आपसी सहयोग पर अंतरराष्ट्रीय संबंधों के फलक पर विस्तृत बहस होती है. इससे बुनियादी रूप में यही निष्कर्ष निकलता है कि कमज़ोर देश संतुलन बनाने या आपसी सहयोग का निर्णय तभी करते हैं, जब उन्हें उदीयमान ध्रुव से ख़तरे की आशंका होती है, भले ही उनके हित साझे हों या न हों. इसका तात्पर्य यह है कि उदीयमान ध्रुव द्वारा संभावित मित्र देशों के साथ समझौते या प्रलोभन के रूप में उन्हें प्रकट या अप्रकट रूप में अलग से भुगतान किया जाता है. क्षेत्रीय सहयोग और गठजोड़ को लेकर ये देश न केवल शुद्ध लाभ, बल्कि आपेक्षिक आर्थिक लाभ के प्रति भी संवेदनशील हैं, ख़ास तौर पर तब, जब समय के साथ संचयी लाभ सैन्य लाभ में परिवर्तित हो जाते हैं. इसलिए व्यापार से होने वाले शुद्ध लाभ पर ध्यान केंद्रित करना काफ़ी नहीं है, बल्कि संभावित मित्र देशों को आश्वस्त भी करना होगा कि आपेक्षिक लाभ, यदि कोई हों, तो वे किसी ख़तरनाक मोड़ में बदल नहीं जाएंगे. जब भारत की अर्थव्यवस्था खुली हुई नहीं थी तो पड़ोसी देशों को इससे सहयोग करने में कोई लाभ नहीं दिखाई देता था, लेकिन उदारीकरण और 7 से 9 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त कर लेने के बाद तस्वीर बदल गई है. क्या इस बात की संभावना है कि भारत राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी आश्वासन के साथ-साथ आर्थिक आश्वासन का प्रलोभन देते हुए आपसी सहयोग की पेशकश करे और अन्य देशों के लिए, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए ऐसे कौन से प्रोत्साहन हैं, जिन्हें देखकर वे अपनी प्रतिक्रिया दें?

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की हाल की बांग्लादेश यात्रा ने भारत-बांग्लादेश सहयोग के क्षेत्र में एक नया अध्याय जोड़ दिया है, जिसमें एक-दूसरे की ज़मीन पर स्थित सीमा पार एन्क्लेव के मुद्दे एवं सीमा विवाद को सहमतिपूर्वक सुलझाने का प्रयास भी शामिल है, जो विभाजन की बिखरी विरासत का एक दर्दनाक पन्ना है. भारत के प्रति बांग्लादेश के सहयोगी रुख़ की शुरुआत अवामी लीग सरकार ने की थी और इसी रुख़ के फलस्वरूप भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों के विद्रोहियों और अन्य आतंकवादी दलों को उसने गुप्त रूप से समर्थन देना बंद कर दिया. इसी प्रकार बीते वर्ष अक्तूबर माह में नेपाली प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के फलस्वरूप द्विपक्षीय निवेश संवर्धन क़रार के साथ-साथ 250 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन मंजूर की गई. ये दोनों ही क़दम दोनों देशों के भावुक रिश्तों को आगे बढ़ाने में मददगार सिद्ध होंगे. इसके अलावा अफ़ग़ानिस्तान के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान व्यापारिक और आर्थिक सहयोग क़रार में 2 बिलियन डॉलर की भारतीय सहायता का वचन दिया गया है. इसमें निवेश संवर्धन क़रार और अत्यंत संवेदनशील सुरक्षा सहयोग के साथ-साथ अफ़ग़ानिस्तान की सशस्त्र सेनाओं की क्षमता निर्माण भी शामिल है. इससे भारत के प्रति अफ़ग़ानिस्तान के झुकाव का भी संकेत मिलता है. पाकिस्तानी मोर्चे पर भी हाल में सूचना मिली है कि व्यापक संवाद प्रक्रिया की शुरुआत के एक भाग के रूप में दोनों देशों के वाणिज्य मंत्रियों के बीच जो वार्ताएं हुईं, उनके फलस्वरूप भारत से (1938 उत्पाद लाइनें) आयात की जाने वाली मदों की छोटी सकारात्मक सूची और 12,000 उत्पादों की लंबी नकारात्मक सूची (संवेदनशील मदों की नकारात्मक सूची छोड़कर) सभी कुछ आयात की जाने वाली मदों की सूची में तब्दील हो जाएगी. दूसरे शब्दों में, सबसे पसंदीदा राष्ट्र (एमएफएन) के नाम के बिना भी वही दर्जा भारत को मिल जाएगा. इसके बदले में पाकिस्तान भारत से ग़ैर टैरिफ बाधाओं में छूट पाना चाहता है. यदि यह उदारता दिखाई जाती है तो उदारीकरण की दिशा में यह एक पहल सिद्ध होगी, भले ही पाकिस्तान भारत के साथ आपसी सहयोग का क़रार न करे तो भी मई, 1998 के भारत-पाक परमाणु परीक्षण के परिप्रेक्ष्य में यह क़दम व्यापार एवं आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में एक दीर्घकालीन परिवर्तन की नींव डालेगा.

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की हाल की बांग्लादेश यात्रा ने भारत-बांग्लादेश सहयोग के क्षेत्र में एक नया अध्याय जोड़ दिया है, जिसमें एक-दूसरे की ज़मीन पर स्थित सीमा पार एन्क्लेव के मुद्दे एवं सीमा विवाद को सहमतिपूर्वक सुलझाने का प्रयास भी शामिल है, जो विभाजन की बिखरी विरासत का एक दर्दनाक पन्ना है. भारत के प्रति बांग्लादेश के सहयोगी रुख़ की शुरुआत अवामी लीग सरकार ने की थी और इसी रुख़ के फलस्वरूप भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों के विद्रोहियों और अन्य आतंकवादी दलों को उसने गुप्त रूप से समर्थन देना बंद कर दिया.

1998 के परमाणु परीक्षण के बाद की गतिविधियों ने पाकिस्तान के विकल्पों को दो स्थितियों में बदल दिया है. दोनों ही स्थितियां ऐसी हैं, जिनके कारण भविष्य में व्यापक आर्थिक सहयोग को तब तक रोक पाना कदाचित आसान नहीं होगा, जब तक कि भारत आर्थिक लाभों को सैन्य लाभों में न बदल दे. पहली स्थिति तो यह है कि पाकिस्तान स्वयं के पास मिसाइल सुविधा के साथ प्रत्यक्ष रूप में परमाणु क्षमता होने के कारण अपनी सुरक्षा के प्रति आश्वस्त हो गया है. दूसरी स्थिति यह है कि कारगिल की पराजय ने उसे यह दिखा दिया है कि कश्मीर के मुद्दे पर भी बातचीत हेतु भारत को बाध्य करने के लिए परमाणु क्षमता को ढाल बनाना अब उसके लिए आसान नहीं होगा. इन स्थितियों के कारण पाकिस्तान संभावित भारतीय हमले को लेकर अब पहले से कहीं अधिक सुरक्षित हो गया है और साथ ही कश्मीर विवाद को सुलझाने के लिए परंपरागत सैन्य बल को चुनौती देने में कम सक्षम रह गया है. इस दृष्टिकोण से पाकिस्तान को भारत के साथ आर्थिक सहयोग से डरने का कोई कारण नहीं रह गया है, बल्कि इससे उसे लाभ ही होगा. कश्मीर पर बातचीत करने और उसकी प्रगति को बंधक बनाने को छोड़कर व्यापार एवं ऊर्जा सहयोग जैसे विभिन्न मुद्दों पर जनवरी, 2004 का समग्र संवाद इसी तर्क श्रृंखला का ही प्रतिफल था. इस नीति ने कश्मीर के मुद्दे पर भी रचनात्मक सहयोग के लिए गुंजाइश बना दी है. कश्मीर का फिर से सीमांकन करने के बजाय दोनों ओर के कश्मीर पर संयुक्त नियंत्रण और सीमाओं को अप्रासंगिक बनाने के मुद्दे पर वार्ता की भी गुंजाइश रखी गई है. परमाणु निवारण द्वारा भारत के प्रति सुरक्षा को लेकर आश्वस्त होने के बाद पाकिस्तान के पास दो बड़े विकल्प रह जाते हैं. पहला विकल्प यह है कि परमाणु निवारण को परंपरागत हमले की ढाल बनाकर इस्तेमाल किया जाए. 2002 के बाद यह विकल्प कारगर नहीं रह गया या फिर भारत की स्थिति में बदलाव लाने के लिए आतंकवादी हमले किए जाएं. यह दूसरा विकल्प भी, जो अब साफ हो जाना चाहिए कि 2008 के बाद विफल हो गया. अगला विकल्प अब यही है कि इन रणनीतियों को बेकार समझ कर विश्वास निर्माण के लिए भारत के साथ व्यापारिक एवं आर्थिक सहयोग किया जाए, ताकि लंबे समय में भारतीय रुख़ को नरम किया जा सके. इस दिशा में अभी बहुत दूर जाना है, लेकिन इस बात को लेकर हैरत नहीं होनी चाहिए कि इस नीति में लगातार परिवर्तन आता जाएगा, भले ही परिवर्तन की रफ़्तार धीमी रहे.

दक्षिण एशिया अंतर-क्षेत्रीय व्यापार और भारत के कुल व्यापार में सार्क देशों का हिस्सा बहुत कम है. भूटान को छोड़कर प्रत्येक प्रमुख पड़ोसी देश के साथ बहुत बड़ा व्यापार अधिशेष है. एक ओर कम आंकड़े भारत के आपेक्षिक आकार को दर्शाते हैं, वहीं ये क्षेत्रीय समन्वय प्रक्रिया की आपेक्षिक विफलता को भी दर्शाते हैं. भारत के साथ व्यापारिक सहयोग के लिए प्रोत्साहन छोटे देशों के लिए काफ़ी अधिक हैं. इसलिए इसके व्यापारिक अधिशेष (पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं श्रीलंका से होने वाले आयात के मुक़ाबले भारत का निर्यात सात-आठ गुना अधिक है) से होने वाले व्यापारिक तनाव एवं राजनीतिक असंतोष को कम करने, राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने और पड़ोसी देशों से होने वाले आयात को बढ़ाकर राजनीतिक अभिमुखीकरण को प्रोत्साहन देने के लिए भारत के पास पर्याप्त मार्जिन है. आर्थिक दृष्टि से तो भारत के लिए यह अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है. यदि भारत को अपने प्रति आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है तो हमारी दक्षिण एशिया नीति में पाकिस्तान की सुरक्षा, उसकी परमाणु निवारण क्षमता और अपनी विशिष्ट पहचान बनाने जैसे विभिन्न मुद्दों पर छोटे पड़ोसी देशों की भारत के प्रति संवेदनशीलता के लिए पर्याप्त गुंजाइश होनी चाहिए. इसमें ग़ैर पारस्परिक व्यापारिक खुलेपन जैसे अनेक प्रकार के प्रोत्साहन शामिल होने चाहिए. पाकिस्तान और बांग्लादेश की ख़तरे की धारणाओं के लिए यह एक महत्वपूर्ण कारक सिद्ध होगा. भारत को नेतृत्व करना चाहिए, लेकिन घमंडी होकर नहीं. इस संबंध में बहुत अच्छी नज़ीरें हैं, 2007 की भारत-भूटान संधि, जिसमें पुराने प्रावधान हटा दिए गए और 1950 की भारत-नेपाल संधि में संशोधन पर विचार करने के लिए सहमति. इन दोनों ही करारों पर पुनर्विचार करने की मंशा छोटे पड़ोसी देशों ने ज़ाहिर की थी. वैसे तो सबसे अच्छा उपाय यही होगा कि साझे मानकों और नीतियों की शासन व्यवस्था अपनाई जाए. यदि सार्क में घरेलू मुद्दों पर बहस पर पाबंदी बनी रहती है तो यह भी संभव नहीं हो पाएगा. इसलिए भारतीय नीति को आगे बढ़ाने का सबसे बढ़िया उपाय यही होगा कि अपने पड़ोसियों के साथ अन्य प्रयासों के समानांतर ही ग़ैर पारस्परिक खुलेपन की भावना से द्विपक्षीय मार्ग अपनाते हुए संबंधों में सुधार लाया जाए. इन प्रयासों के अंतर्गत भारत सहायता राशि दे सकता है, लेकिन इसे आतंकवाद और विद्रोह जैसी भारत की बुनियादी सुरक्षा संबंधी चिंताओं पर पारस्परिकता के साथ सहयोग की भावना से किया जाना चाहिए.

ई श्रीधरन
feedback@chauthiduniya.com

(लेखक पेन्सिल्वेनिया विश्वविद्यालय के भारत संबंधी उन्नत अध्ययन संस्थान में शैक्षणिक निदेशक हैं)

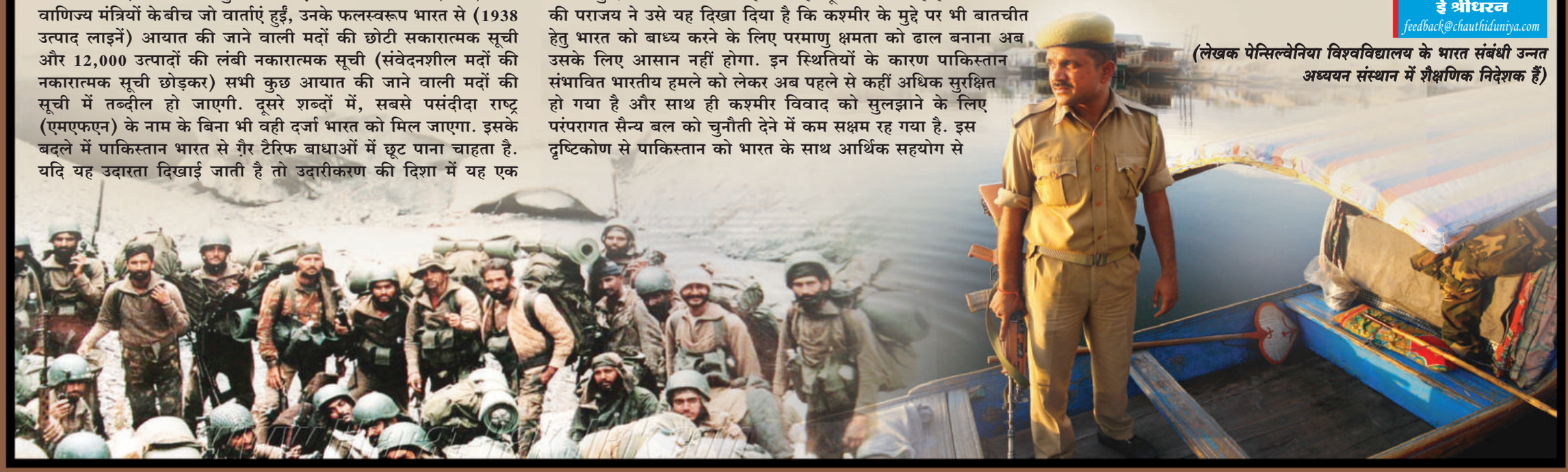

कई मालिक बिना फैक्टरी एक्ट के भी अपने मज़दूरों पर दया रखना चाहते थे. आप कहेंगे, फिर क्यों न उन्होंने ऐसा किया? इसमें भी कारण है.

फैक्टरी एक्ट

महावीर प्रसाद आर मोरारका

भारत में भी इस सदी की शुरुआत में, अंग्रेजों की पहल से फैक्टरी एक्ट्स बने और लागू हुए. इन क़ानूनों की कृपा से यह हुआ कि निश्चित उम्र से कम उम्र के बालकों से कोई काम कतई नहीं लिया जा सकता था. स्त्रियों को कुछ निश्चित काम ही करने हैं. गर्भवती स्त्री को या बच्चे की मां के लिए निर्धारित खुराक का प्रबंध अनिवार्य है. हर मज़दूर के काम करने के घंटे निश्चित कर दिए गए थे. कारखाना या फैक्टरी के चालू रहने का समय निर्धारित हो गया था. कारखाने या फैक्टरी में कोई भी मशीन या हथियार ऐसे हों, जिनसे मज़दूरों को चोट आने का ख़तरा हो तो उन्हें अच्छी तरह बचाव के साधन के साथ रखना अनिवार्य कर दिया गया. मज़दूरी के एवज में मालिक लोग पहले चाहे जैसा सड़ा-गला अनाज या कपड़ा दे दिया करते थे, अब नकद मज़दूरी की रकम देना अनिवार्य बना दिया गया. टट्टी-पेशाब आदि के लिए हर कारखाने में स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर समुचित व्यवस्था की गई. हर कारखाने या फैक्टरी की अमुक समय बाद सफेदी कराना या पुताई कराना, मरम्मत आदि कराना ज़रूरी हो गया. इन सब क़ानूनों को भंग करने की मनोवृत्ति को मिटाने के लिए कई फैक्टरी निरीक्षक नियुक्त कर दिए गए. ये सरकार की तरफ़ से किसी भी समय किसी भी कारखाने या फैक्टरी में घुसकर इस बात का निरीक्षण करने का अधिकार रखते हैं कि फैक्टरी एक्ट पर उचित अमल हो रहा है या नहीं. अगर कहीं भी एक्ट भंग हो रहा होता तो उस मालिक पर मुक़दमा चलाया जा सकता है.

ये क़ानून भी समाजवादी आंदोलन की वजह से नहीं बने, पर मानव की स्वाभाविक वृत्तियों के विकास स्वरूप स्वेच्छा से ही बनाए गए. अंग्रेजों के राज्य में, जो स्वयं पूंजीवाद के कट्टर समर्थक थे, उनके वक़्त में ही ये सुधार हुए थे. देखने-सुनने में ऐसा प्रतीत होता है कि इन तमाम फैक्टरियों के हर मालिक ने विरोध किया होगा, हर मज़दूर प्रसन्न हुआ होगा और उसने इसका जोर-शोर से समर्थन किया होगा, पर बात ऐसी नहीं है. मालिकों में भी अनेक तरह के व्यक्ति होते हैं और श्रमिकों में भी कई तरह के आदमी होते हैं. कई मालिक बिना फैक्टरी एक्ट के भी अपने मज़दूरों पर दया रखना चाहते थे. आप कहेंगे, फिर क्यों न उन्होंने ऐसा किया? इसमें भी कारण है. जो माल वे बनाते हैं, वह माल बाज़ार में कुछ नफे से बिकना चाहिए. अगर एक वस्तु को बनाने में मज़दूरी ज़्यादा लग जाए तो वह मालिक, उन मालिकों के सामने, जो दयावान नहीं हैं और कम मज़दूरी देकर सस्ता माल बेचकर भी मुनाफ़ा कर रहे होंगे, प्रतियोगिता में टिक नहीं सकेगा. सस्ते-कठिन परिश्रम वाले श्रमिकों की वजह से ज़्यादा मुनाफ़ा ही नहीं, पर सस्ता माल बनाना भी संभव है. अगर एक भला मालिक अच्छी तनख्वाह, स्वास्थ्य आदि का समुचित ख्याल रखे तो निश्चय ही वह अपनी वस्तु उतनी सस्ती नहीं बना सकता, जितनी सस्ती दूसरे कठोर मालिक बना सकते हैं.

मालिकों में भी अनेक तरह के व्यक्ति होते हैं और श्रमिकों में भी कई तरह के आदमी होते हैं. कई मालिक बिना फैक्टरी एक्ट के भी अपने मज़दूरों पर दया रखना चाहते थे. आप कहेंगे, फिर क्यों न उन्होंने ऐसा किया? इसमें भी कारण है. जो माल वे बनाते हैं, वह माल बाज़ार में कुछ नफे से बिकना चाहिए.

इसलिए समाज सुधार के ये नियम मानव के व्यक्तिगत औदार्य पर चल सकें, ऐसा संभव नहीं है. कारण, जो उदार बनता है, वह जल्दी मरता है, नष्ट हो जाता है. ऐसे समाज सुधार के लिए शासक द्वारा क़ानून बनाने ही अपेक्षित है. फैक्टरी एक्ट के ख़िलाफ़ श्रमिकों या मज़दूरों का शुरू-शुरू में जो विरोध हुआ, वह मालिकों के विरोध से ज़्यादा उल्लेखनीय है. ग़रीब या एकदम दरिद्र प्रजा को जब यह मालूम हुआ कि उनके लड़के-बच्चे जो काम कर रोज़ाना चार आना-आठ आना मज़दूरी कमा कर लाते हैं, अब नए क़ानून के अनुसार नहीं ला पाएंगे, तो निश्चय ही उनको तकलीफ हुई होगी. हज़ारों या लाखों रुपये वालों को शायद परवाह न भी हो, पर जिस व्यक्ति की या परिवार की आमदनी कुल 4 रुपये रोज़ाना हो, उसमें से आठ आनों की कमी भी घातक होती है. वे माता-पिता जानते हैं कि उनके बालकों के लिए छोटी उम्र में कठिन काम करना कदापि उचित नहीं है, पर भूख या दरिद्रता विवश करती है. इसीलिए पहले पहल तो उस वर्ग ने ही घोर विरोध किया होगा कि फैक्टरी एक्ट बिल्कुल लागू नहीं होने चाहिए.

दरिद्रता ऐसी भयावह चीज है, जिससे मां-बाप की ममता भी नष्ट हो जाती है और वे मजबूर हो जाते हैं कि मासूम बालकों को मज़दूरी करने के लिए भेज दें. इस मज़दूरी का प्रलोभन अथवा इसकी आवश्यकता इस निम्न श्रेणी के लोगों में इतनी अधिक थी कि बच्चों को शिक्षा देना वे नितांत व्यर्थ समझते थे.

feedback@chauthiduniya.com

महावीर प्रसाद आर मोरारका का जन्म 12 अगस्त, 1919 को नवलगढ़ (झुंझनू) राजस्थान में हुआ था. उद्योगपति, स्वप्नदृष्टा और लेखक से कहीं अधिक वह उदात्त मानवीय मूल्यों के संवाहक थे. उनकी गणना भारत के प्रमुख उद्योगपतियों में की जाती है.

जारवा नहीं, हम असभ्य हैं

अंडमान निकोबार स्थित जारवा समुदाय के साथ अमानवीय हरकतों की दास्तां जैसे-जैसे खुल रही है, स्वयं को सभ्य कहने वाले इंसानों का असली चेहरा उजागर हो रहा है. अभी तक कहा जा रहा था कि जारवा समुदाय की स्त्रियों की अर्द्धनग्न वीडियो क्लिप कुछ लोगों ने फिल्माई हैं, परंतु पिछले दिनों ख़ुलासा हुआ कि ऐसी वीडियो क्लिप अंडमान में कार्यरत सभी टूर ऑपरेटरों के मोबाइल में वर्षों से कैद हैं, जिन्हें वे पर्यटकों को दिखाकर उन्हें इन क्षेत्रों में घूमने के लिए प्रेरित करते हैं और उसके बदले उनसे मोटी रकम वसूलते हैं. यदि जारवा नज़र नहीं आए तो ऑपरेटर पर्यटकों के मोबाइल में यही वीडियो क्लिप लोड कर देते हैं. इस तरह यह वीडियो क्लिप अब तक हज़ारों पर्यटकों के मोबाइल तक पहुंच चुकी है. अंडमान निकोबार प्रशासन वीडियो क्लीपिंग पर सवाल खड़ा कर रहा है कि यह क्लीपिंग नई नहीं है, बल्कि कई वर्ष पुरानी है, परंतु वह इस बात का कोई जवाब नहीं दे रहा कि क्लीपिंग नई हो या पुरानी, जब वह क्षेत्र पर्यटन के लिए वर्जित है, तो वहां तक पर्यटकों की पहुंच संभव कैसे हुई? यदि वीडियो क्लीपिंग में पुलिस वाले नहीं, कोई और है तो फिर इन वर्जित क्षेत्रों की सुरक्षा में लगे पुलिसवाले उस वक़्त कहां थे, जब कोई बाहरी यहां अवैध रूप से प्रवेश कर रहा था.

माना जाता है कि नीग्रो मनुष्यों की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई और वहीं से ये पूरी दुनिया में फैले. जारवा इन्हीं के वंशजों में से एक हैं. अनुमानत: 400 लोगों की आबादी वाला जारवा समुदाय सबसे पहले 1998 में बाहरी दुनिया के संपर्क में आया. हालांकि वे आम इंसानों से दूर रहना पसंद करते हैं, लेकिन कई बार जंगलों से निकल कर इंसानी बस्तियों में आते हैं और स्थानीय लोगों से सामानों का आदान-प्रदान करते हैं. पिछले दिनों जारवा समुदाय के कुछ लोग अचानक दक्षिण अंडमान की तुशनाबाद पंचायत स्थित गांवों में पहुंचे. वे अपने साथ तीर-कमान, मछली पकड़ने के सामान, कुछ पैकेट, केकड़े, शहद एवं जंगल के अन्य उत्पाद लेकर आए थे और बदले में गांव वालों से तंबाकू एवं पुराने कपड़ों की मांग कर रहे थे. इस तरह उनका आना-जाना और यदा-कदा बाहरी दुनिया से संपर्क बनाना स्थानीय लोगों के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है.

विकास और औद्योगिकीकरण के नाम पर हमने प्राकृतिक संपदा का जमकर शोषण किया, परंतु जारवा प्रकृति को अपनी जीवनरेखा मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं और प्राकृतिक संसाधनों का केवल उतना उपयोग करते हैं, जितनी उसकी भरपाई हो सके. प्रकृति के प्रति उनकी श्रद्धा का ही परिणाम है कि जिन क्षेत्रों में जारवा निवास करते हैं, वे अंडमान के अन्य जंगली क्षेत्रों से अधिक समृद्ध हैं. प्रकृति को समझने की उनकी क्षमता आधुनिक वैज्ञानिकों से कहीं अधिक उन्नत है. इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण 2004 में आया सुनामी है, जिसके कहर से समूचा दक्षिण एशिया कांप गया था. सभी वैज्ञानिक पूर्वानुमान धरे के धरे रह गए थे. इस प्रलय में हज़ारों लोगों की जानें गई थीं, परंतु एक भी जारवा सुनामी की चपेट में नहीं आया था. इस समुदाय के साथ किसी भी प्रकार की नज़दीकी 2004 में कलकता उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए उस आदेश की अवमानना है, जिसमें कहा गया था कि बाहरी दुनिया का जारवा समुदाय से संबंध इसके अस्तित्व के लिए उस वक़्त तक ख़तरा है, जब तक यह स्वयं शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से तैयार न हो जाए. न्यायालय के इस आदेश का मक़सद जारवा समुदाय को बाहरी दुनिया से होने वाली गंभीर बीमारियों से बचाना था.

इस संबंध में विशेषज्ञों की एक समिति भी बनाई गई थी, जिसने जारवा एवं ग़ैर जारवा के बीच संबंधों पर अपनी रिपोर्ट में भी इन्हीं नीतियों का समर्थन किया था. जारवा आदिवासियों के विशेषज्ञ एवं एंथ्रोपोलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारी एंसटाइस जस्टिन का कहना था कि कुछ वर्ष पूर्व जब वह जारवा लोगों की बस्ती में गए थे, तब वहां तंबाकू एवं गुटखों के पाउच और ऐसे कपड़े मिले थे, जो सरकार ने उन्हें नहीं दिए थे. वैक्सीन न होने के कारण जारवा आम इंसानों के संपर्क में आने के बाद खसरा जैसी गंभीर बीमारियों के शिकार हो गए थे, जिससे कई लोगों की मौत हो गई थी. प्रतिरोधक क्षमता नाममात्र होने और इलाज के अभाव के चलते वे फ़ौरन दम तोड़ देते हैं. सरकार ने जारवा बस्तियों-इलाक़ों में बाहरी लोगों का जाना प्रतिबंधित कर दिया है. हालांकि इस पूरे प्रकरण के बाद सरकार जागी है और वह स्वास्थ्य एवं आहार विशेषज्ञों की मदद से अंडमान निकोबार के जारवा सहित देश के अन्य आदिवासियों के रहन-सहन, तौर-तरीक़ों का अध्ययन करने की योजना बना रही है, ताकि बीमारियों के प्रति उनकी संवेदनशीलता कम की जा सके.

जारवा समुदाय में बाहरी दुनिया के हस्तक्षेप के लिए बहुत हद तक अंडमान ट्रंक रोड को ज़िम्मेदार ठहराया जाता है. नॉर्थ और साउथ अंडमान को जोड़ने वाले इस मार्ग का तक़रीबन 56 किलोमीटर का हिस्सा जारवा रिज़र्व क्षेत्र से होकर गुजरता है. इसलिए जारवा अपना इलाक़ा छोड़कर सीमित क्षेत्रों में रहने के लिए मजबूर हैं. हालांकि 2002 में उच्चतम न्यायालय ने इस क्षेत्र से गुजरने वाली सड़क को बंद करने का आदेश दिया था, परंतु स्थानीय विरोध के कारण ऐसा संभव नहीं हो सका. सांसद विष्णुपद राय का तर्क है कि यह सड़क दक्षिण एवं मध्य अंडमान के निवासियों की जीवनरेखा है. दोनों क्षेत्रों के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामानों से लदे ट्रक प्रतिदिन इसी रास्ते से गुजरते हैं. ऐसे में जब तक कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं खोजा जाता, तब तक इसे बंद करना अन्याय होगा. (चरखा)

जुबैर अहमद
feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

सर्वश्रेष्ठ पत्र

परिवारवाद और कांग्रेस

कांग्रेस में गांधी परिवार की केंद्रीय भूमिका रही है. अगर यह कहा जाए कि गांधी परिवार के बिना कांग्रेस अधूरी है तो ग़लत नहीं होगा. इसलिए यह कहना बिल्कुल ग़लत है कि अगर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई तो राहुल गांधी का सियासी करियर ख़त्म हो जाएगा. इतना ज़रूर है कि कांग्रेस के अच्छे प्रदर्शन से उनका सियासी क़द बढ़ जाएगा. कांग्रेस के परिवारवाद से कौन परिचित नहीं है. इसीलिए कांग्रेस राजनीति से दूर रहने वाली प्रियंका गांधी को भी चुनाव प्रचार में उतार देती है. इस बार तो रॉबर्ट वाडेरा भी बच्चों सहित प्रियंका के साथ दिखाई दिए और उन्होंने राजनीति में आने तक के बयान दे डाले. हालांकि सिर्फ़ चुनाव के समय जनता के बीच जाने पर प्रियंका को आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा. लगता है, देश की जनता को भी गांधी परिवार का परिवारवाद रास आता है, तभी तो यह परिवार सत्ता में सिरमौर रहा है.

-मोहम्मद अफ़ज़ाल, *चांदनी चौक, दिल्ली.*

सराहनीय प्रयास

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक की सबसे बड़ी मॉक ड्रिल हुई. आधिकारिक तौर पर क़रीब 400 स्थानों पर मॉक ड्रिल हुई और इसमें हज़ारों लोगों ने हिस्सा लिया. इसमें सिखाया गया कि दिल्ली में भूकंप के तेज़ झटकों के दौरान ख़ुद को और दूसरों को कैसे बचाया जाए. यह एक बेहतरीन प्रयास है. देश के अन्य हिस्सों में भी लोगों को इस तरह का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, ताकि आपदा के समय होने वाले नुक़सान को कम किया जा सके.

-असलम ख़ान, *दिल्ली.*

लाजवाब अख़बार

सृजनात्मक संसार के सबसे सुंदर और सामाजिक सरोकारों से सर्वाधिक समृद्ध साप्ताहिक चौथी दुनिया का ताजा अंक मिला. पन्ना पलटते ही लगा कि सरकती जाए रुख़ से नक़ाब आहिस्ता-आहिस्ता. सियासी दुनिया, बाक़ी दुनिया, प्रशासन दुनिया तो बेहतर है ही, जब तोप मुक़ाबिल हो, सबसे लाजवाब लगा. साहित्य और समाज का पृष्ठ भी अच्छा है.

-**डॉ. आर के दुबे,** *बक्सर, बिहार.*

एक अनुरोध

चौथी दुनिया का ताज़ा अंक देखा. अख़बार का लेआउट और कलेवर काफ़ी अच्छा है. सभी लेख ज्ञानवर्द्धक हैं. कार्टून भी ग़ज़ब का है. आपसे एक अनुरोध है कि कला-संस्कृति के नाम से भी एक कॉलम शुरू करें, जिसमें इन विषयों से संबंधित लेख प्रकाशित किए जाएं. इसमें दिल्ली की आर्ट गैलरी के कार्यक्रमों की ख़बरें भी हों.

-**समीर मंडल,** *मेरठ, उत्तर प्रदेश.*

अभिव्यक्ति की आज़ादी

पिछले क़रीब एक साल से चौथी दुनिया का नियमित पाठक हूं. सुब्रह्मण्यम स्वामी द्वारा हिंदू राष्ट्र की वकालत एवं हिंदुओं के धर्मांतरण पर पाबंदी की बात करना कितना संवैधानिक और जायज़ है? क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ शब्दों द्वारा किसी का अपमान करना हो सकता है? सुब्रह्मण्यम स्वामी द्वारा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करना करोड़ों देशभक्तों के दिल में भाले चुभोने जैसा है. कुछ भी हो, ऐसी अभिव्यक्ति असामाजिक और ग़ैर ज़िम्मेदाराना है. जहां तक हिंदुओं के धर्मांतरण को रोकने की बात है तो यह उनका मौलिक अधिकार है कि वे किस धर्म में रहना चाहते हैं.

-**अवधेश कुमार,** *बक्सर, बिहार.*

सुविधाओं से वंचित ग़रीब

ग़रीबी और बेरोज़गारी किसी भी प्रगतिशील राष्ट्र के लिए अभिशाप है. बिहार की हालत बहुत ख़राब है. ग्रामीण क्षेत्रों में दलित, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ी जातियों के लोग भुखमरी के शिकार हैं. ग़रीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले हज़ारों लोगों के नाम आज भी बीपीएल सूची में नहीं जुड़ पाए हैं. यह समस्या बिहार के अलावा अन्य राज्यों में भी है. अशिक्षा और भ्रष्टाचार के चलते लोग सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाते, जबकि एपीएल श्रेणी के लोगों के नाम बीपीएल सूची में दर्ज हैं और वे सरकारी सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं. हैरानी की बात यह है कि सरकार के तमाम दावों के बावजूद ग़रीबी दिनोंदिन बढ़ती जा रही है.

-**प्रताप नारायण सिंह,** *बेगूसराय, बिहार.*

अंत में

अंकित मैं कैसे करूं, भ्रष्टों की करतूत
हैं ये मेरे देश में, निर्मम बड़े कपूत,
भ्रष्ट हो गए नेता जी, भ्रष्ट हुआ परिवेश
लूट चुके ये सोन चिरैया, नहीं रहा कुछ शेष,
ले नेता का नाम अब, वोटर मारे हूक
घर में भूजी भांग नहीं, ख़ाली है संदूक,
कहने को किससे कहे, वोटर अपना हाल
महंगाई की चाबुक से, उधड़ रही है खाल,
हाड़तोड़ मज़दूरी करके, घर आता है वोटर
फिर भी भोजन पेट भर, होता नहीं मयस्सर,
इस चुनाव में वोटर-नेता में होगी तक़रार,
ग़म और ग़ुस्से में वोटर कर जाएगा वार.

-*आनंद फ़ैज़ाबादी.*

राजकमल प्रकाशन समूह

1-बी, नेताजी सुभाष मार्ग, नई दिल्ली-110 002
फोन 011-23274463, 23288769, फैक्स 011-23278144
www.rajkamalprakashan.com Email : info@rajkamalprakashan.com
शाखा : अशोक राजपथ, पटना-800006 फोन 0612-2672280
पहली मंजिल, दरबारी बिल्डिंग, महात्मा गांधी मार्ग, इलाहाबाद-211001 फोन 0532-5293858, 2427274

लेखन विधा सम्मान 2011

'चौथी दुनिया' में प्रकाशित सप्ताह के सर्वश्रेष्ठ पत्र को दी जानेवाली 700 रुपए की किताबें

देश के जाने-माने पत्रकार एवं 'चौथी दुनिया' के सम्पादक संतोष भारतीय के संपादन में प्रकाशित 'दलित अल्पसंख्यक सशक्तीकरण' के वैश्विक प्रयासों का तथ्यात्मक दस्तावेज। यह पुस्तक प्रमाणित करती है कि दुनिया भर के गरीब, दबे-कुचले और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग समूहबद्ध होकर यदि शक्तिसम्पन्न होने का संकल्प लें तो वैश्विक स्तर पर बड़े बदलाव सामने आएँगे।

मूल्य ₹ 1000 पृ. : 448
राजकमल प्रकाशन प्रा.लि.

राजकमल प्रकाशन समूह की किसी भी पुस्तक की समीक्षा चौथी दुनिया को भेजें हर महीने की सर्वश्रेष्ठ समीक्षा को 1100 रुपए की पुस्तकें दी जाएंगी
हेल्पलाइन : 09311196029

पाठक पूरे नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार व प्रतिक्रियाएँ इस पते पर भेजें :
चौथी दुनिया, एफ- 2, सेक्टर-11,
नोएडा (उत्तर प्रदेश), पिन - 201301
ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

जनता को अपनी ज़िम्मेदारी समझनी चाहिए

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में महंगाई, बेरोज़गारी, शिक्षा एवं स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली और भ्रष्टाचार आदि मुद्दे साफ़ दिखाई देते हैं, लेकिन इन्हीं के साथ एक और महत्वपूर्ण मुद्दा दिखाई देता है, वह है अपराध. अपराध प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, लेकिन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अपराध से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है राजनीति का अपराधीकरण या अपराधियों का राजनीति में बेख़ौफ़ प्रवेश. ये सारे सवाल सिर्फ़ उत्तर प्रदेश के नहीं हैं, बल्कि पूरे देश के हैं. देश की जनता इन सवालों का सामना कर रही है और उसे जवाब नहीं मिल रहा है. हम इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश उत्तर प्रदेश में इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि वहां चुनाव हो रहे हैं और इन चुनावों में समस्याओं के विशद सर्किल को तोड़ने का तरीक़ा जनता के पास है. पर क्या जनता उस तरीक़े का इस्तेमाल करेगी, यह सबसे बड़ा सवाल है. महंगाई, बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सड़क आदि सवालों के जवाब राजनीतिक दलों को देने हैं या उस राजनीतिक दल को, जो प्रदेश में सरकार बनाने की दौड़ में सबसे आगे रहने वाला है. वह इन सवालों के जवाब उत्तर प्रदेश में इसलिए नहीं दे सका है, क्योंकि बड़े दलों में कोई दल ऐसा नहीं है, जो वहां की सरकार में न रहा हो.

कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी लंबे समय के लिए या कम से कम पांच साल या पांच साल से ज़्यादा के लिए तो सत्ता में रही ही हैं, पर उन्होंने इन सवालों का कोई जवाब जनता को नहीं दिया है. उत्तर प्रदेश 63 सालों में देश के सबसे कम विकसित राज्यों की श्रेणी में पहुंच गया है. अब अगर इसे वहां से बाहर निकालना है तो जो सत्ता में जाने वाले हैं या जीतने वाले हैं, उन्हें ही उत्तर प्रदेश को विकसित करने का फ़र्ज़ पूरा करना है. पर इन सवालों से भी महत्वपूर्ण सवाल या इनके बराबर का महत्वपूर्ण सवाल राजनीति के अपराधीकरण का है. आख़िर राजनीति में आए लोग और सरकार में जाने वाले लोग अपने वादे को पूरा क्यों नहीं कर पाते हैं? विकास का पैसा आता है, लेकिन वह कहां चला जाता है? अगर हम देखें तो पाएंगे कि इसकी जड़ में है राजनीति का अपराधीकरण. वे लोग जो नए-नए ठेकेदार बने हैं, वे लोग जिनका आम लोगों के दु:ख-दर्द से कोई रिश्ता नहीं है और वे लोग जो कभी किसी राजनीतिक दल के लंबे समय तक सदस्य नहीं रहे, राजनीतिक दलों को पैसे देकर टिकट हासिल कर लेते हैं और उसके बाद साम-दाम-दंड-भेद का इस्तेमाल करके विधानसभा में पहुंच जाते हैं. सरकार बनती है और चूंकि हर दल में ऐसे तत्वों का वर्चस्व हो रहा है तो ज़ाहिर है, जो सत्तारूढ़ दल होता है, उसमें भी ऐसे तत्वों का वर्चस्व होता है. वे फिर दबाव डालकर विकास के लिए आए पैसों की बंदरबांट करते हैं. बंदरबांट करने का सीधा तरीक़ा होता है ठेके लेना. ज़्यादातर विधायकों या सांसदों के रिश्तेदार या दूर के मित्र ही ऐसे ठेकेदार होते हैं और वे खुलेआम लोगों की आंखों के सामने विकास के कामों के साथ बेरहमी से मज़ाक़ करते हैं. बेरहमी से मज़ाक़ का मतलब, उन कामों को इस तरह पूरा करते हैं कि साल बीतते-न बीतते वे ख़त्म हो जाएं और उनके लिए दोबारा टेंडर निकलें. भ्रष्टाचार का यह ऐसा ख़तरनाक सिलसिला है, जिसमें इस प्रकार के तत्व, जो कभी मंत्री भी बन जाते हैं और अधिकारियों के ऊपर दबाव डालते हैं, उनकी सीधी हिस्सेदारी दिखाई देती है.

अफ़सोस की बात यह है कि चुनावों में, चाहे वह उत्तर प्रदेश के चुनाव हों या उत्तराखंड के या पंजाब के या गोवा के या फिर इसके पहले हुए चुनाव, किसी पार्टी ने दाग़ियों को, अपराधियों को टिकट देने में कोताही नहीं बरती. जो आया, उसे टिकट दिया गया. हर पार्टी में कम से कम 30 प्रतिशत टिकट बिके हैं. ये टिकट उन लोगों ने ख़रीदे हैं, जिनके पास पैसा है और जिनकी पृष्ठभूमि अपराध की है. उन्होंने पार्टी के किसी न किसी वरिष्ठ नेता को बड़ी रक़म पहुंचा कर टिकट हासिल की है. एक पार्टी ने तो अपनी टिकट डेढ़-डेढ़ करोड़ रुपये में बेची है. सारा पैसा पार्टी के मुखिया के पास गया. पांच साल तक राजनीतिक दल अपराधीकरण के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, लेकिन पांचवां साल आते ही जब चुनाव का वक़्त आता है तो वे उन्हीं अपराधियों को टिकट देते हैं, जिनके ख़िलाफ़ उन्होंने चार-साढ़े चार साल भाषण दिए हैं. इस दलीय व्यवस्था से अलग ज़रा जनता के मनोविज्ञान को समझें. वह जनता जो वोट देकर ऐसे लोगों को जिताती है, उसे लगता है कि जिसके साथ बीस-पच्चीस गाड़ियां नहीं चल रही हैं, जिसके साथ बंदूकें नहीं चल रही हैं, जो शराब नहीं पिला रहा है और जो पैसा नहीं बांट रहा है, वह उम्मीदवार बेकार है. भले ही वह उम्मीदवार कितना भी ईमानदार हो, लेकिन जनता या बहुसंख्यक जनता की नज़रों में उसकी कोई क़ीमत नहीं है. इसलिए जातियों के नाम पर अपराध करने वाले, जातियों के नाम पर ठेकेदारी करने वाले लोग चुनाव में आते हैं तो जनता अपने हितों के ख़िलाफ़ आपस में बंट जाती है और अपनी जाति के सिरमौर अपराधी को वोट देने में अपनी शान समझती है. पर ऐसे समय में आम लोग यह भूल जाते हैं कि उनकी उस एक दिन की ग़लती का ख़ामियाज़ा उन्हें अगले पांच सालों तक भुगतना पड़ेगा.

चुनाव में अच्छे उम्मीदवार को वोट देना भी वैसा ही पवित्र कर्तव्य है, जैसा तीर्थों पर जाना और अपने द्धारा किए गए अपराधों की माफ़ी मांगने के लिए मंदिर के दरवाज़े पर सिर झुकाना. अगर आप अच्छे आदमी को वोट देकर भेजेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने में कुछ मदद कर पाएंगे.

मैं जब इस विशद सर्किल को देखता हूं, विकास न होने के विशद सर्किल को, तो मुझे लगता है कि इसे तोड़ने का केवल एक ही बिंदु है कि उन उम्मीदवारों को वोट न देना, जो अपराधी हैं, दाग़ी हैं. जिन्होंने जनता की सेवा में एक भी दिन नहीं लगाया, जिन्होंने अपराध और भ्रष्टाचार के ज़रिए पैसा कमाया और वे पार्टी के मुखियाओं को पैसा देकर टिकट लेने में कामयाब हो गए. ऐसे लोगों को वोट न देना इस विशद सर्किल को तोड़ने का एकमात्र रास्ता है और यहां पर राजनीतिक दलों से ज़्यादा ज़िम्मेदारी आम जनता की है. आम जनता कभी राजनीतिक दलों के सिद्धांतों को देखकर वोट देती थी, लेकिन पिछले 15 सालों से राजनीतिक दलों के सिद्धांतों को देखकर लोग वोट नहीं देते, बल्कि जाति, धर्म और संप्रदाय देखकर वोट देते हैं. आम लोगों को यह अच्छी तरह समझना चाहिए कि अगर वे जाति, धर्म और संप्रदाय के आधार पर वोट देंगे, उम्मीदवार की ईमानदारी, काम करने के तरीक़े और उसका जनता के प्रति लगाव वोट देने का आधार नहीं बनेगा तो उन्हें वही सब भुगतना पड़ेगा, जो वे 63 सालों से भुगतते चले आ रहे हैं. गांव में सड़कें नहीं होंगी, बिजली नहीं आएगी, स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं सुधरेगी, शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरेगी और महंगाई, भ्रष्टाचार एवं बेरोज़गारी में वृद्धि होगी. इस बात को हिंदुस्तान का मतदाता आख़िर कब समझेगा? उत्तर प्रदेश में जहां चुनाव हो गए और जहां चुनाव होने वाले हैं, वहां अपराधी उम्मीदवारों की भरमार है, लेकिन जनता ने यह नहीं सोचा कि एक बार उसे भी वोट दें, जो दाग़ी नहीं है, जिसके पास बीसियों गाड़ियां नहीं हैं, बंदूकें-राइफलें नहीं हैं, शराब पिलाने के लिए पैसा नहीं है और जो पैसा नहीं बांट सकता.

अगर लोगों ने यह सोच लिया हो कि ऐसे उम्मीदवारों को वोट नहीं देना है और वोट उन्हें देना है, जिनके पास यह सब अवगुण नहीं हैं तो राजनीति को सुधारने का कोई रास्ता शायद मिल सके. अब तो एक नई चीज़ भी हो गई है कि राजनीतिक दलों के पास कार्यकर्ता नहीं बचे हैं. अब कार्यकर्ता के रूप में दैनिक वेतन-भत्ता पाने वाला एक शख़्स आ गया है, जो हज़ार-पांच सौ रुपये रोज़ लेता है, खाने का पैसा लेता है, शराब का पैसा लेता है, पान-तंबाकू-सिगरेट का पैसा लेता है और उसके बाद गाड़ी में बैठकर सुबह 9 बजे से शाम 8 बजे तक घूमता है. उसे कुछ नहीं पता कि जिसके लिए वह घूम रहा है, उसके सिद्धांत क्या हैं, लेकिन वह जाति, धर्म और संप्रदाय के आधार पर वोट ज़रूर मांगता है. यही हमारी चुनाव प्रणाली का, हमारे लोकतंत्र का सबसे कमज़ोर पहलू है, लेकिन इसे ठीक करने का ज़िम्मा राजनीतिक दलों के ऊपर नहीं है. इसे ठीक करने का ज़िम्मा आम आदमी के ऊपर है, आम मतदाता के ऊपर है. जब तक आम मतदाता इस बात को नहीं समझेगा, तब तक यह विशद सर्किल नहीं टूटेगा, क्योंकि महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोज़गारी, विकास, शिक्षा व्यवस्था एवं स्वास्थ्य व्यवस्था की जर्जर हालत के विशद सर्किल को तोड़ने का सिर्फ़ एक रास्ता है कि राजनीति में दाग़ी और अपराधी न जाएं. राजनीति में वे जाएं, विधानसभा में वे जाएं, जो लोगों के बीच काम करते रहे हों, जो लोगों के दु:ख-दर्द और तकलीफ़ को समझते हों, जिनके पास पैसे की भरमार न हो. पर शायद ऐसा लगता है कि आजकल यह सब सोचना भी लोगों के लिए एक अजूबा सा है. पर फिर भी अच्छे की आशा हमेशा रखनी चाहिए. हो सकता है, आम मतदाता के मन में यह सवाल चल रहा हो और वह ऐसा ही करे, जैसा हम लिख रहे हैं. अगर ऐसा होता है तो हिंदुस्तान में लोकतंत्र बचेगा और हिंदुस्तान में अच्छे दिन भी देखने को मिलेंगे. चुनाव में अच्छे उम्मीदवार को वोट देना भी वैसा ही पवित्र कर्तव्य है, जैसा तीर्थों पर जाना और अपने द्वारा किए गए अपराधों की माफ़ी मांगने के लिए मंदिर के दरवाज़े पर सिर झुकाना. अगर आप अच्छे आदमी को वोट देकर भेजेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने में कुछ मदद कर पाएंगे.

संपादक
editor@chauthiduniya.com

मेघनाद देसाई

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और मुद्दे

ब्रिटिश सार्वजनिक जीवन की एक आधारभूत सच्चाई यह है कि वहां के टैक्सी चालक को भी अपने देश के राजनीतिक हालात के बारे में जानकारी होती है और जब आप टैक्सी से यात्रा कर रहे हों तो वह आपको मौजूदा राजनीतिक गतिविधियों के बारे में बता सकता है. इसी आधार पर पिछले दिनों मैंने मुंबई में टैक्सी से जाते वक़्त उसके चालक से वहां के राजनीतिक हालात के बारे में बातें कीं. वह उत्तर प्रदेश का था और भीख नहीं मांग रहा था, जैसा कि राहुल गांधी कहा करते हैं. उसने कहा कि महाराष्ट्र सरकार शिवसेना या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से हमारी सुरक्षा के लिए कोई सहायता नहीं करती है. ये संगठन महाराष्ट्र से बाहर के लोगों, विशेषकर उत्तर प्रदेश वालों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और अगर आप मुस्लिम हैं तो समस्या और भी गंभीर हो जाती है. कांग्रेस की सरकार मुसलमानों को मुसलमानों से सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाती है तो फिर इस बात की उम्मीद कैसे की जा सकती है कि वह शक्तिशाली हिंदू जाति से उनकी सुरक्षा कर पाएगी. इस व्यक्ति ने यह सभी कुछ स्वयं देखा था और अब उसे किसी भी राजनीतिक दल पर भरोसा नहीं है. वह चुनाव में मतदान करने के लिए घर जा रहा था, लेकिन उसे किसी भी दल से कोई विशेष उम्मीद नहीं थी. उसका कहना था कि उसके क्षेत्र में बसपा ने कोई ज़्यादा ग़लत काम नहीं किया है. वह जानता है कि सपा और कांग्रेस उसका वोट पाने के लिए होड़ लगाए हुए हैं, लेकिन वह अपना निर्णय सुरक्षित रखे हुए है. उसने यह भी कहा कि उसका परिवार पिछले चालीस सालों से एक भूमि विवाद में फंसा हुआ है. उसके क्षेत्र के ही एक ताक़तवर आदमी के साथ उसका विवाद चल रहा है, लेकिन उसे अभी तक इंसाफ़ नहीं मिला है. उसके लिए सबसे अधिक आशा-पूर्ण बात यह है कि वह अपनी दो बेटियों को निजी स्कूल में पढ़ने के लिए भेज रहा है. राजनीति और राजनेताओं से निराशा ही मिल रही है. अगर आप अल्पसंख्यक हैं तो सरकार से सुरक्षा मिलना मुश्किल है. स्थानीय दादाओं के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने में न्यायपालिका काफी देर लगाती है. अगर देखा जाए तो आप ख़ुद जो भी अपने और परिवार के लिए कर रहे हैं, उसके अतिरिक्त सरकार से किसी तरह की सहायता की उम्मीद नहीं कर सकते.

कांग्रेस की सरकार मुसलमानों को मुसलमानों से सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाती है तो फिर इस बात की उम्मीद कैसे की जा सकती है कि वह शक्तिशाली हिंदू जाति से उनकी सुरक्षा कर पाएगी. इस व्यक्ति ने यह सभी कुछ स्वयं देखा था और अब उसे किसी भी राजनीतिक दल पर भरोसा नहीं है. वह चुनाव में मतदान करने के लिए घर जा रहा था, लेकिन उसे किसी भी दल से कोई विशेष उम्मीद नहीं थी.

उक्त टैक्सी चालक की बातें सुनकर मुझे किसी तरह का कोई आश्चर्य नहीं हुआ. इस समय उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को वहां के लोगों की समस्याओं को कम करने के तौर पर नहीं देखा जा रहा है, बल्कि उसे केंद्र सरकार पर दबाव कम करने के औज़ार के रूप में देखा जा रहा है. इस चुनाव में कांग्रेस का लक्ष्य राहुल गांधी के माध्यम से वहां सरकार बनाना नहीं है, बल्कि उसका एक लक्ष्य बसपा को सबसे बड़ी पार्टी बनने से रोकना है. देखा जाए तो किसी तरह की कोई विचारधारा उत्तर प्रदेश के चुनाव में सक्रिय नहीं है. मुलायम सिंह मायावती की अपेक्षा कांग्रेस के अधिक विश्वसनीय हो सकते हैं. यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना महत्वपूर्ण यह है कि मुलायम सिंह किसी हालत में भाजपा के साथ नहीं जा सकते हैं, लेकिन मायावती भाजपा के साथ सरकार बना सकती हैं, जैसा कि उन्होंने पहले भी किया है. इस चुनाव के संदर्भ में कांग्रेस की सोच कुछ दूसरे तरह की है. राहुल गांधी वादा कर रहे हैं कि पिछले 22 सालों तक ग़ैर कांग्रेसी सरकार के समय जिस तरह उत्तर प्रदेश पिछड़ा है, उसे रास्ते पर लाने के लिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार लाने की आवश्यकता है, लेकिन शायद कांग्रेस अपने 42 सालों के उस शासन को भूल जाती है, जिसमें पिछड़ों और दलितों के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता रहा है. न केवल उत्तर प्रदेश, बल्कि बिहार और बंगाल की भी यही स्थिति रही है. कांग्रेस इन राज्यों में उच्च जातियों का ही साथ देती रही और

पिछड़ों एवं दलितों की स्थिति बदतर होती रही. यही कारण है कि मंडल आयोग की आवश्यकता महसूस हुई. बिहार तो 15 सालों के लालू यादव के दौर से बाहर निकल आया है, जिनका एजेंडा पिछड़ों को मुख्य धारा में शामिल करना रहा था, लेकिन वास्तविकता कुछ और थी. नीतीश कुमार का एजेंडा बिहार के विकास का है और इसी आधार पर वह चुनाव जीतकर आए हैं. उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार रही है, जिनका एजेंडा भी लालू की तरह का ही था, लेकिन बीच में भाजपा की सरकार बनी, जो कांग्रेस की तरह उच्च जातियों के पक्ष में काम करने के लिए जानी जाती है. मायावती ने भी विकास किया है, लेकिन वह मूर्तियों और पार्कों के कारण ज़्यादा चर्चा में रहीं. इस बार उत्तर प्रदेश की विकास दर भारत की सामान्य विकास दर के आसपास है, जो कि पहली बार हुआ है. उस समय को याद करें, जब उत्तर प्रदेश और बिहार में कांग्रेस के विरुद्ध लोहियावादी आंदोलन चला था और पूरे उत्तर भारत में फैल गया था. उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग कांग्रेस पर तभी भरोसा करेंगे, जबकि वह पुरानी ग़लतियां न दोहराए. राहुल गांधी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन क्या वह ऐसा करेंगे?

feedback@chauthiduniya.com

हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि यह मामला देखने से लगता है कि कई लोग अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को गंभीरता से नहीं लेते.

चौथी दुनिया
दिल्ली, 27 फरवरी–04 मार्च 2012

सूचना का अधिकार
जानने का अधिकार जीने का अधिकार
चौथी दुनिया की पहल

न्यायालय की अवमानना और आरटीआई

पिछले अंक में हमने आपको आरटीआई और संसदीय विशेषाधिकार के बीच के संबंध के बारे में बताया था. हमने कुछ उदाहरणों के साथ यह बताया था कि कई बार जानबूझ कर और बिना किसी ठोस कारण के भी सूचना को सार्वजनिक किए जाने से रोकने की कोशिश की जाती है. ज़्यादातर मामलों में ऐसा होता है कि लोक सूचना अधिकारी मामला न्यायालय में विचाराधीन होने का तर्क देकर सूचना नहीं देता, लेकिन इस प्रावधान का सबसे ज़्यादा दुरुपयोग किया जाता है. इस अंक में हम आपको ऐसी सूचना के प्रकटीकरण से संबंधित बातें बता रहे हैं, जिनका संबंध न्यायालय से है या जिनके बारे में कहा जाता है कि अमुक सूचना को सार्वजनिक करने से न्यायालय की अवमानना होती है. हम आपको बता दें कि लोक सूचना अधिकारी न्यायालय की अवमानना की बात कहकर भी कई बार सूचना देने से मना कर देते हैं. हो सकता है कि कई बार यह तर्क सही भी हो, लेकिन ज़्यादातर मामलों में देखा गया है कि लोक सूचना अधिकारी इस तर्क का ग़लत इस्तेमाल करते हैं. इसलिए यह ज़रूरी है कि आवेदक को न्यायालय की अवमानना की सही परिभाषा के बारे में जानकारी हो. इस अंक में हम आपको उदाहरण सहित यह बता रहे हैं कि न्यायालय की अवमानना कब और कैसे होती है और किन-किन परिस्थितियों में आपको सूचना देने से मना किया जा सकता है और किन परिस्थितियों में नहीं. हमें उम्मीद है कि आप आरटीआई क़ानून का इस्तेमाल कर रहे होंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रोत्साहित कर रहे होंगे. अगर कोई समस्या या परेशानी हो तो हमें बताएं. हम हर क़दम पर आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं.

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 (1)(बी) में ऐसी सूचनाएं, जिनके प्रकाशन पर किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से प्रतिबंध लगाया गया हो या जिनके प्रकटन से न्यायालय की अवमानना होती हो, उनके सार्वजनिक किए जाने पर रोक लगाई गई है. अगर कोई मामला किसी कोर्ट में निर्णय के लिए विचाराधीन है तो उसका यह कदापि अर्थ नहीं है कि उससे संबंधित कोई सूचना नहीं मांगी जा सकती.

विचाराधीन मामलों के संबंध में कोई सूचना सार्वजनिक किए जाने से कोर्ट की अवमानना हो, यह ज़रूरी नहीं है. हां, कोई विशेष सूचना जो कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर सार्वजनिक किए जाने पर रोक लगा दी हो, अगर उसे सार्वजनिक किए जाने की बात होगी तो कोर्ट की अवमानना ज़रूर होगी. गोधरा जांच के दौरान उच्च न्यायालय ने अपने एक फ़ैसले में रेल मंत्रालय को विशेष तौर पर निर्देश दिए थे कि वह गोधरा नरसंहार की जांच रिपोर्ट संसद के समक्ष प्रस्तुत न करे. न्यायालय ने रिपोर्ट सार्वजनिक किए जाने पर रोक लगा दी. इस सूचना के दिए जाने से कोर्ट की अवमानना भी हो सकती थी और धारा 8 (1)(बी) का उल्लंघन भी. ऐसे मुद्दों पर निर्णय देते वक़्त अधिकारियों को केवल वही सूचनाएं देने से मना करना चाहिए, जिन्हें न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर सार्वजनिक किए जाने को निषिद्ध कर रखा हो. कुछ मामलों में देखने में आया है कि सरकारी अधिकारी इस धारा का इस्तेमाल सूचना न देने के बहाने के रूप में धड़ल्ले से कर रहे हैं. एम्स और दिल्ली पुलिस से बाटला हाउस एनकाउंटर के दौरान मारे गए तथाकथित आतंकियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफआईआर की प्रति और दिल्ली में हुए सीरियल धमाकों की तफ्तीश के दौरान हुई गिरफ्तारी आदि की जानकारी मांगी गई थी. जवाब में बताया गया कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है और सूचना नहीं दी जा सकती. जबकि कोर्ट द्वारा सूचना सार्वजनिक न किए जाने के संबंध में दिया गया ऐसा कोई भी आदेश प्रकाश में नहीं आया. ऐसे समय में जबकि सूचना न देना एक नजीर बनता जा रहा हो, सूचना आयुक्तों की भूमिका बहुत बढ़ जाती है.

क्या कहता है क़ानून

सूचना के अधिकार क़ानून में कोर्ट की अवमानना को परिभाषित नहीं किया गया है. इसे समझने के लिए न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 का सहारा लिया जा सकता है. अधिनियम की धारा 2 (ए)(बी) और (सी) में बताया गया है कि–

ए– दीवानी या फौजदारी, दोनों तरह से कोर्ट की अवमानना हो सकती है.

बी– यदि किसी कोर्ट के निर्णय, डिक्री, आदेश, निर्देश, याचिका या कोर्ट की किसी प्रक्रिया का जानबूझ कर उल्लंघन किया जाए या कोर्ट द्वारा दिए गए किसी वचन को जानबूझ कर भंग किया जाए तो यह कोर्ट की दीवानी अवमानना होगी.

सी– किसी प्रकाशन, चाहे वह मौखिक, लिखित, सांकेतिक या किसी अभिवेदन या अन्य किसी माध्यम या कृत्य द्वारा–

1– बदनाम या बदनाम करने की कोशिश या अभिकरण या कोर्ट को नीचा दिखाने की कोशिश.

2– किसी न्यायिक प्रक्रिया में पक्षपात या हस्तक्षेप.

3– न्याय व्यवस्था को किसी प्रकार से हस्तक्षेप या बाधित करना या बाधित करने की कोशिश न्यायालय की अवमानना हो सकती है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमें पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है :

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश, पिन -201301
ई-मेल : rti@chauthiduniya.com

ज़रा हट के

झूठ का महीना

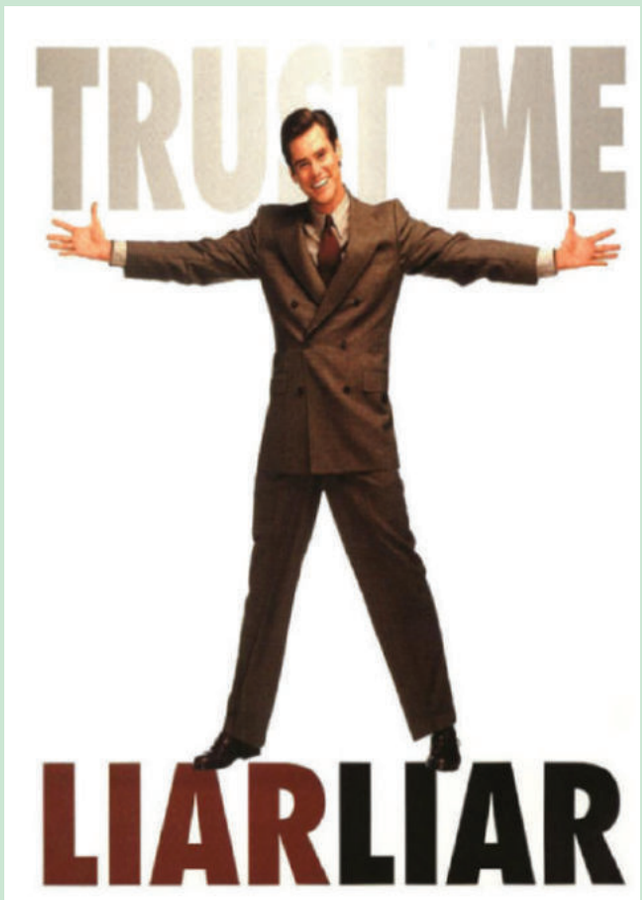

ब्रिटेन में किए गए शोध में एक रोचक तथ्य सामने आया है कि वर्ष के दूसरे महीनों की तुलना में लोग जनवरी में अधिक झूठ बोलते हैं. शोध के मुताबिक़, जनवरी में लोग रोज़ाना सात झूठ बोलते हैं, जबकि बाक़ी के महीनों में वे रोज़ाना चार झूठ बोलते हैं. ब्रिटेन में प्रसारित होने वाले टीवी कार्यक्रम लाई टू मी की रिलीज के अवसर पर कराए गए सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है कि लोग जनवरी में औसतन 217 झूठ बोलते हैं. इस सर्वेक्षण में एक और रोचक बात सामने आई कि जनवरी में लोग सर्दी से होने वाली बीमारी का बहाना करके दफ्तर से छुट्टी लेने के लिए भी झूठ बोलते हैं. सर्वेक्षण के मुताबिक़, लोग पैसे को लेकर सबसे अधिक झूठ बोलते हैं. बहुतेरे लोग क्रिसमस पर की गई ख़रीददारी और क्रेडिट-डेबिट कार्ड से की गई ख़रीददारी को भी छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं. कुछ लोग इस बात को लेकर झूठ का सहारा लेते हैं कि नववर्ष पर उनकी पार्टी किस स्थान पर हुई. लोग कहते हैं कि वे शानदार पार्टी का लुत्फ ले रहे थे, जबकि असल में वे घर में बैठकर टीवी देख रहे थे.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

शादी से लंबा तलाक़

एक दंपत्ति का वैवाहिक जीवन 24 घंटे से भी कम चला और शादी के 30 सालों बाद तलाक़ पर हाईकोर्ट ने पिछले दिनों मुहर लगाई. निचली अदालत ने पति की अर्जी पर 1996 में तलाक़ की डिक्री दी थी, जिसे महिला ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने महिला की अर्जी ख़ारिज करते हुए तलाक़ के फ़ैसले को सही ठहराया. हाईकोर्ट ने कहा कि पति को छोड़कर पत्नी ख़ुद गई थी और यह बात तलाक़ का आधार बनती है. हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि यह मामला देखने से लगता है कि कई लोग अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को गंभीरता से नहीं लेते. राजन और छवि (दोनों बदले हुए नाम) की शादी 30 जून, 1982 को हुई थी. शादी के कुछ दिनों बाद छवि अपने मायके चली गई और फिर वह वापस नहीं लौटी. क़रीब 5 साल बाद राजन ने साथ छोड़ने और क्रूरता के आधार पर निचली अदालत में छवि से तलाक़ लेने की अर्जी दाख़िल की और याचिका में उक्त तथ्यों का ख़ुलासा किया. मामले की सुनवाई हुई और 1996 में अदालत ने राजन के पक्ष में तलाक़ की डिक्री दे दी. इस फ़ैसले को छवि ने हाईकोर्ट में चुनौती दी. छवि की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया कि उसके पति ने शादी के फ़ौरन बाद ही स्कूटर आदि की मांग शुरू कर दी थी और उसे प्रताड़ित भी किया, जिसके चलते वह ससुराल छोड़कर चली गई. हाईकोर्ट ने यह दलील ख़ारिज करते हुए कहा कि जिस तरह महिला अपने पति का घर छोड़कर गई, वह तलाक़ का आधार बनता है, इसलिए निचली अदालत का फ़ैसला सही है.

छह दांत और एक सांप

उत्तरी इजरायल के एक शहर में एक छोटे बच्चे ने एक सांप को पकड़ कर उसका सिर चबा डाला. बच्चे के परिवारीजनों ने बताया कि 13 महीने के इमाद आलियान के अभी सिर्फ़ छह दांत निकले हैं, लेकिन उसे उसकी मां ने एक 20 सेंटीमीटर लंबे सांप को पकड़ कर उसका सिर अपने मुंह में डाले देखा. इस पर उसने चिल्ला कर पड़ोसियों को बुलाया. हैफा से 15 किलोमीटर दूर शेफा अम्र शहर में रहने वाली घादिर आलियान ने बताया, मैं अपने बच्चे के लिए दूध बना रही थी. मैंने पीछे मुड़कर देखा और पाया कि सांप उसके मुंह में है. मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया. शोर सुनकर परिवार के बाक़ी लोग एवं पड़ोसी भी आ गए. बच्चे की रिश्तेदार यासमीन शाहीन ने बताया कि हमने देखा कि बच्चे के मुंह में सांप है और वह उसे चबा रहा है. उन्होंने बताया कि शोर सुनकर पहुंचे एक पड़ोसी ने बच्चे के मुंह से अधमरा सांप खींचकर निकाला और उसे मार दिया. परिवारीजनों ने तुरंत बच्चे की पूरी जांच की कि कहीं उसे सांप ने काटा तो नहीं है. उसे अस्पताल भी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसके सुरक्षित होने की पुष्टि की. यासमीन ने बताया कि जब सांप को बाहर खींचा गया तो इमाद ने रोना शुरू कर दिया. डॉक्टरों ने बताया कि सांप वास्तव में ज़हरीला था, लेकिन हम इस मामले में ख़ुशक़िस्मत रहे कि इस प्रकार का सांप सर्दियों में कम ज़हर छोड़ता है. विशेषज्ञ डॉ. बोआज शाचाम ने बताया कि तस्वीरें देखकर लगता है कि यह सिर पर सिक्के की आकृति वाला सांप था, जो ज़हरीला नहीं होता, लेकिन देखने में वाइपर की तरह लगता है, जो बेहद ज़हरीला होता है. उन्होंने बताया कि इस प्रजाति के सांप 1 से 3 मीटर तक लंबे होते हैं. जिस सांप के सिर को बच्चे ने चबाया, वह बेहद छोटा था. संभवत: सांप ने बच्चे को इसलिए नहीं काटा, क्योंकि ऐसे सांप सर्दियों में सक्रिय नहीं होते.

राशिफल

मेष 21 मार्च से 20 अप्रैल

आप अपनी सोच बदलें और भगवान भरोसे रहकर न चलें. कामयाबी के लिए अपनी तरफ़ से भी हाथ-पांव मारना ज़रूरी है. ईश्वर उनकी मदद करता है, जो अपनी मदद आप करते हैं. अपने हितों की रक्षा करना एक ज़िम्मेदार आदमी का काम है. यदि यह ज़िम्मेदारी आप नहीं उठाते हैं तो आपको कुछ कहने का अधिकार नहीं है.

वृष 21 अप्रैल से 20 मई

इस सप्ताह आप चिंतामग्न रह सकते हैं. जहां तक हो सके, अपने बलबूते पर ही अपनी समस्याओं का हल निकालें, क्योंकि दूसरे का सहारा लेकर या शासन-सत्ता के बल पर कुछ कर लेने से अधिक दिनों तक प्रभाव क़ायम नहीं रहता और यह भी ज़रूरी नहीं है कि इससे कोई स्थायी सफलता मिल पाएगी.

मिथुन 21 मई से 20 जून

आपका भौतिक और सांसारिक दृष्टिकोण इस सप्ताह बदल सकता है. किसी व्यक्ति को देखकर आपके मन में संवेदना, प्रेम एवं सद्भावना जन्म ले रही है. आप उसे तन-मन-धन से मदद कर सकते हैं. वह व्यक्ति आगे चलकर आपके काम आ सकता है. पढ़ने-लिखने का काम निपटाने के लिए यह समय उपयुक्त है.

कर्क 21 जून से 20 जुलाई

यह सप्ताह आनंदप्रद है. सुख-आराम की इच्छा सभी को होती है, परंतु यह तोहफा परिश्रम करने से ही मिलता है. आप भाग्यशाली हैं, इसलिए दूसरों के परिश्रम के सहारे ख़ुद आराम का समय बिता रहे हैं. सप्ताह के मध्य में एक अनोखा एवं सुखद अवसर आपको मिल सकता है, जिससे आपके मौज के दिन फिर से आ जाएंगे.

सिंह 21 जुलाई से 20 अगस्त

फ़ैसले लेने के लिए तैयार रहें. कार्यस्थल में स्थान परिवर्तन एक अच्छा मोड़ लेकर आ रहा है. किसी के प्रति निष्ठा और सुमधुर वाणी रखने से आप लोगों का दिल जीत सकते हैं. एक बार लोगों में मान-प्रतिष्ठा बन जाने पर आजीवन उसका सुख भोग मिलता रहता है.

कन्या 21 अगस्त से 20 सितंबर

इस सप्ताह आप अपने आपको पीड़ित महसूस करेंगे. आप जिस स्तर पर कार्यरत हैं, वहां चुप रहना अधिक कुशलता का सूचक है, लेकिन ऐसी जगह पर काफी लंबे समय तक काम करना किसी के लिए भी संभव नहीं. आपको विकल्प के रूप में अपने लिए कहीं दूसरे व्यवसाय- आजीविका की भी खोजबीन करनी चाहिए.

तुला 21 सितंबर से 20 अक्टूबर

इस सप्ताह व्यवस्था और जीवनयापन के कई सवाल सामने रहेंगे. घरेलू स्तर पर भी आपको काफी उतार-चढ़ाव देखना पड़ सकता है. यदि आप युवा हैं और अभी करियर या व्यवसाय के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो वही काम करने की चेष्टा करें, जिसमें आत्म सम्मान बरकरार रहे और कार्यस्थल का माहौल अच्छा हो.

वृश्चिक 21 अक्टूबर से 20 नवंबर

यह सप्ताह आपके कामकाज में सुधार लाने में विशेष योगदान दे रहा है. किसी जानकार मित्र की सलाह पर आप अपने बिगड़े काम को ठीक कर सकते हैं. कहा भी गया है कि अच्छी सलाह और अच्छा मित्र सदा नहीं मिलते. सप्ताह के अंत में जश्न का दौर चल सकता है अथवा कहीं आना-जाना हो सकता है.

धनु 21 नवंबर से 20 दिसंबर

आपके सभी कार्य शुरुआती दौर में बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब फायदे का समय आता है तो वे अटक जाते हैं. इस सप्ताह भी आप लोगों के साथ टकराव से बचें. यदि आप अपने काम में मग्न रहते हैं तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता.

मकर 21 दिसंबर से 20 जनवरी

सप्ताह के आरंभ में अपने कामकाज अथवा व्यवसाय की तरफ़ नज़र रखना आपकी पहली प्राथमिकता होगी. अपने प्रोजेक्ट का काम किसी दूसरे को सौंपना ठीक नहीं. सप्ताह के मध्य तक आप अपना बिखरा हुआ कारोबार सही तरीक़े से समेट लें.

कुंभ 21 जनवरी से 20 फरवरी

आपके पास अनेक प्रकार के लोग आश्रय लेने आ रहे हैं. अतिथि कुछ अधिक लंबा पड़ाव डालना चाहते हैं, लेकिन इस वक़्त आप पूरे मान-सम्मान से सभी के आदर-सत्कार का फर्ज पूरा करें. हो सकता है, आने वाले समय में आप भी इन लोगों के बीच विशेष व्यक्ति बनकर छुट्टी बिताने की सोच सकते हैं.

मीन 21 फरवरी से 20 मार्च

आप किसी ऐसे स्वार्थी व्यक्ति से टकरा सकते हैं, जो आपसे बार-बार फ़ायदा उठाता रहा. आपको चाहिए कि उससे अधिक न उलझें, क्योंकि ऐसे लोगों का ध्यान आपको नुकसान पहुंचाने में लगा रहता है. अपनी जमा पूंजी पर नियंत्रण रखें. फिजूलखर्ची और लापरवाही से चलने पर आप आर्थिक संकट की चपेट में आ सकते हैं.

पंडित सुदर्शन
feedback@chauthiduniya.com

मोहम्मद नशीद का चुनाव की मांग करना इस ओर इशारा करता है कि मालदीव में सब कुछ ठीक नहीं है. वहां की स्थिति बाहरी तौर पर जितनी शांत और स्थिर दिखाई दे रही है, वह आंतरिक तौर पर उतनी ही अस्थिर है.

मालदीव में सत्ता परिवर्तन
भारत के सामने चुनौती

मालदीव में शांतिपूर्ण तरीक़े से सत्ता परिवर्तन हो गया है. मोहम्मद नशीद ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफ़ा दे दिया तथा उपराष्ट्रपति मोहम्मद वाहिद हसन को राष्ट्रपति बना दिया गया. कुछ दिनों से चल रहा राजनीतिक संकट समाप्त होता दिखाई दे रहा है. लेकिन मोहम्मद नशीद का इस्तीफ़ा देना, सत्ता परिवर्तन को राष्ट्र हित में घोषित किया जाना, वर्तमान राष्ट्रपति का यह बयान कि उसे पुलिस और सेना का समर्थन हासिल है, भारत द्वारा वहां की परिस्थितियों पर नज़र रखने के लिए अपना विशेष दूत का भेजा जाना, अमेरिका का बयान कि मालदीव अभी भी अस्थिर है, पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद का यह कहना कि उन्होंने अपनी मर्ज़ी से सत्ता का त्याग नहीं किया है, बल्कि बंदूक़ की नोंक पर उन्हें इस्तीफ़ा देने के लिए बाध्य किया गया है. साथ ही मोहम्मद नशीद का चुनाव की मांग करना इस ओर इशारा करता है कि मालदीव में सब कुछ ठीक नहीं है. वहां की स्थिति बाहरी तौर पर जितनी शांत और स्थिर दिखाई दे रही है, वह आंतरिक तौर पर उतनी ही अस्थिर है. यह तूफ़ान आने से पहले की शांति जैसी है. चूंकि भारत मालदीव का निकटतम पड़ोसी है, इसलिए वहां की स्थिति पर पैनी निगाह रखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा. मालदीव में लगभग तीस हज़ार भारतीय नागरिक काम कर रहे हैं. मालदीव का न केवल भारत के लिए आर्थिक महत्व है, बल्कि सामरिक दृष्टि से भी यह भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण देश है. इसलिए यह ज़रूरी है कि इस सत्ता परिवर्तन की परिस्थितियों को समझा जाए तथा मालदीव में भारत को किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, इस पर भी ग़ौर किया जाए. ग़ौरतलब है कि मोहम्मद नशीद लोकतांत्रिक तरीक़े से चुनकर आए थे. उन्होंने चुनाव में अपने प्रतिद्वंद्वी ममून

अब्दुल ग़यूम को पराजित किया था. 2008 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में मोहम्मद नशीद को 54 फ़ीसदी मत मिले थे, जबकि ममून अब्दुल ग़यूम को 46 फ़ीसदी मत प्राप्त हुए थे. अब्दुल ग़यूम 1978 से मालदीव के राष्ट्रपति थे. 1978 के बाद 6 बार राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, लेकिन कोई भी ग़यूम के ख़िलाफ़ चुनाव में खड़ा नहीं हुआ. इसके कारण तीस सालों तक अब्दुल ग़यूम ही मालदीव के राष्ट्रपति बने रहे. उन पर अपने विपक्षियों को दबाने का आरोप लगता रहा. मानवाधिकार कार्यकर्ता मोहम्मद नशीद को भी ग़यूम का विरोध करने के कारण जेल जाना पड़ा था, लेकिन आख़िरकार नशीद ने ग़यूम को लोकतांत्रिक तरीक़े से चुनौती दी तथा उन्हें चुनाव में हरा भी दिया. मगर पूर्व राष्ट्रपति ग़यूम की स्थिति बहुत कमज़ोर नहीं रही है. सरकार में अभी तक उनके समर्थक मज़बूत स्थिति में हैं. मोहम्मद नशीद लोकतंत्र के समर्थक रहे हैं तथा मालदीव के सामाजिक–राजनीतिक और धार्मिक ढांचे में अनेक सुधार किए, जिसके कारण उनके दुश्मनों की संख्या बढ़ गई. चूंकि मालदीव एक इस्लामिक राष्ट्र है और नशीद एक उदारवादी लोकतांत्रिक राष्ट्रपति थे. इस कारण वहां के कट्टरपंथियों ने कभी उन्हें पसंद नहीं किया. मौजूदा विवाद का कारण न्यायपालिका में सुधार की कोशिश ही है. न्यायपालिका ने कट्टरता तथा आतंकवाद से जुड़े कतिपय मामलों में धार्मिक आग्रहों के प्रति सहानुभूति दिखाई थी. जब नशीद ने एक वरिष्ठ न्यायाधीश को भ्रष्टाचार, विपक्ष से सहानुभूति रखने के कारण पद से हटाने तथा गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया. इसके बाद पहले मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने और बाद में अन्य लोगों ने प्रदर्शन किया. लेकिन मुख्य वजह कोई और ही थी. ग़यूम समर्थक नशीद को पदच्युत करना चाहते थे. हालांकि राष्ट्रपति वाहिद हसन ने राष्ट्रीय सरकार बनाने की बात कही है और सैन्य तख्तापलट से इंकार किया है. लेकिन आगे उनकी रणनीति क्या होगी, इस पर नज़र रखना भारत के लिए ज़रूरी है. अगर मालदीव कट्टरपंथियों के नज़दीक जाता है तो हमारे पड़ोसी मुल्क इसका फ़ायदा उठा सकते हैं. भारत ने वहां की घटनाओं पर नज़र न रखकर पहले ही ग़लती कर दी है, अब आगे भी ग़लती करता रहा तो एक और पड़ोसी देश में इसके विरुद्ध आवाज़ उठने लगेगी. मालदीव की राजनीतिक स्थिरता और सत्ता का उदारवादी दृष्टिकोण भारत के लिए ज़रूरी है. भारत के समक्ष एक चुनौती आ गई है, इससे निपटना ही होगा.

राजीव कुमार
feedback@chauthiduniya.com

ईरान के ख़िलाफ़ साज़िश!

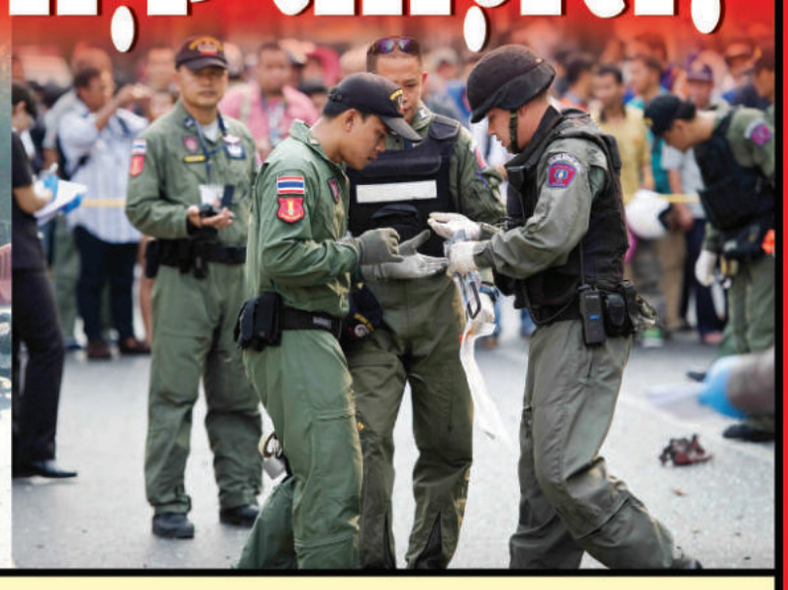

राजीव कुमार

दिल्ली में इज़राईली दूतावास की एक गाड़ी पर बम से हमला किया गया. इस हमले में एक इज़राईली राजनयिक के साथ चार अन्य लोग घायल हो गए. इसी तरह की एक साज़िश का पर्दाफ़ाश जॉर्जिया में भी हुआ. वहां भी इज़राईली दूतावास के पास एक गाड़ी में विस्फोटक सामग्री पकड़ी गई. ज़ाहिर है, अगर यह विस्फोटक सामग्री नहीं पकड़ी जाती तो धमाका किया जाता. इज़राईल का कहना है कि उसके नागरिकों और विभिन्न देशों में उसके दूतावासों पर हमला करने वाला कोई और नहीं, बल्कि ईरान तथा हिजबुल्ला के लोग हैं. इसी तरह की एक घटना थाईलैंड में भी हुई. बैंकॉक में बम धमाके किए गए. वहां धमाका करने वाला ख़ुद भी घायल हो गया. घटनास्थल से ईरान का परिचय पत्र मिला है, जिससे इस घटना में किसी ईरानी के शामिल होने की बात कही जा रही है. एक–दो दिन के अंतराल में घटी इन घटनाओं ने एक साथ कई सवालों को जन्म दिया है. हालांकि जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती और जांच एजेंसियां इन घटनाओं के ज़िम्मेदार लोगों तथा बम धमाके के उद्देश्य का पता नहीं लगा लेती हैं, कुछ भी साफ़ तौर पर नहीं कहा जा सकता है. लेकिन इन घटनाओं तथा वर्तमान परिस्थितियों ने जो सवाल खड़े किए हैं, उनके उत्तर तो ढूंढने ही पड़ेंगे.

सबसे पहले सवाल उठता है कि जब दिल्ली में इज़राईली राजनयिक की कार में विस्फोट हुआ और जॉर्जिया में इज़राईली दूतावास के पास विस्फोटक सामग्री मिली तो इज़राईल ने जांच के बाद आई रिपोर्ट का इंतज़ार किए बिना यह क्यों कह दिया कि इसमें ईरान या हिजबुल्ला का हाथ है. उसने अलक़ायदा या भारत में सक्रिय किसी अन्य आतंकवादी संगठन का नाम क्यों नहीं लिया. इसकी एक वजह है ईरान और हिजबुल्ला के साथ इज़राईल की शत्रुता. हिजबुल्ला लेबनान का संगठन है, जो अपने देश के एक क्षेत्र को इज़राईली क़ब्ज़े से मुक्त कराने के लिए संघर्ष कर रहा है. इज़राईल के निकटतम सहयोगी होने के कारण अमेरिका से भी उसकी दुश्मनी है. उसके पूर्व प्रमुख इमाद मोग्नी की हत्या एक बम विस्फोट में हुई थी तथा हिजबुल्ला का मानना है कि मोग्नी की हत्या में इज़राईल का हाथ है. हिजबुल्ला ने पहले भी अमेरिका और इज़राईल के ठिकानों पर पर हमला किया है. इज़राईल का कहना है कि हिजबुल्ला ने अपने पूर्व प्रमुख का बदला लेने के लिए ही इज़राईली दूतावास के अधिकारी पर हमला किया है तथा वह बताना चाहता है कि अभी अपने पूर्व प्रमुख की हत्या को वह भूला नहीं है. इज़राईल की ऐसी ही शत्रुता हमास से भी है जिसे वह आतंकी संगठन मानता है. हालांकि हमास फ़िलीस्तीन में ही सक्रिय है तथा चुनाव जीत चुका है. लेकिन इज़राईल ने हमास का नाम नहीं लिया. उसने हिजबुल्ला और ईरान का ही नाम लिया. इसका एक कारण यह हो सकता है कि अभी कुछ दिनों पहले हिजबुल्ला और ईरान के बीच के संबंध का ख़ुलासा हुआ था. हिजबुल्ला प्रमुख हसन नसरल्ला ने भी स्वीकार किया है कि उसकी पार्टी को ईरान से आर्थिक तथा राजनीतिक समर्थन मिलता है. यह बात उसने इसलिए स्वीकार की, क्योंकि उस पर नशीले पदार्थों की तस्करी और धन उगाही का आरोप लग रहा था. अभी ईरान पर वैसे भी कई आरोप लग रहे हैं. इज़राईल, अमेरिका और यूरोपीय संघ ने ईरान पर परमाणु बम बनाने का आरोप लगाया है. उसके परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए उस पर आर्थिक प्रतिबंध भी लगाया गया है. यही नहीं अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के एक उम्मीदवार ने तो यहां तक कह दिया कि राष्ट्रपति बनने के बाद वह ईरान पर आक्रमण करेगा. अमेरिका की तरफ़ से यह भी बयान आ रहा है कि नवंबर तक ईरान पर आक्रमण किया जा सकता है. ब्रिटेन, फ्रांस आदि यूरोपीय देश भी ईरान पर आक्रमण करने के पक्ष में हैं. लेकिन अभी चीन और रूस का साथ इन देशों को नहीं मिल रहा है. भारत ने भी ईरान से तेल ख़रीदने पर लगाए गए प्रतिबंध का समर्थन नहीं किया है तथा ईरान से तेल आयात करते रहने का फ़ैसला किया है. भारत का कहना है कि वह केवल संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को मानेगा किसी अन्य संगठनों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध से उसे कोई विशेष लेना देना नहीं है. ऐसे में संभावना इस बात की है कि कहीं इन घटनाओं के तार ईरान को वैश्विक स्तर पर बदनाम करने की कोशिश से तो नहीं जुड़े हैं. कहीं ईरान पर आक्रमण करने से पहले अमेरिका–इज़राईल तथा कुछ यूरोपीय देश यह साबित करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं कि ईरान वैश्विक शांति के लिए ख़तरा बनता जा रहा है. ऐसी संभावनाओं से इंकार भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अमेरिका इससे पहले भी ऐसा कर चुका है. ईराक़ पर आक्रमण करने के लिए भी अमेरिका ने ऐसे ही आरोप सद्दाम हुसैन पर लगाए थे. लेकिन अभी तक इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिल पाया कि सद्दाम हुसैन का संबंध आतंकवादी संगठनों के साथ था अथवा वह परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा था. हो सकता है कि ऐसी ही कोशिश ईरान के लिए भी की जा रही है और इन घटनाओं के साथ ईरान को जोड़कर ईरान के ख़िलाफ़ साज़िश की जा रही है.

दूसरी बात यह है कि अगर ईरान ने इज़राईली अधिकारियों को टारगेट किया है, तो इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है. कुछ दिनों पहले ही ईरान के एक परमाणु वैज्ञानिक मोस्तफ़ा अहमदी रोशन की हत्या कर दी गई थी. ईरान में परमाणु वैज्ञानिक की हुई यह पहली हत्या नहीं थी. पिछले दो वर्षों में ईरान के तीन अन्य परमाणु वैज्ञानिकों मसूद अली मोहम्मद, माजिद शहरीयारी और रेजेनेयाद की हत्या हो चुकी है तथा एक वैज्ञानिक अब्बासी द्वानी हमले के शिकार होने के बाद बच गए. ईरान ने साफ़ तौर पर आरोप लगाया है कि उसके वैज्ञानिकों की हत्या में अमेरिका तथा इज़राईल का हाथ है. ईरान ने उस समय कहा था कि इस हत्या के लिए ज़िम्मेदार देशों को वह उन्हीं के तरीक़े से जवाब देगा. ईरानी वैज्ञानिक की हत्या में जिस स्टीकी बम का इस्तेमाल किया गया था, उसी तरह के बम का इस्तेमाल दिल्ली के धमाके में भी किया गया है. भारतीय जांच एजेंसियों का भी कहना है कि इस तरह के बम का इस्तेमाल पहले नहीं किया गया है. ऐसे बम बाहर से मंगवाए गए हैं. हो सकता है कि इस धमाके में ईरान का हाथ हो. जब तक धमाके की गुत्थी नहीं सुलझ जाती, साफ़ तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है. लेकिन अगर ईरान का हाथ है और उसने अपने वैज्ञानिकों की हत्या का बदला लेने के लिए ऐसा किया है तो इसे विश्व के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता है. इज़राईल और ईरान दोनों को इस बारे में सोचना चाहिए. इससे एक ऐसी परंपरा की शुरुआत हो जाएगी, जिसे रोक पाना शायद संभव न हो. भारत के ईरान के साथ अच्छे संबंध रहे हैं. भारत में हुए इस धमाके का कहीं ग़लत तरीक़े से इस्तेमाल न हो इस बात का ध्यान रखा जाना भी बहुत ज़रूरी है. अभी रहस्य से पर्दा उठना बाक़ी है, लेकिन इतना तो कहा ही जा सकता है कि भारत में हुए इस धमाके को ईरान पर हमला करने का आधार नहीं बनने देना चाहिए.

feedback@chauthiduniya.com

देश का पहला इंटरनेट टीवी

हर दिन 50,000 से ज़्यादा दर्शक

- दो टूक-संतोष भारतीय के साथ
- ब्लैक एंड व्हाइट रोज़ाना 1 बजे
- पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया
- स्पेशल रिपोर्ट
- नायाब हैं हम-उर्दू के मशहूर शायरों, गीतकारों के साथ मुलाक़ात
- साई की महिमा

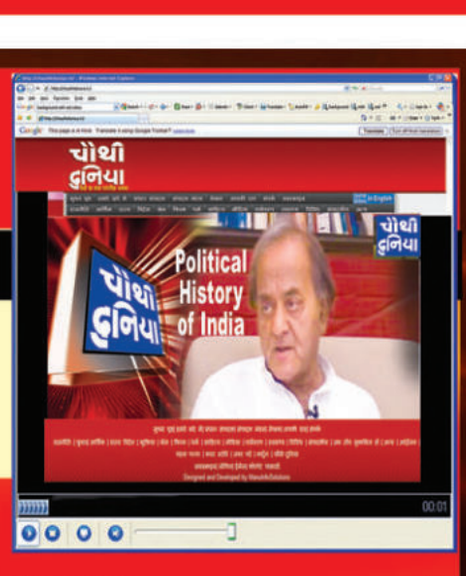

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301 www.chauthiduniya.tv

पंचायत स्तर के सभी कर्मचारियों की उपस्थिति स्वयं प्रमाणित करती हूं. 2010-11 में मनरेगा के तहत रोजगार की मांग करने वाले सभी लोगों को 100 दिनों का रोज़गार दिया गया.

साई बाबा और सोमदेव स्वामी

स्वामी को अब और भी अधिक घबराहट होने लगी. उन्होंने कहा, मैंने अनेक साधु-संतों के दर्शन किए हैं, परंतु यह संत कोई बिरला ही है, जो इस प्रकार ऐश्वर्य की वस्तुएं संग्रह कर रहा है. ऐसे साधु के दर्शन न करना ही उत्तम है, ऐसा कहकर वह वापस लौटने लगे. तीर्थयात्रियों ने प्रतिरोध करते हुए उन्हें आगे बढ़ने की सलाह दी और समझाया, तुम यह संकुचित मनोवृत्ति छोड़ दो.

अब एक अन्य संशयालु व्यक्ति की कथा सुनिए, जो बाबा की परीक्षा लेने आया था. काका साहेब दीक्षित के भ्राताश्री भाई जी नागपुर में रहते थे. जब वह 1906 में हिमालय गए थे, तब उनका गंगोत्री घाटी के नीचे हरिद्वार के समीप उत्तर काशी में एक सोमदेव स्वामी से परिचय हो गया. दोनों ने एक-दूसरे के पते लिख लिए. पांच वर्ष पश्चात सोमदेव स्वामी नागपुर आए और भाई जी के यहां ठहरे. वहां श्री साई बाबा की कीर्ति सुनकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और उनके दर्शन करने की तीव्र उत्कंठा भी. मनमाड और कोपरगांव निकल जाने पर वह एक तांगे में बैठकर शिरडी के लिए चल पड़े. शिरडी के समीप पहुंचने पर उन्होंने दूर से ही मस्जिद पर दो ध्वज लहराते हुए देखे. सामान्यत: देखने में आता है कि भिन्न-भिन्न संतों के बर्ताव, रहन-सहन और बाह्य सामग्रियों में काफी अंतर होता है, परंतु केवल इसी से उनकी योग्यता का आकलन कर लेना बड़ी भूल है. सोमदेव स्वामी कुछ भिन्न प्रकृति के थे. उन्होंने जैसे ही ध्वजों को लहराते देखा तो वह सोचने लगे कि बाबा संत होकर इन ध्वजों में इतनी दिलचस्पी क्यों रखते हैं, क्या इससे उनका संतपन प्रकट होता है? ऐसा प्रतीत होता है कि यह संत अपनी कीर्ति का इच्छुक है. अतएव उन्होंने शिरडी जाने का विचार त्याग कर अपने सहयात्रियों से कहा, मैं तो वापस लौटना चाहता हूं. तब वे लोग कहने लगे कि फिर व्यर्थ ही इतनी दूर क्यों आए, अभी केवल ध्वज देखकर तुम इतने उद्विग्न हो उठे हो, तो जब शिरडी में रथ, पालकी, घोड़ा और अन्य सामग्रियां देखोगे, तब तुम्हारी क्या दशा होगी? स्वामी को अब और भी अधिक घबराहट होने लगी. उन्होंने कहा, मैंने अनेक साधु-संतों के दर्शन किए हैं, परंतु यह संत कोई बिरला ही है, जो इस प्रकार ऐश्वर्य की वस्तुएं संग्रह कर रहा है. ऐसे साधु के दर्शन न करना ही उत्तम है, ऐसा कहकर वह वापस लौटने लगे. तीर्थयात्रियों ने प्रतिरोध करते हुए उन्हें आगे बढ़ने की सलाह दी और समझाया, तुम यह संकुचित मनोवृत्ति छोड़ दो. मस्जिद में जो साधु हैं, वह इन ध्वजाओं एवं अन्य सामग्रियों या अपनी कीर्ति का स्वप्न में भी सोच-विचार नहीं करते. यह सब तो उनके भक्तगण प्रेम एवं भक्ति के कारण उन्हें भेंट करते हैं. अंत में वह शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करने के लिए तैयार हो गए. मस्जिद के मंडप में पहुंचते ही वह द्रवित हो गए. उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, कंठ रुंध गया, सभी दूषित विचार हवा हो गए और उन्हें अपने गुरु के शब्दों की स्मृति हो आई कि मन जहां अति प्रसन्न और आकर्षित हो जाए, उसी स्थान को अपना विश्राम धाम समझना. वह बाबा की चरण रज में लोटना चाहते थे, परंतु जैसे ही वह उनके समीप गए, बाबा क्रोधित होकर जोर-जोर से चिल्लाकर कहने लगे, हमारा सामान हमारे साथ रहने दो, तुम अपने घर वापस लौट जाओ. ऐसे संत के दर्शन ही क्यों करने चाहिए, जो मस्जिद पर ध्वजाएं लगाकर रखे. क्या ये संतपन के लक्षण हैं. एक क्षण भी यहां न रुको. अब उन्हें अनुभव हो गया कि बाबा ने उनके हृदय की बात जान ली है और वे कितने सर्वज्ञ हैं. उन्हें अपनी योग्यता पर हंसी आने लगी और पता चल गया कि बाबा कितने निर्विकार एवं पवित्र हैं. उन्होंने देखा कि वह किसी को हृदय से लगाते हैं, किसी को हाथ से स्पर्श करते हैं, किसी को सांत्वना देकर प्रेम दृष्टि से निहारते हैं और किसी को उदी प्रसाद देकर सुख-संतोष पहुंचा रहे हैं, तो फिर मेरे साथ ऐसा रूखा बर्ताव क्यों? अधिक विचार करने पर वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इसकी वजह उनके आंतरिक विचार थे और उन्हें अपना आचरण सुधारना चाहिए. बाबा का क्रोध तो उनके लिए वरदान है. अब यह कहना व्यर्थ होगा कि वह बाबा की शरण में आ गए और उनके परम भक्त बन गए.

नाना साहेब चांदोरकर

एक बार नाना साहेब म्हालसापति और अन्य लोगों के साथ मस्जिद में बैठे हुए थे, तभी बीजापुर से एक संभ्रांत यवन परिवार श्री साई बाबा के दर्शनार्थ आया. कुलवंतियों की लाज रक्षण भावना देखकर नाना साहेब वहां से निकल जाना चाहते थे, परंतु बाबा ने उन्हें रोक लिया. स्त्रियां आगे बढ़ीं और उन्होंने बाबा के दर्शन किए. उनमें से एक महिला ने अपने मुंह से घूंघट हटाकर बाबा के चरणों में प्रणाम करके फिर घूंघट डाल लिया. नाना साहेब उसके सौंदर्य से आकर्षित हो गए और एक बार पुन: वह छटा देखने के लिए लालायित हो उठे. नाना के मन की व्यथा जानकर उन लोगों के चले जाने के पश्चात बाबा उनसे कहने लगे, नाना, क्यों व्यर्थ में मोहित हो रहे हो, इंद्रियों को अपना कार्य करने दो. हमें उनके कार्य में बाधक नहीं बनना चाहिए. भगवान ने यह सुंदर सृष्टि निर्माण की है. अत: हमारा कर्तव्य है कि हम उसके सौंदर्य की सराहना करें. यह मन तो क्रमश: ही स्थिर होता है और जब सामने का द्वार खुला है, तब हमें पिछले द्वार से क्यों प्रविष्ट होना चाहिए. चित्त शुद्ध होते ही किसी कष्ट का अनुभव नहीं होता. यदि हमारे मन में कुविचार नहीं है तो हमें किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं. नेत्रों को अपना कार्य करने दो. इसके लिए तुम्हें लज्जित और विचलित नहीं होना चाहिए. उस समय शामा भी वहीं थे. उनकी समझ में नहीं आया कि आखिर बाबा केकहने का तात्पर्य क्या है. इसलिए लौटते समय इस विषय में उन्होंने नाना से पूछा. उस परम सुंदरी के सौंदर्य को देखकर जिस प्रकार नाना मोहित हुए और यह जानकर बाबा ने उन्हें जो उपदेश दिए, उसे उन्होंने शामा को इस प्रकार समझाया, हमारा मन स्वभावत: चंचल है, पर हमें उसे लंपट नहीं होने देना चाहिए. इंद्रियां चाहे भले ही चंचल हो जाएं, परंतु हमें अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण रखकर उसे अशांत नहीं होने देना चाहिए. इंद्रियां तो अपने विषय पदार्थों के लिए सदैव चेष्टा करती हैं, पर हमें उनके वशीभूत होकर उनके इच्छित पदार्थों के समीप नहीं जाना चाहिए. क्रमश: प्रयत्न करते रहने से इस चंचलता को नियंत्रित किया जा सकता है. यद्यपि उस पर पूर्ण नियंत्रण संभव नहीं है तो भी हमें उसके वशीभूत नहीं होना चाहिए. प्रसंगानुसार हमें उसका वास्तविक रूप से उचित गति अवरोध करना चाहिए. सौंदर्य तो आंखें सेंकने का विषय है, इसलिए हमें निडर होकर सुंदर पदार्थों की ओर देखना चाहिए. यदि हमारे अंदर किसी प्रकार के कुविचार न आएं तो इसमें लज्जा और भय की आवश्यकता ही क्या है. यदि मन को निरिच्छ बनाकर ईश्वर के सौंदर्य को निहारो तो इंद्रियां सहज और स्वाभाविक रूप से अपने वश में आ जाएंगी और विषयानंद लेते समय भी तुम्हें ईश्वर की स्मृति बनी रहेगी. यदि उसे इंद्रियों के पीछे दौड़ने दोगे और उनमें लिप्त रहोगे तो तुम्हें जन्म-मृत्यु के पाश से कदापि छुटकारा नहीं मिलेगा. विषय पदार्थ इंद्रियों को सदा पथभ्रष्ट करने वाले होते हैं. अतएव हमें विवेक को सारथी बनाकर मन की लगाम अपने हाथ में लेकर इंद्रिय रूपी घोड़ों को विषय पदार्थों की ओर जाने से रोक लेना चाहिए. ऐसा विवेक रूपी सारथी हमें विष्णु-पद की प्राप्ति करा देगा, जो हमारा यथार्थ में परम सत्य धाम है और जहां गया हुआ प्राणी फिर कभी यहां नहीं लौटता.

श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु शुभं भवतु.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

सामरदा पंचायत

मानव विकास की जीती-जागती मिसाल

बीकानेर ज़िले की खाजूवाला पंचायत समिति की सामरदा पंचायत के कार्यालय एवं परिसर को देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह उन चुनिंदा पंचायतों में से एक है, जो स्वशासन का सपना साकार करने के लिए प्रयासरत हैं. राजीव गांधी भारत निर्माण भवन, सरपंच कार्यालय, कंप्यूटर रूम, दीवारों पर चस्पां विभिन्न सूचनाएं और लोगों का आवागमन इस बात की पुष्टि करता है कि इस पंचायत का नेतृत्व कोई जागरूक एवं कुशल नेता कर रहा है. पारदर्शिता और जवाबदेही यहां केवल सैद्धांतिक बात नहीं, बल्कि पंचायत के कार्य व्यवहार में दिखाई देती है. इसका श्रेय सरपंच तारा देवी बाघेला को जाता है. तारा देवी का यह दूसरा कार्यकाल है. वर्ष 2000 में सामरदा पंचायत का सरपंच पद महिलाओं के लिए आरक्षित होने के बाद उन्होंने पहली बार जीत हासिल की थी. अनुसूचित जाति की महिला होने के बावजूद तारा देवी का सरपंच बनना बड़ी बात है, क्योंकि यहां उच्च जाति के लोगों की अच्छी-खासी आबादी है.

73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायत का यह दूसरा पंचवर्षीय कार्यकाल है, जिसमें तारा देवी को सरपंच बनने का अवसर मिला. सामाजिक एवं राजनीतिक स्तर पर महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं में नेतृत्व करने को लेकर वातावरण और सोच में कोई खास बदलाव नहीं आया था. तारा देवी के सामने कुशल नेतृत्व देने की चुनौती थी. वह बताती हैं, पहले मुझे पंचायत के कामकाज के बारे में अधिक जानकारी नहीं थी, बैठकों-आयोजनों में बोलने में झिझक होती थी. प्रत्येक काम किसी से पूछकर थी, लेकिन पंचायत के प्रत्येक समुदाय से अच्छा व्यवहार रखने का नतीजा है कि लोगों ने मुझे दूसरी बार सरपंच बनने का मौक़ा दिया. तारा देवी ने शादी से पूर्व 8वीं और शादी के बाद 10वीं तक की पढ़ाई पूरी की. 2005 में दोबारा सरपंच के चुनाव हुए तो तारा देवी ने चुनाव नहीं लड़ा. वह एक स्वैच्छिक संस्था से जुड़ गईं और उसके माध्यम से महिला जनप्रतिनिधियों की नेतृत्व क्षमता विकास का कार्य करने वाले अंतरराष्ट्रीय संस्थान द हंगर प्रोजेक्ट दिल्ली द्वारा आयोजित प्रशिक्षणों में प्रशिक्षक के तौर पर काम करने लगीं. द हंगर प्रोजेक्ट द्वारा महिला जनप्रतिनिधियों में नेतृत्व क्षमता विकास हेतु आगाज नामक एक वर्षीय कोर्स प्रारंभ किया गया था. फरवरी 2010 में तारा देवी ने दोबारा चुनाव लड़ा और एक बार फिर सरपंच बन गईं. वह बताती हैं, इस बार चुनाव में आठ उम्मीदवार खड़े थे. पंचायत के लोगों ने बैठक की और चार उम्मीदवारों ने नाम वापस ले लिए. इसके बाद मेरे सामने 3 उम्मीदवार बचे, दो पुरुष एवं एक महिला. पंचायत के अधिकांश लोग मेरे साथ थे. इसका कारण यह था कि मेरा व्यवहार सभी के साथ समान है. लोगों को विश्वास था कि मैं निष्पक्ष रूप से काम करती हूं. तारा देवी कहती हैं, मेरी पंचायत में 90 प्रतिशत प्रसव संस्थागत होते हैं और बच्चों का टीकाकरण 95 प्रतिशत है. जब मैंने कार्यभार संभाला, तब पंचायत के पांच गांवों में मात्र एक एएनएम थी, अब यह संख्या तीन हो गई है. पंचायत मुख्यालय के विद्यालय में मात्र दो अध्यापक थे, आज पांच अध्यापक हैं. इनमें दो गणित एवं अंग्रेजी विषय के विशेषज्ञ हैं. माधो डिग्गी गांव में एक अध्यापक समय पर और नियमित रूप से नहीं आता था. लोगों ने मुझसे शिकायत की. मैंने लगातार तीन दिनों तक स्कूल का दौरा किया और हाजिरी रजिस्टर में उस अध्यापक की अनुपस्थिति दर्ज की. पंचायत की आंगनवाड़ियों-स्कूलों में मिड डे मील एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदि की निगरानी के लिए हमने सहभागी व्यवस्था बनाई. पंचायत स्तर के सभी कर्मचारियों की उपस्थिति स्वयं प्रमाणित करती हूं. 2010-11 में मनरेगा के तहत रोज़गार की मांग करने वाले सभी लोगों को 100 दिनों का रोज़गार दिया गया. अपना खेत-अपना काम योजना के तहत खेतों की सिंचाई के लिए 29 खाले पक्के कराए गए, 16 खालों की डाट कवरिंग का काम भी चल रहा है. इसके अलावा 63 मुख्यमंत्री आवास एवं 21 इंदिरा आवास बनवाए गए. पेयजल संकट से निजात पाने के लिए जल संग्रहण पर कार्य चल रहा है. वास्तव में अगर किसी पंचायत में स्वशासन और मानव विकास से जुड़े कार्य देखने हैं तो सामरदा पंचायत भी एक मॉडल के रूप में देखी जा सकती है. सरकार को ऐसी पंचायतों की पहचान करके इन्हें अतिरिक्त मानव, तकनीकी एवं वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए, ताकि लोग इन्हें देखकर सीख ले सकें. (चरखा)

तारा देवी के सामने कुशल नेतृत्व देने की चुनौती थी. वह बताती हैं, पहले मुझे पंचायत के कामकाज के बारे में अधिक जानकारी नहीं थी, बैठकों-आयोजनों में बोलने में झिझक होती थी. प्रत्येक काम किसी से पूछकर थी, लेकिन पंचायत के प्रत्येक समुदाय से अच्छा व्यवहार रखने का नतीजा है कि लोगों ने मुझे दूसरी बार सरपंच बनने का मौक़ा दिया.

दिलीप बीदावत
feedback@chauthiduniya.com

गूगल पर पढ़ी जा सकने वाली मुफ्त किताबों की वजह से विवाद भी हुआ, लेकिन गूगल का कहना है कि इससे ज़्यादा लोग किताबें पढ़ सकेंगे.

अनंत विजय

आत्मकथा के बहाने इतिहास

इंद्र कुमार गुजराल से मेरी पहली मुलाकात तब हुई थी, जब संसद के बालयोगी सभागार में संतोष भारतीय ने विश्वनाथ प्रताप सिंह की कविता पाठ का आयोजन किया था. वह एक तरह की अनूठी योजना थी, जिसमें चार पूर्व प्रधानमंत्रियों ने अपने साथी पूर्व प्रधानमंत्री के आयोजन के लिए एक साथ लोगों को आमंत्रित किया था. उसी दौरान गुजराल साहब से एक बार मुलाकात हुई थी. उस वक़्त उनकी बातों से लगा था कि देश को ऐसे राजनेताओं की ज़रूरत है, जो न केवल पढ़ते-लिखते हों, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपने विजन और विचारों से पूरे विश्व को प्रभावित कर सकते हों. गुजराल साहब से दूसरी मुलाकात भी संयोगवश संतोष जी की किताब-दलित अल्पसंख्यक सशक्तिकरण के विमोचन के अवसर पर हुई. तब तक गुजराल साहब पर उम्र का असर दिखने लगा था, लेकिन दो मुलाकातों के बाद हमेशा यह इच्छा रहती थी कि उनके विचारों को सुना जाए. इसलिए जब एक दिन उनकी आत्मकथा डाक से मिली तो पढ़ना शुरू किया, लेकिन नौकरी की अपनी व्यस्तता की वजह से लंबे समय तक पढ़ नहीं पाया. अचानक एक दिन उसे पढ़ने के लिए उठाया तो लगातार पढ़ता ही चला गया. अपनी आत्मकथा में गुजराल साहब ने पाकिस्तान से भारत आने के बाद से अपनी जिंदगी की कहानी कही है, बल्कि यह कहना ज़्यादा सही होगा कि यह गुजराल की राजनीतिक आत्मकथा है. अपनी इस आत्मकथा में गुजराल ने इंदिरा गांधी के जमाने से लेकर अपने प्रधानमंत्री बनने तक के राजनीति घटनाक्रमों को समयबद्ध तरीक़े से पेश किया है. गुजराल की इस आत्मकथा में राजनीतिक हलके का भ्रष्टाचार और लेन-देन भी उजागर हुआ है.

यह वाकया उस वक़्त का है, जब इंद्र कुमार गुजराल बिहार से राज्यसभा का चुनाव लड़ रहे थे. उस वक़्त राजनीति में लालू यादव का सितारा बुलंद था. बिहार के अलावा देश की राजनीति में भी लालू की तूती बोलती थी. बिहार का यह राजनेता अपने आपको किंग मेकर कहा करता था. उसी माहौल में लालू यादव ने एक दिन इंद्र कुमार गुजराल को दिल्ली के बिहार भवन में बुलाया और बातों-बातों में यह इशारा किया कि राज्यसभा के चुनाव में पैसे ख़र्च कर वोट ख़रीदे जा रहे हैं. झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों के हवाले से बातें करते हुए लालू ने संकेत किया कि गुजराल को राज्यसभा का चुनाव जीतने के लिए पैसों का इंतज़ाम करना होगा. लालू के सांकेतिक प्रस्ताव को गुजराल ने विनम्रतापूर्वक टाल दिया. अपनी बात न मानने से लालू खासे ख़फ़ा हो गए और उन्होंने लगभग चिल्लाते हुए गुजराल को अपने कमरे से बाहर निकाल दिया. इस वाकए के बाद गुजराल इतने आहत हो गए थे कि वह तुरंत वी पी सिंह के पास पहुंचे और उनसे अपनी शिकायत दर्ज कराने के बाद इस अपमान को सार्वजनिक करने की इजाज़त मांगी, लेकिन वी पी सिंह की सलाह पर गुजराल ने लालू से अपनी बातचीत के ब्यौरे को सार्वजनिक नहीं किया. बाद में गुजराल का वी पी सिंह से भी मोहभंग होता है. जनता दल की एक कमिटी में जगह न मिलने से गुजराल काफी नाराज़ हो जाते हैं और उसके लिए विश्वनाथ प्रताप सिंह को ज़िम्मेदार मानते हैं. गुजराल कहते हैं कि मैंने वी पी सिंह में बहुत ज़्यादा विश्वास करना शुरू कर दिया था और यह भूल गया था कि विश्वनाथ प्रताप सिंह कांग्रेस पार्टी की राजनीति में दीक्षित हुए हैं, जो यह सिखाती है कि पलक झपकते ही किसी को धोखा दिया जाना ग़लत नहीं है. गुजराल ने यह माना कि कालांतर में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इस बात को साबित भी किया कि वह किसी के दोस्त नहीं हो सकते. इन दो वाकयों के अलावा नब्बे के दशक में देश में चल रही राजनीतिक उथलपुथल पर भी उस वक़्त राजनीति के लगभग केंद्र में रहे इंद्र कुमार गुजराल ने अपनी आत्मकथा-मैटर्स ऑफ डिस्क्रीशन एन ऑटोबायोग्राफी में विस्तार से लिखा है. इंद्र कुमार गुजराल भारत के उन चंद चुने हुए राजनेताओं में से हैं, जिनकी गिनती संवेदनशील और विचारवान नेताओं में की जाती है. इंद्र कुमार गुजराल भारत विभाजन के बाद दिल्ली आ गए और 1958 में नई दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी के उपाध्यक्ष मनोनीत किए गए. उसके बाद वह तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी के क़रीब आए और उनका विश्वास हासिल कर लिया. इंदिरा गांधी की कृपा से 1964 में राज्यसभा पहुंच गए. वहीं से उनकी सक्रिय राजनीति की शुरुआत मानी जा सकती है. एक बेहद दिलचस्प प्रसंग उस वक़्त का है, जब लाल बहादुर शास्त्री की मौत के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनीं तो उन्होंने गुजराल को उपमंत्री बनने का प्रस्ताव दिया था, जिसे गुजराल ने अपनी तौहीन मानते हुए ठुकरा दिया था. इसका खामियाजा उन्हें तब भुगतना पड़ा, जब इंदिरा गांधी ने उन्हें मंत्री बनाने से इंकार कर दिया और फिर खासी मशक्कत के बाद संसदीय कार्य राज्यमंत्री बनाया था. यह उस वक़्त के हालात थे, जब गुजराल को दिनेश सिंह, यशपाल कपूर और उमाशंकर दीक्षित के साथ इंदिरा गांधी की किचन कैबिनेट का हिस्सा माना जाता था. गुजराल बताते हैं कि एक बार यशपाल कपूर ने उन्हें चेताते हुए कहा था, तुम इंदिरा के साथ ज़्यादा दिनों तक चल नहीं पाओगे, क्योंकि तुम संवेदनशील हो. हम उनके साथ इस वजह से काम कर पा रहे हैं, क्योंकि हम उनके कुत्तों की तरह हैं. जब वह नाराज़ होती हैं या चिल्लाती हैं तो हम वफादार कुत्ते की तरह दुम हिलाते हैं, लेकिन तुम बुरा मान जाते हो.

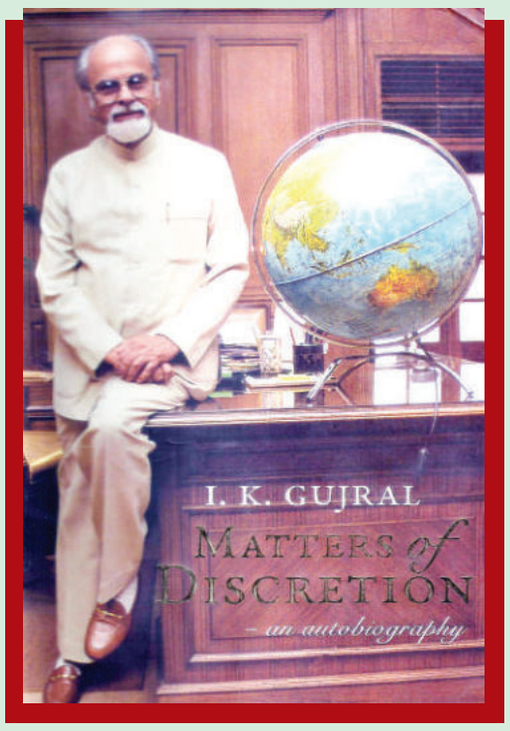

गुजराल की ये बातें इस वक़्त थोड़ा आश्चर्यचकित करने वाली हैं, क्योंकि तब उन्हें भी इंदिरा गांधी का यस मैन माना जाता था. गुजराल ने इंदिरा गांधी के बारे में लिखा है कि वह अपनी किसी बात के ठुकराए जाने को दिल से लगाकर रख लेती थीं और जब भी मौक़ा मिलता था, उसका बदला लेती थीं. जब देश में इमरजेंसी लगी तो गुजराल को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से हटाकर रूस में राजदूत बना दिया गया. गुजराल इस बात से बेहद ख़फ़ा थे और यह मानते थे कि उनका यह तबादला राजनीतिक वनवास है, लेकिन उस वक़्त मास्को में उनकी यह पोस्टिंग बाद में उनके विदेश मंत्री बनने की ज़मीन तैयार कर गई. इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद जब मोरार जी देसाई और चरण सिंह प्रधानमंत्री बने, तब भी गुजराल रूस में भारत के राजदूत बने रहे. अपने मास्को प्रवास के दौरान गुजराल ने भारत की वामपंथी पार्टियों और रूस की कम्युनिस्ट पार्टी के संबंधों पर टिप्पणियां की हैं. उस वक़्त भारत की कम्युनिस्ट पार्टी हर नीतिगत फ़ैसले के लिए रूस का मुंह ताकती थी और वहां से जैसा सिग्नल मिलता था, उसी के हिसाब से काम करती थी. जाने-अनजाने गुजराल ने देश की कम्युनिस्ट पार्टी की रूस परस्ती को बेनकाब कर दिया. अस्सी के दशक में गुजराल फिर देश लौटे और बाद में वी पी सिंह के साथ हो लिए. अपनी आत्मकथा में गुजराल ने वी पी सिंह की सरकार के गठन और उसके पतन के बाद का विस्तार से विवरण देकर भारतीय राजनीति के मौकापरस्त चेहरे से पर्दा हटा दिया है. गुजराल ने अपनी आत्मकथा में नरसिंहराव के बाद के दौर का भी दस्तावेजीकरण किया है. अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर जाने के बाद किस तरह लालू यादव ने देवगौड़ा को प्रधानमंत्री बनवा दिया और बाद में फिर किस तरह लालू और देवगौड़ा एक-दूसरे के सियासी दुश्मन बन गए. वजह बनी चारा घोटाले में लालू की फंसती गर्दन. गुजराल की आत्मकथा को पढ़ते हुए नब्बे के दशक की मौकापरस्त राजनीति का स्याह चेहरा सामने आ जाता है. देवगौड़ा की सरकार गिर जाने के बाद किस तरह शरद पवार ने कांग्रेस तोड़कर सरकार बनाने की असफल कोशिश की, उसकी ओर भी गुजराल ने इशारा किया है. कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई और सीताराम केसरी की प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश की कहानी भी इस आत्मकथा के माध्यम से सामने आती है. बहुत ज़्यादा ब्यौरे से गुजराल की यह आत्मकथा कई जगहों पर बोझिल हो जाती है, लेकिन देश की राजनीति में रुचि रखने वालों के लिए यह एक बेहतर किताब है और पठनीय भी.

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)

anant.ibn@gmail.com

इंटरनेट पर किताबों की दुनिया

फ़िरदौस ख़ान

किताबें हमें अंधेरे से रोशनी की तरफ़ ले जाती हैं. किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, क्योंकि अच्छे दोस्त न होने पर किताबें ही हमारी सबसे अच्छा साथी साबित होती हैं. किताबें कितना सुकून देती हैं, यह कोई किसी पुस्तक प्रेमी से पूछे. यह कहना क़तई ग़लत न होगा कि किताबें उस पारसमणि की तरह होती हैं, जिसकी छुअन से अज्ञानी भी ज्ञानी बन जाता है. बाल गंगाधर ने कहा था, अच्छी किताबों के साथ मैं नर्क में रहने के प्रस्ताव का भी स्वागत करूंगा. मानव की ज्ञान पिपासा का बेहतरीन साधन किताबें ही हैं. अब अंतरजाल यानी इंटरनेट के ज़रिए ऑनलाइन किताबें पढ़ी जा सकती हैं. ऐसी अनेक वेबसाइट्स हैं, जहां पर यह सुविधा दी गई है. ई-किताब यानी इलेक्ट्रॉनिक किताब, जिसका मतलब है डिजिटल रूप में किताब. ई-किताबें काग़ज़ की बजाय डिजिटल संचिका के रूप में होती हैं, जिन्हें कंप्यूटर, मोबाइल और इसी तरह के अन्य डिजिटल यंत्रों पर पढ़ा जा सकता है. इन्हें इंटरनेट पर प्रकाशित भी किया जा सकता है. साथ ही इसका प्रचार-प्रसार भी आसानी से किया जा सकता है. ये किताबें कई फाइल फॉर्मेट में होती हैं, लेकिन पीडीएफ यानी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट सर्वाधिक प्रचलित फॉर्मेट है.

ग़ौरतलब है कि गूगल ने 6 दिसंबर, 2010 से इलेक्ट्रॉनिक बुक स्टोर की दुनिया में क़दम रखते हुए अमेजन को टक्कर दी थी. 2004 में गूगल बुक्स प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद से गूगल ने सौ देशों से चार सौ भाषाओं में क़रीब डेढ़ करोड़ किताबें डिजिलाइस की हैं. हालांकि लेखकों और प्रकाशकों ने गूगल के किताबें डिजिलाइज करने पर ऐतराज़ जताया था. जिन किताबों का कॉपीराइट है या फिर जिनके लेखकों का कोई पता नहीं है, ऐसी किताबें ई-बुक स्टोर पर नहीं बेची जाएंगी. गूगल पर पढ़ी जा सकने वाली मुफ्त किताबों की वजह से विवाद भी हुआ, लेकिन गूगल का कहना है कि इससे ज़्यादा लोग किताबें पढ़ सकेंगे. हमें विश्वास है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा ई-बुक पुस्तकालय होगा. मुफ्त पढ़ी जा सकने वाली किताबों को मिलाकर इनकी कुल संख्या तीस लाख से ज़्यादा है. मैकमिलन, रैन्डम हाउस, साइमन एंड शूस्टर जैसे मशहूर प्रकाशकों की हज़ारों डिजिटल किताबें ई-बुक स्टोर में बेची जाएंगी. जहां तक क़ीमतों का सवाल है, ई-बुक्स स्टोर की किताबें बाज़ार के हिसाब से होंगी, जबकि कई फ्री किताबें पहले ही गूगल पर मौजूद हैं. एक शोध के मुताबिक़, अकेले अमेरिका में ई-बुक डिवाइस का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या 2015 तक 2 करोड़ 94 लाख तक पहुंच जाएगी. फॉरेस्टर सर्वे के मुताबिक़, ई-बुक पढ़ने वाले लोगों में 35 फ़ीसदी लोग लैपटॉप पर किताब पढ़ते हैं, 32 फ़ीसदी अमेजन के किंडल पर और 15 फ़ीसदी लोग एप्पल के आई फोन पर पढ़ते हैं. कई ऐसी वेबसाइट्स हैं, जहां जाकर आप अपनी मनपसंद किताब पढ़ने का लुत्फ़ उठा सकते हैं.

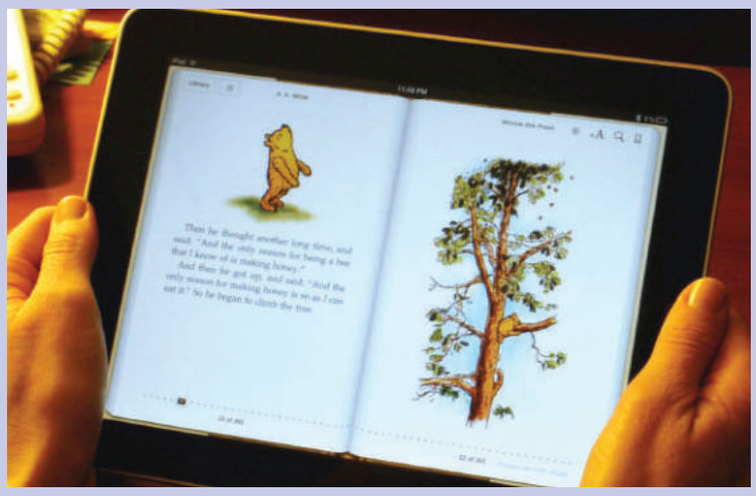

www.gutenberg.org

यह वेबसाइट किताबों का ख़ज़ाना है. यहां दुनिया भर की क़रीब 60 भाषाओं में 38 हज़ार किताबें मौजूद हैं, जिन्हें ऑनलाइन पढ़ा जा सकता है. यहां इन्हें डाउनलोड करने की भी सुविधा है. यहां कॉपीराइट फ्री किताबें रहती हैं. वेबसाइट इन किताबों का ई संस्करण तैयार कराती है. गुटनबर्ग का लक्ष्य अगले साल तक पुस्तक प्रेमियों को ऑनलाइन एक लाख किताबें मुहैया कराना है. हर रोज़ दो लाख यूजर इसका इस्तेमाल करते हैं. गुटनबर्ग एक ऐसी योजना पर काम कर रहा है, जिसके तहत लोग अपनी मर्ज़ी से वेबसाइट को किताबें दान करते हैं. यहां किताब तलाशना बेहद आसान है.

books.google.co.in

यहां भी किताबें ही किताबें हैं. यहां पर किसी भी लेखक का नाम या किताब का नाम सर्च करके अपनी मनपसंद किताब तक आसानी से पहुंचा जा सकता है. यहां भी गीत, ग़ज़ल, कहानी, उपन्यास सहित विभिन्न विषयों पर आधारित किताबें मौजूद हैं. किसी की आत्मकथा पढ़नी हो, किसी की जीवनी पढ़नी हो या कोई और रचना, सब कुछ यहां एक क्लिक की दूरी पर उपलब्ध है.

www.bartleby.com

यह वेबसाइट भी बहुत पसंद की जाती है. इस वेबसाइट पर इनसाइक्लोपीडिया, रिफ्रेंस बुक, शब्दकोष भी हैं. साहित्य और पत्रकारिता के छात्र इसे ख़ूब पसंद करते हैं. कुल मिलाकर यह वेबसाइट छात्रों, विशेषकर शोध के छात्रों के लिए बेहद उपयोगी है.

onlinebooks.library.upenn.edu

इस वेबसाइट पर भी सैकड़ों किताबें मौजूद हैं. यहां आप अपनी मनपसंद किताबें पढ़ सकते हैं. यहां भी कॉपीराइट फ्री किताबें उपलब्ध हैं. इसके प्रशंसकों की तादाद भी दिनोंदिन बढ़ रही है.

www.free-ebooks.net

यहां नए लेखकों की रचनाएं रहती हैं. यहां आपको विभिन्न विषयों पर रोचक किताबें मिल जाएंगी. यहां विभिन्न विषयों की उपयोगी किताबें हैं. यहां पर अलग-अलग फॉर्मेट में किताबें उपलब्ध हैं. आप अपनी सुविधा के हिसाब से कोई भी फॉर्मेट चुन सकते हैं.

www.easylib.com

यहां भी सैकड़ों किताबें मौजूद हैं. आप किसी भी विषय से संबंधित किताबें यहां देख सकते हैं.

www.amazon.co.uk

यहां भी किताबों का ख़ज़ाना मौजूद है. इस वेबसाइट पर ऑनलाइन किताबें ख़रीदने की सुविधा भी दी गई है.

अलबत्ता, आप मनपसंद किताबों को डाउनलोड कर अपनी एक डिजिटल लाइब्रेरी भी बना सकते हैं, ताकि जब चाहें, किताबों को आसानी से पढ़ सकें. ये किताबें दोस्तों और परिचितों को बतौर उपहार भी भेजी जा सकती हैं.

firdaus@chauthiduniya.com

किताब मिली

पुस्तक का नाम
बैठक जारी है...

लेखक
अंतर जगदीश

प्रकाशक
डायमंड बुक्स

मूल्य
100 रुपये

यह किताब व्यंग्य कथाओं का संग्रह है. नाट्य विधा में लिखी गई ये कथाएं भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करती हैं.

लेखक और प्रकाशक इस कॉलम के लिए अपनी किताबें हमें भेज सकते हैं.

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301
ई मेल : feedback@chauthiduniya.com

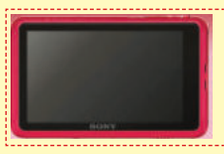

इस स्लिम कैमरे में 3.3 इंच की ओ लिड स्क्रीन दी गई है. इस स्लिम कैमरे की रेशियो 16:9 है.

रेसिंग बाइक केटीएम ड्यूक 200

कारों में रोज़ आते नए-नए मॉडल्स के बावजूद आज भी मोटरसाइकिल का क्रेज बरक़रार है. मोटरसाइकिल के प्रति क्रेज ख़ासकर युवाओं में देखा जाता है. स्पीड और स्टाइल के फैन युवा ही होते हैं. मोटरसाइकिल के चाहने वालों के लिए एक बड़ी ख़बर है. बजाज ऑटो ने स्पोर्ट्स बाइक ड्यूक 200 को बाइक लवर्स और रेस करने के शौक़ीनों के लिए लांच किया है. अपने स्कूटरों के लिए मशहूर देश की दूसरी सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी बजाज ऑटो ने ऑटोमोबाइल बाज़ार में नया धमाका करते हुए ड्यूक 200 बाइक पेशकश की है. बजाज ने यह बाइक अपनी ऑस्ट्रियन सहयोगी केटीएम के पोर्टफोलियो के सहयोग से पेश की है. इसकी संभावित क़ीमत कंपनी ने लगभग एक लाख 18 हज़ार रुपये तय की है. ड्यूक 200 का विकास इन दोनों कंपनियों ने संयुक्त रूप से किया है. इस गठजोड़ के तहत भारत में पेश की गई यह पहली बाइक है. ड्यूक का 125सीसी संस्करण पहले यूरोप में उतारा गया था. केटीएम पावर स्पोर्ट्स एजी में बजाज ऑटो की 40 फ़ीसदी हिस्सेदारी है. केटीएम यूरोप की सबसे बड़ी

स्पोर्ट्स बाइक कंपनी है. फ़िलहाल यह बजाज ऑटो के मौजूदा 34 प्रो-बाइकिंग शोरूम के ज़रिये हाई-एंड यूरोपीय बाइकों की बिक्री करती है. इसकी शुरुआत केटीएम लाइवरी के साथ होगी. 2012 के अंत तक इसमें छह नए मॉडल शुरू होंगे.

सोनी साइबर शॉट डीएससी-टीएक्स 55

अपने जीवन के ख़ूबसूरत पलों को संजोने के लिए कैमरा एक बेहतरीन गैजेट है. कैमरे में दिन प्रतिदिन नए-नए आविष्कार हो रहे हैं. आजकल अल्ट्रा पोर्टेबल कैमरों का क्रेज है, ज़्यादा बड़े साइज के कैमरों की मांग पोर्टेबल कैमरे के मुक़ाबले कम है. सोनी ने यूजरों की मांग को ध्यान में रखते हुए नया पोर्टेबल साइबर शॉट डीएससी-टीएक्स 55 डिजिटल कैमरा बाज़ार में लांच किया है. कंपनी के अनुसार, यह दुनिया का सबसे स्लिम कैमरा है. सोनी साइबर शॉट डीएससी-टीएक्स 55 में 3डी इमेज कैपचरिंग की सुविधा भी दी गई है, 109 ग्राम भार के साथ कैमरे को आसानी से उठाया जा सकता है. सोनी ने नए साइबर शॉट कैमरे को ब्लैक, सिल्वर और गोल्ड कलर ऑप्शन के साथ 20,000 रुपये में लांच किया है. इसमें असरदार टच इंटरफेस है जो आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है.

कंपनी के अनुसार, यह दुनिया का सबसे स्लिम कैमरा है. सोनी साइबर शॉट डीएससी-टीएक्स 55 में 3डी इमेज कैपचरिंग की सुविधा भी दी गई है, 109 ग्राम भार के साथ कैमरे को आसानी से उठाया जा सकता है. सोनी ने नए साइबर शॉट कैमरे को ब्लैक, सिल्वर और गोल्ड कलर ऑप्शन के साथ 20,000 रुपये में लांच किया है.

3डी इमेज कैपचरिंग के साथ एवीसीएचडी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है. इस स्लिम कैमरे में 3.3 इंच की ओ लिड स्क्रीन दी गई है. इस स्लिम कैमरे की रेशियो 16:9 है. इसमें डाटा ट्रांसफर के लिए किसी भी अटैचमेंट को जोड़ने के लिए एचडीएमआई यूएसबी पोर्ट दिया गया है. यह कैमरा फुल टच स्क्रीन बेस्ड है. 109 ग्राम वज़न वाले इस कैमरे की क़ीमत 20,000 रुपये है.

अल्ट्रासोनी का नया हेडफोन

जर्मन बेस कंपनी अल्ट्रासोनी ने सिगनेचर नाम से नए हेडफोन बाज़ार में लांच किए हैं. अपने हाई क्वालिटी हेडफोन की रेंज में इस ख़ास प्रोडक्ट के ज़रिये अल्ट्रासोनी की यह नई डिवाइस अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब रहेगी, क्योंकि तकनीकी रूप से हेडफोन में प्रोफेशनल कंफीग्रेशन का प्रयोग किया गया है. कंपनी के अनुसार हेडफोन में टाइटेनियम प्लेटेड ट्रांसडयूसर का प्रयोग किया गया है, जो हेडफोन की साउंड क्वालिटी को और बेहतर बनाता है. हेडफोन 8 हर्ट्ज से लेकर 42 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को सपोर्ट करते हैं. डिवाइस में एस लॉजिक प्लस तकनीक का प्रयोग किया गया है, जो साउंड क्वालिटी को और बेहतर बनाता है. 300 ग्राम के अल्ट्रासोनी हेडफोन में 3 सेमी. की कॉर्ड के साथ 6.3 एमएम न्यूट्रिक प्लग दिया गया है. क़ीमत के हिसाब से हेडफोन काफ़ी महंगे हैं, मगर इनकी साउंड क्वालिटी का मुक़ाबला किसी साधारण हेडफोन से नहीं किया जा सकता. अल्ट्रासोनी के नए सिगनेचर हेडफोन बाज़ार में 64,000 रुपये की अनुमानित क़ीमत में उपलब्ध हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

इस टैबलेट में कई फीचर दिए गए हैं जो यूजरों की लगभग सभी ज़रूरतों को पूरा करेंगे. हालांकि अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में गैलेक्सी 680 पहले ही लांच किया जा चुका था.

सैमसंग गैलेक्सी 680 टैबलेट

हर दिन अलग साइज़, डिज़ाइन के साथ नए टैब भारतीय बाज़ार में दस्तक दे रहे हैं. मगर अभी भी एंडॉएड टैब की क़ीमत काफ़ी ज़्यादा है. कुछ टैबलेट को छोड़कर लगभग सभी टैबलेट की क़ीमत उनके फीचरों को देखते हुए काफ़ी अधिक रहती है. कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र की दिग्गज कंपनी सैमसंग ने भारत में एक नया टैब लांच किया है, जिसमें कई फीचर दिए गए हैं जो यूजरों की लगभग सभी ज़रूरतों को पूरा करेंगे. हालांकि अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में गैलेक्सी 680 पहले ही लांच किया जा चुका था. लेकिन भारत में यह पहली बार उतारा गया है. तकनीकी रूप से टैब में 1.4 गीगाहर्ट का ड्यूल कोर प्रोसेसर दिया गया है. गूगल एंड्रॉएड 3.2 ओएस से लैस गैलेक्सी 680 में 7.7 इंच की टच स्क्रीन दी गई है, जो 1280/800 रेज्योलूशन सपोर्ट करती है. यूजर टैब में वीडियो कांफ्रेंसिंग और फोटो कैपचरिंग भी कर सकता है. इसके लिए गैलेक्सी 680 में 3 मेगा पिक्सल का रियर कैमरा और 2 मेगा पिक्सल का फ्रंट कैमरा मौजूद है. वहीं डाटा सेव करने के लिए टैब में 16 जीबी की शानदार इंटरनल मेमोरी दी गई है, जिसे 32 जीबी तक एक्सपेंड भी कर सकते हैं. अन्य फीचरों में वाईफाई, यूएसबी पोर्ट जैसे कई शानदार फीचर दिए गए हैं. सैमसंग ने भारत में गैलेक्सी टैब 680 को 35,000 रुपये में लांच किया है.

एलजी के नए स्मार्टफोन सोल और हब

एड्रीनो 200 जीपीयू और एड्रीनो 200 जीपीयू यूटीलिटी दिया गया है. इसमें भी बढ़िया पिक्चर क्वालिटी के लिए 5 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है.

जिंजरबेड ओएस से लैस एलजी ने दो नए स्मार्टफोन बाज़ार में पेश किए हैं. हाई इंड रेंज में एलजी के दोनों स्मार्टफोन काफ़ी दमदार हैं. एलजी सोल ई730 में 3.8 इंच की अल्ट्रा एमोल्ड स्क्रीन दी गई है, जो यूजर को बेहतर पिक्चर प्रोवाइड करती है. देखने में सोल का लुक काफ़ी शानदार है. 9.8 एमएम आकार के सोल में इनबिल्ड प्रोसेसर 1.4 गीगाहर्ट प्रोसेसर की स्पीड प्रोवाइड करता है. वहीं एलजी के दूसरे फोन हब ई 510 में 3.5 इंच की टच स्क्रीन और 800 मेगाहर्ट का एआरएम प्रोसेसर इनबिल्ड है. एलजी के दोनों स्मार्टफोन में एंड्रॉएड 2.3 जिंजरब्रेड आपरेटिंग सिस्टम दिया गया है. इसके अलावा एलजी सोल में कुछ और ख़ास फीचर्स हैं, जैसे 3.8 इंच अल्ट्रा एमोल्ड स्क्रीन और फोन का आकार 9.8 एमएम. 1.4 गीगा हर्ट फ्लेट स्क्रीन के साथ यह वाईफाई डीएलएनए, एचएसडीपीए, जीपीएस सपोर्ट करता है. इसमें बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी के लिए 5 मेगापिक्सल ऑटो फोकस कैमरा भी दिया गया है. दूसरे फोन एलजी ऑप्टिमस हब में भी कुछ ख़ास फीचर्स हैं, जैसे 3.5 इंच की टीएफटी टच स्क्रीन जिसका रेज्योलूशन है 480/320. इसमें पॉवरफुल एआरएम प्रोसेसर दिया गया है. एड्रीनो 200 जीपीयू और एड्रीनो 200 जीपीयू यूटीलिटी दिया गया है. इसमें भी बढ़िया पिक्चर क्वालिटी के लिए 5 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है. यह वाईफाई, जीपीआरएस, ऐज, 3जी, वाईफाई को सपोर्ट करता है.

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

कोच का इस्तीफ़ा

इंग्लैंड की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के कोच फेबियो कापेलो ने इस्तीफ़ा दे दिया है. कापेलो ने फुटबॉल एसोसिएशन (एफए) द्वारा जॉन टेरी को कप्तान पद से हटाए जाने के विरोध में इस्तीफ़ा दिया है. वेबसाइट ईएसपीएन डॉट कॉम के मुताबिक़, एफए ने कहा है कि संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से पूरे मामले पर प्रकाश डाला जाएगा. एफए ने फ़िलहाल कापेलो के इस्तीफ़े की पुष्टि की है. कापेलो ने यूरो 2012 से ठीक पहले टेरी को कप्तान पद से हटाने संबंधी एफए के फ़ैसले पर नाराज़गी जताई थी. उनकी नज़र में टेरी ही इंग्लिश टीम के कप्तान हैं. एफए ने नस्लीय टिप्पणी को लेकर टेरी को बीते सप्ताह इंग्लिश टीम के कप्तान पद से हटा दिया था. टेरी पर बीते वर्ष अक्टूबर में खेले गए इंग्लिश प्रीमियर लीग मुक़ाबले के दौरान क्वींस पार्क रेंजर्स टीम के डिफेंडर एंटन फर्डीनांड के ख़िलाफ़ नस्लीय टिप्पणी का आरोप है. इसे लेकर यूरो 12 के बाद सुनवाई होनी है. कापेलो ने कहा कि ऐसे में, जबकि टेरी के ख़िलाफ़ सुनवाई चल रही है, एफए द्वारा उन्हें कप्तान पद से हटाया जाना बिल्कुल युक्तिसंगत नहीं है, लेकिन एफए उनके इस विचार से इत्तेफाक़ नहीं रखता.

भारत की दावेदारी

अंडर-17 विश्वकप फुटबॉल-2017 की मेज़बानी की भारतीय दावेदारी को मज़बूती मिल सकती है, क्योंकि फीफा अध्यक्ष सेप ब्लाटर देश में विकास कार्यों का जायज़ा लेने के लिए ख़ुद भारत का दौरा करेंगे. अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के उपाध्यक्ष सुब्रत दत्ता ने कहा कि ब्लाटर आगामी नौ मार्च को भारत आएंगे. एएफसी चैलेंज कप (आठ से उन्नीस मार्च) के दौरान उनके नेपाल दौरे का कार्यक्रम है. वह एआईएफएफ की कार्यकारी समिति के सदस्यों से मिलेंगे. फीफा अध्यक्ष द्वारा बांग्लादेश दौरे की भी उम्मीद है. ब्लाटर शिष्टाचार यात्रा पर भारत आ रहे हैं, लेकिन वह 2017 के अंडर-17 विश्वकप के लिए बुनियादी ढांचे की भारत की तैयारी के बारे में जानने के इच्छुक हैं. भारत को अगर इस प्रतियोगिता की मेज़बानी मिलती है तो यह देश में होने वाली सबसे बड़ी फुटबॉल प्रतियोगिता होगी. दत्ता ने कहा कि ब्लाटर की यात्रा यह दर्शाती है कि फीफा भारत को कितनी अहमियत दे रहा है. देश में सही बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए इस वैश्विक संस्था का समर्थन हमारी उम्मीद से अधिक है.

Brasil 2014 FIFA WORLD CUP

युवराज का विकल्प

बीसीसीआई ने आख़िरकार सहारा समूह की मांग मानते हुए उसे युवराज सिंह के बदले किसी अन्य खिलाड़ी को पुणे वारियर्स टीम में शामिल करने की अनुमति दे दी है. बोर्ड अध्यक्ष एन श्रीनिवासन ने कहा कि नियमों के मुताबिक़ सहारा समूह युवराज के स्थान पर किसी अन्य खिलाड़ी को पुणे वारियर्स में शामिल कर सकता है. प्रायोजन साझीदार के बारे में सहारा कोई भी फ़ैसला करने के लिए स्वतंत्र है और बीसीसीआई को इससे कोई लेना-देना नहीं है.

विवाद मिलकर सुलझाएं

अदालत ने हॉकी इंडिया और इंडियन हॉकी फेडरेशन (आईएचएफ) से कहा है कि उनकी लड़ाई में खिलाड़ियों के हितों को नुक़सान नहीं होना चाहिए. अदालत ने कहा कि घरेलू सीरीज़ के भविष्य और खिलाड़ियों के हितों को देखते हुए दोनों संस्थाएं मिलकर विवाद सुलझाएं. कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति ए के सीकरी एवं न्यायमूर्ति राजीव सहाय की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि देश में कोई भी सीरीज़ होती है तो उसका फ़ायदा खिलाड़ियों को मिलता ही है, लेकिन यदि इसी प्रकार का विवाद होता रहा तो खिलाड़ियों का हित नहीं हो सकता. दोनों पक्ष मिलकर मामले का हल निकालें, यही खिलाड़ियों के हित में है. यदि सीरीज़ के कारण मैचों की तिथियों का तालमेल नहीं बैठता है तो वे इस मामले को इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के पास ले जा सकते हैं. खंडपीठ हॉकी टीम के पूर्व कोच जोएकिम कार्वेलो द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी. उन्होंने हॉकी इंडिया पर आरोप लगाया कि वह विश्व सीरीज़ हॉकी में भाग लेने की स्थिति में खिलाड़ियों को कड़ी कार्रवाई की धमकी दे रहा है.

गेंदबाजी की हालत

अब डेव्स टीम इंडिया के नए गेंदबाजी कोच होंगे. डेव्स दक्षिण अफ्रीका के एरिक सिमंस की जगह लेंगे, जिनका दो वर्ष का कार्यकाल आस्ट्रेलिया दौरे के साथ ही समाप्त हो रहा है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की हाल में चेन्नई में हुई बैठक में सिमंस के अनुबंध का नवीनीकरण न करने का फैसला किया गया. टीम इंडिया द्वारा विदेशी जमीन पर लगातार आठ टेस्ट गंवाने के बाद माना जा रहा था कि सिमंस का अनुबंध आगे नहीं बढ़ाया जाएगा. डेव्स ने 1997 से 2005 के बीच क्वींसलैंड के लिए 76 मैच खेले, लेकिन माइकल कैस्प्रोविच और एंडी बिशेल जैसे गेंदबाजों की मौजूदगी में वह ऑस्ट्रेलियाई टीम में जगह नहीं बना सके. घुटने की चोट के कारण उनका गेंदबाजी करियर जल्द ही समाप्त हो गया, जिसके बाद वह क्वींसलैंड के लिए कोचिंग करने लगे. डेव्स जून 2011 में साउथ आस्ट्रेलिया के गेंदबाजी कोच बने. वह बिग बैश लीग के 2011-12 संस्करण में एडिलेड स्टाइकर्स के भी गेंदबाजी कोच रहे. दक्षिण अफ्रीका के पूर्व आल राउंडर सिमंस वर्ष 2010 में टीम इंडिया के साथ गेंदबाजी सलाहकार के रूप में जुड़े थे. उन्हें आईपीएल के पांचवें संस्करण के लिए दिल्ली डेयरडेविल्स का कोच नियुक्त किया गया. सिमंस टीम इंडिया के पूर्व कोच गैरी कर्स्टन के साथ कोचिंग स्टाफ के रूप में भारतीय टीम से जुड़े थे. कर्स्टन ने टीम इंडिया के साथ अपने अनुबंध का नवीनीकरण नहीं किया था, लेकिन सिमंस टीम के साथ जुड़े रहे. देखते हैं कि इनके आने से टीम इंडिया की हालत कितनी बेहतर होती है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

स्पोर्ट्स ऑफ द वीक

स्नोबॉल फाइटिंग

इस बार का स्पोर्ट्स ऑफ द वीक है स्नोबॉल फाइटिंग. जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर होता है कि यह एक फाइटिंग गेम है. एक ऐसा फाइटिंग गेम, जिसमें न तो मुक्कों से लड़ाई होती है और न हथियारों से. स्नोबॉल फाइटिंग में बर्फ को हथियार बनाया जाता है. इसमें दो टीमें एक-दूसरे पर बर्फ के गोलों की बौछार करती हैं और फिर होता है स्नोबॉल में बर्फ और खेल का दोहरा मज़ा. वैसे आप लोगों ने बचपन में कई बार पिलो फाइट यानी तकियों की लड़ाई वाला खेल ज़रूर खेला होगा. स्नोबॉल फाइटिंग भी काफी हद तक पिलो फाइट से मिलता जुलता है. अंतर इतना है कि पिलो फाइट घर के अंदर यानी इंडोर गेम है, जबकि स्नोबॉल फाइटिंग घर के बाहर यानी उस जगह पर खेला जाता है, जहां पर्याप्त मात्रा में बर्फ की उपलब्धता हो. अरे भाई, बर्फ के गोले बनाने के लिए बर्फ की ज़रूरत तो पड़ेगी न! 10 फरवरी, 2006 को मिशीगन टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के लगभग 3749 छात्रों ने मिलकर यह खेल खेला था. इतनी बड़ी संख्या में स्नोबॉल फाइटिंग प्रतियोगिता में शामिल होने पर इसे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के तौर पर माना गया. इसके अलावा जापान में हर साल स्नोबॉल फाइटिंग प्रतियोगिता यूकिगासेन आयोजित की जाती है. जापानी में यूकिगासेन का अर्थ होता है हिम युद्ध. जर्मनी में बाकायदा इसकी वर्ल्ड चैंपियनशिप आयोजित की जाती है. वैसे अब यह खेल कई देशों में खेला जाने लगा है. मसलन पेससिलवेनिया, बेल्जियम, वाशिंगटन डीसी, नॉर्थ अमेरिका, वर्जीनिया और उन तमाम मुल्कों में, जिन्हें बर्फीली जलवायु वाला देश माना जाता है. कहा जाता है कि क़रीब बीस साल पहले जापान के माउंट शोवा-शिनज़ैन रिसॉर्ट ने ठंड के मौसम में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए यह खेल ईजाद किया था. यह खेल शतरंज, पेंटबॉल और बैकयार्ड ब्रावलिंग का मिश्रण है. इसे 44 बाई 12 गज के मैदान में खेला जाता है.

हॉकी के मैदान जैसी लाल और नीले रंग की लकीरों से मैदान को बांटा जाता है. मैच में तीन मिनट के तीन भाग होते हैं. जो टीम दो भाग जीत लेती है, वह विजेता होती है. हर भाग में जिस टीम के अधिक खिलाड़ी खड़े पाए जाते हैं, वह जीत जाती है. इसके अलावा बर्फ के गोलों से बचते हुए जो दूसरी टीम का झंडा छीन लेता है, उसकी टीम जीत जाती है. फ़िलहाल जापान में यूकिगासेन की दो हज़ार से ज़्यादा टीमें हैं. पिछले साल अमेरिका में भी इसकी कई प्रतियोगिताएं हुई थीं. ऐसा भी नहीं है कि इस खेल में हमेशा मज़ा ही आता है, कभी-कभी यह मजेदार खेल कई प्रतियोगियों पर भारी भी पड़ जाता है. उदाहरण के तौर पर 9 दिसंबर, 2009 की घटना को ले लीजिए. इस दिन लगभग 4000 छात्रों ने बॉसकाम हिल पर स्नोबॉल फाइटिंग प्रतियोगिता में भाग लिया, लेकिन इस दौरान कई प्रतियोगियों को काफी चोटें आईं. कई लोगों की नाक टूटी तो कई लोगों ने अपनी कुहनियां तुड़वाईं. यहां तक तो ठीक था, लेकिन मामला तब बिगड़ गया, जब भीड़ ने बेकाबू होकर लूटपाट शुरू कर दी और सार्वजनिक संपत्ति को नुक़सान पहुंचाया. जिस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए इसका आयोजन किया गया था, वह तो नहीं टूटा, कई लोग अपना अंग भंग ज़रूर करा बैठे.

राजेश एस कुमार
rajeshy@chauthiduniya.com

ETV पर देखिए दो टूक
देश का सबसे निर्णायक टीवी कार्यक्रम

शनिवार रात 8 : 30 बजे
रविवार शाम 6 : 00 बजे
ईटीवी के सभी हिन्दी चैनलों पर

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

चौथी दुनिया

दिल्ली, 27 फरवरी-04 मार्च 2012

आते ही श्री ने माफ़ी मांगते हुए कहा, देर से आने के लिए माफ़ी चाहती हूं. मुंबई के ट्रैफिक की वजह से हमें देर हो गई.

फिल्म प्रीव्यू

श्रीदेवी की वापसी

अस्सी के दशक की जानी मानी कलाकार श्रीदेवी जब चार दिन की चांदनी फिल्म के म्यूज़िक लांच पर पहुंचीं तो हर कोई उनके चमकते चेहरे को देखकर प्रसन्न हो उठा. चार दिन की चांदनी निर्देशित समीर कार्निक की रोमांटिक फिल्म है, जिसमें तुषार कपूर और कुलराज रंधावा लीड रोल में हैं. इस फिल्म का आकर्षण ओह मेरी चांदनी है. ऋषि कपूर और जितेंद्र भी इस म्यूज़िक लांच पर पहुंचे थे. बस इंतज़ार था तो श्री का जो काफ़ी देरी से बोनी कपूर के साथ पहुंचीं. आते ही श्री ने माफ़ी मांगते हुए कहा, देर से आने के लिए माफ़ी चाहती हूं. मुंबई के ट्रैफिक की वजह से हमें देर हो गई. तुषार की फिल्में मैंने देखी हैं. हर फिल्म में उन्होंने बेहतरीन अभिनय से सबका मन मोह लिया है और मेरी दुआ है कि यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाए. अपनी पुरानी फिल्म चांदनी को याद करते हुए उन्होंने कहा कि यशराज बैनर तले बहुत सी रोमांटिक फिल्में बनीं, जिनका मैं भी हिस्सा रह चुकी हूं. मुझे रोमांटिक फिल्में बहुत पसंद हैं. अस्सी एवं नब्बे के दशक को हम रोमांटिक गोल्डन एरा फिल्में बनाने का दशक भी कह सकते हैं. चलिए रोमांटिक माह है तो श्री ने हमें याद करके बताया कि मेरी और बोनी कपूर की रोमांटिक पहली डेट...कुछ सोच कर बोलीं... याद करके बताती हूं. बोनी बीच में ही बोल पड़े, हम साथ-साथ हैं इसलिए रोमांटिक डेट तो रोज़ ही हो सकती है. श्री इंग्लिश विंग्लिश के बारे में बोलीं, जी हां, इंग्लिश विंग्लिश की निर्देशक गौरी शिंदे आर बाल्की की बीवी हैं. यह एक स्त्री प्रधान फिल्म है. मेरा रोल प्रोफेसर का नहीं है. बस मैं इतना ही कह सकती हूं कि इस फिल्म से मेरी फिल्मी दुनिया में वापसी हो रही है. मिस्टर इंडिया कब शुरू होगी ये कुछ निश्चित नहीं किया गया है. बस इतना कह वह चल पड़ती हैं.

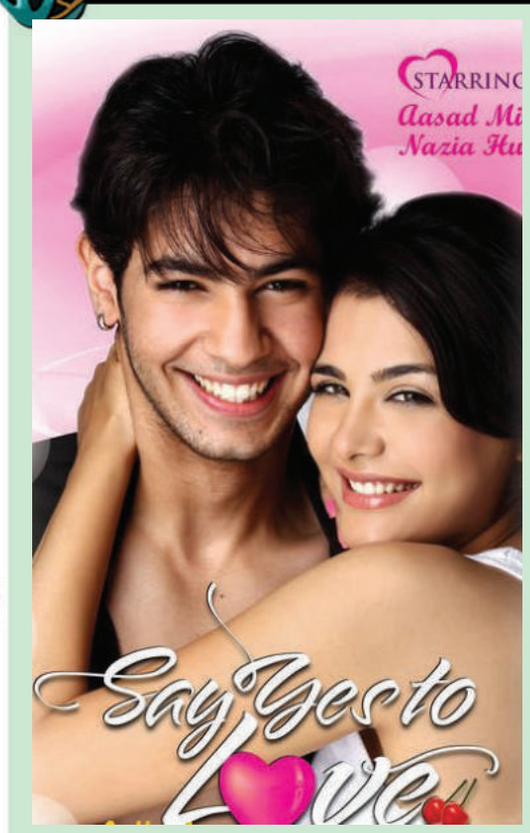

से यस टू लव

अपने बेटे या बेटी को सिल्वर स्क्रीन पर उतारने का प्रोड्यूसर्स का फंडा पुराना है. इसी लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है. दरअसल, असद मिर्ज़ा अपने पिता माहरूख़ मिर्ज़ा की फिल्म से यस टू लव से बॉलीवुड में अपना फिल्मी करियर शुरू करने जा रहे हैं. माहरूख़ मिर्ज़ा ने बॉलीवुड को अपने निर्देशन और बैनर मिर्ज़ा ब्रदर्स के तहत माशूक़ यारा दिलदारा और रामा ओ रामा जैसी फिल्में दी हैं. माहरूख़ मिर्ज़ा के निर्देशन में बनी फिल्म से यस टू लव की हीरोइन नाज़िया हुसैन हैं. वह संजय दत्त की भांजी और नरगिस के बड़े भाई अख्तर हुसैन की पोती हैं. संजय दत्त की भांजी होने के बावजूद उन्होंने फिल्मों में ब्रेक पाने के लिए कभी किसी के नाम का सहारा नहीं लिया. एक साल पहले उन्होंने से यस टू लव के लिए ऑडिशन दिया था. लंबे इंतज़ार के बाद उन्हें प्रोड्यूसर की तरफ़ से बुलावा आया. मुश्किल यहां भी आसान नहीं हुई, रोल पाने के लिए उन्हें दो अन्य लड़कियों से मुक़ाबला करना पड़ा. उन लोगों के साथ उन्होंने स्क्रीन टेस्ट दिया. वर्कशॉप में शामिल हुई और कुछ समय तक रिहर्सल में भी भाग लिया. अंत में मेहनत रंग लाई और उन्हें पहली फिल्म में ब्रेक मिला. नाज़िया आर्ट्स से बैचलर हैं और एक्टिंग में डिप्लोमा किया है, लेकिन हमेशा से अभिनेत्री ही बनना चाहती थीं. फिल्म से यस टू लव एक रोमांटिक म्यूज़िकल फिल्म है, जिसमें दो अलग-अलग ढंग से जीने वाले लोग एक-दूसरे से प्यार करने लगते हैं. इसमें उन्होंने अक्खड़ और निडर लड़की की भूमिका निभाई है. इस फिल्म में वह आज़ाद ख्याल वाली, ज़िद्दी और बोल्ड ऐंड स्मार्ट लड़की है. उसकी ज़िंदगी में पुरुषों की कोई अहमियत नहीं है. इस फिल्म की ज़्यादातर शूटिंग देश के अलग-अलग हिल स्टेशन में हुई है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

आमिर ख़ान का अलग अंदाज़

बात जब आमिर ख़ान की हो तो दिमाग़ में आता है कि अब ज़रूर कुछ नया होने वाला है. जी हां, आमिर ख़ान हैं ही ऐसी शख्सियत जो हमेशा कुछ न कुछ नया करने पर आमादा रहते हैं. उनका फिल्म प्रमोशन का तरीक़ा भी कुछ अलग होता है. कभी-कभार तो वह लोगों के बीच वेशभूषा बदल कर भी चले जाते हैं और दर्शकों के साथ अपनी ही फिल्म का मज़ा लेते हैं. आमिर ख़ान ने अपनी पहचान मिस्टर परफेक्शनिस्ट के रूप में बनाई है, क्योंकि वह जो भी काम करते हैं उसमें उनका अलग नज़रिया होता है. ख़ुद को भी वह वैसा ही बना लेते हैं, जैसी स्क्रिप्ट की डिमांड हो. बीते दिनों वह जैसलमेर की सैर पर गए और वहां के माहौल का ख़ूब मज़ा भी लिया. सुनने में आया है कि वहां ख़ुद ही कार भी ड्राइव की. उनसे पूछे जाने पर उनका जवाब था, यहां मैं सिर्फ़ घूमने आया हूं. लगता है, आमिर वहां ज़रूर लोकेशन देखने गए हैं. जो भी हो, पर हम इतना ज़रूर जानते हैं कि आमिर जहां जाते हैं, वहां उनका मक़सद भी उनके साथ जाता है. ग़ौरतलब है कि आमिर ख़ान पैलेस ऑन व्हील में सवार होकर उदयपुर से जैसलमेर पहुंचे, जहां उनका ख़ूब स्वागत भी हुआ.

अमृता राव की यादें

फरवरी रोमांस का महीना है. अमृता का कहना है कि आज मैं जो कुछ भी हूं अपने फैंस की वजह से ही हूं. दरअसल, हम लोग इतने बिजी रहते हैं कि समय ही नहीं मिल पाता है. सो मैंने इस बार अपने फैंस को शीप बार में मिलने की ठानी. मैं चाहती थी कि मुंबई नगरिया की भीड़-भाड़ से परे इन सब फैंस के साथ एक प्यार भरी शाम गुज़ारूं. वह अपने लिए पहली बार प्यार से व्याकुल किसी शख्स को याद करते हुए बोलीं, हां आज भी मैं उस दिन को याद कर शोक्ड हो जाती हूं. उस समय मैं केवल आठवीं कक्षा में थी. दरवाज़े की घंटी बजती है और मेरे पापा दरवाज़ा खोलते हैं. यह देखकर हम सब शोक्ड हो जाते हैं कि कोई बहुत ही सुंदर फूलों का गुलदस्ता मेरे लिए भेजता है. यह एक बेनाम गुलदस्ता होता है जिसे देखकर मेरे सारे रिश्तेदार जो घर पर मौजूद थे, मुझे शक की नज़रों से देखने लगते हैं. मैं बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करती हूं. हालांकि मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं था, किंतु मेरे रिश्तेदारों को मैं यह बात कैसे बताती. ख़ैर जैसे-तैसे बात टल गई, किंतु जब भी उस दिन को मैं याद करती हूं तो कुछ खट्टी-मीठी यादें ताज़ा हो जाती हैं. रोमांटिक फिल्मों के बारे में भी उन्होंने कहा, मुझे रोमांटिक फिल्में ही पसंद हैं. ड्रामा और मारधाड़ वाली फिल्में मुझे पसंद नहीं हैं. मुझे प्यार में एक पॉजिटिव फीलिंग मिलती है. निगेटिव चीज़ों से मुझे परहेज़ है. अमृता की प्यार की परिभाषा के बारे में मेरा ऐसा मानना है कि प्यार कनडिशनल नहीं होता है. यह तो जब होना है, जिससे होना है, हो जाता है. इस प्यार में न तो कोई उम्र की सीमा होती है और न किसी जात-पात की. बस जब होना है, हो जाता है. प्यार में हर औरत का ऐसा मानना है कि उन्हें शादी से पहले जो प्यार उनके पति से मिलता है वह शादी के बाद नदारद हो जाता है. यह सच है कि हर आदमी यह चाहता है कि वह औरत का पहला प्यार हो, किंतु हर औरत यह चाहती है कि कोई भी मर्द उसका आख़िरी प्यार हो.

जॉन अब्राहम बूढ़े हुए

मॉडल और अभिनेता जॉन अब्राहम आजकल काफ़ी सुर्ख़ियों में हैं. आप सोच रहे होंगे, ज़रूर किसी फिल्म के लिए. जी नहीं, यह ख़बर लड़कियों के दिल तोड़ने वाली है. जॉन अब्राहम अपनी गर्ल फ्रेंड प्रिया रुचल के साथ जल्द ही शादी कर सकते हैं. क्यों न हो एक-दूसरे से प्यार जो करते हैं. अरे प्यार तो वह बिपाशा बासु से भी करते थे. शायद दोनों की कैमिस्ट्री नहीं जमी या फिर कुछ और वजह रही होगी. इसलिए नौ साल के प्यार को ठुकरा कर अपनी नई गर्ल फ्रेंड के साथ शादी करने जा रहे हैं. बिपाशा बासु से जॉन इब्राहिम और प्रिय रुचल के रिश्ते के बारे में पूछे जाने पर बिपाशा का जवाब था- जॉन पुराने हो गए, मेरी सलाह उनको है कि वह जल्द शादी कर लें. इसका तो सिर्फ़ एक ही मतलब है कि जॉन अब ओल्ड मैन हो गए हैं. जॉन इब्राहिम का जब ब्रेकअप हुआ था, तब भी जॉन ने इस बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताया. अब इस रिश्ते के बारे में भी वह मीडिया से दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं.

ओ पी दत्ता को नमन

सदी की शुरुआत में एक और झटका. फिल्म निर्माता और लेखक ओ पी दत्ता अब इस दुनिया में नहीं रहे. निमोनिया से उनका निधन हो गया. उन्होंने अपनी आख़िरी सांस मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में ली. उनकी दी हुई सौग़ात को हम कभी भुला नहीं पाएंगे. 9 फरवरी, 1921 में पैदा हुए ओ पी दत्ता ने बहुत सी अच्छी फिल्में दीं, जिनमें एल ओ सी कारगिल, रिफ्यूजी और बॉर्डर जैसी फिल्में चर्चा में रहीं. उनका करियर निर्देशन से शुरू हुआ, लेकिन उन्हें कामयाबी लेखन में मिली. यह सारी फिल्में उन्होंने ही लिखी थीं, जिनमें से ज़्यादातर फिल्में उनके बेटे जे पी दत्ता ने निर्देशित कीं. फिल्म एल ओ सी कारगिल को इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकादमी और फिल्म फेयर अवॉर्ड भी मिला. बाद में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से भी नवाज़ा गया. बाप-बेटे की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर ख़ूब कमाल दिखाया. हालांकि ओ पी दत्ता ने अपने लगभग नौ फिल्में ही निर्देशित कीं, जिसमें प्यार की जीत उनकी पहली फिल्म थी. बाद में उन्होंने हमारी मंज़िल 1949, सूरजमुखी 1950, एक नज़र 1951, पर्वत 1952, मालकिन 1953, लगन 1955, दुलारे 1957 और आंगन 1959 में निर्देशित की. उन्होंने 1959 तक फिल्मों का निर्देशन किया. उसके बाद वह डायलॉग राइटर, स्क्रिप्ट राइटर और स्टोरी राइटर बन गए. अगर देखें तो यह बात साफ़ नज़र आती कि उन्होंने निर्देशन को छोड़ कर लेखन कार्य सिर्फ़ अपने बेटे जे पी दत्ता के लिए शुरू किया. इसका नतीजा दुनिया ने भी देखा और बेटे जे पी दत्ता का करियर बुलंदी को छू गया. ओ पी दत्ता को अपने ऊपर भरोसा रहा होगा, तभी वह निर्देशन छोड़कर लेखक बन गए और इस फिल्म इंडस्ट्री को कई अच्छी फिल्में दीं. उन्होंने आख़िरी फिल्म उमराव जान लिखी जो 2006 में रिलीज हुई. हालांकि यह फिल्म कुछ ख़ास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन इसका विषय दूसरी फिल्मों से अलग था. बेशक उनकी जगह को भर पाना आसान नहीं है. ऐसे महान कलाकार बार-बार पैदा नहीं होते. बीती 9 फरवरी को उन्होंने कोकिलाबेन अस्पताल में आख़िरी सांस ली. चौथी दुनिया की तरफ़ से इस महान कलाकार को भावभीनी श्रद्धांजलि.

हॉलीवुड से

व्हिटनी ह्यूस्टन का निधन

अमेरिका की मशहूर पॉप सिंगर व्हिटनी ह्यूस्टन का 48 वर्ष की उम्र में निधन हो गया. वह लॉस एंजेलिस स्थित बेवर्ली हिल्टन होटल के एक कमरे में मृत पाई गईं. उनकी अचानक हुई मौत से प्रशंसकों को गहरा धक्का पहुंचा है. उनकी मौत के कारणों का ख़ुलासा नहीं हुआ है. वह काफ़ी समय से नशीली दवाओं का सेवन कर रही थीं. इससे छुटकारा पाने के लिए वह कई बार पुनर्वास केंद्र में भी रह चुकी थीं. व्हिटनी के प्रचारक क्रिसटन फोस्टर ने सबसे पहले सिंगर की मौत की जानकारी एक न्यूज़ एजेंसी को दी. अपने करियर के शिखर के दिनों में ह्यूस्टन को कई बड़े पुरस्कारों से नवाज़ा गया. उन्हें दो एमी, छह ग्रैमी सहित 415 पुरस्कार मिले. गायिका के तौर पर कई पुरस्कारों की विजेता ह्यूस्टन अभिनेत्री, मॉडल एवं निर्माता भी थीं. उन्होंने वर्ष 1992 में फिल्म द बॉडीगार्ड के ज़रिये अभिनय की दुनिया में क़दम रखा और उन्हें काफ़ी सराहना मिली. उनके क़रीबी मित्रों का कहना है कि पिछले काफ़ी समय से वह अकेलापन महसूस कर रही थीं, जिसके कारण वह नशा करने लगी थीं. उनका वैवाहिक जीवन भी बहुत सुखद नहीं रहा था. उन्होंने कुछ समय पहले सिंगर बॉबी ब्राउन के साथ शादी की थी, लेकिन यह रिश्ता लंबा चल नहीं पाया और बहुत जल्द ही इस रिश्ते का दर्दनाक अंत हो गया था. हो सकता है कि उन्होंने इसी ग़म के कारण मौत को गले लगा लिया हो, लेकिन अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि उन्होंने आत्महत्या की है. ह्यूस्टन की मौत पर पॉप गायिका लेडी गागा ने कहा, उनकी आवाज़ संगीत की सभी शैलियों में सटीक बैठती थी. एक आवाज़ जो स्वर्गिक उपहार थी, वह जहां से आई थी वापस चली गई.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

दिल्ली, 27 फरवरी-04 मार्च 2012

www.chauthiduniya.com

इन माननीयों को शर्म नहीं आती

प्रवीण महाजन

हमारे मौजूदा सत्ताधीशों का नैतिकता से कोई वास्ता नहीं रह गया है. उनके द्वारा किए गए कदाचार बार-बार उजागर होने के बाद भी वे ख़ुद को बड़ी मासूमियत से पाक-साफ़ बताने का अभियान शुरू कर देते हैं. भले ही अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया हो, उन पर जुर्माना लगाया हो, लेकिन वे बेशर्मी की चादर ओढ़े अपने को बेगुनाह बताते फिरते हैं. वे जनता द्वारा दी गई जिस कुर्सी पर विराजते हैं, उसी को ढाल बनाकर अपने गुनाहों एवं उसके सबूतों पर पर्दा डालने का प्रयास करते हैं और निरंतर सत्ता का उपभोग करते नज़र आते हैं. उन पर कोई असर नहीं पड़ता है, मानो वे अपने आपको देश के संविधान-क़ानून से ऊपर समझते हैं, इसलिए अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए सारे-नियम क़ानून को परे रखकर कार्य करते हैं. ऐसा ही एक वाक़िया महाराष्ट्र की राजनीति में फिर उठा है. राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा केंद्रीय मंत्री विलासराव देशमुख के ख़िलाफ़ एक मामला सामने आया है, जिसमें उन्होंने सारे नियम-क़ायदों को ताक़ पर रखकर अपने बेटे को फिल्मी दुनिया में स्थापित करने के लिए एक फिल्म निर्माता-निर्देशक को करोड़ों की ज़मीन आवंटित की थी. इस पर अदालत ने उनके कदाचार पर तीखी टिप्पणियां की हैं और उन्हें इसके लिए ज़िम्मेदार ठहराया है. दरअसल पूरा मामला सत्ता के दुरुपयोग का है. पूरा प्रकरण देखने से साफ़ पता चलता है कि विलासराव देशमुख ने मुख्यमंत्री रहते हुए फिल्म निर्माता-निर्देशक सुभाष घई और फिल्म सिटी गोरेगांव में स्थित उनके महत्वाकांक्षी संस्थान विसलिंग वुड्स को वर्ष 2000 में 20 एकड़ क़ीमती ज़मीन कौड़ियों के भाव दे दी थी. बड़े-बुजुर्ग कह गए हैं कि व्यक्ति का पाप लाख छुपाने पर भी एक न एक दिन सबके सामने आ ही जाता है. विलासराव देशमुख ने भी सत्ता में रहते हुए जो कदाचार किए हैं, वे अब खुलकर सामने आ रहे हैं. इस बार आरटीआई कार्यकर्ता राजेंद्र सोनटक्के एवं चार अन्य ने मुंबई उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाख़िल कर देशमुख के मनमाने निर्णय को चुनौती दी थी. याचिका में आरोप लगाया गया था कि मुख्यमंत्री रहते हुए विलासराव देशमुख ने सत्ता का दुरुपयोग करके ज़मीन का आवंटन सुभाष घई को किया है. याचिका की सुनवाई के बाद मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मोहित शाह और न्यायाधीश गिरीश गोडबोले ने अपने दिए फ़ैसले में कहा कि हम प्रतिवादी नंबर 3 व 4 (घई और विसलिंग वुड्स) को निर्देश देते हैं कि वह तुरंत 14.5 एकड़ ज़मीन ख़ाली करे और राज्य सरकार इसे अपने क़ब्ज़े में ले. शेष साढ़े पांच एकड़ ज़मीन पर जहां विसलिंग वुड्स संस्थान बना है, उसे सरकार 31 जुलाई, 2014 तक अपने क़ब्ज़े में ले. इसके साथ ही पीठ ने सुभाष घई को वर्ष 2000 से अब तक 5.3 करोड़ के हिसाब से वार्षिक किराया जमा करने का निर्देश दिया है. साथ ही घई को आदेश दिया है कि वह अब अपने संस्थान में किसी छात्र को प्रवेश न दें, क्योंकि जिस साढ़े पांच एकड़ में संस्थान बना है उसे 31 जुलाई, 2014 तक उपयोग करने की छूट वहां वर्तमान में अध्ययनरत छात्रों के हितों को ध्यान में रखकर दी है, ताकि उनका भविष्य प्रभावित न हो. न्यायाधीशद्वय ने अपने फ़ैसले में कहा है कि विलासराव देशमुख ने फिल्म निर्माता सुभाष घई के संस्थान विसलिंग वुड्स को 20 एकड़ ज़मीन देकर उन्हें उपकृत करने का प्रयास किया है. उन्होंने इस मामले में न सिर्फ़ अपने पद एवं अधिकारों का दुरुपयोग किया है, बल्कि क़ानून की अवहेलना भी की है. राज्य का प्रमुख होने के नाते मुख्यमंत्री से क़ानून के अनुरूप कार्य करने की अपेक्षा की जाती है, लेकिन ज़मीन आवंटन प्रक्रिया को देखकर प्रतीत होता है कि देशमुख ने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया है. इस फ़ैसले से केंद्रीय विज्ञान व उच्च तकनीकी मंत्री विलासराव देशमुख एक बार पुन: कटघरे में आ गए हैं. खंडपीठ ने अपने फ़ैसले में साफ़ किया है कि ऐसा महसूस होता है कि देशमुख ने अपने बेटे (रितेश देशमुख) को बॉलीवुड में स्थापित करने के बदले सुभाष घई को ज़मीन आवंटित कर उपकृत किया है. इससे यह बात साफ़ हो जाती है कि देशमुख ने पुत्र मोह में सारे नियम-क़ायदों को नज़रअंदाज कर इस कार्य को अंजाम दिया है. अदालत में देशमुख यह कहकर अपनी खाल बचाने का प्रयास करते रहे कि ज़मीन आवंटन करने में उनकी नीयत में कोई खोट नहीं थी. इस पर अदालत का कहना था कि कोई कैसे बिना निविदा मंगाए एवं भूखंड का आर्थिक आकलन किए बग़ैर किसी को ज़मीन का आवंटन कर सकता है. ग़ौरतलब है कि वर्ष 1995 में मुंबई के ज़िलाधिकारी ने बाज़ार भाव के आधार पर इस ज़मीन की क़ीमत 45 करोड़ रुपये निर्धारित की थी. वर्ष 2000 में जब यह ज़मीन सुभाष घई को दी गई तब उसका बाज़ार भाव 66 करोड़ रुपये था. छूट देने के बाद भी उसका वार्षिक किराया क़रीब 7.11 करोड़ रुपये होता है. इतनी क़ीमती ज़मीन विलासराव देशमुख ने 3 करोड़ में सुभाष घई को दे दी. ऊपर से कहते हैं कि उनकी नीयत में खोट नहीं थी. यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जब सुभाष घई को उक्त ज़मीन का आवंटन किया गया तब विलासराव देशमुख के पुत्र रितेश देशमुख बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने के लिए हाथ-पैर मार रहे थे. शायद इसलिए तत्कालीन मुख्यमंत्री ने सुभाष घई के सहारे अपने पुत्र की मदद की थी. हद तो तब हो गई जब सुभाष घई और उनके संस्थान को ज़मीन देने के संबंध में हुए क़रार में सरकार का मुखिया होने के बाद भी विलासराव देशमुख ने घई की ओर से गवाह के रूप में हस्ताक्षर किए थे. उल्लेखनीय है कि जिस व्यक्ति के पक्ष में मुख्यमंत्री स्वयं गवाह (साक्षीदार) होगा, उसकी फाइल को भला कौन अधिकारी ठुकराने की हिम्मत जुटा पाएगा? सुभाष घई को ज़मीन आवंटन मामले में अदालत की ओर से क़ानून उल्लंघन का दोषी क़रार दिए जाने के बाद से विपक्षी दलों ने उनसे केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफ़ा देने की मांग की है. वहीं भाजपा नेता एकनाथ खड़से ने कोर्ट के फ़ैसले के बाद कहा कि अदालत ने घई को ज़मीन आवंटन के मामले में विलासराव देशमुख को ज़िम्मेदार ठहराया है. इसलिए उन्हें केंद्रीय मंत्री पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है. यह पहली ऐसी घटना नहीं है, जिसमें विलासराव देशमुख को किसी मामले में संलिप्त पाया गया हो. इससे पहले वर्ष 2011 में उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र के खामगांव के विधायक दिलीप सानंदा के साहूकार पिता के ख़िलाफ़ पुलिस अधिकारी को एफआईआर दर्ज करने से रोकने का दोषी ठहराया था. इसके अलावा मुख्यमंत्री द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करने पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी राज्य सरकार पर लगाया था. उस समय भी सभी विपक्षी दलों ने राज्य सरकार से जुर्माने की रक़म विलासराव देशमुख से वसूल करने की मांग की थी और केंद्र सरकार से उन्हें बर्ख़ास्त करने की मांग की थी. हालांकि विलासराव देशमुख के राजनीतिक जीवन में इन अदालती फ़ैसलों का कोई असर नहीं पड़ा. उन पर औरंगाबाद में वक़्फ़ बोर्ड की ज़मीन अपने भाई दिलीप देशमुख की हाउसिंग सोसायटी को भी आवंटित करने का आरोप लगाया जाता है. वैसे यह मामला भी न्यायालय में विचाराधीन है. आदर्श सोसायटी घोटाला मामले में भी विलासराव देशमुख का नाम निरंतर आ रहा है. यहां तक उनके मातहत कार्य करने वाले अधिकारी ने जांच आयोग के सामने अपने बयान में कहा है कि रक्षा विभाग की ज़मीन आदर्श सोसायटी को आवंटित करने की पहल विलासराव देशमुख के कार्यकाल में ही हुई थी. किरीट सोमैया ने यह भी ख़ुलासा किया है कि सुभाष घई को महाराष्ट्र के अलावा भी कई राज्यों की कांग्रेसी सरकारों ने उदारता से ज़मीन मुहैया कराई है. यह दरियादिली विलासराव देशमुख की सिफ़ारिश पर की गई है. अकसर विवादों में रहने के बाद भी पार्टी आलाकमान की उन पर हमेशा मेहरबानी बनी रहती है. कांग्रेस नेता भी मानते हैं कि देशमुख पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के विश्वासपात्रों में से एक हैं. इसलिए हर बार मुसीबत में पड़ने के बाद पार्टी उनका बचाव करती है. उन्होंने मुंबई पर हुए 26/11 के हमले के दौरान फिल्म निर्माता-निर्देशक रामगोपाल वर्मा को लेकर ताज होटल का दौरा किया था. उसके बाद विपक्षी दलों ने उनकी तीखी आलोचना की थी. तब भी उन्होंने इस्तीफ़ा देने से इंकार कर दिया था, लेकिन भारी जन दबाव में उनसे पार्टी नेतृत्व ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा देने को कहा था, लेकिन पार्टी आलाकमान की मेहरबानी के चलते उन्हें तुरंत ही दिल्ली बुलाकर केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कर पुनर्स्थापित कर दिया गया था.

feedback@chauthiduniya.com

सवाल उठने लगे

कांग्रेस में पार्टी नेतृत्व के दोहरे रवैये के प्रति सवाल भी उठने लगे हैं. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण के समर्थकों का सवाल है कि पार्टी नेतृत्व विलासराव देशमुख को बचाने के लिए दोहरा रवैया क्यों अपना रहा है? अशोक चव्हाण का आदर्श सोसाइटी मामले में नाम आते ही उनसे इस्तीफ़ा देने को कहा गया. दूसरी ओर विलासराव देशमुख का नाम आदर्श सोसायटी घोटाले के अलावा कई मामलों में न केवल आया है, बल्कि अदालत ने उन्हें ज़िम्मेदार भी ठहराया है. सुप्रीम कोर्ट ने देशमुख पर अपने पद का दुरुपयोग करने पर 10 लाख का जुर्माना भी लगाया, जो देश व राज्य के इतिहास में शायद अनोखा मामला है जिसमें किसी राज्य के मुख्यमंत्री पर जुर्माना लगाया हो. अब सुभाष घई को नियम-क़ायदों को ठेंगा बताकर ज़मीन देने का मामला सामने है. इसके बाद भी पार्टी आलाकमान देशमुख का बचाव कर रही है.

घई सुप्रीम कोर्ट जाएंगे

मुंबई उच्च न्यायालय के फ़ैसले के बाद फिल्म निर्माता सुभाष घई ने उच्चतम न्यायालय जाने का मन बनाया है. घई का कहना है कि मैं न्यायालय के फ़ैसले का सम्मान करता हूं, लेकिन इस मामले में मैंने कोई ग़लती नहीं की है. मैं कहीं ग़लत नहीं रहा हूं. मैंने वर्ष 2002 में क़ानूनी तौर पर फिल्म सिटी के साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर का मीडिया संस्थान स्थापित करने के लिए इमारत बनाने का सरकार के साथ समझौता किया था. इसमें क्या ग़लत है? इसलिए मैं इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ उच्चतम न्यायालय जाऊंगा.

सरकार अपील कर सकती है

फ़ैसले के बाद मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा है कि सुभाष घई के विसलिंग वुड्स के मामले में न्यायालय के निर्णय की प्रति अभी मैंने नहीं देखी है. यदि यह फ़ैसला राज्य सरकार के ख़िलाफ़ होगा तो हम ऊपरी अदालत में अपील कर सकते हैं.

महाराष्ट्र हलचल

मल्टीप्लेक्स से डूबा करोड़ों का टैक्स

छत्तीसगढ़ की तर्ज़ पर टैक्स लगे : मिश्रा

मयूर रंगारी

...आने से पूर्व महाराष्ट्र में लगभग 864 सिंगल स्क्रीन टॉकीजें थीं. मल्टीप्लेक्स के आने के बाद इनकी आय में इतनी कमी आ गई कि इनमें से क़रीब 142 टॉकीजें बंद हो गई हैं. मुंबई-ठाणे में 19 और नागपुर में 10 सिंगल स्क्रीन टॉकीजें बंद हो गई हैं. जानकारों ने बताया कि राज्य सरकार ने एक ओर मल्टीप्लेक्स को बढ़ावा देने के लिए उसे मनोरंजन कर में छूट तो दी, लेकिन सिंगल स्क्रीन टॉकीजों को कोई राहत...

मल्टीप्लेक्स बेहतर है : दर्शक

feedback@chauthiduniya.com

बुलढाना में जल संकट

पानी के लिए लोग तरस रहे हैं

अनूप महाजन

गर्मी का मौसम शुरू होने में भले ही अभी समय हो, लेकिन विदर्भ के बुलढाना ज़िले की 4 तहसीलों में अभी से भीषण जलसंकट की स्थिति पैदा हो गई है. इनमें खामगांव, नांदुरा, मेहकर और देऊलगांव राजा का समावेश है. पिछले वर्ष औसत से कम बारिश होने के कारण यहां के नदी-तालाब सूख चुके हैं. परिसर के कई कुंए या तो सूख चुके हैं या फिर उनका जलस्तर काफ़ी नीचे चला गया है. जलापूर्ति की व्यवस्था में काफ़ी ख़ामियां होने के कारण पानी के लिए लोग दर-दर भटक रहे हैं. सरकारी आंकड़ों के अनुसार इन 4 तहसीलों के 65 गांवों में जलसंकट की स्थिति है, लेकिन वास्तव में गांवों की संख्या इससे कहीं अधिक है. बुलढाना ज़िले की 13 में से शेगांव, जलगांव जामोद और संग्रामपुर तहसीलों के लगभग 200 गांव पहले ही खारे पानी पट्टे में आते हैं. प्रशासन बार-बार यहां टैंकर से जलापूर्ति करने का दावा करता है, लेकिन वास्तविक स्थिति इससे कहीं अधिक विपरीत है. प्रशासन की उदासीनता के कारण ज़िले के 200 गांव संकट में है, उसमें और 4 तहसीलों के गांवों का समावेश हो गया है. ज़िले में पिछले वर्ष औसत से कहीं कम बारिश दर्ज की गई. यही कारण है कि यहां की छोटी-बड़ी नदियां समय से पहले ही सूख चुकी हैं. प्रकल्प में भी पर्याप्त जलसंग्रह नहीं है. इसी कारण गर्मियां आने के पूर्व ही कई गांवों में जलसंकट की स्थिति निर्माण हो गई है. खारे पानी पट्टे और जल संकट से ग्रस्त 9 तहसीलों के अधिकतर गांवों की जलापूर्ति योजनाएं अधूरी हैं, जिससे लोगों को पेयजल के लिए तालाब, कुंए और कूप नलिकाओं पर ही निर्भर रहना पड़ता है. जानकारी के अनुसार, कई कूप नलिकाएं ख़राब अवस्था में हैं. इसके बारे में कई बार प्रशासन को जानकारी दी गई है, लेकिन स्थिति अभी भी जस की तस है. पर्याप्त बारिश नहीं होने से तालाबों में काफ़ी कम जल है. भूजल स्तर काफ़ी नीचे चले जाने के कारण कई कुंए सूख चुके हैं. ऐसे में प्रशासन की ओर से गांवों में टैंकर से जलापूर्ति नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से पेयजल के लिए ग्रामीणों को काफ़ी दिक़्क़तों का सामना करना पड़ रहा है. ग्रामीणों को पानी के लिए दर-दर भटकते हुए देखा जा सकता है. जो गांव खारे पानी के पट्टे में आते हैं, वहां ग्रामीणों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है. उन्हें मजबूरन उस पानी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जो पीने के लायक़ ही नहीं है. यहां के भूजल में कैडमियम, लेड, मैग्नेशियम, मरक्यूरी जैसे शरीर के लिए घातक रसायन मिले हैं, जिस वजह से लोगों को पेट की बीमारियां हो रही हैं. सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, किडनी ख़राब होने से यहां कई लोगों की मौत हो गई. इसके बावजूद यहां लोगों को परेशानी से निकालने के लिए प्रशासन तत्पर नहीं नज़र आता.

प्रस्ताव की खानापूर्ति

एक ओर जहां ज़िले के कई गांवों के लोगों को भीषण जल संकट का सामना करना पड़ रहा है, वहीं प्रशासन उपाय योजना के प्रस्ताव की काग़ज़ी कार्यवाही कर खानापूर्ति करने में लगा है. पंचायत समिति के जलापूर्ति विभाग द्वारा प्रस्तुत जल संकट से ग्रस्त 65 गांवों में तीन चरणों की उपाय योजना की रिपोर्ट को ज़िलाधिकारी ने मंज़ूरी प्रदान की है. इस योजना के अनुसार, अक्टूबर से दिसंबर माह में पहले चरण में 6 गांवों के 4 निजी कुंओं का अधिग्रहण और नल योजनाओं की विशेष दुरुस्ती का काम किया गया है. जनवरी से मार्च के दूसरे चरण में 17 गांवों में उपाय योजनाएं प्रस्तावित हैं. इनमें 11 गांवों में नए बोरवेलों का निर्माण करने, 5 गांवों के विंधन कुंओं की दुरुस्ती का प्रस्ताव है. अप्रैल से जून के आख़िरी चरण में 58 गांवों में से कई गांवों में उपाय योजनाओं को मंज़ूरी मिली है. इनमें गांवों के निजी कुंओं का अधिग्रहण और 24 नए हैंडपंपों का निर्माण कार्य प्रमुख है. ग्रामवासियों का कहना है कि जैसे-जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी, वैसे-वैसे और भी गांवों में भीषण जल संकट निर्माण होगा.

जलापूर्ति योजना अधर में लटकी

नागपुर में हुए राज्य विधान मंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्य सरकार के जलापूर्ति मंत्री लक्ष्मणराव ढोबले ने बताया था कि वान बांध से बुलढाना ज़िले की खारे पानी पट्टे की जलगांव जामोद और संग्रामपुर तहसील के 141 गांवों के लिए जलापूर्ति की व्यवस्था आगामी दो वर्षों में की जाएगी, लेकिन यह योजना पिछले कई वर्षों से राज्य सरकार के उदासीन रवैये के कारण लटकी पड़ी है. इसे पूरा करने में कम से कम 3 वर्षों की कालावधि लगेगी, लेकिन सरकार इसे दो वर्षों में पूरा करने का आश्वासन दे रही है. इसे पूरा करने के लिए संबंधित गांवों की ग्राम पंचायतों को ख़र्च की 10 फ़ीसदी राशि सरकार को देनी होगी. हालांकि सरकार ने इसमें कमी करके 7 से 8 फ़ीसदी करने का वादा किया है. अनुमान है कि यह राशि 20 से 25 लाख रुपये तक पहुंच सकती है. ऐसे में सवाल उठता है कि ग्राम पंचायत इतनी अधिक राशि कहां से लाएगी?

feedback@chauthiduniya.com

अदानी प्रोजेक्ट से विद्युत उत्पादन संशय में

क्या वाक़ई महाराष्ट्र लोडशेडिंग से मुक्त राज्य हो जाएगा? उपमुख्यमंत्री व वित्त-ऊर्जा मंत्री अजीत पवार की विधानसभा में की गई घोषणा के अनुसार महाराष्ट्र चालू वर्ष 2012 के अंत तक बिजली कटौती से मुक्त हो जाएगा. यदि ऐसा हो गया तो यह जनता के लिए सबसे बड़ी ख़ुशी होगी. ख़ासकर राज्य में चल रहे उद्योगों के लिए यह बात किसी ख़ुशख़बरी से कम नहीं होगी. इसके साथ ही आघाड़ी सरकार की यह उपलब्धि अगले विधानसभा चुनाव में उसकी सत्ता में वापसी की गारंटी साबित हो सकती है, लेकिन आज की स्थिति में चालू वर्ष के अंत तक राज्य के लोडशेडिंग मुक्त होने के कोई आसार नज़र नहीं आते हैं. मिसाल के तौर पर महाराष्ट्र में स्थापित हो रहे अदानी बिजली प्रोजेक्ट को लिया जा सकता है, जिसमें इस वर्ष के उत्तरार्ध तक 1320 मेगावाट बिजली उत्पादन होना तय माना जा रहा था, लेकिन कोयला आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है. दरअसल, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने वर्ष 2012 के अंतिम महीने में गोंदिया ज़िले के तिरोडा में स्थापित बिजली प्रोजेक्ट से 1320 मेगावाट बिजली उत्पादन शुरू होने की संभावना के मद्देनज़र ही राज्य के लोडशेडिंग मुक्त होने की घोषणा की थी. उनकी इस घोषणा के फलीभूत होने में कोयला खलनायक बनता नज़र आ रहा है. अदानी ग्रुप के प्रबंधन ने सरकार को चेताया है कि बिजली उत्पादन के लिए पर्याप्त देसी कोयला उपलब्ध कराया जाए या फिर आयातित कोयले से उत्पादित महंगी बिजली ख़रीदने को तैयार रहे. इसके जवाब में राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से अदानी को देसी कोयला उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है. ग़ौरतलब है कि इन दिनों अदानी पावर कंपनी के बिजली प्रोजेक्ट का काम तेज़ी से चल रहा है, जिसके लिए कोयले की आपूर्ति करने हेतु सरकार ने चंद्रपुर ज़िले में स्थित ताड़ोबा बाघ अभयारण्य में कोयला खदान शुरू करने को मंज़ूरी दी थी. लेकिन पर्यावरणविदों द्वारा खदान के शुरू होने पर बाघों की सुरक्षा पर सवाल उठाए गए थे और इस मुद्दे पर आंदोलन भी हुए थे. पर्यावरण व वन्यजीव प्रेमियों की आपत्तियों पर ग़ौर करते हुए तत्कालीन वन व पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने कोयला खदान शुरू करने को दी गई अनुमति को रद्द कर दी. कोयला खदान की अनुमति रद्द हो जाने के बाद अदानी बिजली प्रोजेक्ट को कोयले की आपूर्ति की समस्या खड़ी हो गई, लेकिन सरकार ने अब तक उसे कोई वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई. जब अदानी पावर कंपनी प्रबंधन ने सरकार को चेताया तब राज्य सरकार की आंख खुली. कंपनी प्रबंधन ने साफ़ कर दिया है कि यदि कोयले की आपूर्ति की समस्या का समाधान नहीं किया जाता है तो वर्ष 2012 के अंत तक बिजली उत्पादन शुरू नहीं हो सकेगा. यदि सरकार विदेशों से आयातित कोयले से उत्पादित बिजली ख़रीदने को तैयार हो, तो कंपनी इसके लिए तैयार है. राज्य की महावितरण कंपनी ने भी अदानी बिजली प्रोजेक्ट से उत्पादित 1320 मेगावाट बिजली ख़रीदने के लिए 25 साल की लंबी अवधि के लिए क़रार किया है. इस क़रार के अनुसार, महावितरण को अदानी पावर कंपनी 2 रुपये 64 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली देगी. हालांकि यह क़रार भी अब खटाई में पड़ता दिखाई दे रहा है. इससे राज्य के लोडशेडिंग मुक्त होने की संभावना कम दिख रही है. अदानी पावर कंपनी के प्रबंधन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोयले की आपूर्ति की समुचित व्यवस्था नहीं की गई तो क़रार के अनुसार, महावितरण को 2 रुपये 64 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली देना संभव नहीं होगा. यदि आयातित कोयले से बिजली उत्पादन किया जाता है, तो महावितरण को महंगी बिजली ख़रीदनी होगी और क़रार को नया रूप दिए जाने की ज़रूरत पड़ेगी.

यदि महावितरण कंपनी महंगी बिजली ख़रीदने को तैयार नहीं है, तो क़रार से मुक्त करने का आग्रह अदानी पावर कंपनी ने किया है. कंपनी प्रबंधन का स्पष्ट कहना है कि जब तिरोडा में बिजली प्रोजेक्ट बनाने का प्रस्ताव सरकार के सामने पेश किया था, तो कोयला खदान साथ में देने का वादा किया गया था. उसके बाद केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालय ने कोयले की खदान शुरू करने पर रोक लगा दी. अब यह सरकार की ज़िम्मेदारी है कि वह बिजली उत्पादन के लिए कोयले की पर्याप्त आपूर्ति करे. वरना उसके पास विदेशों से कोयला मांगा कर महंगी बिजली उत्पादन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है. अब देखना यह है कि सरकार इस समस्या से निपटने के लिए क्या क़दम उठाती है. बहरहाल, महावितरण के अधिकारी इस मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं. उन्हें आशा है कि राज्य में बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार कोई न कोई रास्ता ज़रूर निकालेगी. इस समस्या को लेकर महावितरण कंपनी अधिकारी राज्य के ऊर्जा मंत्रालय के संपर्क में हैं. वहीं राज्य के ऊर्जा मंत्री अजीत पवार महानगर पालिका व ज़िला परिषद चुनाव में व्यस्त हैं. कहा जा रहा है कि सरकार इस मुद्दे पर स्थानीय निकाय चुनाव संपन्न हो जाने के बाद गंभीरता से ग़ौर करेगी, लेकिन इतना अवश्य है कि ताड़ोबा के बाघों की चिंता ने अदानी पावर कंपनी के संचालकों को भी चिंता में डाल दिया है. अब देखना यह है कि सरकार का इस मामले में क्या निर्णय होता है, क्योंकि राज्य के अन्य बिजली घरों में भी कोयले की मांग बढ़ती जा रही है. उसमें भी अच्छी क्वालिटी के कोयले की आपूर्ति एक गंभीर समस्या बनती जा रही है. फ़िलहाल तो अदानी पावर कंपनी द्वारा उत्पादित की जाने वाली 1320 मेगावाट की बिजली के उत्पादन पर संशय के काले बादल मंडरा रहे हैं, जिससे राज्य के लोडशेडिंग मुक्त होने पर अल्पविराम लग गया है.

महाराष्ट्र ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

अमरावती विभाग में पदोन्नति घोटाला

अमरावती विभाग के पांच ज़िलों में पदोन्नति घोटाला सामने आया है. अमरावती, अकोला, बुलढाना, वाशिम और यवतमाल ज़िला परिषदों के 59 कर्मचारियों की पदोन्नति नियमों को ताक़ पर रखकर की गई है. ज़िला परिषद कर्मचारियों को सेवा वरिष्ठता के अनुसार मिलने वाली पदोन्नति सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार होती है, लेकिन अमरावती विभाग में वर्ष 2004 से पदोन्नति करते समय इन दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया गया है. आरोप है कि इन पदोन्नतियों में बड़े पैमाने में पैसों का लेन-देन हुआ. कुछ अधिकारियों ने नाम नहीं लिखने की शर्त पर बताया कि यदि इस मामले की उच्चस्तरीय जांच की गई, तो कई बड़े नाम सामने आएंगे.

राज्य में पदोन्नति के कई मामलों में भ्रष्टाचार होने की ख़बरें आती रहती हैं. इसमें वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक के शामिल होने के आरोप लगते रहते हैं. सरकारी कर्मचारी यदि पात्र हैं, तो भी उसे पदोन्नति पाने के लिए जेब ढीली करनी पड़ती है. अमरावती विभाग के 5 ज़िला परिषदों में हुए 59 कर्मचारियों की पदोन्नति के मामले में भी यही होने का आरोप है. ज़िला परिषद कर्मचारियों को सेवा वरिष्ठता सूची के अनुसार पदोन्नति दी जाती है. इस सूची में जिस कर्मचारी का नाम प्रथम क्रमांक पर होगा, पदोन्नति में उसे प्राथमिकता दी जाती है. सूची तैयार करते समय सरकार के नियमों के अनुसार वरिष्ठता क्रम निर्धारित कर पदोन्नति देने का निर्णय लिया जाता है. अमरावती विभाग में सूची तैयार करते समय भारी अनियमितता हुई है. आयुक्त कार्यालय के संबंधित कर्मचारियों ने अपनी पहचान के लोगों के नाम डाले हैं. महाराष्ट्र ज़िला परिषद सेवा नियम 1981 के अनुसार, ज़िला परिषद में क्लास 3 के पद का कार्यभार संभालने के 4 वर्ष या कम से कम 3 मौक़ों में सेवा प्रवेशोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है. इस समयावधि में यदि संबंधित कर्मचारी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाया, तो उसे वेतन श्रेणी के अनुसार आगामी वेतन बढ़ोत्तरी मंज़ूर नहीं की जाती. साथ ही उस कर्मचारी को सेवामुक्त किया जाता है. इस नियम का उल्लंघन कर परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हुए कर्मचारियों को पदोन्नति देने की बात सामने आई है. इससे साफ़ है कि आयुक्त कार्यालय के संबंधित कर्मचारियों और पदोन्नत कर्मचारियों के बीच बड़े पैमाने पर लेन-देन हुआ है. वरिष्ठ अधिकारियों को भी इसकी जानकारी न हो, यह बात समझ से परे है. इस संबंध में बार-बार हो रही जांच की मांग को नहीं मानना भी कई सवालों को जन्म देता है. जिन कर्मचारियों ने अपनी पदोन्नति कराने के लिए भ्रष्टाचार किया हो, उनसे अच्छे काम की अपेक्षा कैसे की जा सकती है. ज़ाहिर है इससे ज़िला परिषदों में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा.

ग़ौरतलब है कि किसी भी कार्यालय के कामकाज का भार मुख्य रूप से क्लास 3 के कर्मचारियों पर ही होता है. फाइल बनाने से लेकर, फाइलों में कमी निकालने और उन्हें अच्छे-बुरे मार्क के साथ वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष पेश करने की ज़िम्मेदारी वही निभाते हैं. उन्हें नियमों की अच्छी समझ होती है. किस नियम का क्या तोड़ है, यह उन्हें अच्छी तरह मालूम होता है. इससे ज़िला परिषद के काम पर असर पड़ेगा. भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलने से लोगों के मन में प्रशासन की छवि और मलीन होगी. पहले ही काम समय पर नहीं होने और छोटे-छोटे कामों के लिए कर्मचारियों को पैसे देने के लिए ज़िला परिषद विभाग बदनाम है. ऐसे में ज़रूरी है कि कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारियों को बढ़ावा दिया जाए, न कि नियमों को तोड़-मरोड़कर और वरिष्ठ अधिकारियों से अच्छे संबंध बनाकर पदोन्नति का सपना देखने वाले कर्मचारियों को.

ज़िला	- ग़ैर वरीयता प्राप्त पदोन्नत कर्मियों की संख्या
अमरावती	- 22
बुलढाना	- 15
यवतमाल	- 11
वाशिम	- 06
अकोला	- 05

महाराष्ट्र ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

नोट-शराब और लोकतंत्र

पिछले दिनों राज्य में संपन्न हुए महानगर पालिका चुनाव के दौरान पुलिस ने नाकाबंदी की तो कई वाहनों से करोड़ों की शराब और नगदी बरामद हुई. ज़ब्त...

ये क्या हो रहा है...

संक्षिप्त समाचार

महिला पुलिस के मोबाइल पर रोक लगे

ड्यूटी पर तैनात पुलिस जवानों के पास काम के संबंध में बातचीत करने के लिए वॉकीटाकी होता है. इसके बावजूद अधिकांश महिला पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के दौरान अपने निजी मोबाइल से बात करते देखा जाता है. अखिल भारतीय ग्राहक कल्याण परिषद ने इस बात को गंभीरता से लिया है. परिषद ने मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, सतारा, नागपुर में जांच किया तो उसने पाया कि महिला पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी के 60 प्रतिशत समय में अपने निजी मोबाइल से चिपकी रहती हैं. मोबाइल से बात करते समय यदि कोई पीड़ित उनके पास अपनी समस्या को लेकर जाता है तो उसे इंतज़ार करने के लिए कहा जाता है. इससे यह बात तो ज़ाहिर हो जाती है कि ड्यूटी पर रहते हुए भी उनका ध्यान काम में कम ही रहता है. इसके अलावा पुलिस वाले हेलमेट न पहने लोगों पर मोटर व्हीकल एक्ट 1987 के तहत कार्रवाई कर उनका चालान काटते हैं, पर स्वयं बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हैं. परिषद ने इस संबंध में राज्य के गृह मंत्रालय के सचिव एवं नागपुर के पुलिस आयुक्त अंकुश धनविजय को पत्र लिखकर मांग की है कि महिला पुलिस कर्मियों के मोबाइल पर निरंतर बात करने पर तत्काल अंकुश लगाया जाना चाहिए. इसके साथ ही पुलिस द्वारा अपने ही नियमों का उल्लंघन करने पर भी रोक लगाई जानी चाहिए.

सफल चाचाओं को देख, भतीजों में गुदगुदी

महाराष्ट्र की राजनीति में कई चाचा-भतीजों की जोड़ी सक्रिय है. पिछले दिनों भाजपा नेता गोपीनाथ मुंडे और उनके भतीजे धनंजय मुंडे के बीच का विवाद राजनीति में काफ़ी चर्चित रहा है. इसके अलावा शिवसेना प्रमुख बालासाहब ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता राज ठाकरे के बीच तनाव का मामला भी अक्सर सुर्ख़ियों में रहता है. इसके अलावा सबसे अधिक चर्चित काका-पुतना (चाचा-भतीजा) की जोड़ी राकांपा नेता एवं केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार और राज्य के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की है. जब शिवसेना प्रमुख बालासाहब ठाकरे से राज्य में राज ठाकरे, अजीत पवार और धनंजय मुंडे के राजनीतिक उदय के संबंध में पूछा गया तो उनका जवाब था चाचाओं की सफलता मिलते देखकर भतीजों के पेट में गुदगुदी होने लगती है. उनके सिर नेतृत्व का भूत सवार हो जाता है. इसलिए जब उनके चाचाओं की जनता के बीच वाहवाही होती है तो उनमें गुदगुदी होने लगती है. उन्होंने राज ठाकरे के विषय में कहा कि राज उन लोगों में से हैं, जो हमसे अलग हो गए. उसको मातोश्री (बांद्रा स्थित शिवसेना प्रमुख का आवास) में ढाला गया है. राज के शिवसेना में वापसी के संबंध में उनका मत था कि चाहना एक बात होती है, लेकिन अंततः है तो ठाकरे ख़ून ही. बालासाहब ने याद दिलाया कि राज ने एक बार कहा था कि उसके और उसके चचेरे भाई उद्धव के बीच राजनीति आई तो वह राजनीति छोड़ देगा.

अभियंता और डकैती

अभियंता व प्राध्यापक जैसे पद पर कार्य करने वाला व्यक्ति क्या कभी डकैती करने की बात भी सोच सकता है? लेकिन महाराष्ट्र के परतवाड़ा शहर में एक पूर्व कार्यकारी अभियंता और उसके 6 साथियों के ख़िलाफ़ एक किसान की शिकायत पर पुलिस ने डकैती का मामला दर्ज किया है. परतवाड़ा के शांतिनगर इलाक़े में रहने वाले प्रभाकर देवीदास दौड़ (44) ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि वह अपने खेत का मुआयना करने गए थे, तभी शरद गावंडे और उनके साथियों ने उनको घेर कर 50 हज़ार रुपये की मांग की. पैसे देने से इंकार करने पर उसके साथ मारपीट की और गले में पहनी हुए एक तोले की सोने की चैन एवं चार हज़ार नग़दी छीन ली. इस शिकायत पर पुलिस ने भादसं की धारा 395 के तहत शरद गावंडे और उसके साथी जयंत बबनराव गावंडे, राजेश कृष्णराव वानखडे, सत्यनारायण श्रीराम वाघोडे, राजेश कृष्णराव आसरे, विनोद किसनराव ताडपीलवार, गोपाल कोल्हे के ख़िलाफ़ डकैती का मामला दर्ज कर मुख्य आरोपी को छोड़कर अन्य सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. इसमें मुख्य आरोपी शरद गावंडे अपर वर्धा प्रकल्प और पूर्णा माध्यम प्रकल्प के कार्यकारी अभियंता रह चुके हैं. वहीं शरद गावंडे की पत्नी प्राध्यापक शारदा शरद गावंडे द्वारा शिकायतकर्ता प्रभाकर देवी दौड के ख़िलाफ़ घर में चोरी का मामला दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस ने दौड को भी पकड़ लिया है. बहरहाल, इस मामले की हक़ीक़त पर से पर्दा उठाने के लिए पुलिस जांच करने में जुटी है.

देश का सबसे महंगा फ्लैट

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के ख़ूबसूरत कफ परेड इलाक़े में स्थित आलीशान इमारत जॉली मेकर वन की 21वीं मंज़िल का फ्लैट 29 करोड़ रुपये में बिका. ख़रीददार ने इस फ्लैट को ख़रीदने के लिए 1 लाख 11 हज़ार रुपये प्रति स्क्वेयर फुट के हिसाब से भुगतान किया. देश के सबसे...

महाराष्ट्र ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

वर्धा में हुए क़रीब 50 करोड़ के शिष्यवृत्ति घोटाले में सामाजिक न्याय विभाग ने कोई ठोस क़दम क्यों नहीं उठाया?

Postal Regn. No. RNP/NP/CITY/383/2011-13, RNI No. DELHIN/2009/30467

ब्रिटिशकालीन पैसेवारी पद्धति से किसान परेशान

राजेश नामदेव

आज़ादी के साढ़े छह दशक बाद भी लगता है कि हम आज भी अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त नहीं हो पाए हैं. आज भी हम उनके छोड़े अवशेषों को ढो रहे हैं. हम उसमें कुछ बदलाव करने का कष्ट उठाना ही नहीं चाहते हैं. उससे चाहे जनता को जितना नुक़सान क्यों न होता हो. एक बात जगज़ाहिर है कि अंग्रेजों ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व अन्य जो भी नीतियां स्वतंत्रता से पूर्व बनाई थीं, उसमें उनका एकमात्र मक़सद भारत में अपनी सत्ता को अधिक से अधिक मज़बूत करना और भारत में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों दोहन व जनता का शोषण करना था. उनकी कृषि नीति भी किसानों को फ़ायदा पहुंचाने की बजाय कृषकों से अधिक से अधिक लगान वसूल करने की थी. हैरत की बात यह है कि आज भी कृषि उपज की पैसेवारी का आकलन करने के लिए शासन-प्रशासन ब्रिटिशकालीन प्रक्रिया को अपनाए हुए है. स्वतंत्रता पश्चात ब्रिटिशकालीन पैसेवारी की प्रक्रिया को अपनाए रखने का आख़िर क्या औचित्य हो सकता है? इससे तो यही पता चलता है कि हमारे सत्ता प्रतिष्ठानों का कृषकों-कृषि के प्रति रुख़ में कोई बदलाव नहीं आया है. वे अंग्रेजों द्वारा किसानों का शोषण करने वाली मानसिकता का अनुसरण कर रहे हैं. इसलिए 40 किलो प्रति एकड़ पैदावार को आज भी ब्रिटिशकालीन पद्धति के हिसाब से 100 प्रतिशत उत्पादन मान लिया जाता है. कहीं कृषि का बेड़ा ग़र्क़ करने में यही ब्रिटिशकालीन पैसेवारी तो ज़िम्मेदार नहीं है? इस सवाल पर शायद हमारे कृषि-कृषक हितचिंतकों ने ग़ौर करने की ज़हमत नहीं उठाई है. वहीं दूसरी ओर देश में किसानों के आत्महत्या करने के आंकड़ों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है. इसे राज्य के किसानों का दुर्भाग्य नहीं तो और क्या कहेंगे कि जिस नीति के ज़रिये स्वतंत्रता से पूर्व उनका शोषण ब्रिटिश सत्ता करती थी, उसी नीति को हमारी सरकार अपनाए हुए है. जिस 150 साल पुरानी ब्रिटिशकालीन नीति से किसानों से अधिक लगान अंग्रेजों ने वसूला, आज भी उसी पद्धति से कृषि उपज का आकलन किया जा रहा है. इस पद्धति ने किसानों का पूरा गणित ही बिगाड़ रखा है. यह किसी से छिपा नहीं है कि कृषि का पूरा ढांचा मानसूनी बारिश पर निर्भर रहता है. इसलिए क़रीब हर साल कहीं अतिवृष्टि से फ़सलों को नुक़सान पहुंचता है तो कहीं सूखे से फ़सलें बर्बाद होती हैं. इससे किसान की आर्थिक हालत लगातार बदतर होती जा रही है. कृषि को होने वाले नुक़सान के लिए सरकार पैसेवारी निकालती है और उसी हिसाब से किसानों को राहत प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू होती है. इस प्रक्रिया में जुड़ी शर्तों का सीधा असर छोटे किसानों पर पड़ता है. छोटे किसान इस ब्रिटिशकालीन पैसेवारी फार्मूले के सबसे अधिक शिकार होते हैं और सरकार से मिलने वाली मदद से वंचित हो जाते हैं.

ब्रिटिशकालीन फार्मूला क्या है

कृषि उपज निर्धारण के लिए पैसेवारी विशेष पद्धति या फार्मूला है. पूरे महाराष्ट्र में 150 करोड़ हेक्टयरों को चार हज़ार मंडल में विभाजित किया गया है. साधारणत: एक मंडल में 10 गांवों को शामिल किया जाता है. इन मंडलों से राज्य की 27 हज़ार ग्राम पंचायतों को भी जोड़ा गया है. हर साल सरकार राज्य में कृषि उपज की स्थिति का आकलन करने की ज़िम्मेदारी मंडल अधिकरियों को सौंपती है. मंडल अधिकारी गांव के स्तर पर पैसेवारी निकालने के लिए समिति का गठन करता है. मंडल अधिकारी इस समिति का अध्यक्ष होता है और समिति के सदस्यों में सरपंच, पुलिस पाटिल, महिला कृषक, कम खेती भू-धारक किसान को शामिल किया जाता है. यही समिति कृषि उपज की दृष्टि से न के बराबर खेतिहर ज़मीन (हलकी), मध्यम उपज वाली खेतिहर ज़मीन और उत्तम (भारी) खेतिहर ज़मीन का सर्वेक्षण करती है. इस सर्वे के तहत 10 बाय 20 या 10 बाय 10 की जगह पर होने वाली कृषि उपज को आधार मान कर पैसेवारी का आकलन किया जाता है. 10 बाय 20 या 10 बाय 10 ज़मीन के टुकड़ों पर कपास, ज्वारी, मूंग, तुअर व अन्य फ़सलों की उपज के आधार पर ही हेक्टयर के हिसाब से कुल उपज का अनुमान लगाया जाता है. इसी गणितीय फार्मूले के आधार पर गांव में होने वाली उपज तय की जाती है. इस उपज से दस साल पहले होने वाले उत्पादन की तुलना की जाती है. उसके बाद इस तुलनात्मक दृष्टि से पैसेवारी तय की जाती है. मिसाल के तौर पर वर्ष 2001 में 10 बाय 10 की खेतिहर ज़मीन पर 40 किलो उपज किसान ने प्राप्त की और वर्ष 2011 में भी 40 किलो उपज प्राप्त हुई तो उसे 100 प्रतिशत उपज माना जाएगा. इस ब्रिटिशकालीन पद्धति में 10 पूर्व की बीजों की जाति और दस साल के अंतराल के मध्य बीजों संकरित संस्करण से कृषि उपज में होने वाली घट-बढ़ के तथ्य को पूरी तरह नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है. इसके अलावा पैसेवारी तय करने के दौरान इस बात को भी ध्यान में नहीं रखा जाता है कि दस सालों की अवधि में उस क्षेत्र में अच्छी बारिश, अकाल, प्राकृतिक आपदाओं का ज़िक्र तक नहीं किया जाता है. लिहाज़ा जिन गांवों में कृषि उपज 40 प्रतिशत भी होती है तो ब्रिटिशकालीन पद्धति के अनुसार पैसेवारी 100 प्रतिशत मान ली जाती है. महाराष्ट्र में चालू आर्थिक वर्ष में पैसेवारी के लिहाज़ से केवल 1 हज़ार 767 गांवों में प्रतिशत से कम उपज होने का अनुमान व्यक्त किया गया है. उसमें भी नासिक के 1130 गांव, औरंगाबाद के 23 गांव और पुणे 614 गांवों को शामिल किया गया है. हालांकि दोषपूर्ण पद्धति से निकाली गई पैसेवारी के लिहाज़ से अमरावती और नागपुर विभाग गांवों की कृषि उपज की पैसेवारी 50 प्रतिशत से अधिक ठहराकर आर्थिक मदद से बाहर कर दिया गया है. हक़ीक़त यह है कि अमरावती और नागपुर विभाग के किसानों की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है. दरअसल वर्तमान में पैसेवारी का फार्मूला तय करने के लिए 10 बाय 20 या 10 बाय 10 की ज़मीनी टुकड़े की जगह एकड़ को मानक माना जाना चाहिए. इस पुराने फार्मूले की सबसे अधिक मार पड़ती है मझोले और छोटे किसानों पर. इसकी वजह यह है कि पैसेवारी का आकलन करने के लिए जिन ज़मीनों का चयन किया जाता है अधिकतर वे ज़मीन बड़े किसानों की रहती है. इसी पद्धति की ख़ामियों में छिपा है मध्यम-छोटे किसानों की आर्थिक बदहाली का हाल, क्योंकि किसानों की हालत चिंताजनक होने के बाद भी कृषि उपज पैसेवारी के हिसाब से 100 प्रतिशत दर्शायी जाती है. गुलामी की प्रतीक 150 वर्षीय पुरानी पद्धति से तय की गई पैसेवारी के आधार पर ही कृषि ज़मीन की महसूल तय किया जाता है. कर्ज वसूली की जाती है. पानी कर व संपत्ति कर का निर्धारण किया जाता है और अगले वर्ष में कृषि ऋण वितरित करने की नीति तय की जाती है. इस वजह से किसानों से बैंक सख्ती से क़र्ज़ वसूली करने का अभियान शुरू करते हैं. इस दोषपूर्ण पद्धति से विदर्भ व अन्य जगहों में किसानों की आर्थिक हालत में निरंतर गिरावट आ रही है, जिससे क़र्ज़ में डूबे किसान आत्महत्या की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं. वहीं सरकार इस पद्धति की ख़ामियों को दूर करने की बजाय त्वरित राजनीतिक फ़ायदों के लिए राहत राशि या पैकेज की घोषणा करने में ही किसान की भलाई मानती है. इस वजह से कृषि प्रधान इस देश में खेतीबाड़ी को अब घाटे का सौदा माना जाने लगा है.

feedback@chauthiduniya.com

सामाजिक न्याय विभाग घोटाले पर पर्दा डाल रहा है

हमारी सरकारें अपने कदाचारों को छुपाने के लिए क्या-क्या उपाय नहीं अपनाती है. समय आने पर अपनी ही नीति को बदल देती है. ऐसे उदाहरण अक्सर हमारे सामने आते रहते हैं. इसका ताज़ा उदाहरण है राज्य का सामाजिक न्याय विभाग, जिसने शिष्यवृत्ति प्रदान करने के विषय में नया आदेश निकाल कर पिछले दस वर्ष में हुए घोटालों को ढकने का नया रास्ता निकाला है. अपने नए आदेश में सामाजिक न्याय विभाग ने कहा है कि सरकारी कोटे के तहत प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को ही शिष्यवृत्ति यानी फ्रीशिप मिलेगी, लेकिन सवाल यह है कि पिछले दस साल में करोड़ों के घोटालों का क्या होगा? उसके लिए ज़िम्मेदार अधिकारियों, संस्था संचालकों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी कि नहीं? वर्धा में हुए क़रीब 50 करोड़ के शिष्यवृत्ति घोटाले में सामाजिक न्याय विभाग ने कोई ठोस क़दम क्यों नहीं उठाया? वर्धा के अलावा अन्य ज़िलों में शिष्यवृत्ति वितरण में हुए फ़र्ज़ीवाड़े की जांच क्यों नहीं कराई गई? आख़िर पिछले दस वर्षों में सामाजिक न्याय विभाग ने तक़रीबन करोड़ों-अरबों रुपये की शिष्यवृत्ति का वितरण किया है. वर्ष 2011 में चौथी दुनिया के 23 से 29 मई के अंक में उच्च शिक्षण संस्थाओं का फ़र्ज़ीवाड़ा शीर्षक से वर्धा में हुए शिष्यवृत्ति घोटाला उजागर किया था. इस घोटाले में वर्धा ज़िले के सभी उन वरिष्ठ नेताओं व कथित शिक्षा महर्षियों की शिक्षण संस्थाओं के नाम शामिल थे, जो इस घोटाले के बल पर लखपति से करोड़पति बन गए, लेकिन समाज कल्याण विभाग ने शिष्यवृत्ति घोटाले के दोषियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की बजाय उस अधिकारी का ही तबादला कर दिया था जिसकी तत्परता से यह मामला उजागर हुआ था. इसके अलावा तथाकथित शिक्षण महर्षियों के करोड़पति बनने के रहस्य को उजागर करते हुए एस एफ आई की छात्र नेता कल्पना भोयर ने सरकार को एक चिट्ठी लिखी थी. इस चिट्ठी में भी बोगस छात्रों के नाम पर करोड़ों की शिष्यवृत्ति के गोरखधंधे का उल्लेख किया गया था. इसके बाद भी सरकार ने शिष्यवृत्ति घोटाले के दोषियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की. वहीं समाज कल्याण मंत्री शिवाजीराव मोघे ने राजनीतिक दबाव में समाज कल्याण अधिकारी आर एस पांडे का की तबादला कर दिया, जिसने इस पूरे गोलमाल में शामिल अपने विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत को सामने लाने का साहस किया था और दोषी संस्था संचालकों की गड़बड़ी को रोकने के लिए एफआईआर दर्ज कराने का क़दम उठाया था. हालांकि वर्धा के सारे नेताओं ने मामले को दबाने के लिए पांडे का ही ज़िले से बोरिया बिस्तर बांधने की व्यवस्था कर डाली. एक ही ज़िले वर्धा मात्र में 50 करोड़ शिष्यवृत्ति घोटाला हुआ तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यदि राज्य के सभी ज़िलों में जांच की जाती तो कितना बड़ा घोटाला सामने आ सकता था. अब सरकार ने दस साल में हुए हज़ारों करोड़ों के शिष्यवृत्ति घोटाले पर पर्दा डालने के लिए नया आदेश निकाला है. वर्ष 2001 से व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत लाखों विद्यार्थियों को सामाजिक न्याय विभाग ने करोड़ों-अरबों रुपये की शिष्यवृत्ति का वितरण किया है. व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में शिष्यवृत्ति मिलने की बात सामने आने के बाद राज्य में व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाने वाली संस्थाओं के लिए भरपूर फ़सल काटने का मौसम आ गया था. उसके बाद तो संस्था संचालकों ने बोगस विद्यार्थी दिखा कर सरकार के ख़ज़ाने में डकैती डालना शुरू कर दिया. तबसे यह दौर शुरू हो गया था कि 1 हज़ार 117 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में से 4-6 कोर्स शुरू करना और उसमें पढ़ने वाले बोगस विद्यार्थियों की संख्या बताना और अधिक से अधिक शिष्यवृत्ति वसूल करने का कारोबार कई तकनीकी संस्था संचालकों ने चला रखा था. इससे विद्यार्थियों को तो कोई आर्थिक लाभ नहीं मिला, लेकिन संस्था संचालक लखपति से करोड़पति व अरबपति ज़रूर बन गए. अब सामाजिक न्याय विभाग के नए आदेश के जारी किए जाने से 1 हज़ार 117 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत क़रीब तीन लाख विद्यार्थियों को शिष्यवृत्ति के तहत मिलने वाली स्कॉलरशिप से वंचित होना पड़ेगा. विशेष बात यह है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के माध्यम से होने वाले प्रवेश (मेडिकल, इंजीनियरिंग, एमबीए, एमसीए, आर्किटेक्चर, कृषि आदि संबंधी विषयों के पाठ्यक्रमों के लिए) में सरकारी कोटा रहता है. इस सरकारी कोटे के तहत प्रवेश लेने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति, विशेष रूप से पिछड़े और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को शिष्यवृत्ति की सुविधा मिलती है. राज्य तकनीकी शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों में किसी तरह का सरकारी कोटा निर्धारित न होने से उनमें प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को शिष्यवृत्ति के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता व आर्थिक छूट से वंचित होना पड़ेगा. सामाजिक न्याय विभाग ने स्पष्ट किया है कि नए आदेश को लेकर किसी तरह की गड़बड़ी, भ्रम न हो इसलिए पहले के सभी आदेश रद्द किए जा रहे हैं और नए आदेश के तहत ही शिष्यवृत्ति की सुविधा विद्यार्थियों को दी जाएगी. तकनीकी शिक्षा परिषद के तहत संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और इसी तरह अल्पावधि के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए किसी तरह की शिष्यवृत्ति लागू नहीं होती है. इस तरह का उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग का स्पष्ट आदेश होने के बाद भी वर्ष 2001-2002 से लेकर अब तक सामाजिक न्याय विभाग ने करोड़ों की शिष्यवृत्ति का वितरण कर डाला है. इसके लिए केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान का उपयोग किया गया है, लेकिन दस साल में उच्च व तकनीकी शिक्षा परिषद के नियमों-निर्देशों को नज़रअंदाज़ कर शिष्यवृत्ति के नाम पर सरकारी तिजोरी को लुटाने एवं लूटने वालों के ख़िलाफ़ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है. लगता है कि विभाग नया आदेश जारी कर शिष्यवृत्ति की रक़म पचाने वाले करोड़पति बने शिक्षा महर्षियों को बचाना चाहता है.

आंदोलन की चेतावनी

महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय शिक्षण संस्था परिषद ने सामाजिक न्याय विभाग के शिष्यवृत्ति संबंधी नए आदेश पर नाराज़गी ज़ाहिर की है. व्यवसाय शिक्षण संस्था परिषद ने व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को शिष्यवृत्ति देने और संबंधित संस्थानों को शिक्षण शुल्क और परीक्षा शुल्क लागू करने देने की मांग की है. इस संबंध में परिषद के अध्यक्ष दीपांकर तेलगोटे ने मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड़ और सामाजिक न्याय विभाग के सचिव दिनेश वाघमारे को पत्र लिख कर नए आदेश को रद्द करने की मांग की है. उनका मत है कि शासन द्वारा शिष्यवृत्ति रद्द करने का निर्णय लेना विद्यार्थी और संस्था संचालकों को परेशान करने वाला है. यह व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों पर अन्याय है. इस आदेश को यदि 15 दिन के अंदर सरकार रद्द नहीं करती है तो आक्रामक आंदोलन छेड़ा जाएगा.

महाराष्ट्र ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया बिहार झारखंड

दिल्ली, 27 फरवरी-04 मार्च 2012

www.chauthiduniya.com

सेहत के महकमे में लूट की महागाथा

समय के साथ अस्पतालों से डॉक्टर व दवाइयां ग़ायब होती गईं और कल्याणकारी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गईं. अस्पताल प्रशासन दलालों की मदद से ग़रीब मरीजों का हक़ मार रहा है और ग़रीब इलाज न होने के कारण बीमारी से मर रहे हैं. चौथी दुनिया ने बिहार के कई ज़िलों में अस्पतालों के मौजूदा हालात व वहां फैले भ्रष्टाचार को जांचने व परखने की कोशिश की.

सरोज सिंह

अभी ज़्यादा वक़्त नहीं बीता, जब सूबे के स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे ने डॉक्टरों के हाथ काटने की धमकी दे डाली थी. हालांकि बाद में हंगामा होने पर उन्होंने कहा कि मैंने मुहावरे के तौर पर हाथ काटने की बात की थी. दरअसल, हाथ काटने का यह बयान एक सार्वजनिक समारोह में मंत्री महोदय के सामने बिहार विधान परिषद के सभापति ताराकांत झा द्वारा यह कहे जाने से उपजा बताया जा रहा है, जिसमें झा ने सेहत महकमे में भारी कमियों की ओर इशारा किया था. दरअसल, सभापति महोदय के इस बयान से चौबे काफ़ी आहत हुए. हताशा इतनी बढ़ी कि उन्होंने डॉक्टरों के हाथ काटने की बात तक कह डाली. लेकिन तल्ख़ सच्चाई यह है कि मंत्री महोदय से कहीं ज़्यादा सूबे के मरीज़ हताश व परेशान हैं. अस्पतालों का मौजूदा हाल बता रहा है कि मरीज़ व उनके परिजन रोज़ाना कितनी ज़लालत व हताशा झेल रहे होंगे. शुरू में दवाओं एवं डॉक्टरों की उपलब्धता और बहुत सारी कल्याणकारी योजनाओं की वजह से आम लोगों का रुझान सरकारी अस्पतालों की ओर बढ़ा. लेकिन समय के साथ अस्पतालों से डॉक्टर एवं दवाइयां ग़ायब होती गईं और कल्याणकारी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गईं. अस्पताल प्रशासन दलालों की मदद से ग़रीब मरीज़ों का हक़ मार रहा है और ग़रीब इलाज न होने के कारण बीमारी से मर रहे हैं. चौथी दुनिया ने बिहार के कई ज़िलों में अस्पतालों के मौजूदा हालात एवं वहां फैले भ्रष्टाचार को जांचने-परखने की कोशिश की. जो सच्चाई सामने आई, वह परेशान और हैरान करने वाली है.

राज्य सरकार द्वारा विधानसभा से लेकर विभिन्न राजनीतिक मंच पर चीख़-चीख़कर राज्य की बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था का दंभ भरा जाता है, लेकिन बिहार के सभी स्वास्थ्य केंद्रों की ज़मीनी हक़ीक़त पर अगर नज़र डाली जाए तो यह प्रमाणित हो जाएगा कि सरकार की कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का अंतर है. राज्य का शायद ही कोई ज़िला होगा, जहां की स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हो. किसी ज़िले में अगर पर्याप्त स्वास्थ्य केंद्र और उपस्वास्थ्य केंद्र हैं तो डॉक्टरों तथा परिचारिकाओं का घोर अभाव है. कहीं-कहीं अगर यह व्यवस्था उपलब्ध है, तो दवा का अभाव सरकार को मुंह चिढ़ाने के लिए काफ़ी है. बिहार के अन्य ज़िलों की बातों को अगर कुछ देर के लिए नज़रअंदाज़ कर भी दिया जाए तो भी राजधानी पटना का हाल भी देखा नहीं जाता है. पीएमसीएच में प्रवेश करते ही यह लगने लगेगा कि अन्य व्यवस्था की बात तो दूर सफ़ाई व्यवस्था के प्रति भी अस्पताल प्रशासन गंभीर नहीं है. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी एनआरएचएम में घोटाले से मुज़फ्फ़रपुर भी अछूता नहीं रहा. बताया जा रहा है कि यहां भी मरीज़ों की न तो जांच कराई गई और न ही दवा दी गई, फिर भी उनके नाम से भुगतान लिया जा रहा है. सदर अस्पताल के उपाधीक्षक बी एन झा ने मामला सामने आने पर भुगतान पर रोक लगाते हुए पिछले तीन माह की रिपोर्ट मांगी है. ग़ौरतलब है कि पिछले तीन माह में 1500 महिलाओं को पूरी राशि का वितरण किया गया है. लदौरा निवासी लाडली ख़ातून की डिलीवरी 21 जनवरी, 2012 को हुई, जबकि इसकी जांच 24 जनवरी, 2012 को कराने की बात काग़ज़ पर है. सोनबरसा की ख़ुशबू देवी की डिलीवरी 16 जनवरी, 2012 को हुई है तथा जांच भी इसी दिन दिखाई गई है. सारण ज़िले में परिवार नियोजन का लक्ष्य काफ़ी पीछे छूट गया है. इस वित्तीय वर्ष के लिए 35,000 का लक्ष्य रखा गया था. लेकिन अभी तक लक्ष्य के आसपास भी नहीं पहुंचा जा सका है, जबकि महज़ कुछ ही दिनों में यह वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाएगा. गोपालगंज में सर्पदंश निरोधक दवा न रहने के कारण अभी तक दर्जनों लोगों की जानें जा चुकी हैं. इसके बावजूद अभी तक सर्पदंश की दवा यहां उपलब्ध नहीं कराई गई है. हालात का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुछ माह पूर्व चांदपरना गांव में सर्पदंश का शिकार होकर मौत की आग़ोश में समाने वाले एक मृतक को देखने गए जदयू विधायक मंजीत सिंह को भारी ज़लालत का सामना करना पड़ा था. ग्रामीणों के कोप का शिकार हुए विधायक ने इस तरह की स्थिति से स्वास्थ्य मंत्री के साथ-साथ मुख्यमंत्री को भी अवगत कराया था. मामले की गंभीरतता को भांपते हुए स्वास्थ्य मंत्री द्वारा तत्कालीन सिविल सर्जन को निलंबित कर दिया गया था. अन्य कई समस्याएं सुरसा के समान मुंह बाए खड़ी हैं, लेकिन समस्याओं के निपटारे के लिए शायद कोई आगे आने को तैयार नहीं है. उधर, छपरा सदर अस्पताल का पिछले दिनों निरीक्षण करने पहुंचे स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने दो दिनों के अंदर आईसीयू यूनिट को चालू करने का आदेश दिया था. छपरा सदर अस्पताल में ही प्रेसवार्ता के दौरान विनय कुमार ने स्पष्ट कर दिया था कि दस दिनों के अंदर आईसीयू यूनिट का चालू होना तय है, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई कार्रवाई न होने से विभिन्न दुर्घटनाओं में घायल लोगों की मौत का सिलसिला अनवरत जारी है. पूर्णिया ज़िले की स्वास्थ्य व्यवस्था पर अगर नज़र डाली जाए तो ऐसा लगेगा कि भ्रष्टाचार, विवाद और कुव्यवस्था पूर्णिया सदर अस्पताल का अंग बनकर रह गया है. सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष के नेता तक का कहना है कि कई आरोपों से घिरे सिविल सर्जन रामचरित्र मंडल के विरुद्ध जब तक कार्रवाई नहीं होगी, उनका तबादला नहीं होगा, तब तक स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार आना मुश्किल रहेगा. जदयू किसान सभा के प्रदेश सचिव गौतम वर्मा ने सिविल सर्जन के विरुद्ध कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मंडल ने दवा घोटाले के नाम पर सरकार को करोड़ों रुपये का चूना तो लगाया ही है, बंध्याकरण के नाम पर फ़र्ज़ी महिलाओं का नाम दिखाकर पैसों की निकासी भी की है. प्रदेश सचिव की बातों पर अगर विश्वास करें तो अमौर रेफरल अस्पताल में आठ लाख एवं नगर स्वास्थ्य केंद्र में छह लाख रुपये की हेराफेरी का आरोप सीएस पर है. खगड़िया और बेगूसराय ज़िले की स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल भी सही नहीं है. इन दोनों ज़िलों के सदर अस्पताल सहित अन्य स्वास्थ्य केंद्र के आसपास दलालों की सक्रियता देखी जा सकती है. खगड़िया सदर अस्पताल के आसपास सक्रिय रहने वाले दलाल भोले-भाले लोगों को बेहतर चिकित्सा का झांसा देकर किसी झोलाछाप चिकित्सक के पास ले जाते हैं और उनका जमकर शोषण किया जाता है. एक नए अस्पताल भवन का निर्माण होने के बाद लोगों को लगा था कि खगड़िया की स्वास्थ्य व्यवस्था में चार चांद लगना तय है, लेकिन अभी तक नया भवन विभाग को सौंपा ही नहीं गया है. दूसरी तरफ़ विरोधी दल के मुख्य सचेतक सह परबत्ता विधायक राकेश कुमार उर्फ़ सम्राट चौधरी का कहना है कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल किसी से छुपा नहीं है. सरकार दावे तो बहुत कर रही है, लेकिन पीएचसी हो या सदर अस्पताल, कहीं भी पर्याप्त मात्रा में दवा उपलब्ध नहीं है. डॉक्टर बहाल भी नहीं हुए, लेकिन वह सरकार से पगार पा रहे हैं यानी डॉक्टर बहाली के नाम पर भी जमकर लूट का खेल खेला गया. इस तरह से सभी स्वास्थ्य योजनाओं के नाम पर लूट मची है. बिहार के किसी भी ज़िले में अत्याधुनिक अस्पताल का न होना इस बात को प्रमाणित करता है कि सरकार बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था बहाल कराने के मामले में काफ़ी पीछे चल रही है. वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए स्वास्थ्य विभाग को तीस करोड़ तथा यूनिसेफ द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रम के लिए पचास लाख रुपये मोतिहारी ज़िले को प्राप्त हुए थे. इतनी बड़ी राशि ख़र्च होने के बावजूद सबसे निचले पायदान पर पहुंचना यह साबित करता है कि केवल राशि की बंदरबाट हुई है.

कांग्रेस बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अनिल सुलभ का मानना है कि राज्य सरकार आंकड़ों के खेल में माहिर है. बिहार के 90 प्रतिशत स्वास्थ्य और उपस्वास्थ्य केंद्र में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है. बिहार नक़ली दवाओं का बाज़ार बनकर रह गया है. जब तक नक़ली बाज़ार पर क़ाबू नहीं पाया जाएगा तब तक स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार किसी भी क़ीमत पर संभव नहीं है. सरकार आंकड़ों का खेल दिखाने के बजाय ग्रामीण इलाक़ों में नियोजित किए गए चिकित्सकों का मानदेय बढ़ाते हुए अतिरिक्त चिकित्सा सेवा बहाल कराए. बक्सर के राजपुर तथा इठाढ़ी प्रखंडों के 6-6 बेड वाले अस्पतालों में प्रतिदिन 18-20 प्रसव काग़ज़ में दिखाकर अनुदान राशि की बंदरबांट की जा रही है. राजद के भाई विरेंद्र भी स्वास्थ्य व्यवस्था से ख़ासे नाराज़ हैं. इनका कहना है कि राज्य सरकार अख़बार और रेडियो के बल पर चल रही है. सरकार का स्वास्थ्य व्यवस्था या किसी अन्य व्यवस्था से कोई सरोकार नहीं है. वह केवल अख़बार, रेडियो और टीवी पर आंकड़े प्रस्तुत कर अपनी पीठ ख़ुद थपथपा रही है. बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पर जितनी भी राशि मिल रही है, वह सरकारी नुमाइंदे और दलाल गटक रहे हैं. सवाल यह है कि भरोसा हासिल करने के बाद सेहत का यह महकमा आख़िर भरोसा खो क्यों रहा है? ग़रीब मरीज़ों के लिए बस एक रास्ता सरकारी अस्पताल की ओर जाता है. अगर यह रास्ता भी बंद हो गया तो वे बेमौत ही मर जाएंगे. इस आलेख का मक़सद सरकार का ध्यान इसी रास्ते को दुरुस्त करना है. उम्मीद करते हैं कि ग़रीब मरीज़ों के लिए रास्ता ज़रूर आसान होगा.

feedback@chauthiduniya.com

डॉक्टर बहाल भी नहीं हुए और वेतन पा रहे हैं. स्वास्थ्य योजनाओं के नाम पर पूरे बिहार में लूट मची है. दवा व डॉक्टर के अभाव में ग़रीब मरीज़ मर रहे हैं.

-सम्राट चौधरी

सरकार केवल एक्सपायरी दवाओं की ख़रीद में लगी है और पैसे का बंदरबांट कर इन दवाओं को गड्ढे में डाल देती है. नीतीश सरकार पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने में एक्सपर्ट है.

-नवल यादव

बिहार नक़ली दवाओं का बाज़ार बन गया है. स्वास्थ्य केंद्रों पर बुनियादी सुविधाएं भी न होने से मरीज़ बेहाल हैं. इन मरीज़ों की आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है.

-अनिल सुलभ

सेहत का महकमा चौपट है. ग़रीब मरीज़ों के नाम पर जो पैसा दिया जा रहा है, उसे सरकारी नुमाइंदे एवं दलाल गटक रहे हैं. यह सब पटना से लेकर ज़िलों में बैठे अफ़सर व दलाल कर रहे हैं.

- भाई वीरेंद्र

चौथी दुनिया

इस योजना में बीपीएल परिवारों को हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराकर तीस हज़ार रुपये तक का इलाज मुफ़्त कराने लाभ दिया गया है और इस रक़म को दलालों और माफ़ियाओं की नज़र लग गई है.

बक्सर के राजपुर तथा इठाढ़ी प्रखंडों के 6-6 बेड वाले अस्पतालों में प्रतिदिन 18-20 प्रसव काग़ज़ में दिखाकर अनुदान राशि की बंदरबांट की जा रही है.

चौथी दुनिया

अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र खोलने में फिसड्डी

मरीज़ों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के बाद भी राज्य में पर्याप्त नए अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र नहीं खुल रहे हैं. यह इस बात का प्रमाण है कि बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध कराने के मामले में बिहार कितना सुस्त है. इतना ही नहीं स्वास्थ्य ढांचे की समीक्षा के क्रम में भी यह पाया गया है कि बिहार में ग़रीब मरीज़ काफ़ी उम्मीदों के साथ सरकारी अस्पताल तो पहुंच रहे हैं, लेकिन नए अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र खोलने के मामले में बिहार फिसड्डी है.

स्वास्थ्य के मामले में बिहार के अव्वल रहने की बात तब पीछे छूट जाती है, जब स्वास्थ्य ढांचे के संदर्भ में की गई समीक्षा की रिपोर्ट पर नज़र पड़ती है. मरीज़ों के मामले में अव्वल स्थान रखने वाला बिहार नए अस्पताल खोलने के मामले में क्यों पीछे है, यह तो बहस का बेहद गंभीर मसला है, लेकिन स्वास्थ्य ढांचे के मामले में पिछड़े पाए गए बिहार में अस्पताल और उप स्वास्थ्य केंद्र भी ज़रूरत के लिहाज़ से आधे हैं. रेफरल अस्पताल की संख्या सहित अन्य मामले में भी बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था काफ़ी पीछे है. ज़रूरत के मुक़ाबले महज़ 11.5 प्रतिशत रेफरल अस्पताल ही बिहार में हैं. हद तो तब दिखती है, जब यह जानकारी मिलती है कि जच्चा-बच्चा के बेहतर स्वास्थ्य के लिए शुरू किए गए जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) की सेहत बिगड़ी हुई है. हालांकि बात अलग है कि पिछले कुछ वर्षों में राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था में काफ़ी हद तक सुधार हुआ है. इसका नतीजा भी सामने आया है. बीते वर्ष 2008 तक राज्य के अस्पतालों में प्रतिवर्ष आठ लाख मरीज़ भर्ती हुए, लेकिन वर्ष 2011 तक संख्या में तीन गुना इज़ाफ़ा हुआ. आठ लाख से मरीज़ों की संख्या बढ़कर प्रतिवर्ष 24 लाख तक पहुंच गई है. 24 लाख में चार लाख महिला मरीज़ों ने विभिन्न अस्पतालों में भर्ती होकर बच्चों को जन्म दिया. इस तरह की तस्वीर वर्ष 2005 से शुरू किए गए राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन (एनआरएचएम) के दौरान हुए बदलाव की समीक्षा (सीआरएम-5) के दरम्यान नज़र आई. समीक्षा के दौरान ही यह तथ्य भी सामने आया कि बिहार के विभिन्न ज़िलों में पर्याप्त अस्पताल नहीं हैं. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अनुपात के मुताबिक़ जहां 45 फ़ीसदी हैं, वहीं उप स्वास्थ्य केंद्र 53 फ़ीसदी. सबसे दुखद स्थिति तो रेफरल अस्पतालों की है. 604 के मुक़ाबले महज़ 70 रेफरल अस्पताल का होना सूबे की स्वास्थ्य व्यवस्था को मुंह चिढ़ाने के लिए काफ़ी है. बहरहाल, संबंधित विभाग के पदाधिकारियों द्वारा इस संदर्भ में चाहे जो भी दलील दी जाए, लेकिन हक़ीक़त यही है कि कुल 2915 निर्माण कार्य को मंज़ूरी मिलने के बाद भी अभी तक महज़ 872 कार्यों का पूरा हो पाना इस बात का पुख़्ता करता है कि बिहार नए अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र निर्माण के मामले में बेहद सुस्त है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

ख़र्च 31.5 करोड़, उपलब्धि शून्य

यूनिसेफ के प्रशिक्षण में घोटालों का खेल

इंतेज़ारुल हक़

ख़र्च साढ़े तीस करोड़ व उपलब्धि शून्य. यह हाल है मोतिहारी स्वास्थ्य विभाग का. कभी पूरे बिहार में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने में सफल रहा इस ज़िले का स्वास्थ्य विभाग इन दिनों रैंकिंग में पूरे बिहार में 36वें स्थान पर पहुंच गया है. वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए स्वास्थ्य विभाग को तीस करोड़ रुपये तथा यूनिसेफ द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम के लिए पचास लाख रुपये ज़िले को प्राप्त हुए थे. इसके बावजूद सबसे निचले पायदान पर पहुंचना यह साबित करता है कि केवल राशि की बंदरबाट हुई है. राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा दिए गए निर्देशों के विपरित कार्य करने वाले सिविल सर्जन कामेश्वर मंडल ने अपने कार्यालय के कर्मचारियों को ज़िला स्वास्थ्य समिति की संचिकाओं को देखने के लिए तैनात कर दिया है. ज़िला कार्यक्रम प्रबंधक के बार-बार अनुरोध के बावजूद सीएस ने उन्हें अपने कार्यालय में नहीं लिया, जबकि राज्य स्वास्थ्य समिति के निदेशक डॉ. केपी रमैया ने अपने पत्रांक एसएचबीबी एडमिन/74/2005/4018 दिनांक 06.07.2007 में स्पष्ट निर्देश दिया है कि ज़िला स्वास्थ्य समिति के कार्यों में किसी भी सूरत में सरकारी कर्मचारियों को तैनात नहीं करना है. इस आदेश की अवहेलना करते हुए सीएस ने अपने स्टैनों मनोज कुमार शाही को अनुबंध आधारित चिकित्सा पदाधिकारियों की नियुक्ति एवं अवधि विस्तार से संबंधित संचिकाएं लिपिक नरेश कुमार को, एएनएम ग्रेड नर्स की नियुक्ति एवं अवधि विस्तार से संबंधित सभी संचिकाएं, वरीय लिपिक सुशील कुमार व मृत्युंजय कुमार को ज़िला स्वास्थ्य समिति की दवा व उपस्कर क्रय से संबंधित संचिकाएं राजीव कुमार को वित्तीय संचिकाएं, अखिलेश्वर पांडेय को आधारभूत संरचना एवं भूमि दान से संबंधित संचिकाएं प्रशिक्षक शिवशंकर कुमार को संचिकाओं का संधारण, भंडारपाल चंद्रमोहन प्रसाद श्रीवास्तव को भंडार से संबंधित सभी संचिकाएं, राजा राम को ज़िला एवं प्रखंड स्तरीय सभी प्रशिक्षण से संबंधित संचिकाएं देखने के लिए तैनात किया गया है. ज़िला मुख्यालय स्थित सदर अस्पताल की सफ़ाई का मामला हो या मरीज़ों के इलाज एवं भोजन का या बिजली आपूर्ति के लिए जनरेटर का या फिर यूनिसेफ द्वारा चलने वाले नवजात शिशु एवं बाल्यकाल बीमारियों की समेकित देखभाल कार्यक्रम का, इन तमाम योजनाओं में लूट मची हुई है. सफ़ाई व्यवस्था के नाम पर केवल ख़ानापूर्ति की जाती है. मेनू का हाल तो और बुरा है. मरीज़ों को कभी भी मेनू के अनुसार भोजन नहीं दिया जाता है, जिसके कारण हंगामा भी होता रहता है. डीएम के बार-बार आदेश के बावजूद यहां तैनात चिकित्सक निजी सेवा में अधिक व्यस्त रहते हैं और बहुत कम समय मरीज़ों को दे पाते हैं. बीती 9 फरवरी को चिकित्सकों की लापरवाही के कारण रामपुर खजुरिया से प्रसव कराने आई भागवती देवी नामक महिला की हालत चिकित्सक न रहने के कारण काफ़ी ख़राब हो गई थी और बाद में उसे निजी नर्सिंग होम का सहारा लेना पड़ा. इस दौरान इसके परिजनों ने हंगामा भी किया था. उधर यूनिसेफ द्वारा चलाया जा रहा नवजात शिशु एवं बाल्यकाल बीमारियों की समेकित देखभाल कार्यक्रम सिविल सर्जन समेत अस्पताल के कई चिकित्सकों के लिए कमाई का ज़रिया बना हुआ है. साल भर में 44 बैचों में चलने वाला यह प्रशिक्षण इस बार दो माह पहले ही समाप्त कर दिया गया है. उक्त प्रशिक्षण को पहले प्रखंड स्तरीय करना था, इसके बाद ज़िला स्तर पर होना चाहिए था, किंतु ऐसा नहीं हुआ और सीधे ज़िला स्तर पर आयोजित कर क़रीब पचास लाख रुपये की बंदरबाट की गई. प्रशिक्षण में प्रशिक्षक के रूप में चिकित्सा पदाधिकारियों, बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों, महिला पर्यवेक्षकों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को शामिल करना चाहिए था, किंतु यह भी नहीं हुआ और सभी नियमों को ताक़ पर रखकर प्रशिक्षण के नाम पर ख़ानापूर्ति की गई. इतना ही नहीं उक्त कार्यक्रम के नोडल पदाधिकारी अस्पताल एवं ज़िला स्वास्थ्य समिति के किसी अधिकारी को बनाया जाना चाहिए था, किंतु सीएस इस मामले में भी काफ़ी आगे निकले और ख़ुद नोडल पदाधिकारी बन गए. अस्पताल के सूत्रों के अनुसार एक बैच पर एक लाख 36 हज़ार रुपये का आवंटन मिला था. एक बैच में चौबीस सेविकाएं प्रशिक्षण में शामिल हुईं. चार बैच एक साथ चले और 96 सेविकाएं प्रशिक्षित हुईं. प्रशिक्षण पूर्ण रूप से आवासीय था और प्रशिक्षण के दौरान चौथा, पांचवां व सातवां दिन आंगनवाड़ी केंद्रों को भ्रमण कराने का निर्देश था, किंतु ऐसा नहीं हुआ और पुरानी गाड़ी का फोटो दिखा कर राशि का बंदरबाट कर लिया गया. प्रत्येक गाड़ी का किराया एक हज़ार निर्धारित है. कई सेविकाओं ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि आख़िरी दिन उनसे सादे काग़ज़ पर दस्तख़त भी कराया जाता है. इतना ही नहीं प्रशिक्षण आवासीय होने के बावजूद मात्र बीस से पच्चीस सेविकाएं ही ठहरती थीं और 96 का बिल बनता था. हालांकि अस्पताल की व्यवस्था सुधारने के लिए साप्ताहिक समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी अभिजीत सिन्हा द्वारा सिविल सर्जन कामेश्वर मंडल को दर्जनों बार आवश्यक हिदायतें दी जा चुकी हैं. कई बार फटकार भी लगी, किंतु कोई सुधार नहीं हुआ. दूसरी तरफ़ ढाका के निर्दलीय विधायक पवन जायसवाल ने आउटसोर्सिंग के मामले में जांच कराने का मामला उठा दिया है. अस्पताल में बिजली आपूर्ति के लिए चल रहे जनरेटर, वॉर्डों की सफ़ाई में हुई गड़बड़ी की जांच कराने की बात उन्होंने कही है. कुल मिलाकर स्वास्थ्य विभाग कुव्यवस्था एवं भ्रष्टाचार को लेकर पूरे ज़िले में चर्चा का विषय बना हुआ है. दूसरी तरफ़ सिविल सर्जन मंडल ने पूछे जाने पर कुछ बताने से परहेज़ किया.

ज़िला मुख्यालय स्थित सदर अस्पताल की सफ़ाई का मामला हो या मरीज़ों के इलाज व भोजन का या बिजली आपूर्ति के लिए जनरेटर का या फिर यूनिसेफ द्वारा चलने वाले नवजात शिशु एवं बाल्यकाल बीमारियों की समेकित देखभाल कार्यक्रम का, इन तमाम योजनाओं में लूट मची हुई है. सफ़ाई व्यवस्था के नाम पर केवल ख़ानापूर्ति की जाती है.

feedback@chauthiduniya.com

एक नज़र

पंचायत सचिवालय का उद्घाटन

हटरगंज प्रखंड के उरैली पंचायत सचिवालय का उद्घाटन प्रखंड विकास पदाधिकारी छुटेश्वर दास, प्रमुख दीपा भारती, मुखिया चिंता देवी ने संयुक्त रूप से किया. प्रखंड में इस प्रकार का पहला पंचायत सचिवालय है, जो पूर्ण रूप से अस्तित्व में आया है. उद्घाटन के मौक़े पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों के साथ-साथ पंचायत समिति सदस्य मुन्नी देवी आदि उपस्थित थे.

वन क्षेत्र उजड़ने की कगार पर

हंटरगंज प्रखंड के सोनबरसा वन क्षेत्र को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अधिकारी अपने आप में किस तरह से मस्त हैं और वनक्षेत्र में सक्रिय तस्करों की चांदी कट रही है. हंटरगंज प्रखंड के उत्तरी वन क्षेत्र के रेंजर एल डी महतो के कार्यकाल में प्रखंड के अधिकांश वन क्षेत्रों पर माफ़ियाओं का क़ब्ज़ा हो गया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की स्थिति के कारण वन क्षेत्र उजड़ता जा रहा है. कई स्थानीय नेताओं ने आक्रोशित लहजे में कहा है कि रेंजर महतो के कार्यकाल में वन क्षेत्र को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया, जिसके कारण सरकार को प्रतिवर्ष लाखों का नुक़सान हो रहा है.

लवालौंग में अनाज का वितरण

लावालौंग प्रखंड के आदिम जनजाति बिरहोर व बैगा परिवारों के बीच मुफ़्त अनाज का वितरण कल्याण विभाग द्वारा किया गया. प्रखंड कल्याण पदाधिकारी गोपाल प्रसाद, ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक विश्वनाथ प्रसाद सिंह एवं पंचायत समिति सदस्य उगन साव की उपस्थिति में आदिम जनजाति के 258 परिवारों के बीच अनाज के रूप में 70 किलोग्राम चावल दिया गया.

आजसू पार्टी की बैठक संपन्न

हंटरगंज प्रखंड स्थित बोड़ा मोड़, डाकबंगला परिसर में सक्रिय छात्र संगठन आजसू की बैठक का आयोजन किया गया. आजसू के प्रखंड अध्यक्ष पप्पू कुमार की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर चतरा विधानसभा क्षेत्र से संभावित विधानसभा प्रत्याशी अशोक कुमार गहलोत आदि उपस्थित थे. इस बैठक के दौरान ही एक सौ लोगों ने भाजपा एवं राजद का दामन छोड़कर आजसू की सदस्यता ग्रहण की. मौक़े पर आजसू के केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य विनोद चंद्रवंशी, कटैया पंचायत के पंचायत समिति सदस्य शिवशंकर यादव, बासुदेव यादव, हारुण अंसारी, जावेद अंसारी, अरविंद वर्मा, सत्येंद्र कुमार दास, करमा पंचायत के उपमुखिया नरेशदत्त पाठक इत्यादि उपस्थित थे .

कृषि शिविर का आयोजन

गोगरी अनुमंडल अंतर्गत गोविंदपुर पंचायत के कन्हैया चक में कृषि शिविर का आयोजन किया गया. इसमें ज़िला कृषि पदाधिकारी रतन कुमार भगत एवं ज़िला उद्यान पदाधिकारी डॉ. राकेश कुमार द्वारा 133 किसानों के बीच बर्मी वेड का वितरण किया गया. इस अवसर पर मुखिया रामबालक सिंह, जयजय राम सिंह, रामचौधरी, सरपंच शंभू शंकर चौधरी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी नवीन कुमार, कृषि सलाहकार सदानंद तिवारी एवं तकनीकी सलाहकार निरंजन हजारी उपस्थित थे.

गंगातट पर शंकराचार्य का प्रवचन

गोगरी अनुमंडल अंतर्गत अगुआनी गंगा तट पर हो रहे रामनाम से कीर्तन महायज्ञ में प्रवचन के क्रम में धर्म प्रर्वतक जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा कि शाही के पूर्व गौरी की पूजा की जाती है, जिसमें उनके पुत्री के पति का असीम स्नेह प्राप्त होता है. हर मां-बाप को चाहिए कि पुत्री को गौरी के समान ही दामाद द्वारा सम्मान मिले. मिथलांचल की तीन चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं. इनमें पान, मखान सहित विभिन्न चीज़ें मिथिला की धरती की असीम वस्तु मानी जाती हैं.

-चौथी दुनिया ब्यूरो

रविदास जयंती मनाई

चतरा शहर स्थित किशुनपुर मोहल्ले के हरिजन टोला में राजनीतिक संगठन झाविमो अनुसूचित जाति मोर्चा के नेतृत्व में संत रविदास जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई. इस अवसर पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर झाविमो के सिमरिया विधायक जयप्रकाश सिंह भोक्ता शामिल हुए. इस अवसर पर अनुसूचित जाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष छटु सिंह भोक्ता, झाविमो के जिलाध्यक्ष बालेश्वर यादव, अनुसूचित जाति के केंद्रीय अध्यक्ष बलबीर पासवान, अनुसूचित जाति मोर्चा के महासचिव कृष्णा दास, वार्ड पार्षद नंदकिशोर भारती, झाविमो के जिला प्रवक्ता अमेश कुमार, नगर अध्यक्ष कैलाश पासवान, हंटरगंज प्रखंड अध्यक्ष राम बुझावन रजक, कुंदा प्रखंड अध्यक्ष अंबिका सिंह भोक्ता, प्रतापपुर प्रखंड अध्यक्ष विशुनदेव अंगार समेत सैकड़ों लोग उपस्थित थे .

-चंद्रेश शर्मा

महिला क्रिकेट कप पर भागलपुर का क़ब्ज़ा

गोगरी अनुमंडल अंतर्गत अंतर ज़िला महिला क्रिकेट टूर्नामेंट फाइनल मैच में भागलपुर ने मोतिहारी की टीम को कड़े मुक़ाबले में दो विकेट से पराजित कर कप पर क़ब्ज़ा जमाया. मैन ऑफ द मैच, बेस्ट बैट्समैन, वूमैन ऑफ द सीरीज भागलपुर की कप्तान शान शैफ़ अली को दिया गया. इस मौक़े पर बीडीओ नौशाद आलम एवं कार्यपालक पदाधिकारी मणि रंजन ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया, जबकि गोगरी थानाध्यक्ष सुनील कुमार ने शील्ड पर क़ब्ज़ा जमाने वाली टीम को 5000 हज़ार का पुरस्कार दिया तथा पीएल शिक्षा निकेतन के प्राचार्य की ओर से तीन हज़ार का चेक प्रदान किया गया.

-अमरेंद्र प्रताप सिंह

श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई

माघी पूर्णिमा के अवसर पर गोगरी अनुमंडल अंतर्गत गंगा तट पर श्रद्धालुओं ने गंगा में स्नान किया. इस तट पर सीताराम नाम महायज्ञ का भी आयोजन किया गया. इस पूर्णिमा के अवसर पर गंगा में स्नान करना शुभ माना जाता है तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है. इस अवसर पर ज़िला प्रशासन द्वारा काफ़ी चौकसी बरती गई, जिस कारण शांति पूर्ण ढंग से महायज्ञ संपन्न हुआ. वहीं नया गांव के रामघाट तथा गोगरी के भेलवा गंगा तट पर भी हज़ारों श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई.

-गीता कुमार

बचाव का अच्छा उपाय परहेज़ है

डॉ. सुनील कुमार अग्रवाल

डायबिटीज रोगियों की संख्या में लगातार वृद्धि होना निश्चित तौर पर बिहार जैसे ग़रीब प्रदेश के लिए गंभीर चिंता का विषय है. समय-समय पर चिकित्सक इस रोग से बचने तथा खान-पान में परहेज़ करने की हिदायत लोगों को देते रहे हैं. पटना के बेहद चर्चित फिजिशियन एवं डायबेट्रो कार्डियोलोजिस्ट डॉक्टर सुनील कुमार अग्रवाल ने डायबिटीज जैसे रोग तथा इसके बचाव पर खुलकर बातचीत की.

डायबिटीज रोग की पहचान कैसे संभव है?

बार-बार प्यास लगना, चिड़चिड़ापन, कमज़ोरी महसूस होना, वज़न में लगातार कमी आना, आंखों की रोशनी में कमी, बार-बार

ariskon Pharma Pvt.Ltd.
ASRFEN-P
Aceclofenac + paracetamol Serratiopeptidase Tab.
ECTALOPAM
Escitalopram Oxalate &Clonazepam Tablets
SILIPLEX
Silymarin, Vitamin B-Complex, Calcium & Lactic Acid Bacillus Capsules/Syp
ACOBA CAP/SYP/INJ
Methylcobalamin, Lycopene, Multivitamin Multimineral, Ginseng & Antioxidant
Carbo-XT
Ferrous Ascorbate With Folic Acid Tab.
AREX
Dextromethorphan,Guaiphenesine Ammonium Chloride Cough Syp.
MENSOSET
Her Tonic With Ashoka 1800mg.
MUSTAL
Levocetirizine Hydrochloride Montelukast Sodium Tab.

पेशाब लगना आदि कुछ ऐसी पहचान हैं, जिससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि डायबिटीज होने का ख़तरा बढ़ता जा रहा है. अगर सही समय पर लोग डायबिटीज की जांच कराने में भलाई समझें तो तत्काल इस रोग पर नियंत्रण पाकर शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव को रोका जा सकता है.

डायबिटीज होने के बाद परहेज़ के तौर पर क्या करना चाहिए?

डायबिटीज को नियंत्रण में रखकर इसके कुप्रभाव से बचते हुए सामान्य जीवन जिया जा सकता है. दवाओं की सही मात्रा, उचित देखभाल और सही चिकित्सकीय सलाह से सक्रिय और स्वस्थ्य जीवन जीने में कोई परेशानी नहीं है. जब तक रक्त में ग्लूकोज सामान्य रहेगा, तब तक रोगियों को परेशानी नहीं होगी. तेज़ चलने, तैराकी करने, साइकिल चलाने तथा संतुलित आहार का सेवन भी एक अच्छा परहेज़ माना गया है. अधिक से अधिक हरी सब्ज़ी तथा फल का सेवन करना डायबिटीज रोगियों के लिए श्रेयस्कर है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

पांच हज़ार में बिक रहे हैं हेल्थ कार्ड

अरुण साथी

शेखपुरा

स्वास्थ्य विभाग में किस क़दर लूट मची है, इसका ख़ुलासा उस समय हो गया जब बरबीघा रेफरल अस्पताल में जननी बाल सुरक्षा योजना की राशि को लेकर हुए विवाद में एक चिकित्सक ने नर्स से थूक चटवाया एवं थप्पड़ जड़ दिया. मामला निजी क्लीनिक में बच्चे के जन्म लेने के बाद जच्चा-बच्चा को सरकारी अस्पताल में नर्स, आशा कार्यकर्ता एवं चिकित्सक की मिलीभगत से भर्ती कराकर पैसा निकालने का है. बरबीघा में डॉ. मंजु भदानी के क्लीनिक में पिंजड़ी गांव निवासी लक्ष्मी देवी भर्ती हुई और वहीं उसने बच्चे को जन्म दिया.

क्लीनिक के आंकड़े के अनुसार, लक्ष्मी देवी ने दिनांक 6 फरवरी को क्रम संख्या 62 के अनुसार एक बच्ची को जन्म दिया और फिर सरकारी मिलीभगत से इसे रेफरल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया. जननी बाल सुरक्षा योजना की राशि की इस बंदरबांट में प्रसूता को पांच सौ रुपये देने का क़रार हुआ एवं आशा पुष्पा देवी को 500 तथा बाक़ी की राशि नर्स और अस्पताल में वितरित होनी तय हुई. इस मामले को लेकर विवाद तक हुआ. जब डॉ. रविंद्र प्रसाद ने इसका विरोध करते हुए झांसे में रखकर हस्ताक्षर कराने पर भड़क गए और फिर हुए विवाद में पहले तो नर्स मनोरमा देवी से थूक चाटने को कहा गया और फिर एक थप्पड़ जड़ दिया गया. इस घटना के बाद नर्स सहित अन्य कर्मचारियों ने हंगामा किया और धरने पर बैठ गए. फिर मामले को दबाने को लेकर ज़िला स्वास्थ्य पदाधिकारी सिविल सर्जन जवाहर प्रसाद ने आकर दोनों पक्षों में समझौता करा दिया. दूसरा सबसे बड़ा घोटाला केंद्र सरकार की चल रही हेल्थ कार्ड योजना में सामने आ रहा है. इस योजना में बीपीएल परिवारों को हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराकर तीस हज़ार रुपये तक का इलाज मुफ़्त कराने लाभ दिया गया है और इस रक़म को दलालों और माफ़ियाओं की नज़र लग गई है. बिना किसी बीमारी या ऑपरेशन के ही पांच-पांच हज़ार में हेल्थ कार्ड ख़रीदा जा रहा है. हेल्ट स्मार्ट कार्ड धारक को पांच हज़ार रुपये दिए जाते हैं और बाक़ी 15 से 20 हज़ार निकाल कर इस कार्य के लिए चिन्हित क्लीनिक द्वारा रख लिया जाता है. यह मामला पिंजड़ी गांव में भी सामने आया, जहां कार्ड धारक नवल पासवान के कार्ड से राशि निकाल ली गई और उसे मात्र दो हज़ार दिए गए. इसी गांव के त्रिवेणी यादव के साथ भी यही किया गया. ज़िले में पांच क्लीनिकों को यह कार्य करने का अधिकार आईसीआईसीआई लिंबार्ड नामक इंश्योरेंस कंपनी द्वारा दिया गया है. यह अधिकार लेने में ही क्लीनिक के संचालक को लाखों का नज़राना देना पड़ा और फिर वसूली शुरू हो गई. साधारण सा ऑपेडिंस का ऑपरेशन जहां निजी स्तर पर कराने पर 2000 से 3000 हज़ार रुपये लिए जाते हैं, वहीं कार्ड धारक का कार्ड लेकर उससे 10000 निकाल लिए जाते हैं. स्मार्ट कार्ड का यह काला करोबार करोड़ों में किया जा रहा है. जननी बाल सुरक्षा योजना की राशि में लूट को लेकर सिविल सर्जन जवाहर प्रसाद ने इससे इंकार करते हुए कहा कि इस तरह का मामला सामने आने पर कार्रवाई की जाएगी.

नवल पासवान

feedback@chauthiduniya.com

रोहतास

केवल काग़ज़ों पर सुधरी सेहत

रोहतास ज़िले में जननी बाल सुरक्षा योजना सफ़ेद हाथी बनकर रह गई है. इस योजना पर ख़र्च तो करोड़ों हुए, लेकिन परिणाम सिफ़र रहे. ख़र्च की राशि काग़ज़ों पर काफ़ी मज़बूती से योजना के पालन के हर बिंदु को दर्शा रही है. जब जांच सामने आई तो पता चला कि सभी प्रखंडों में योजना में हुई घपलेबाज़ी के विरोध में हो रहे आंदोलन और प्रदर्शन कितने वाजिब हैं. वर्ष 2011-12 के चौथे तिमाही बजट तक रोहतास ज़िले में 4 करोड़ 68 लाख 32 हज़ार 477 रुपये ख़र्च करने का लक्ष्य था. इसमें दिसंबर तक ही 4 करोड़ 15 लाख 95 हज़ार 747 रुपये ख़र्च कर स्वास्थ्य विभाग अपनी योजना के सफल होने की गारंटी ख़ुद ही देकर अपनी पीठ थपथपाने में जुटा हुआ है. हक़ीक़त यही है कि दिसंबर महीने में नोखा प्रखंड मुख्यालय पहुंचकर 4 बार जननी बाल सुरक्षा की लाभार्थी महिलाएं अपनी राशि के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का घेराव कर चुकी हैं. चेनारी प्रखंड मुख्यालय में दो महीने से यह कहानी दोहराई जा रही है.

रोहतास ज़िले के उग्रवाद क्षेत्र में स्थित नौहट्टा, रोहतास और तिलौथू प्रखंड के लाभुकों को यह जानकारी ही नहीं कि जननी बाल सुरक्षा योजना में कितनी राशि एक लाभार्थी को मिलती है. रोहतास ज़िला स्वास्थ्य समिति द्वारा जारी की गई अधिकारिक रिपोर्ट पर नज़र दौड़ाई जाए तो तिलौथू, नौहट्टा, शिवसागर, सूर्यपुरा जैसे पिछड़े हुए प्रखंडों के नाम कम राशि ख़र्च करने वाले प्रखंडों में शुमार है. इस वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही लक्ष्य में तिलौथू को 9 लाख 86 हज़ार 479 रुपये ख़र्च करने थे. इसी तरह से शिवसागर में 4 लाख 48 हज़ार, नौहट्टा में 6 लाख 10 हज़ार रुपये. इसके विपरीत ज़िला मुख्यालय सासाराम में सर्वाधिक 80 लाख, इसके बाद दिनारा में 53 लाख और बिक्रमगंज और कोचस में क्रमश: 45 और 43 लाख रुपये ख़र्च करने थे. ज़िले के संपूर्ण लक्ष्य पर नज़र दौड़ाने के बाद स्थिति साफ़ हो जाती है, जिसमें दिसंबर 2011 तक 4 करोड़ 15 लाख 95 हज़ार 447 रुपये ख़र्च किए गए. दूसरे ही महीने जनवरी 2012 में 38 लाख 50 हज़ार 489 रुपये ख़र्च कर डाले, जो पिछले 9 महीने के ख़र्च अनुपात का लगभग 10 प्रतिशत हिस्सा हैं. लक्ष्य 4 करोड़ 68 लाख 32 हज़ार 477 रुपये का है. अब तक 4 करोड़ 54 लाख 46 हज़ार 236 रुपये ख़र्च हो चुके हैं. नौहट्टा प्रखंड मुख्यालय स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर गत सप्ताह जुटी लगभग एक दर्जन महिलाओं में से बाहर निकलकर धोबिनिया टिकर की इंदुमती देवी ने कहा कि तीन महीने से हम बाल जननी सुरक्षा योजना को लेकर मिलने वाली राशि के लिए चक्कर लगा रहे हैं, जो नहीं मिल रही है. दावथ प्रखंड मुख्यालय पर इटवां से पहुंची कलावती देवी ने बताया कि वह भी पिछले दो महीने से इस योजना की राशि के लिए लगभग 4 बार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आ चुकी हैं, उन्हें भी राशि नहीं मिली. नोखा प्रखंड मुख्यालय के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जनवरी महीने में 3 बार बाल जननी सुरक्षा योजना की राशि को लेकर महिलाओं ने घेराव और प्रदर्शन तक किया, लेकिन परिणाम सिफ़र रहा. यह प्रदर्शन राशि में हो रही कटौती के ख़िलाफ़ भी हुए हैं, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचकर प्रति महिला मिलने वाली 1600 रुपये की राशि में 200 रुपये आशा कार्यकर्ताओं के लिए काटने का विरोध है. ज़िले में स्वास्थ्य समिति द्वारा दिखाए गए आंकड़े भले ही योजना की सफलता की गारंटी दे रहे हों, लेकिन यहां यह योजना स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए दुधारू गाय के समान हो गई है. इस संदर्भ में जब ज़िला सिविल सर्जन डॉ. शिवानंद सिन्हा से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि जननी बाल सुरक्षा योजना को लेकर विभाग द्वारा जारी किया गया ख़र्च का लेखा-जोखा सही है. उधर, कई स्वास्थ्य संगठनों ने विभाग द्वारा इस योजना की राशि में की गई बंटरबांट को लेकर आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है.

ममता चौहान
feedback@chauthiduniya.com

बक्सर

फोटो : संजय सिंह

बेड छह और प्रसव 20

बेहतर चिकित्सा सुविधा के नाम पर बक्सर ज़िले के सरकारी अस्पतालों में मातृत्व अनुदान की जमकर लूट-खसोट की जा रही है. विभागीय अधिकारी तथा दलालों की साठगांठ से इस घोटाले का खेल लंबे अरसे से चल रहा है. बक्सर के राजपुर तथा इठाढ़ी प्रखंडों के 6-6 बेड वाले अस्पतालों में प्रतिदिन 18-20 प्रसव काग़ज़ में दिखाकर अनुदान राशि की बंदरबांट की जा रही है. सरकारी अस्पतालों में प्रसव होने के बाद प्रति महिला 14 सौ रुपये दिए जाते हैं. घर में या निजी अस्पतालों में होने वाले प्रसूति महिला का नाम दर्ज कर घोटाले को अंजाम दिया जाता है.

घोटाले की गूंज राज्य मुख्यालय तक पहुंच गई है, पर जांच के नाम पर मामले को दफ़न करने के लिए रिकॉर्डों में भी छेड़छाड़ की गई है. इठाढ़ी प्रखंड के बसंतपुर गांव निवासी सरस्वती देवी को एक प्रसव के बाद दो बार लाभ दिया गया. इसी गांव कि देवबसिया देवी के नाम पर राजपुर तथा इटाढ़ी प्रखंडों से दो बार अनुदान दिया गया. कुकढ़ा गांव की सुमित्रा देवी के नाम पर दो बार तथा चिलहर गांव की भगमनिया देवी को प्रसव न होने के बाद भी दो बार यानी 28 सौ रुपये की निकासी की गई. इस तरह घोटालेबाज़ों द्वारा प्रसव न करने वाली महिलाओं के नाम पर घोटालों का खेल जारी है. इस मामले में पूछे जाने पर सीएस रामचंद्र प्रसाद ने कहा कि जांच का आदेश दिया गया है. रिपोर्ट न मिलने की बात पर कुछ भी बताने से इंकार किया. आश्चर्य तो यह है कि तीन माह पूर्व जांच के आदेश देने के बाद भी आज तक जांच नहीं हुई. यहां के वरीय उपसमाहर्ता तथा स्वास्थ्य विभाग के नोडल पदाधिकारी आलोक कुमार ने जांच कर घोटले की पुष्टि करते हुए रिपोर्ट डीएम को दी थी. डीएम के आदेश के बाद भी इस रिपोर्ट पर अमल नहीं किया गया. आलोक कुमार ने स्वीकार किया कि घोटाले का दायरा व्यापक है तथा मातृत्व अनुदान के नाम पर बड़े पैमाने पर अनियमितता कर सरकारी राशि की जमकर लूट की गई है.

जयमंगल पाण्डेय
feedback@chauthiduniya.com

PATALIPUTRA SCHOOL OF FIRE & SAFETY MANAGEMENT
Authorised Study Centre of EIILM University. Code-CIIP/101683
Diploma/PG Diploma/Bachelor Degree/PG Degree
In the following Subjects :
FREE
410, Ashiana Galaxy, Exhibition Road, Patna-800 001
Ph: 0612-3297011, Mob.: 9334107607, 9234929075

Enjoy with Nature
MOULDED FURNITURE
NATURE
1 YEAR GUARANTY
Contact : 9386595926, 9334115955

सारण एक नज़र

बाल कलाकारों ने जलवा बिखेरा

दिघवारा के मुसेपुर के शिशु मंदिर में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बाल कलाकार बबली कुमारी, गुड़िया कुमारी, पूनम कुमारी, नेहा कुमारी, तनु कुमारी, निशु कुमारी, शिल्पी कुमारी, काजल कुमारी, सोनू लाल एवं अलोक कुमार की सराहनीय प्रस्तुति रही. इस कार्यक्रम का उद्घाटन विधायक ज्ञानचंद्र मांझी एवं विनय सिंह तथा मंच का संचालन सत्येंद्र सिंह ने किया. इस मौक़े पर मुखिया मुन्ना राय, सर्वानंद राय, रामअनुग्रह सिंह, विश्वनाथ सिंह, राजेश सिंह, अशोक सिंह, सतीश सिंह, रीतेश शर्मा, रंजन सिंह, नेहा सिंह, राजकुमारी देवी एवं अन्य अभिभावकगण उपस्थित थे.

शिक्षा अधिकार पदयात्रा का जत्था रवाना

शिक्षा के अधिकार क़ानून में 18 वर्ष तक के सभी बच्चों को शामिल करने, बारहवीं कक्षा तक नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा लागू करने, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, माध्यमिक विद्यालय, संस्कृत विद्यालय और मदरसों में कार्यरत शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को नियमित वेतनमान, सेवा शर्त निर्धारित करने आदि मांगों को लेकर बीती 30 जनवरी से भितिहरवां से शुरू हुई जनअधिकार पदयात्रा के पदयात्रियों ने राजेंद्र बाबू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर आगे के लिए प्रस्थान किया. जत्थे का नेतृत्व वित्त संपोषित शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी कल्याण महासंघ के अध्यक्ष प्रो. गणेश प्रसाद सिंह, प्रो. वशिष्ठ नारायण सिंह, प्रवेश अध्यक्ष बिहार इंटरमीडिएट शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचारी महासंघ, प्रो. रविंद्र प्रसाद सिंह, उपाध्यक्ष नागेंद्र शुक्ला बिहार संस्कृत विद्यालय के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह, बसंत कॉलेज गड़खा के प्राचार्य प्रो. वियज कुमार सिंह आदि कर रहे थे. सनद रहे कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आज़ादी की लड़ाई और भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर ने भी अपनी राजनीतिक पदयात्रा का प्रारंभ भितिहरवां से ही किया था.

सर्वदलीय छात्र मोर्चा की बैठक

गोपालगंज के गंगा सिंह कॉलेज में छात्र नेताओं की सर्वदलीय बैठक हुई. इसकी अध्यक्षता छात्र राजद के विश्वविद्यालय अध्यक्ष सुशील कुमार डब्लू ने की. छात्र दल के नेताओं को सिंडिकेट एवं सीनेट में बैठने के लिए फ़ैसला लेना था, पर उन्होंने कोई फ़ैसला नहीं लिया है. इस कारण सभी दल के छात्र नेताओं का उन्होंने अपमान किया है. इस बैठक में कार्यक्रम की सफलता के लिए तीन कमेटी का गठन किया गया है. इस बैठक में छात्र जदयू के विश्वविद्यालय अध्यक्ष रणवीर कुमार सिंह, शोध विधार्थी के विश्वजीत कुमार चंदेल छात्र राजद के उपाध्यक्ष मनीष कुमार यादव, सुहैल अख्तर, रंजीत कुमार, अभिषेक कुमार, छात्र राजद प्रवक्ता राजु कुमार, छात्र जदयू ज़िला अध्यक्ष रंजन यादव, चंदन कुमार, चुन्नू कुमार आदि उपस्थित थे.

शिक्षक नियुक्ति पत्र पाकर झूम उठे

उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक में वेतनमान में नियुक्त होने वाले शिक्षकों को ज़िला स्कूल के परिसर में जिलाधिकारी विनय कुमार ने नियुक्ति पत्र दिया. नियुक्ति पत्र पाकर शिक्षक झूम उठे. बहुत से ऐसे शिक्षक भी थे, जिन्हें कुछ वर्ष नौकरी करने को मिलेगी. इनमें महिला शिक्षिकाओं की संख्या भी थी. जिन शिक्षकों को अपने गृह ज़िले में नियुक्ति पत्र मिला है, उनकी ख़ुशी कई गुनी बढ़ गई थी. नियुक्ति पत्र पाने वाले शिक्षक पिछले दिनों उत्तम मुहूर्त में योगदान देने की योजना बना रहे थे.

घाटे का बजट पेश

[illegible]

छात्र नेताओं ने ज्ञापन दिया

[illegible]

सरोज कुमार, छात्र राजद विधि अध्यक्ष सुशील कुमार डब्ल्यू, उपाध्यक्ष सह ज़िला प्रवक्ता राजू कुमार जिलाध्यक्ष गोपाल गंज, प्रदीप देव, सिवान से मिथिलेश यादव, छपरा मनीष कुमार यादव, मंटु ओझा, प्रवीन कुमार चौरसिया, मो. गुफराण, रोहिन प्रताप सिंह, इक़बाल यादव, विवि उपाध्यक्ष नंदकिशोर यादव, मो. सुल्तान इदरीसी आदि उपस्थित थे.

स्वास्थ्य कार्यशाला संपन्न

[illegible]

प्रस्तुति-शुभम रानी चौहान, मनीष कश्यप, जयनाथ सिंह

समस्तीपुर

ज़हरीले धुएं से लोगों का जीना दूभर

अफ़जल ईमाम मुन्ना

प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम की धज्जियां उड़ाने में छोटे जनरेटर चालक ही लिप्त नहीं हैं, बल्कि बड़े-बड़े होटल, नर्सिंग होम, सिनेमा हॉल, फोटोस्टेट, स्टूडियो, इंटरनेट कैफे, जांच घर, एक्सरे आदि वाले भी इसमें पीछे नहीं हैं. ये सभी धुंआ रहित जनरेटर की जगह धुंआ उगलने वाला जनरेटर चला रहे हैं. इन जनरेटरों की ध्वनि बेहद कर्कश होती है. परिणामस्वरूप शहरवासियों को वायु प्रदूषण के साथ-साथ ध्वनि प्रदूषण का दंश भी झेलना पड़ रहा है,

समस्तीपुर का प्रदूषण नियंत्रण विभाग लगता है बस देखने की ही चीज़ बनकर रह गया है. प्रदूषण नियंत्रण क़ानून की धज्जियां यहां जनरेटर चालक खुलेआम उड़ा रहे हैं, पर विभाग चुप है. परिणाम है कि ज़हरीले धुएं से लोगों का जीना दूभर हो गया है. बदलते वायु प्रदूषण से सरकार, पर्यावरणविद् तथा बुद्धिजीवी सभी चिंतित हैं.

प्रदूषण की रोकथाम के लिए तरह-तरह की तरकीबे अपनाई जा रही हैं. पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है. बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो बाक़ायदा सदस्यता अभियान की शुरुआत पौधारोपण अभियान से करने की अपील जद (यू) कार्यकर्ताओं से की है. उन्होंने 25 पौधे लगाने वाले सक्रिय सदस्य को पदाधिकारी बनाने तक का ऐलान किया है. जद (यू) कार्यकर्ताओं ने पेड़ लगाओ अभियान को सफल कर दिया. लेकिन प्रदूषण नियंत्रण पर अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया है, जबकि सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम बना रखा है. सड़कों पर धुंआ निकालने वाले वाहनों पर रोक है, पर समस्तीपुर शहर की घनी आबादी वाले इलाक़े हों या सघन बाज़ार, नलकूप से निकलने वाले पानी की तरह धुंआ उगलते जनरेटर हर जगह दिख जाएंगे. प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम की धज्जियां उड़ाने में छोटे जनरेटर चालक ही लिप्त नहीं हैं, बल्कि बड़े-बड़े होटल, नर्सिंग होम, सिनेमा हॉल, फोटोस्टेट, स्टूडियो, इंटरनेट कैफे, जांच घर, एक्सरे आदि वाले भी इसमें पीछे नहीं हैं. ये सभी धुंआ रहित जनरेटर की जगह धुंआ उगलने वाला जनरेटर चला रहे हैं. इन जनरेटरों की ध्वनि बेहद कर्कश होती है. परिणामस्वरूप शहरवासियों को वायु प्रदूषण के साथ-साथ ध्वनि प्रदूषण का दंश भी झेलना पड़ रहा है, जबकि सरकार ने इस तरह के धुंआ उगलने और कर्कश ध्वनि वाले जनरेटरों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा रखा है. इतना सब होने के बाद भी प्रशासन की नज़र इस ओर नहीं जा रही है, जिससे आए दिन इनकी संख्या में वृद्धि होती जा रही है. नतीजतन, कई तरह की बीमारियां फैल रही हैं, जिनका पता न चलने के कारण डॉक्टर सही इलाज नहीं कर पा रहे हैं.

आलम यह है कि कई जगहों पर एक साथ पांच से दस जनरेटर चलाए जा रहे हैं. यहां से गुज़रने पर लोगों का दम घुटने लगता है. लोगों के स्वास्थ्य से खेल रहे और प्रदूषण अधिनियम की धज्जियां उड़ाने वाले इन जनरेटर चालकों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने वाला कोई नहीं है. कई जगहों पर तो लोगों का अपने घरों में रहना मुश्किल हो गया है, क्योंकि बिजली की आंख मिचौली से परेशान लोगों की नाक में जब पड़ोसी के जनरेटर का धुंआ प्रवेश करता है तो उनका दम घुटने लगता है. प्रभावित लोगों का कहना है कि आख़िर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और स्थानीय प्रशासन की क्या मजबूरी है कि प्रदूषण के लिए जवाबदेह लोगों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है. इसको लेकर प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण विभाग के ख़िलाफ़ लोगों में बेहद गुस्सा दिखाई पड़ रहा है. राजद विधायक दुर्गा प्रसाद सिंह ने इस पर जल्द नियंत्रण करने की मांग सरकार से की है. ताकि प्रदूषण नियंत्रण से लोगों को निजात मिल सके.

feedback@chauthiduniya.com

Earth Infrastructures Ltd.
4th Floor Bhagwati Dwarika Arcade (Opp. Pandey Motors), Exhibition Road
Patna - 800001
TEL: +91-612-6500643, +91-612-3215709
Mob: +91-09266637081, 09266637082, 09266670292, 09266632054
Founder member Indian Green Building Council
Member of: CREDAI
earthinfra.com
FOR CORPORATE ENQUIRY +91- 09266637088
Disclaimer : Visual representation shown in the advertisement are purely conceptual. All plans, specifications etc are tentative and subject to variation & modification by the company or the competent authorities and the company does not bear any legal consequences for it.

अररिया

आंगनवाड़ी केंद्र बदहाल हैं

अधिकांश केंद्रों पर बच्चे व गर्भवती के वज़न के लिए मशीन तक उपलब्ध नहीं है. सेविकाएं अपने मूल दायित्व का निर्वहन नहीं करती हैं. सेविका अपने पोषक क्षेत्र के घरों में कौन महिला गर्भवती हुई और किसके घर नवजात ने जन्म लिया, इसका भी लेखा-जोखा रखना मुनासिब नहीं समझती हैं.

उपेंद्र यादव

बच्चों व महिलाओं के स्वास्थ्य की महत्वाकांक्षी योजना बाल विकास परियोजना कार्यक्रम के तहत संचालित आंगनवाड़ी केंद्र सीडीपीओ, पर्यवेक्षिका व सेविकाओं के लिए दुधारू गाय साबित हो रहे हैं. इस परियोजना की सबसे ख़राब हालत अगर कहीं है तो वह अररिया ज़िले की है. अररिया ज़िले के विभिन्न प्रखंडों में आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन तो होती है. मगर केंद्र के बच्चे, धात्री व गर्भवती महिलाओं को दिया जाने वाला पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है. यहां तक कि अधिकांश केंद्रों पर सेविका की जगह उसके पति या फिर नौकर पर नौकर की तरह किसी अन्य महिलाओं को शिक्षक के रूप में रख कर बच्चों की पढ़ाई एवं देखरेख करने का भी धंधा करने से हिचकते नहीं हैं. आंगनवाड़ी केंद्रों की गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण एवं वज़न भी नहीं जांचा जाता है. अधिकांश केंद्रों पर बच्चे एवं गर्भवती के वज़न के लिए मशीन तक उपलब्ध नहीं है. सेविकाएं अपने मूल दायित्व का निर्वहन भी नहीं करती हैं. वे अपने पोषक क्षेत्र के घरों में कौन महिला गर्भवती हुई और किसके घर बच्चे ने जन्म लिया, इसका भी लेखा-जोखा रखना ज़रूरी नहीं समझती हैं. हालांकि ज़िला प्रशासन की ओर से जन जागरण शक्ति संगठन द्वारा सामाजिक अंकेक्षण भी करवाया गया है. इस अंकेक्षण में भी व्यापक पैमाने पर अनियमितताएं उजागर हुई हैं.

ज़िले के नौ प्रखंडों में किस प्रखंड में कितने केंद्र

अररिया-355
रानीगंज-300
जोकीहाट-232
भरगामा-180
सिकटी-124
फारबिसगंज-374
कुर्साकांटा-115
नरपतगंज-258
पलासी-187

feedback@chauthiduniya.com

इंडियन इंस्टीच्युट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एण्ड रिसर्च
हेल्थ इंस्टीच्युट रोड, बेउर, पटना-२
(बिहार सरकार, भारतीय पुनर्वास परिषद, भारत सरकार तथा आइ.ए.पी.से मान्यता प्राप्त)
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया से संबंधन प्राप्त

We Impart:-
POST GRADUAGE COURSES:
MPT Master of Physiotherapy
MOT Master of Occupational Therapy
MPO Master of Prosthetic & Orthotic
MASLP Master of Audiology & Speech Language Pathology
BPT Bachelor of Physiotherapy
BOT Bachelor of Occupational Therapy
BPO Bachelor of Prosthetic & Orthotic
BASLP Bachelor of Audiology & Speech Language Pathology
BMRT Bachelor of Radio Imaging Technology
BMLT Bachelor of Medical Laboratory Technology
B.Ed. (Special Education)
B.Ophth. Bachelor of Ophthalmology

संस्थान द्वारा संचालित निशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं
- स्वास्थ्य परीक्षण एवं परामर्श
- टीकाकरण
- फिजियोथेरापी
- अकुपेशनल थेरापी
- स्पीच थेरापी
- नेत्र जाँच
- सभी प्रकार की विकलांगता पोलियो,लकवा,गठिया,हड्डी, जोड़ एवं नस से संबंधित सभी प्रकार के रोगों की जांच एवं उपचार
- हकलाना, तुतलाना सहित गूंगे-बहरों की जाँच एवं उपचार हियरिंग-एड
- मानसिक विकलांगता तथा मंद बुद्धिपता जाँच एवं उपचार
- कृत्रिम हाथ,पैर,कैलीपर,पोलियो के जूते,वैशाखी, सर्वाइकल कॉलर, बेल्ट आदि का निर्माण एवं वितरण
- लाचार विकलांगों को तिपहिया-साकिल तथा व्हीलचेयर
- विकलांगों की शल्य चिकित्सा,सर्जिकल करेक्शन
- रियायती दर पर पैथोलोजिकल जाँच,एक्स-रे, इ.सी.जी. तथा शल्य

1 Yr. ABRIDGED DEGREE For DPT & DOT

DIPLOMA COURSES:
DPT Diploma in Physiotherapy
DPO Diploma in Prosthetic & Orthotic
DMLT Diploma in Medical Lab. Tech
D-X-Ray Diploma in x-ray Technology.
DHM Diploma in Hospital Management
DOTA Diploma in Operation Theater Assistant
DECG Diploma in E.C.G.
certificate courses:
CMD Certificate in Medical Dressing
Foundation Course for Teachers in Disability

Form & Prospectus:- Available at the institute counter against payment of Rs. 300/-. Send a DD of Rs. 350/-only for postal delivery, in favour of Indian Institute of Health Education & Research, Patna-2
Eligibility:- For Post Graduate Courses- Degree in the same. 10+2 with science for Under Graduate & Diploma Courses. For B.Ed. Degree in any Subject.

Admission Going On...

डा. अनिल सुलभ
निदेशक-प्रमुख

फोन न. : 0612-2253290, 2252999, फैक्स: 0612-2253290,email. iiher_beur@gmail.com, www.iiher.org

चौथी दुनिया

उत्तर प्रदेश
उत्तराखंड

दिल्ली, 27 फरवरी-04 मार्च 2012

www.chauthiduniya.com

शिक्षा जगत का सबसे बड़ा घोटाला

प्रारूप के बारे में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने 11 फरवरी, 2011 को राज्यों को दिशा-निर्देश जारी किया था. एनसीटीई के दिशा-निर्देशों पर अमल करते हुए एससीईआरटी ने मई 2011 के पहले सप्ताह में अध्यापक पात्रता परीक्षा का प्रारूप तैयार कर उसके आयोजन का प्रस्ताव शासन को मंज़ूरी के लिए भेज दिया. 12 मई को बेसिक शिक्षा मंत्री धर्म सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई विभाग की मासिक समीक्षा बैठक में मंत्री और सचिव ने विभागीय अफ़सरों को बताया कि टीईटी के आयोजन की ज़िम्मेदारी यूपी बोर्ड को सौंपी जाएगी. तर्क यह दिया गया कि एससीईआरटी के पास टीईटी के आयोजन के लिए न तो पर्याप्त संसाधन हैं और न ही विशेषज्ञ. यूपी बोर्ड माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन है, इसलिए मई में ही सचिव बेसिक शिक्षा अनिल संत ने सचिव माध्यमिक शिक्षा जितेंद्र कुमार को पत्र लिखकर टीईटी के आयोजन की ज़िम्मेदारी यूपी बोर्ड को सौंपे जाने के बारे में सहमति मांगी थी. अगस्त में तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा मंत्री रंगनाथ मिश्र ने यूपी बोर्ड को टीईटी के आयोजन का दायित्व सौंपे जाने के प्रस्ताव से असहमति जताते हुए संबंधित पत्रावली बेसिक शिक्षा विभाग को वापस भेज दी थी. माध्यमिक शिक्षा मंत्री का यह तर्क था कि दिसंबर से यूपी बोर्ड की प्रायोगिक और मार्च से मुख्य परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं.

अफ़सरों ने सितंबर के पहले हफ्ते में टीईटी के आयोजन की ज़िम्मेदारी यूपी बोर्ड को सौंपने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री से अनुमोदित करा लिया. सात सितंबर को इस सबंध में शासनादेश भी जारी हो गया. जब बेसिक शिक्षा विभाग ने टीईटी के आयोजन की ज़िम्मेदारी यूपी बोर्ड को सौंपे जाने के बारे में माध्यमिक शिक्षा महकमे से सहमति मांगी, तो इस पर शासन ने यूपी बोर्ड से अभिमत मांग लिया. बोर्ड के सभापति और माध्यमिक शिक्षा निदेशक संजय मोहन ने शासन को पत्र लिखकर बताया कि यदि शासन यूपी बोर्ड को टीईटी के आयोजन की ज़िम्मेदारी सौंपना चाहता है, तो वह इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा-9 (4) के तहत बोर्ड को यह निर्देश दे सकता है. शिक्षकों की भर्ती के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) ने टीईटी का पाठ्यक्रम तैयार किया. एससीईआरटी ने टीईटी कराने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा. शासन ने टीईटी कराने की ज़िम्मेदारी माध्यमिक शिक्षा परिषद को देने का निर्देश दिया. इसके आधार पर एससीईआरटी से संशोधित प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन माध्यमिक शिक्षा परिषद ने टीईटी कराने से इंकार करते हुए प्रस्ताव वापस कर दिया. माध्यमिक शिक्षा परिषद से प्रस्ताव वापस होने के बाद शासन स्तर पर होने वाली साप्ताहिक समीक्षा बैठक में केंद्रीय बोर्ड से टीईटी कराने पर विचार-विमर्श किया गया. एससीईआरटी ने इसके आधार पर प्रस्ताव बनाने की तैयारियां भी शुरू कर दीं, लेकिन एक बार फिर माध्यमिक शिक्षा परिषद से टीईटी कराने के लिए दबाव बनाया गया. दबाव में माध्यमिक शिक्षा परिषद ने टीईटी की तैयारियां शुरू कीं और इसके लिए अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे गए, जिसकी अर्हता बीएड उत्तीर्ण थी. प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए टीईटी 13 नवंबर को प्रदेश के सभी मंडलों में आयोजित की गई. इस परीक्षा में कुल 11 लाख 53 हज़ार 155 अभ्यर्थियों ने भाग लिया. लेकिन शिक्षा माफ़ियाओं द्वारा परीक्षा के दिन पेपर आउट कराने का झांसा देकर लाखों की ठगी करने के आरोप में दो लोग पुलिस गिरफ्त में आए. बदइंतज़ामी के बीच परीक्षा हो गई और 26 नवंबर को परिणाम घोषित कर दिया गया, जिसमें 2 लाख 70 हज़ार अभ्यर्थी सफल हुए. परिणाम आते ही इलाहाबाद में यूपी बोर्ड मुख्यालय पर हंगामा शुरू हो गया. परीक्षार्थियों ने परीक्षा में ग़लत सवालों का आरोप लगाया. कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में अर्ज़ी दी. कुछ छात्रों के नंबर अचानक अधिक बढ़ गए. इसे लेकर आपत्तियां उठीं, लेकिन मामले को दबा दिया गया. बीएड बेरोज़गारों ने जब इस पर सवालिया निशान लगाया, तो इसकी अनदेखी कर दी गई. टीईटी में नंबर बढ़ाए जाने के संबंध में आ रही ख़बरों के जवाब में माध्यमिक शिक्षा परिषद की सचिव प्रभा त्रिपाठी की तरफ़ से स्पष्टीकरण जारी कराकर स्थिति संभालने की कोशिश की गई. इसमें कहा गया कि केवल उन्हीं छात्रों के अंक बढ़ाए गए हैं, जो पात्र थे. बोर्ड सचिव ने परिणाम संशोधित करने का आश्वासन देकर परीक्षार्थियों से अपनी जान छुड़ाई. लेकिन परीक्षा में हुई त्रुटियों पर अंगुलियां उठती ही रहीं. क़रीब 70 हज़ार परीक्षार्थियों का वेबसाइट पर नाम ही नहीं मिला.

कई ऐसे केस भी संशोधित हुए, जिनको दोगुने नंबर तक मिल गए. 23 दिसंबर को आख़िरी संशोधित परिणाम बोर्ड की ओर से घोषित कर दिया गया. मज़े की बात यह है कि टीईटी के लिए बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली संशोधन के बाद परीक्षा के एक हफ्ते पहले शिक्षा पात्रता परीक्षा को शिक्षक अर्हता परीक्षा में बदल दिया गया, वहीं 72 हज़ार से अधिक शिक्षकों की भर्ती के लिए एक महीने की अवधि तय कर दी गई. इससे परीक्षार्थियों में शिक्षक बनने की होड़ सी दिखने लगी. इस परीक्षा का दारोमदार शिक्षा निदेशक संजय मोहन पर डाला गया था. कहते हैं कि संजय मोहन मायावती और मुलायम के शासनकाल में सत्ता के क़रीबी रहे. वर्ष 2000 से विभिन्न पदों पर रहने के बाद संजय मोहन 2001 में माध्यमिक शिक्षा निदेशक बने. बीच में दो वर्ष के लिए उन्हें इस पद से हटना पड़ा, लेकिन फिर वह इस पद पर विराजमान हो गए. साथ ही उन्हें वैकल्पिक एवं साक्षरता निदेशक का अतिरिक्त चार्ज भी सौंप दिया गया. निदेशक बनने के बाद से ही उन पर स्कूलों में भर्ती से लेकर बोर्ड परीक्षा केंद्र सेट कराने की ज़िम्मेदारी को निर्वहन करना ही था. टीईटी परीक्षा की ज़िम्मेदारी लेने के बाद मानो उनकी लाटरी ही खुल गई थी. इस बीच 31 दिसंबर को टीईटी में नंबर दिलाने के नाम पर एक गिरोह का पर्दाफ़ाश हुआ. पुलिस द्वारा रमाबाई नगर में 87 लाख रुपये के साथ पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया. इस गिरफ्तारी के बाद टीईटी परीक्षा परिणाम पर उंगली उठने लगी. इस दरम्यान दो बार रिजल्ट 2 जनवरी और 10 जनवरी को फिर संशोधित किया गया. 7 जनवरी को एसटीएफ ने टीईटी द्वारा परीक्षा में नंबर बढ़ाने के नाम पर वसूली करने वाले रैकेट पर शिकंजा कसा. पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से 35 हज़ार की नक़दी बरामद की. टीईटी के विज्ञापन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई भर्ती पर रोक लग गई. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने स्कूलों में नि:शुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद शिक्षकों की नियुक्ति एक परीक्षा के ज़रिये करने का निर्देश दिया था. इसमें इंटरमीडिएट, स्नातक, बीएड और टीईटी की मेरिट के अंकों को मिलाकर चयन की मेरिट बनाई जानी थी, लेकिन 13 नवंबर को टीईटी की परीक्षा के सप्ताह भर पहले इस मानक को बदलकर चयन के लिए सिर्फ़ टीईटी की मेरिट को आधार बना दिया गया. शिक्षक संगठनों का कहना है कि यह सिर्फ़ 12 करोड़ की धांधली का खेल नहीं है, बल्कि नौकरी के लिए दस-दस लाख रुपये देने वाले लोगों ने तीन-तीन लाख रुपये में सौदा कर लिया और सभी 72825 रिक्त पदों के लिए इस कारनामे को अंजाम दिया गया. हालांकि अध्यापक पात्रता परीक्षा के एक सप्ताह पहले आए शासनादेश ने इस परीक्षा में धांधली की बुनियाद रख दी थी. शासनादेश आने के बाद प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के मानक ही बदल गए और शिक्षक चयन के लिए टीईटी की मेरिट को आधार मान लिया गया. इसके साथ ही ज़िला स्तर पर मेरिट निर्धारण की व्यवस्था कर दी गई. शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सौदेबाज़ी तीन-तीन लाख में शुरू हो गई. इस धांधली के मास्टरमाइंड अभी भी गिरफ्त में नहीं हैं. माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट के प्रवक्ता आरपी मिश्र ने एनआरएचएम की तरह टीईटी में धांधली की सीबीआई जांच कराने की मांग की है, ताकि असली गुनहगार तक पहुंचा जा सके.

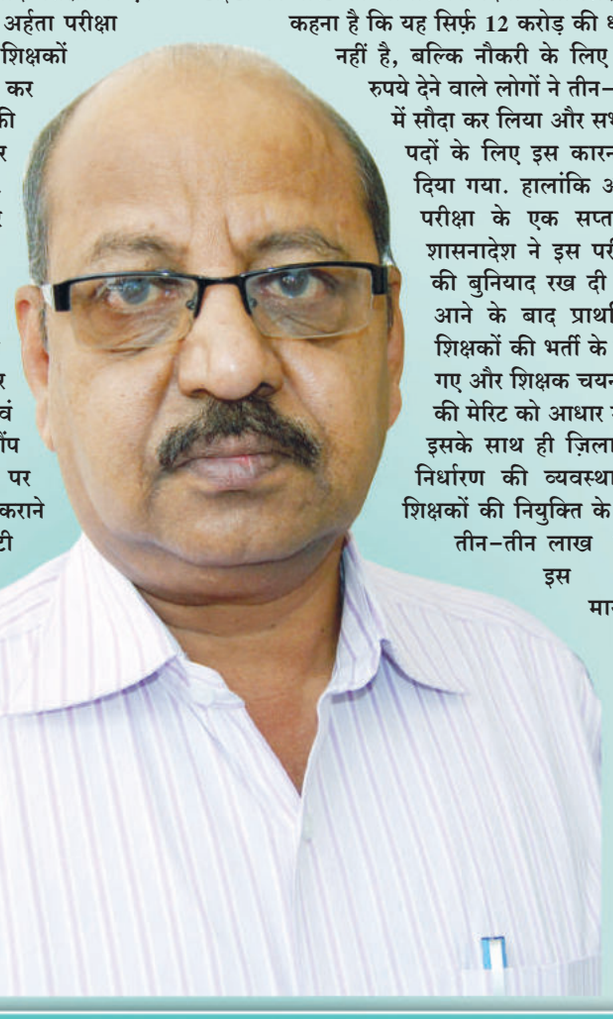

टीईटी में रिजल्ट के अपडेट को लेकर शिक्षा निदेशक संजय मोहन एवं सचिव प्रभा त्रिपाठी की ओर से सफ़ाई दी गई. विभाग के अफ़सरों का कहना है कि निदेशक तो फाइलों के निस्तारण में लगे रहते थे, टीईटी की सेल अलग थी और रिजल्ट के निकालने में उन्हीं का हाथ था. शिक्षा नेता आरपी मिश्र का कहना है कि टीईटी के आवेदन में ही परिषद को 50 करोड़ रुपये की आय हुई थी, जो 12 करोड़ का चार गुना है. ऐसे में अभी भी इस खेल के आक़ाओं को बचाया जा रहा है. हालांकि आयोजन की ज़िम्मेदारी इलाहाबाद स्थित यूपी बोर्ड के कार्यालय पर थी. कापियां जांचने से लेकर परिणाम तक सारे निर्णय वहीं हुए. अब जिन अधिकारियों पर निगाह है, उनमें शिक्षा निदेशालय, यूपी बोर्ड के साथ ही बेसिक शिक्षा विभाग के भी कुछ अधिकारी शामिल हैं. एसटीएफ संजय मोहन के इन क़रीबी अफ़सरों पर भी ध्यान केंद्रित किए हुए है, जो परीक्षा प्रक्रिया से तो नहीं जुड़े लेकिन अभियान का हिस्सा थे. माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेशीय मंत्री डॉ. आरपी मिश्र ने कंप्यूटर एजेंसी पर ही सवाल खड़ा कर दिया है. उनका कहना है कि कंप्यूटर एजेंसी का टेंडर ही नहीं किया गया था. रिजल्ट व मार्कशीट में अंक बढ़ाए जा सकें, इसके लिए किसी ख़ास कंप्यूटर एजेंसी को ठेका दे दिया गया. उन्होंने कहा कि शिक्षक भर्ती के लिए टीईटी को सुनियोजित ढंग से मेरिट का आधार बनाया गया. चूंकि शासनादेश बदलकर यह निर्णय लिया गया. इसलिए साफ़ है कि शिक्षामंत्री और सरकार की सहमति के बिना यह संभव नहीं. ऐसे में साफ़ है कि संजय मोहन की गिरफ्तारी और 12 करोड़ का मामला सामने आना सिर्फ़ शुरुआत मात्र है. पात्रता परीक्षा के संशोधित परिणाम में फेल अभ्यर्थियों को पास करने के आरोप में माध्यमिक शिक्षा निदेशक संजय मोहन की गिरफ्तारी के बाद पुलिस उनके मातहतों और कई बड़े नामों से कड़िया जोड़ने में जुट गई है. पुलिस सूत्रों के अनुसार 800 लोगों का परिणाम बदलने के लए इन अभ्यर्थियों से डेढ़ से तीन लाख रुपये तक वसूले गए हैं. इन अभ्यर्थियों से क़रीब 18 करोड़ रुपये की वसूली हुई है. शिक्षा विभाग के अधिकारी और शिक्षक नेता परिणाम संशोधित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या दो हज़ार से अधिक बता रहे हैं. इनसे पैंतालीस से पचास करोड़ रुपये वसूले गए हैं.

शिक्षा निदेशक के पास से पांच लाख रुपये बरामद हुए हैं. वहीं 87 लाख रुपये अकबरपुर, कानपुर की पुलिस ने पकड़े और पांच लाख रुपये की ज़मीन ख़रीदने का हिसाब ही पुलिस लगा सकी है. यह राशि मात्र एक करोड़ रुपये है, लेकिन शेष पैसा कहां गया? मामला उच्च न्यायालय तक गया और परीक्षा परिणाम को कई बार संशोधित किया गया. समय रहते टीईटी में हुई धांधली से पर्दा उठ गया. राष्ट्रीय लोकदल ने निवर्तमान माध्यमिक शिक्षा निदेशक संजय मोहन के मामले में राज्य सरकार पर करारा हमला बोला है. प्रदेश प्रवक्ता अनिल दूबे ने कहा है कि संजय मोहन ने जो बयान दिया है कि वह रिहा होने के बाद मुंह खोलेंगे. अधिकारियों का कहना है कि घोटाला काफ़ी बड़ा है, लिहाज़ा विजिलेंस और एंटीकरप्शन विभाग से जांच कराने पर भी विचार चल रहा है. माध्यमिक शिक्षक संघ भी 100 करोड़ रुपये से अधिक धन उगाही का आरोप लगा रहा है. सपा के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि सपा सरकार आने पर इसकी पूरी जांच होगी. बहरहाल, शिक्षा महकमे के खेल में लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लग गया है, पर महकमे के अधिकारी इस मामले में कुछ भी टिप्पणी नहीं करना चाहते. मामला बहुत ऊपर का है, इसलिए शिक्षाधिकारी तो इस मामले में मुंह भी नहीं खोलना चाहते.

टीईटी में चयन घोटाले में माध्यमिक शिक्षा निदेशक संजय मोहन को गिरफ्तार कर माती जेल भेज दिया गया है. ज़िला जज के सामने पेशी होने के बाद कोर्ट से बाहर निकलने पर संजय मोहन ने यह कहा था कि रिहा होने के बाद कई बड़े राज़ खोल देंगे.

दर्शन शर्मा, लखनऊ ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के मुस्लिम चेहरे सलमान ख़ुर्शीद को यह काम सौंपा गया. मुसलमानों को आरक्षण की बात सपा की काट के रूप में खोज ली गई.

मथुरा में पांच विधानसभा सीटों पर कांग्रेस-रालोद गठबंधन, भाजपा, सपा व बसपा मुक़ाबले में हैं.

एक नज़र

जगदंबिका पाल के बेटे के प्रचार के लिए शीला और अज़हरुद्दीन बस्ती आए

कांग्रेस के जगदंबिका पाल के बेटे के प्रचार के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और कांग्रेस के सांसद और क्रिकेट खिलाड़ी मोहम्मद अज़हरुद्दीन बस्ती आए. चौधारी चरण सिंह एयरपोर्ट से शीला दीक्षित और सांसद अज़हरुद्दीन को लेकर एक हेलीकॉप्टर ने बस्ती के लिए उड़ान भरी. हेलीकॉप्टर को चुनावी जनसभा से दो किलोमीटर दूर उतारा गया था. इस दौरान पायलट ने देखा कि अंधेरा हो रहा है. डीजीसीए की गाइड लाइन का उल्लंघन होने से इस पर तलवार लटक सकती है. इसलिए बिना ख़तरा उठाए पायलट शाम सवा पांच बजे हेलीकॉप्टर लेकर वापस एयरपोर्ट पहुंच गया. जनसभा के बावजूद मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और सांसद अज़हरुद्दीन पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ हेलीपैड पर पहुंचे, लेकिन वहां हेलीकॉप्टर नहीं था. बाद में पता चला कि हेलीकॉप्टर लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच गया है. नेताओं ने पायलट को ख़ूब खरी खोटी सुनाई, लेकिन पायलट ने गाइड लाइन का हवाला देते हुए किसी तरह समझाकर अपने को बचाया. पायलट का कहना था कि डीजीसीए की गाइड लाइन व एटीसी के बढ़ते दबाव के कारण उसे समय से लखनऊ पहुंचना था. विवश होकर दोनों नेता सड़क मार्ग से बस्ती से लखनऊ आए. तब कहीं जाकर उन्हें हेलीकॉप्टर मिला.

कांशीराम के भाई दरबारा सिंह ने कहा, बहुजन समाज पार्टी को वोट न दें

बहुजन संघर्ष पार्टी के अध्यक्ष व कांशीराम के भाई एस दरबारा सिंह ने उत्तर प्रदेश की जनता से आह्वान करते हुए कहा कि लोग बहुजन समाज पार्टी को वोट न दें. उन्होंने कहा कि कांशीराम का समाज तो बहुजन ही रह गया, लेकिन मायावती उनके भाई आनंद धन-जन हो गए. जब तक इस धन को बहुजन समाज को वापस नहीं दिला देंगे, तब तक वह चैन की सांस नहीं लेंगे. दरबारा सिंह ने लखनऊ में कहा कि चुनाव आयोग ने आचार संहिता के तहत मायावती एवं हाथी की मूर्तियों को ढकने का आदेश दिया था. लेकिन शासन के लोगों ने गैर क़ानूनी तरीक़े से बहुजन महानायक कांशीराम की मूर्ति को भी ढक दिया, जिससे आघात लगा है. बहुजन समाज के वोट के बल पर सत्ता का सुख भोगने वाली मायावती ने कांशीराम की मूर्तियों को ढके जाने का विरोध नहीं किया. दरबारा सिंह ने आरोप लगाया कि मायावती ख़ुद को कांशीराम का उत्तराधिकारी बताती है, लेकिन उन्हें यह पता ही नहीं है कि लोकतंत्र में उत्तराधिकारी नहीं होता. उनका कहना है कि कांशीराम ने जो कुर्बानी बहुजन समाज को आगे बढ़ाने के लिए दी थी, मायावती इससे भटक गई हैं. बहुजन समाज की मेहनत से एकत्र किए गए धन को सतीश चंद्र मिश्र, पोंटी चड्ढा, बाबू सिंह कुशवाहा, मायावती के भाई आनंद की कंपनियों ने जमकर लूटा है. इसके लिए उनकी पार्टी संघर्ष करेगी. कांशीराम के भाई ने बहुजन समाज पार्टी के लोगों से अपील की है कि वह विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को वोट न दें. इससे पहले उन्होंने राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय जाकर अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक ज्ञापन देकर मायावती के साथ कांशीराम की बंद की गई मूर्ति को खुलवाने की मांग की. इस मौक़े पर उनके दल के कई पदाधिकारी भी थे.

बीवी को लेकर दुविधा में मियां

उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद की ठाकुर द्वारा विधानसभा सीट पर घोषित भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सर्वेश सिंह की पत्नी साधना सिंह को परिसीमन के बाद पड़ोसी ज़िले बिजनौर की सीट बढ़ापुर से महान दल का प्रत्याशी घोषित कर दिए जाने से भाजपा प्रत्याशी के सामने धर्मसंकट आ गया है. भाजपा से चार बार के विधायक रह चुके ठाकुर द्वारा के सर्वेश सिंह इस बार अपनी पत्नी के लिए भी बढ़ापुर से पार्टी का टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने सर्वेश सिंह की पत्नी के बजाय इसी क्षेत्र से कभी पार्टी के विधायक रहे डॉ. इंद्रदेव सिंह को प्रत्याशी घोषित कर दिया. विधानसभा के पिछले चुनाव में भाजपा के सर्वेश सिंह ठाकुर द्वारा सीट पर बसपा प्रत्याशी विजय यादव से हार गए थे. विजय यादव को इस बार बसपा से टिकट नहीं मिला तो वे महान दल के प्रत्याशी बन गए. उनके मुक़ाबले भाजपा ने सर्वेश सिंह को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया. भाजपा प्रत्याशी सर्वेश सिंह अपनी पत्नी साधना सिंह को भी बढ़ापुर से टिकट दिए जाने की जिद पर अड़े थे. लेकिन वहां पूर्व में अफजलगढ़ (बिजनौर) से दो बार भाजपा के टिकट पर जीते डॉ. इंद्रदेव सिंह को ही अंततः पार्टी ने उम्मीदवार बनाया. लोकसभा के पिछले चुनाव में सर्वेश सिंह मुरादाबाद संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी थे. कांग्रेस के अज़हरुद्दीन ने उन्हें लगभग 50 हज़ार मतों से हरा दिया था. चौहान जाति बहुल बढ़ापुर नए परिसीमन में बिजनौर की नई सीट बनी सीट पर सर्वेश सिंह अपनी पत्नी साधना सिंह के लिए भाजपा से टिकट मांग रहे थे, लेकिन भाजपा ने साधना सिंह की बजाय इंद्रदेव को प्रत्याशी बना दिया. इस पर साधना सिंह ने महान दल की उम्मीदवारी स्वीकार कर ली है. अब मियां जी बीवी के विरोधी दल में होने से धर्म संकट में फंस गए हैं.

लखनऊ का बाघ प्रभावित मतदान केंद्र

मलिहाबाद विधानसभा के काकोरी इलाक़े के चार मतदान केंद्रों को बाघ प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है. चुनाव आयोग के अनुसार दो मतदान केंद्रों को संवेदनशील और दो मतदान केंद्रों को अतिसंवेदनशील चिन्हित किया गया है. मलिहाबाद विधानसभा के एसडीएम एवं आर ओ अशोक कुमार ने बताया कि बाघ के कारण चुनाव प्रभावित न हों, इसलिए जिलाधिकारी एवं ज़िला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार सागर के निर्देश पर दुगोल ग्राम पंचायत के मतदान केंद्र दुगोल और मजरा इलरापुर पोलिंग स्टेशन संख्या 248 और पोलिंग सेंटर 249 में मोहम्मद नगर और रहमतनगर के मीठेपुर गांव में मतदान के एक दिन पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी जाएगी. मीठेपुर और इलरपुर के लोगों को मतदान के दिन पेट्रोलिंग कर मतदान केंद्र तक लाया जाएगा. सात जानवारों का शिकार कर चुके बाघ के कारण आग आदि जलाकर कांबिंग होगी. बाघ से बचाने के लिए सशस्त्र पुलिस लगाए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

कांग्रेस बढ़ती रही, उत्तर प्रदेश पिछड़ता रहा

अजय कुमार

देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था. कांग्रेस ने यहां क़रीब चालीस साल तक राज किया. इस दौरान प्रदेश भले ही पिछड़ता गया, लेकिन प्रदेश की बदौलत कांग्रेस दिल्ली तक में अपनी विजय पताका फहराती रही. [illegible]

कम रहा. आपातकाल के साये और लोकनायक जय प्रकाश नारायण के आंदोलन के बीच हुए 1977 चुनाव में देश के साथ-साथ प्रदेश में जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन यह प्रयोग कामयाब नहीं रहा. तीन साल बाद ही कांग्रेस फिर सत्ता में वापस लौट आई. राज्य में सबसे बड़ा बदलाव 1989 में आया. उस समय राम मंदिर आंदोलन गति पकड़ रहा था. अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद को मंदिर बनाने के लिए शिलान्यास करने की अनुमति कांग्रेस की केंद्र सरकार से मिल गई. हालांकि कांग्रेस के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने बाबरी मस्जिद से दूर शिलान्यास की अनुमति दी थी, फिर भी मुसलमान कांग्रेस से नाराज़ हो गए. यह न केवल प्रदेश बल्कि देश की राजनीति में भी नया टर्निंग प्वाइंट साबित हुआ. बोफोर्स व बाबरी मस्जिद विवाद की छाया में हुए लोकसभा तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जनता दल की जीत हुई तो भाजपा की सफलता का भी ग्राफ बढ़ा. जनता दल सरकार में भी आपसी कलह की शिकार हो गई. दूसरी तरफ़ मंदिर आंदोलन तेज़ी पकड़ता गया. इससे निपटने के लिए वीपी सिंह ने मंडल कमीशन का कार्ड चला तो भाजपा ने सोमनाथ से लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा निकाल कर अयोध्या मुद्दे को हवा दे दी. इसी बीच एक ख़ामोश क्रांति भी जन्म ले रही थी. दलित मूवमेंट की. इसके अगुवा कांशीराम थे. वह दलितों के मसीहा के रूप में उभर रहे थे. इसमें पिछड़ों के लिए तो जगह थी, लेकिन अपर कास्ट के लिए दरवाज़े बंद थे. कांशीराम के साथ मायावती लगी थीं. उनकी मुखरता दलितों में एक नया जोश और जुनून पैदा कर रही थी. बसपा ने पहली बार 1989 में राज्य की विधानसभा में अपने पैर रखे और इसके 13 प्रत्याशी चुनाव जीते.

मंडल-कमंडल की राजनीति को चरम से नीचे ढकेलने का काम कांशीराम का दलित मूवमेंट करता जा रहा था. इसके बावजूद मंडल-कमंडल की राजनीति करने वाले हार मानने का तैयार नहीं थे. वर्ष 1991 में राम लहर चली तो भाजपा प्रदेश पर सत्तारूढ़ हो गई. भाजपा हिंदू वोटों के सहारे जीती थी. फिर भी बसपा 12 सीटें निकालने में सफल रही. इसे 9.52 फ़ीसदी वोट मिले. वर्ष 1992 में विवादित ढांचा गिरने के बाद भाजपा हिंदू वोटों को लेकर मुग़ालते में आ गई, तो मुलायम सिंह मुस्लिम कार्ड खेलकर भाजपा को पटख़नी देने की फ़िराक़ में लग गए. मुलायम को यह लगा कि भाजपा की आंधी को अकेले रोकना उनके लिए मुश्किल है तो उन्होंने बसपा से हाथ मिला लिया. यह गठजोड़ प्रभावशाली रहा. बसपा को 67 सीटें एवं 11.11 फ़ीसदी वोट मिले. भाजपा सत्ता से बाहर हो गई. गठजोड़ के सहारे ही सही दलितों ने पहली बार सत्ता का स्वाद चखा, लेकिन बसपा संस्थापक कांशीराम व मायावती उतने से कहां संतुष्ट होने वाले थे. वह तो जिसकी जितनी भागीदारी, उसकी उतनी साझेदारी की बात कर रहे थे. मुलायम इसके लिए सीढ़ियों से अधिक कुछ नहीं थे. मौक़ा देखकर अपने साथ चलने वाली मायावती को मान्यवर कांशीराम ने प्रदेश में अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर दिया. इस बीच प्रदेश में सपा-बसपा गठबंधन की सरकार में दरार बढ़ती जा रही थी. दलितों के उत्थान के लिए बसपा किसी को अछूत नहीं मानती थी. वह सत्ता में भागीदारी के लिए कांग्रेस, भाजपा या फिर समाजवादी पार्टी किसी से समझौता करने में गुरेज़ नहीं करती. आख़िरकार मई 1995 में भाजपा और बसपा के बीच अप्रत्याशित समझौता हुआ. बसपा ने मुलायम सिंह यादव की सरकार से समर्थन वापस ले लिया. बसपा विधायकों को अपहृत करने के चक्कर में 2 जून को स्टेट गेस्ट हाउस की घटना हुई. बसपा ने मुलामय सरकार से समर्थन वापस लिया तो भाजपा ने बसपा की सरकार बनवा दी. मायावती को पहली दलित मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य मिला.

इसके बाद उत्तर प्रदेश विकास की दौड़ में पिछड़ता गया और जातिवाद हावी होता गया. मायावती सरकार सिर्फ़ पांच माह चली, लेकिन दलितों को सत्ता का स्वाद लग चुका था. 1996 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने कांग्रेस से हाथ मिलाकर पिछड़ों और दलितों को साथ लेकर अपनी ताक़त को बढ़ाने का प्रयोग किया. पार्टी ने 67 सीटें जीतीं और 19.67 फ़ीसदी वोट मिले, लेकिन बसपा ने सरकार बनाने के लिए कांग्रेस का हाथ झटक कर भाजपा का हाथ थामने में ज़रा भी देरी नहीं की. भाजपा और बसपा के बीच 6-6 माह मुख्यमंत्री के लिए समझौता हुआ. पहले मायावती की बारी आई. मायावती ने अपनी बारी तो पूरी कर ली, लेकिन जब भाजपा का मौक़ा आया तो वह आंखें दिखाने लगीं. बसपा-भाजपा का यह क़रार फिर टूटा. बसपा को कोई अफ़सोस नहीं हुआ. उसके नेता तो कहते थे कि जल्द चुनाव से उनकी पार्टी को फ़ायदा मिलता है तो उन्हें जल्द चुनाव से कोई परहेज़ नहीं हैं. अब तक बसपा के पंख निकल आए थे. वह अकेले उड़ान भरने को उतावली होने लगी. 2002 के विधानसभा चुनाव में बसपा अकेले दम पर लड़ी. क़रीब सौ सीटें जीतकर बसपा ने भाजपा को तीसरे स्थान पर धकेल दिया. 2002 के विधानसभा चुनाव में दलित सवर्ण समीकरण के सार्थक नतीजे दिखे तो बसपा ने 2007 के विधानसभा में भी इसे आगे बढ़ाया और इसमें मुसलमानों को भी जोड़कर सोशल इंजीनियरिंग के दम पर 206 सीटों का जादुई आंकड़ा हासिल करके क़रीब डेढ दशक के लंबे अंतराल के बाद प्रदेश में बहुमत की सरकार बनाने में सफ़ल रही. अबकी बार भी बसपा इसी समीकरण पर काम कर रही है. वहीं अन्य दल बसपा की सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले पर पानी फेरने के चक्कर में हैं. अबकी बार राहुल मुस्लिम वोटरों के सहारे बसपा को सत्ता से बाहर करने की जुगत भिड़ा रहे हैं, वहीं भाजपा सवर्ण-पिछड़ों के सहारे अपनी नैया पार करने के चक्कर में हैं. मुलायम भी भाजपा की तरह मुसलमानों और यादवों के अलावा पिछड़ों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ समस्या यह है कि वह एक को मनाते हैं तो दूसरा रूठ जाता है.

feedback@chauthiduniya.com

पश्चिमी उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी आगे

[illegible]

मुक़ाबला रोमांचक हुआ

फ़िरोज़ाबाद के शहरी सदर सीट पर सपा, बसपा और भाजपा ने मज़बूत प्रत्याशी उतारे हैं. कांग्रेस की भी इस सीट पर नज़र है, जिससे यहां मुक़ाबला चतुष्कोणीय बन गया है. पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के राज बब्बर ने चुनाव जीता था. इस बार विधानसभा चुनाव में सपा ने फ़िरोज़ाबाद की शहरी सदर सीट को अपनी प्रतिष्ठा बना लिया है. यहां से बसपा के राष्ट्रीय महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीक़ी चुनाव लड़ रहे हैं. पिछले चुनाव में उन्होंने यह सीट जीती थी. उन्होंने दलित, मुस्लिम और पिछड़ी जातियों के बूते सफलता हासिल की थी. 2002 के चुनाव में सपा के अज़ीम भाई चुनाव जीते थे. पार्टी ने एक बार फिर इन पर भरोसा जताया है. बसपा ने ख़ालिद नसीर, कांग्रेस ने आज़ाद अकरम को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि भाजपा ने विवादास्पद रहे मनीष असीजा को टिकट थमा दी है. सदर सीट पर तीन लाख से ज़्यादा मतदाता हैं, जिनमें एक लाख मुस्लिम मतदाता हैं. कांच उद्योग के कारण इस क्षेत्र में व्यापारिक कार्य अच्छे स्तर पर होता है. मुस्लिमों के बाद शहरी सीट पर वैश्य मतदाता प्रभावी हैं. आमतौर पर वैश्यों को भाजपा समर्थक माना जाता है. वैश्य मतदाता भाजपा के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन प्रत्याशी से नाराज़ हैं. अपनी नाराज़गी दर्ज कराने के लिए वे सपा, बसपा अथवा कांग्रेस प्रत्याशी को वोट कर सकते हैं. स्वाभाविक रूप से भाजपा के विकल्प के तौर पर वैश्य मतदाता कांग्रेस प्रत्याशी को समर्थन दे सकते हैं. सपा, बसपा और कांग्रेस ने मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दी है, इसलिए भाजपा यह मानकर चल रही है कि चुनाव तक मुस्लिम और हिंदू वोट के बीच बंटवारा होगा और मनीष असीजा विजयी हो जाएंगे. दलित और अधिसंख्य पिछड़ी जाति के मतदाता भाजपा के पक्ष में न होकर बसपा और सपा के बीच विभाजित हैं. इन दोनों दलों से नाराज़ यह वोट बैंक कांग्रेस को समर्थन भी दे सकता है. भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ अन्ना हजारे के आंदोलन को समर्थन देने वाली भाजपा यदि साफ़ छवि वाले किसी उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारती तो उसकी विजय के अवसर बढ़ जाते. भाजपा प्रत्याशी केवल मत विभाजन की स्थिति में ही जीत की आस लगा सकते हैं. वहीं बसपा प्रत्याशी को मुसलमानों का वोट अवश्य मिलेगा, लेकिन सत्ता विरोधी लहर का ख़ामियाज़ा उसे भुगतना पड़ सकता है. सपा ने पूर्व विधायक अज़ीम भाई को चुनावी मैदान में उतारकर जंग छेड़ दी है, तो कांग्रेसी सांसद राज बब्बर ने भी इसे अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है.

भी हो सकता है. पिछले चुनाव में रालोद को प्रदेश में 10 सीटें हासिल हुई थी, इस बार इसका आंकड़ा 15 से ज़्यादा नहीं होने वाला है. त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति में कई स्थानों में इसे हार का सामना भी करना पड़ेगा, जबकि कांग्रेस को 22 सीटें मिली थीं. [illegible]

अमिताभ आकाश
feedback@chauthiduniya.com

सियासी महाकुंभ में डुबकी लगाते सितारे

उत्तर प्रदेश के सियासी दल प्रत्याशियों को जिताने के लिए पार्टी के स्टार प्रचारकों का सहारा ले ही रहे हैं. वहीं फिल्म स्टार राजा बुंदेला और गोरखपुर की कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर भोजपुरी फिल्मों में किरदार निभाने वाली काजल निषाद भी चुनाव मैदान में तक़दीर आज़मा रही हैं. कांग्रेस का जहां हाईटेक प्रचार जारी है, वहीं पार्टी ने सबसे ज़्यादा फिल्म स्टार और सिने तारिकाओं को प्रचार के लिए आमंत्रित किया है. वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव में सपा से किनारा कर चुके अमर सिंह ने आज़म ख़ां को हराने के लिए अभिनेत्री और सांसद जयाप्रदा को पहले तो चुनाव मैदान में उतारने का मन बना लिया था, लेकिन कुछ सोचकर जयाप्रदा को रोक दिया. अब जयाप्रदा लोकमंच के लिए प्रचार कर रही हैं. कांग्रेस पार्टी ने गोविंदा, सलमान ख़ान, नग़मा, संजय दत्त, रज़ा मुराद, राज बब्बर, मुज़फ्फ़र अली जैसे कई कलाकारों को प्रत्याशियों के प्रचार के लिए भेजा है. राजनीतिक गलियारों में चर्चा यह है कि बुंदेलखंड कांग्रेस चुनाव प्रचार में फिल्मी सितारों की एक बड़ी टीम लेकर आई है, जिसमें अभिनेत्री सुष्मिता मुखर्जी, रघुवीर यादव, ओमपुरी, सतीश कौशिक, आशुतोष राणा, राजपाल यादव प्रमुख हैं. भाजपा ने अभिनेता सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, स्मृति ईरानी तथा हेमा मालनी को चुनाव प्रचार के लिए प्रदेश में बुलाया है. अंबेडकर नगर में अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि जनता का विश्वास नेताओं से उठ गया है, क्योंकि नेताओं ने सेवा नीति त्याग दी है. कांग्रेसी सांसद व सिने स्टार राज बब्बर ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती हैं. फिल्म अभिनेत्री नग़मा ने कहा कि अपनी ताक़त को पहचानें और इसका सही प्रयोग करें. कांग्रेस पार्टी ही प्रदेश का विकास करा सकती हैं. अभिनेता संजय दत्त दो क़दम आगे बढ़कर कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट देना ज़रूरी है. मैं दो साल के लिए भटक गया था, लेकिन वापस आ गया. फ़िलहाल ख़बर यह है कि निर्वाचन आयोग ने पहले चरण के मतदान वाले ज़िलों से इन सभी स्टार प्रचारकों एवं नेताओं को तत्काल ज़िला छोड़ने का हुक्म दिया है जो इस क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं.

दर्शन शर्मा
feedback@chauthiduniya.com

राजनीतिक दलों के खोखले वादे

[illegible]

योगेंद्र सिंह चौहान
feedback@chauthiduniya.com

एक नज़र

धौलाना में मुस्लिम मत विभाजन से भाजपा ख़ुश

कांग्रेस, सपा और बसपा में मुस्लिम तुष्टीकरण नीति से भाजपा ख़ेमे में ख़ुशी छाई है. कांग्रेस ने जहां मुस्लिमों को साढ़े चार प्रतिशत आरक्षण का लॉलीपॉप देकर अपनी तरफ़ आकर्षित किया है. वहीं सपा सुप्रीमो ने सत्ता में आने पर आबादी के हिसाब से 18 प्रतिशत आरक्षण की बात उठाई है. बसपा ने भी मुस्लिमों को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है. हापुड़ की धौलाना विधानसभा सीट से बसपा ने दबंग नेता असलम चौधरी को उम्मीदवार बनाया है. बसपाइयों का मानना है कि असलम चौधरी की लोकप्रियता से वह विजयी होंगे. कांग्रेस-रालोद गठबंधन में इस सीट पर रालोद ने पहले बॉसिद प्रधान को प्रत्याशी घोषित किया. बाद में कार्यकर्ताओं के आक्रोश के चलते उम्मीदवार को बदलना पड़ा. अतः प्रधान की जगह वकील अयूब अली को प्रत्याशी घोषित किया गया. क्षेत्र में इस बात की चर्चा है कि कांग्रेस के प्रधान का टिकट कट जाने से उन्होंने पीस पार्टी का दामन थाम लिया. सपा ने धर्मेश तोमर को उम्मीदवार बनाया है. उनका मानना है कि मुस्लिम समाज उनके साथ है. ठाकुर और मुसलमानों के सहारे उनके प्रत्याशी को विजय मिलेगी. भाजपा ने वाईपी सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है. भाजपा को विश्वास है कि सपा, बसपा और रालोद तथा पीस पार्टी के बीच मुस्लिम मतों का विभाजन तय है, जिसका पूरा लाभ भाजपा प्रत्याशी को मिलेगा.

उमा भारती का जवाब साधना भारती

भाजपा की फायर ब्रांड नेत्री उमा भारती के आक्रामक तेवरों से सभी परिचित हैं. वह पार्टी की स्टार प्रचारक हैं. अपने ओजस्वी भाषणों और तर्कों से वह मतदाताओं पर असर डाल देती हैं. चुनाव प्रचार के दौरान उनके जुमले समाचार पत्रों की सुर्ख़ियां बनतीं हैं. उनकी लोकप्रियता का अंदाज़ा उनकी जनसभाओं में उमड़ने वाली भीड़ से लगाया जा सकता है. राममंदिर आंदोलन के दौरान उनके भाषणों से भाजपा का वोट बैंक बढ़ गया था और भाजपा ने उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि नई दिल्ली में भी सरकार बना ली थी. उमा भारती की भाषण शैली का जवाब कांग्रेस ने ढूंढ लिया है. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उनकी ही शैली में उनकी ही जाति की उनके ही तेवरों में लगभग इसी अंदाज़ में कांग्रेस की साधना भारती मतदाताओं के बीच कांग्रेस की नीतियों का बखान कर रही है. उसकी उम्र महज़ 14 साल ही है, लेकिन उसके बोलने की बेबाक शैली मतदाताओं को आकर्षित कर रही है. पूरे प्रदेश का दौरा कर रही साधना भारती की जनसभाओं में भीड़ जुट रही है. वह केंद्रीय विद्यालय दिल्ली में 12 कक्षा की छात्रा है. उसे कांग्रेस के इतिहास की अच्छी ख़ासी जानकारी है. कांग्रेस की नीतियों में आस्था रखने वाली साधना भारती पर कांग्रेस के दिग्गज दिग्विजय सिंह की नज़र पड़ी तो उन्होंने इसे सोनिया गांधी, राहुल गांधी से मिलवाया. साधना की जानकारी और बोलने के अंदाज़ के बाद पार्टी ने इसे अपना स्टार प्रचारक घोषित कर उत्तर प्रदेश में चुनावी सभाओं को संबोधित करने के लिए भेजा है.

-प्रियंका सिंह

जनता भुखमरी से बेहाल

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी हंगर इंडैक्स की रिपोर्ट के अनुसार, [illegible]

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

यह पहला मौक़ा था जब उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनावी समर में पूरा परिवार सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा प्रियंका गांधी वाड्रा, रेहान और मिराया एक साथ दिखाई दिए.

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. DELHIN/2009/30467

गांधी परिवार की पांचवी पीढ़ी भी दिखी चुनावी जंग में

संजय सक्सेना

गांधी परिवार में आजकल अजीब सी उथल–पुथल दिखाई दे रही है. ऐसा लग रहा है गांधी परिवार के कंधों पर कांग्रेस की साख और अपने परिवार की प्रतिष्ठा दोनों ही बचाए रखने की ज़िम्मेदारी आ गई है. इसलिए नानी (सोनिया गांधी) से लेकर प्रियंका के बच्चे (रेहान और मिराया) तक ठीक वैसे ही राजनीतिक मंच पर हाथ हिलाते नज़र आने लगे हैं, जैसे कभी इंदिरा गांधी के साथ उनके बेटे संजय और राजीव गांधी नज़र आते थे. इसके बाद राजीव गांधी के साथ प्रियंका और राहुल गांधी नज़र आने लगे थे. रेहान और मिराया को आगे लाकर प्रियंका ने इस परंपरा को आगे बढ़ाने का ही काम किया है. यह पहला मौक़ा था जब उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनावी समर में पूरा परिवार सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा प्रियंका गांधी वाड्रा, रेहान और मिराया एक साथ दिखाई दिए. फ़र्क़ बस इतना था कि पूरा परिवार तो कांग्रेस के मंच पर दिखा, लेकिन गांधी ख़ानदान एकजुट नहीं हो सका. गांधी ख़ानदान का एक परिवार कांग्रेस को मज़बूत करने का बीड़ा उठाए हुए था तो दूसरा परिवार कांग्रेस को परास्त करके भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने की मुहिम में लगा था. सोनिया और राहुल गांधी से इतर गांधी ख़ानदान की दूसरी बहू मेनका गांधी और पौत्र वरुण गांधी भाजपा के चिराग़ बने हुए हैं. पहली बार उत्तर प्रदेश में गांधी ख़ानदान के आठ सदस्य चुनाव प्रचार मैदान में हैं. इन आठों में से न तो कोई विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है और न ही सत्ता का सुख भोग रहा है. फिर भी सभी को स्टार प्रचारक का दर्जा मिला हुआ है. बदलाव की बात की जाए तो नेहरू–इंदिरा और राजीव गांधी के समय में कांग्रेस में पूरे परिवार का नहीं किसी एक सदस्य का दबदबा रहता था, जैसा आज गांधी परिवार में देखने को नहीं मिल रहा है.

उत्तर प्रदेश के चुनावी समर में गांधी परिवार के सदस्यों को विभिन्न मंचों पर देखकर वे लोग तो काफ़ी खुश हैं जो इस परिवार से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, लेकिन दुखद पहलू यह भी है कि प्रचार के दौरान गांधी परिवार के भीतर की राजनीतिक कशमकश खुलकर सामने आ रही है. अमेठी में दिया गया रॉबर्ट वाड्रा का बयान, अभी राहुल का समय है, फिर प्रियंका का आएगा ने राजनीति में सनसनी फैला दी. इससे कांग्रेसी उबर भी नहीं पाए थे कि उनका ही एक और बयान आ गया, अगर जनता चाहेगी तो मैं चुनाव लड़ सकता हूं. भला हो प्रियंका का जो उन्होंने यह कहकर बात संभाल ली कि रॉबर्ट अपने बिजनेस में ख़ुश हैं और राजनीति में नहीं आना चाहते हैं. बहरहाल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंदिरा गांधी के हाथों से होते हुए सोनिया गांधी के हाथों तक कांग्रेस की बागडोर पहुंचते–पहुंचते कांग्रेस में काफ़ी कुछ बदल गया है. वर्ष 1964 में नेहरू के निधन के बाद ही इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की कैबिनेट में शामिल हुईं. इसके बाद कांग्रेस ने वर्ष 1967 का चुनाव इंदिरा की अगुवाई में लड़ा तो वह मरते दम तक कांग्रेस की बागडोर संभाले रहीं. इंदिरा गांधी के समय में कुछ समय के लिए संजय गांधी राजनीति में दिखे तो ज़रूर, लेकिन सत्ता सुख उठाने की लालसा उन्होंने कभी नहीं दिखाई. संजय इमरजेंसी के बाद चुनाव मैदान में आए. 1977 में हारे तो 1980 में यह कहते हुए अमेठी से चुनाव लड़े कि जीते तो उत्तर प्रदेश की सत्ता की कमान वही थामेंगे, लेकिन उनका यह सपना पूरा नहीं हो पाया. वर्ष 1980 में संजय गांधी की अकाल मृत्यु के बाद राजीव गांधी राजनीति में आए. इसके बाद इंदिरा गांधी के असामायिक मौत के बाद वर्ष 1984 में राजीव गांधी ने काफ़ी दबाव के बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली. वर्ष 1991 में राजीव गांधी की भी असमय मौत हो गई.

राजीव गांधी के जाने के बाद एक तरह से गांधी परिवार में राजनीति के प्रति शून्यता सी आ गई. संजय गांधी की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी ने बहू मेनका के लिए घर के दरवाज़े बंद कर दिए थे और सोनिया गांधी देश की ख़ातिर अपने परिवार की क़ुर्बानी देने को तैयार नहीं थीं. वह पर्दे के पीछे से तो राजनीति करती रहीं, लेकिन सामने नहीं आईं. यह दौर कांग्रेस के लिए काफ़ी बुरा रहा. राजीव की मौत के लगभग छह साल बाद सक्रिय राजनीति में प्रवेश करने वाली सोनिया गांधी वर्ष 1998 में प्रधानमंत्री बनने के लिए इतनी उत्साहित दिखीं कि जब वाजपेयी सरकार गिरी तो समर्थन का आंकड़ा जोड़े बग़ैर ही वह राष्ट्रपति के पास सरकार बनाने का दावा लेकर पहुंच गईं. राष्ट्रपति भवन में क्या बातें हुईं, यह तो कोई नहीं जानता लेकिन इसके बाद सोनिया ने कभी प्रधानमंत्री बनने का सपना नहीं पाला. वर्ष 2004 में चुनाव के दौरान सोनिया गांधी को ही कांग्रेस ने बतौर प्रधानमंत्री सामने किया था. इसके बाद से वह लोकसभा का चुनाव तो लड़ती रहीं, लेकिन प्रधानमंत्री बनने की बजाय उन्हें किंगमेकर की भूमिका निभाना ज़्यादा रास आया. वह प्रधानमंत्री तय करने की भूमिका निभाती हैं. मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हैं, तो इसका सारा श्रेय गांधी परिवार को जाता है. वैसे कहा यही जा रहा है कि अगर नतीजे कांग्रेस के पक्ष में रहे तो वर्ष 2014 में गांधी परिवार फिर सत्ता की बागडोर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाकर अपने हाथ में ले सकता है. सोनिया गांधी ने सक्रिय राजनीति में आने के बाद पहला काम राहुल को राजनीति की बिसात पर उतारने का किया, लेकिन राहुल को प्रधानमंत्री का ताज पहनते देखने के लिए उन्होंने कोई जल्दबाज़ी नहीं की. उन्होंने इस बात का भी ध्यान रखा कि गांधी परिवार को कोई चुनौती न दे पाए. इसलिए सोनिया ने तमाम दिग्गज कांग्रेसी नेताओं को अनदेखा करके मनमोहन सिंह जैसे सीधे–साधे अर्थशास्त्री को दो बार लगभग केयरटेकर प्रधानमंत्री की तरह कुर्सी पर बैठा दिया.

सोनिया के दौर में कांग्रेस का इतिहास पहली बार बदलता दिखा, क्योंकि जो गांधी परिवार सत्ता से लेकर पार्टी तक पर अपनी लगाम रखता था, वह सत्ता से दूर पार्टी संगठन में भी कई हिस्सों में बंटता दिखने लगा. सोनिया गांधी से अलग कहीं राहुल गांधी तो कहीं प्रियंका और राबर्ट वाड्रा में कांग्रेसी अपनी पहचान तलाशते रहे. मानो सबको इस परिवार के आशीर्वाद की ज़रूरत हो. अगर सोनिया से आशीर्वाद न मिले तो राहुल से, राहुल से न मिले तो प्रियंका से और इनसे भी न मिले तो रॉबर्ट वाड्रा से आशीर्वाद हासिल करने वालों की हसरत बढ़ती ही गई. इन परिस्थितियों ने गांधी परिवार में नए अंतर्विरोध पैदा कर दिए. आज गांधी परिवार को लेकर कांग्रेस का मन बदल गया है. इसी का असर है कि अमेठी में प्रचार करते हुए रॉबर्ट ने एक ही झटके में कह दिया कि अगर जनता ने चाहा तो वह भी चुनाव लड़ने को तैयार हैं. निश्चित तौर पर रॉबर्ट का यह बयान गांधी परिवार के तिलिस्म को तोड़ता है और 19वीं सदी के गांधी परिवार से 21वीं सदी की चौथी पीढ़ी को अलग–थलग भी करता है. इसी का प्रभाव है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के संगठन से लेकर उम्मीदवारों को जिताने या इन्हें मंच से पहचान देने के लिए भी गांधी परिवार को ही मशक़्क़त करनी पड़ रही है. इस मशक़्क़त में अब पांचवी पीढ़ी के रूप में प्रियंका के बच्चे भी खड़े हो गए हैं. निश्चित ही कहीं न कहीं गांधी और वाड्रा परिवार में यह सोच काम कर रही है कि किस तरह से कांग्रेस को अपनी मुट्ठी में कर लिया जाए. हो सकता है कि नेहरू से शुरू होकर गांधी और इसके बाद वाड्रा परिवार को यह मौक़ा मिल जाए. कांग्रेस पर ढीली पड़ती सोनिया की पकड़ और परिवार में जारी कशमकश परिवार में बिखराव का संकेत दे रहे हैं. पहले मेनका गांधी द्वारा अपने पुत्र के साथ परिवार से दूर होकर अलग रास्ता पकड़ना और अब प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा के मन में राजनीतिक महत्वाकांक्षा का जगना लोग गांधी परिवार के तीसरे कोण के रूप में देख रहे हैं.

feedback@chauthiduniya.com